



The Gazette of India

श्राधिकार से त्रकारित PUBLISHED BY AUTHORITY

r 0 16

नई बिल्ली, शनियार, अप्रैल 19, 1986/चैत्र 29, 1908

No. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1986/CHAITRA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह मजन संकारन के रूप में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—सण्ड ३—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

> विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

स्चना

का. आ. 1540. नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना वी जाती है कि श्रीमती यास छिखार, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली राज्य में व्यवसाय करने के लिए गेटरी के रूप में नियक्त किया आए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकादन के जीवह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(39)/86-न्या.]

आर. एन. पोववार, सकम गाधिकारी

MINISTRY OF LAW & JUSTICE (Department of Legal Affairs)
New Delhi, the 7th April, 1986

NOTICE

S.O. 1540.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Mrs. Yash Chhibber, Advocate for apopintment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(39) /86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गह मंत्रालय

नई विल्ली, 8 प्रप्रील, 1986

का. शा. 1541: — सःवंजिनिक परिसर (श्रवेश कब्जा वेदलली) श्रीधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्निकित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित श्रीधिकारी को, भारत सरकार का एक राजपित श्रीधिकारी होने के नाते उक्त श्रीधिनियम के प्रयोजन के लिए संपद्य श्रीधिकारी नियुक्त करती है और शांगे निवेश देती है कि यह श्रीधिकारी सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में उक्त श्रीधिनियम के द्वारा श्रीधिकारी को श्री श्री हम संबंध में उक्त श्रीधिनियम के द्वारा श्रीधित उसके श्रीधीन संपदा श्रीधिकारी को श्री

भिकारी का पद

सावंजनिक परिश्ररों की श्रेणिया

2

1

सहायक निवेशक (प्रशासन) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्ष पुलिस बल, मई दिल्ली। संपदा निदेशालय द्वारा केण्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल महानिवेशालय की सौपे गए केन्द्रीय पूल भावास सिंहत केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल महा।नवेशालय, नई विल्ली से संबंधित सार्वजनिक भवन या लीज पर 1 2

सिए गए या प्रशिवाहीत किए गए या जनकी जीर से लिए गए सरकारी भवन

[सं. प-2-6/86-प्रका. 3/के.पि.पु.च./गू.मं./एफ पी-4] भी. के. जैन, संगुक्त समित्र ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1541—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in the column (1) of the Table below being a Gazetted officer of the Government of India, to be the state officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said Officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table:—

TABLE

Designation of the officer	Categories of the public pre- mises
1	2
Assistant Director Administration), Directorate General, Contral Reserve Police Force, New Delhi.	Public premises belonging to or taken on lease requisitioned by or on behalf of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi including the General Pool accommodation placed at the disposal of the Directorate General, Central Reserve Police Ferce by the Directorate of Estates in Delhi/New Delhi.

[No. A-II-6/86-Adm-3/CRPF/MHA/F.P. IV]

V. K. JAIN Jt. Secy.

वित्त मेनावय

(राषस्य विभाग)

नर्ष दिल्ली, 3 मार्च, 1986

आयकर

का. वा. 1542 — आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (क) द्वारा प्रदत्त शिक्षतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतब्द्वारा, ''मायलापोर, मचास स्थित दि जी वलीश्वर मन्दिर/देवस्थानम्, मदास'' को ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में अधिस्थित करती है।

[सं. 6611 (फा.सं. 176/76/85-आ.क.नि. 1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd March, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 1542.—In exercise of the powers conferred by subsection (2)(b) of Sction 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies

"The Sri Valleeswarar Temple Devasthanam, at Mylapore, Madras as a place of historic importance,

[No. 6611(F. No. 176/76/85-IT(AI)]

का. आ. 1543.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2) (स) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते छुए केन्द्रीय सरकार एतव्हारा, ''श्री आस्मानाथ सामी श्रीवर, तिस्थ्यस्नतृर, हमिलनाड़'' को समस्त तिमलनाड़ राज्य में विस्थात सार्वजनिक पूजा स्थल अधिसूचित करती है।

[सं. 6610 (फा. सं. 176/48/85-अर.क. नि.-1)]

S.O. 1543.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) (b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sri Athmanathasamy Temple at Thirupperunthurai, Tamil Nadu" as a place of public worship renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6610/F. No. 176/48/85-TT(A1)] सेन्द्रोय प्रस्यक्षकर बोर्ड मई दिल्ली, 28 फरवरी, 1986

(प्रायकर)

का.द्या. 1544: — द्यायकर प्रधिनियन, 1961 (1961 का 43) की क्षारा 121 की उपघारा (1) द्वारा प्रवत्त कनितयों का प्रयोग करते द्वुए केन्द्रीय प्रस्थक कर बोर्ड विनोक 29-10-1981 की प्रपनी ग्रधि सूचना सं. 4286 (का.सं. 187/30/81—आ.क. (नि.-1) के साथ संतरक प्रमुखी में निम्निविद्यित संसोधन करता है:---

- (1) इत. सं. श्रव के सामने कालम 2, 3 तथा 4 की प्रविष्टियों का विलोध किया जाता है।
- (2) क.सं. 9 तथा 9क के सामने काजम 2, 3 तथा 4 की प्रक्रिप्टियां निम्म प्रकार से प्रतिस्थापित की जाती हैं:--

क. शायकर प्रायुक्त सं.		म् स्यासय	भेक्षाधिकार	
1	¥	3	4	
9. f	देल्ली (केन्द्रीय)-1	गई विल्ली	नेत्रज्ञीय परिसम्बन्त-1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, जीर 20	
944	दिल्ली (केल्ब्रोय)-2	मई दिल्ली	केन्द्रीय परिमण्डल-3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 25 तवा 26	

यह अधिसूचना 1-3-1986 से आगू होगी।

[सं. 6607 (फा.सं. 187/2/86-माई. टो. ए-1]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES New Delhi, the 28th February, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 1544. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of Income tex Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Texes makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 4286 dated 29-10-1981 (F.No.187/30/81- I(AT):—

(1) Entries in Col. 2, 3 & 4 against S. No. 9B are deleted.

(2) Entri s in Col. 2, 3 & 4 against S.No. 9 and 9A are substituted as under:—

S. No.	Commissioner of Income-tax	Headquar- ters	Jurisdiction
1	2	3	4
9.	Delhi (Centrol)—I	New Delhi	C.ntral Circl s-I, II , IV,V,VI,XI,XII, XIII,XIV,XV, XVIII,XIX & XX.
9A.	Delhi (Central)—II	New Delhi	Central Circles-III, VI I,VIII,IX,X,XVI XVII,XXI,XXII, XXV & XXVI.

This notification shall take offict from 1-3-1986.

[No. 6607 (F.No.187/7/86-IT(AI]

नक्ष विल्ली, 5 मार्च, 1986 शुद्धिपत्र (आयकर)

का. आ. 1545. — आयकर अभिनियम, 1961 की भारा
121 की उपभारा (1) द्वारा प्रवक्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 1-3-1986 की अभिस्चना
संख्या 6607 के संबंध में निम्नलिश्वित शुद्धि-पत्र जारी करता
है:---

के लिए ''यह अधिसूचना 1-3-1986 से लागू होगी ।'' पढ़िए

"दह अभिसूचना 1-4-1986 सागू होगी ।"

[संख्या 6612 (फा.सं. 187/2/86-आ.क.नि.-1)]

भार. को. तिकारी, अवर रुचिय कोन्द्रीय प्रस्थक्ष कर कोड

Now Dolhi the 5th March CORRIGENDUM

(INCOME-TAX)

S.O. 1545:—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes issues the following corrigendum in respect of Notification No. 6607 dated 1-3-1986.

FOR

READ

'This notification shall take 'This notification shall take effect from 1-3-1986.' effect from 1-4-1986.'.

No. 61612(F. No. 187/2/86-IT (AI))

R.K. TEWARI, Under Secy.

Contral Board of Direct Taxes

नई विल्ली, 4 मार्च, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1546. -- भारतीय स्टांम्य अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की भारा 9 की उपभारा (1) की संख (स) धारा प्रवत्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्व्हारा महाराष्ट्र राण्य विसीय निगम, बम्बई को मात्र वो लाखा अट्ठासी हजार सास सौ पचास रूपये के समें कित स्टाम्प शुल्क की अधायगी करने की अमुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा मात्र सीन करोड़ पचासी लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों ''9 प्रतिकृत एय. एस. एफ.सी. बंधपत्र 2000 (सृतीय शृंखला)'' पर स्टाम्य शृल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 16/86-स्टाम्प (फा. सं. 33/18/85-वि.क.)] बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th April, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 1546.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees two lakhs and eighty-eight thousand, seven hundred and fifty only, chargeable on account of the stamp duty on "9 per cent M.S.F.C. Bonds 2000 (III Series)" being bonds in the form of debentures of the face value of rupees three crores and eighty-five lakhs only to be issued by the said Corporation.

[No. 1686-Stamps-F. No. 33/18/85-ST]
B. R. MEHMI, Under Secy.

समप्रकृत सम्पत्ति अपीन अधिकरण

नई दिल्ली,)4 अप्रैल, 1986

का . भां . 1547.— समपहृत सम्पत्ति भ्रष्)ल श्रीविकरण, सस्कर भीर विदेशी मुद्रा छलसावक (संपत्ति समपहृरण) श्रीवित्यम, 1976 (1976 का 13) की घारा 12 की उपधारा (7) द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, सर्थात :

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्म—(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 है।
 - (2) ये तुरस्त प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं इन नियमों में, जब शक कि संदर्भ से ग्रम्थका अप्रैक्षित न हो
 - (क) प्रशिविनयम' से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) ग्रीविनयम, 1976 (1976 का 13) ग्रीभिन्नेत है;
 - (च) "भ्रपील" से श्रविनियम की घारा 12 की उपधारा (4) के भ्रधीन की गई भ्रपील भ्रमिश्रेत है;
 - (ग) "अपीलार्थी" से वह स्पन्ति प्रमिन्नेत हैं जो सक्तम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होकर प्रधिकरण को अपील करता है, और इसके अन्तर्गत अपीलार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है;
 - (भ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से निम्निसिखित प्रभिन्नेत है,
 - (i) किसी घपीलार्थी के संबंध में,
 - (म) कोई व्यक्ति जो प्रपीलाधीं का संबंधी है या धपीलाधीं के नियमित नियोजन में है या था, और जो प्रपीलाधीं द्वारा प्रक्रिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित मैं प्राविकृत किया गया है; या
 - (मा) भारत में किसी सिविल ग्यासालय में विक्रि कार्य करने का हकदार कोई विक्रि व्यवसायी जिसे

- भ्रपोतार्थी द्वारा श्रक्षिकरण के समक्ष श्रजिर होने के लिए लिखित में प्राधिद्वत किया गया है ; या
- (इ) कोर्ड लेखापाल को चार्टर प्रकारनेट प्रधिनियम, 1949 (1949 का 38) की घारा 3 के अधीन गठित इंस्टीट्यूट झाफ चारटर प्रकारनेट झाफ इंडिया का या लागत और संकर्म अकाउन्टेंट झाफ इंडिया 1959 (1959 का 23) की घारा 3 के अधीन गठित इंस्टेंट्यट झाफ कास्ट एण्ड वर्स एकाउन्टेंट झाफ इंडिया का सदस्य है तथा जिसे अभीनार्थी हारा अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए लिखत में प्रायक्तित किया गया है; या
- (ii) असी सक्षम प्राधिकारी के संबंध में, जो प्रधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में एक पक्षकार है:---
- (भ) केन्द्रीय सरकार का कोई विधि भ्रधिकारी ;
- (भा) केन्द्रीय सरकार का सरकारी श्रधिवक्ता या स्थायी परामशी, वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ;
- (इ) केन्द्रीय सरकार का कोई मधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्न में भधिसूचना द्वारा इस निमित्त मधिसूचित किया है;
- (ई) कोई विधि व्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमिक्त प्राधिकत किया गया है;
- (उ) कोई विधि ब्यवसायी या केन्द्रीय सरकार का ग्रधिकारी जो इस प्रकार ग्रथिमूचित या प्राधिकृत थिसी व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है;
- (ङ) 'न्यायपीठ' से धारा 12 की उपधारा (६) या (६क) के अधीन गठिस अधिकरण की न्यायपीठ अभिन्नेत है;
- (स) 'प्रध्यक्ष' से अधिकरण का भ्रध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
- (छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से धारा 3 की उपधारा (1) के खाण्ड (ख) में परिभावित सक्षम प्राधिकारी प्रभिन्नेत हैं;
- (ग) 'नियित प्रतिनिधि से बहु व्यक्ति प्रभिन्नेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधितया प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत बहु व्यक्ति भी है जिसे अधिकरण अपने समक्ष लिखता कार्यवाहियों में मृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है;
- (म) "सदस्य" से भधिकरण का सदस्य मिश्रित है भीर इसके मंतर्गत भ्रष्टक भी है।
- (ञा) किसी श्रापील के संबंध में 'पक्षकार'' के श्रापीलार्थी, या प्रत्यर्थी ग्राभिप्रेत हैं भीर ''पक्षकारों' पद का ग्रार्थ श्रापीलार्थी भीर प्रत्यर्थी लगाया जाएगा ;
- (ट) "रजिस्ट्रार" से मधिकरण का रजिस्ट्रार मिन्नेत है मौर इसके मंतर्गंत ऐसा मन्य मधिकारी भं। है जिसे मध्यक्ष ने रजिस्ट्रार के क्रत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किया है;
- (ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा भ्रमिप्रेत है;
- (इ) ''भिधिकरण'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समयहूत सम्पत्ति अपील मिधिकरण मिभिन्नेत हैं।
- अधिकरण की भाषा---(1) अधिकरण के समक्ष सभी अभिवसन, अपीलार्थी के विकल्पानुसार, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में हो सकते हैं।
- (2) ग्राधिकरण के समां भावेश भीर मन्य कार्यवाहियां, मधिकरण के विकल्पानुसार, भंग्रेजी या हिन्दी में हो सकते हैं।

- प्रधिकरण का मुख्यालय प्रादि—(1) प्रधिकरण का मुख्यालय नई विल्लं। में होगा।
- (2) सभी भाषीलों भौर भ्राजियों की सुनवाई सामान्यतया मुख्यालय पर की जाएंगी या भाष्यक्ष के विधेकानुसार मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता या किसी भन्य स्थान पर की जासकती है।
- (3) अधिकरण का कार्यालय एैसे अवकाश दिनों और अन्य श्रवकाश दिनों को बन्द रहेगा जिन दिनों केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय बन्द रहते हैं।
- 5. मपील भौर अजियां वाखिल करने की प्रक्रिया
- (1) प्रश्नित्यम की धारा 7 या धारा 9 की उप-धारा (1) या धारा 10 के प्रधीन प्रादेश से व्यथित कोई व्यक्ति प्रधिकरण को प्रपील कर सकता है भौर प्रपील का ज्ञापन इन नियमों से सपास द प्रकृष में होगा।
- (2) अपील का ज्ञापन अंग्रेजी या हिन्दी में होगा और उसमें अपील के प्राप्तार संक्षेप में भीर विभिन्न शीर्षों के भ्रदीन, किसी तर्क या विवरण के बिना, दिए जायेंगे भीर ऐसे भाधारों की कमानुसार संख्यांकित किया जाएगा।
- (3) अपील का ज्ञापन और अर्जी बार प्रतियों में होगी और अपील के ज्ञापन की दशा में उसके साथ उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपोल की गई है, बार प्रतियों होंगी तथा उनमें से एक प्रति ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति या अपीलार्थी पर तामोल किया गया आदेश होगी।
- (4) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट, इन नियमों से उपाबद्ध प्रक्षों में कम सं. 5 पर दिया गया पता, प्रपीलार्थी का "रिकस्ट्रीफ़ृत पता" कहलाएगा भौर जब तक उसमें धिधकरण को दिए गए धावेदन द्वारा, सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता वह प्रपील तथा धन्य संबंधित कार्यवाहियों में, जब तक पश्चात् दो वर्ष की घविष्ठ सक, सभी सूचनाघों, आदेशिकाघों भौर ग्रम्य संसूचनाघों को तामील के प्रयोजन के लिए प्रपीलार्थी का पता समझा जाएगा।
- (5) प्रत्येक 'अपील में सक्षम प्राधिकारी को, जिसने वह आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा ।
- (6) धपील का ज्ञापन प्रपीलार्थी द्वारा स्वयं या जहां एक से प्रधिक प्रपोलार्थी हैं वहां उनमं से ऐसे किसी एक के द्वारा या उसके प्रधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रिजण्ड्रार के समक्ष या ऐसे अध्य अधिकार के समक्ष जी अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा या रिजस्ट्रार को संबोधित रिजस्ट्री ढाक से भेजा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण--इस उपनियम में, "प्राघक्रत प्रतिनिधि" पद के धतर्गत धपीलार्थी की भोर से हाजिर होने के लिए प्रधिकृत किए गए किसी विधि व्यवसायी या धकांउन्टेंट के नियोजनाधीन कोई व्यक्ति भी है।

- (7) जब अपील का ज्ञापन रिजस्ट्री काक से भेजा जाता है तब उक्त ज्ञापन की अधिकरण के कार्यालय पर पहुंच की तारीख अपील वाखिल करने की तारीख होगी और रिजस्ट्रार अपील के प्रत्येक ज्ञापन पर बह तारीख पृथ्ठांकित करेगा जिसको वह अधिकरण के कार्यालय पर प्रस्तुत किया जाता है या प्राप्त होता है तथा पृथ्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।
- (8) जब अपं स अपीलार्थी पर तामील किए गए घावेश की प्राप्त के 45 दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन को अध्यसात वाजिल की जात। है तब उसके साथ एक शपथ पत्न से झसम्यित घावेदन होगा जिसमें उन सध्यों का झिकयन होगा जिन पर भ्रेपीलार्थी घिषकरण का यह समाधान करने के लिए निर्मर करता है कि पैतालीस दिन के भीतर घपील न वाजिल करने के लिए पास उसके पास पर्याप्त हेतुक था।

- ं (9) घधिकरण के समक्ष वाश्विल की गई प्रस्येक धर्जी के साथ, जिसके संतर्गत रोकने की सर्जी भी है किन्तु भौपचारिक या नेमी प्रकृति की धर्जियां नहीं हैं, एक शपधपक होगा धौर ऐसी वस्तावेओं की प्रतियां भी होंगी जिल पर वह धर्जी के समर्थन के लिए निर्धर है।
- 6. घपीलों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया——(1) सकाम प्राधिकारी के भावेश का तामील के पैंतालीस विन के भीतर वाजिल प्रत्येक घपील कापन जो इन नियमों से उपायद्ध प्रारूप में हो भीर अन्यया सही हो, इस प्रयोजन के लिए रखी गई बहु। में रजिस्टर किया आएगा जो घपील रजिस्टर कहलाएगी भीर रजिस्ट्रार सवनुसार अपंत्राचीं माउसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को संसूचित करेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) के अंतर्गत वाखिल किया गया अपील आपन श्रुटिपूर्ण है किन्तु श्रुटियां गैंण या तकनीको प्रकृति की हैं तो रिजस्ट्रार अपील को अनित्तम आधार पर रिजस्ट्रार करेगा और अपील लागीं को उन सुटियों को उतने समय के भीतर, जो विनिर्विष्ट की आए, दूर करने के लिए कहेगा और ऐसी विनिर्विष्ट अवधि के भीतर सुटियां दूर कर विए जाने पर रिजस्ट्रीकरण अनित्तम नहीं रहेगा और अपील उपनियम (1) के अक्षीन नियमित रूप से रिजस्टर की गई समझी जाएगी
- (3) जब प्रपील का ज्ञापन सक्षम प्राधिकार के प्रादेश की तामील की तारी खा से पैतालीस दिन का समाप्ति पर किन्सू साठ विल के मातर दाखिल किया जाए और वह प्रन्यथा सही हो, तथा उसके साथ विलंध को माफ करने के लिए प्रजी वो गई है, तो उसे इस बात के प्रधीन रहते हुए प्रमन्तिम रूप से सीक्यांकि और रिजस्टर किया जाएगा कि प्रधिकरण को, प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात थीर पश्कारों को सूचने के पश्चात यदि यह समाधान हो जाता है कि प्रपीलार्थी समय पर प्रपील वाखिल करने में पर्यान्त कारणों से निवारित रहा था और प्रधिकरण विलंध को माफ कर देता है भीर सब रिजस्ट्रीकरण प्रनित्तम गहीं रहेगा और भ्रपील का निपटारा इस प्रकार किया आएगा मानों वह उपनियम (1) के प्रधीन रिजस्टर की गई थी।
- (4) जब प्रपील का शापन सक्षम प्राधिकारी के प्रावेश की तामील के पश्चात पैतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात किन्तु साठ दिन की प्रविध के भीतर दाखिल किया जाता है और उसके साथ विलंब को माफ करने की प्रजी नहीं दी जाती है तो रिजस्ट्रार प्रपील को प्रनित्तम रूप से रिजस्टर कर सकता है और प्रपीलार्थी से, ऐसी प्रविध के भीतर जो विनिर्विष्ट की जाए, विलम्ब को माफ करने की धर्जी दाखिल करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार की प्रजी प्राप्त होने की दश्म में उसका निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह प्रपील के शापन के साथ प्राप्त हुई यी भीर तब प्रपील का निपटारा प्रधिनियम (3) में विहिस रूप से किया जाएगा।
- (5) यदि इस निमित्त विनिर्विष्ट धविध के भीतर द्वुटियों को दूर नहीं किया जाता है या विलंब की माफी के लिए धर्जी दाखिल नहीं की जाती है तो मामला भिधकरण के समक्ष उसके भावेश के लिए रखां जाएंगा।
- (6) यदि प्रपील के ज्ञापन की सारमूत विशिष्टियों में बृटि हो तो रिजस्ट्रार तृटियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है भौर अपील के ज्ञापन को संशोधन करने के लिए तथा सुधार करने के पश्चात पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापिस कर सकता है भौर जब भपील का ज्ञापन पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निपटारा इन नियमों के भनुसार किया जाएगा।
- (7) जब अपील का शापन प्रथम दृष्ट्या सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तामील कः तारीख से साठ दिन से अधिक के प्रश्वात दाखिल किया गया प्रतीत हो तो अपील रिजस्टर नहीं की जाएगी अपितृ रिजस्ट्रार अपीलार्थी से यह हेतुक दिलत करने की अपेला करेगा कि अपीलार्थी कालातील होने के कारण खारिज क्यों नहीं कर दी जाए।

- (8) देरी की माफी का प्रत्येक झावेदन और समय के पश्चात् वाखिल किया गया प्रत्येक अपील का क्षापन अध्यक्त के समक्ष रखा जाएगा जो झावेदन/अपील की झिछकरण के समक्ष उसके झादेशों के लिए रखे जाने का निदेश दे सकेगा।
- 7. भपील के रिजस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया——(1) भ्रपंत रिजस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात भ्रपील के शापन भीर उसके उपाबंधों की एक
 प्रति, यथाणी झ, सक्षम प्राधिकारी को या तो पावती पत्न सहित रिजस्ट्री
 बाक से भेजकर या संवेशवाहक के भाष्यम से तामील की जाएगा तथा
 पक्षकारों से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की भविध के
 भीतर, या ऐसी मितिरिक्त भविध के भीतर जो भनुशात को जाए
 भपना पेपर बुक दाखिल करने की अपेक्षा की जाएगी।
- (2) प्रत्येक पक्षकार स्रपनी पेपर युक्त की चार प्रतिया दाखिल करेगा---
 - (i) जो सुपाठ्य रूप से टाइप की गई या किसी यांत्रिक साधन से अत्यक्षा तैयार की गई होगी;
 - (ii) जिसमें वे सभी दस्तावेज होंगी जन पर पक्षकार सुनवाई के प्रमुक्तम में निर्भर रहना चाहता है;
 - (iii) जिसमें केवल ऐसी वस्तावेओं और ऐसी सामग्री होगी जो सलम प्राधिकारी के समक्ष निर्विष्ट या प्रस्तुत की गई हो या जिस पर निर्भर किया गया हो;
 - (iv) जिसके पृष्ठ कमानुसार संख्याकित होंगे; भौर ;
 - (V) जिसमें पूरी विषय-सूची या विषय सारणी होगी।
- (3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट पेपर युक्त में कोई घरतावेज अंग्रेजी से या हिन्दी से ि.ज भाषा में है तो उसका अंग्रेज़ी या हिन्दी में सही धनुवाद भी जीड़ा जायेगा ।
- (4) पक्षकारों को पानती पन्न सहित रिजस्ट्री डाक से या संवेशवाहक के माध्यम से सूचना तामील करके प्रपील की सुनवाई की तारीच और सभय पक्षकारों की सूचित किया जायेगा।

परन्तु यदि पक्षकार ग्रधिकरण के समक्ष हाजिर हैं तो ग्रधिकरण उन्हें ग्रपील की सुमनाई की तारीख और समय मौखिक रूप से सूचित कर सकता है।

- (5) साक्षियों या दस्तावेओं को समन करने के लिये किसी प्रजीं पर, यदि ग्राव्ययक हो तो, ग्रन्य पक्षकार की सूचना देने के पश्चात् सुनवाई की जा सकती है।
- (6) प्रधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक ध्रध्यपेक्षा निर्वेशपक्ष, प्राधिकार पत्न या लिखित सूथना पर रिजस्ट्रार हस्ताक्षर करेगा और वह पावती पत्न सहित रिजस्ट्री डाक से या सन्येशवाहक के भाष्यम से भेजा जायेगा या भेजी जाएगी।
- 8. प्रपीलों की संयुक्त सुनवाई और निष्पादन : प्रधिकरण, जब भी वह ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन समझता है, एक या प्रधिक अपीलों की सुनवाई एक साथ कर सकता है और उनका निष्पादन एक ही धावेश द्वारा कर सकता है।
- . 9. अपील के झाघार: झपीलाणीं झिकरण की झमुनति के सिबाय, ऐसे किसी झाघार के समर्थन में, जो झपील के जापन में अधिकथित नहीं है, न तो तर्क कर सकता है और न सुना जायेगा, किस्तु झिकरण झपील का विनिश्चय करने में, केवल उन झुझारों तक स्वयं को सीमित नहीं रखेगा जिल्हों झपील के जापन में उपवर्णित किया गया है या जिनके लिग्ने इस नियम के झधीन झिकरण की झनुमति प्राप्त की गई है:

परम्तु प्रक्षिकरण क्षपना विनिश्चय अपील के कापन में वर्णित ग्राधारों से िम किसी ऐसे ग्राधार पर तब तक नहीं करेगा अब तक कि उस प्रकार को जो उससे प्रमावित हो सकता है, इस ग्राधार पर सुनवाई का जवित ग्रवसर प्रवास नहीं कर दिया जाता है

- 10. स्वयन—प्रश्विकरण किसी मामले की तुमवाई किसी धन्य सारीब के सिये स्वयित कर सकेशा और पक्षकारों को मानले की सुमवाई की की प्राथमी सारीब और स्थान से सुवित करेगा।
- 11. प्रपीकार्यी के स्पतिकम के कारण प्रपील का खारिज किया जाना—यदि सुनवाई के लिये नियत किये गये दिन या किसी प्रश्य दिन जिस को सुनवाई के लिये नियत की गई हो, प्रपीकार्यी प्रपील की सुनवाई के किये पुकार किये जाने पर हाजिर नहीं होता है, तो प्रक्रिकरण स्पतिकम के कारण प्रपील को खारिज कर सकता है या उसकी एक प्रकीय सुनवाई के लिये प्रवस्त हो सकता है।

परस्तु अहां अपील न्यतिकम के कारण वारित्र की गई हो या उस पर एक पसीय कार्यशाही की गई हो और अपीलार्थी तरपत्रवात् हाकि र हो जाता है भीर अधिकरण का यह सभावान कर देता है कि सुनवाई के लिये पुकार किये जाने के सभय उसके हाजिर न होने के लिये पर्याप्त हेतुक था, तो अधिकरण, प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात् वारिजी के धावेश को या एक पक्षकीय कार्यवाही को अपास्त कर सकता है और अपीस को उसके मूल संख्यांक पर पुनः रख सकता है।

- 12. मृत्यु, बोबालियापन साथि का सपीश पर प्रभाव: (1) सपीसाथीं की मृत्यु मा उसके वीवालिया ग्यायनिर्णित किये जाने भाव के कारण सपीस खपशोमित नहीं होगी।
- (2) प्रधिकरण मृत प्रपीलाणीं के विधिक प्रतिनिधि द्वारा इस निमित प्रावेदन किये आगे पर उसे प्रजनार बना सकता है और प्रपील में क्षाये कार्रवाई कर सकता है।
- (3) यदि ध्रमीलाधीं की मृथ्यु के नम्बे दिन के भीतर या ऐसी खतिरिक्त समित के भीतर जो सिकरण मृत समीलाधीं के विधिक प्रति-निश्चि की स्रितिख कर लाने के लिये मनुझात करे, कोई समिवन महीं किया काता है तो समीस उपसमित हो आयेगी।
- (4) प्रपीक्षाची के बीबालिया हो जाने पर प्रपील लेनवारों के फायबे के लिये समन्देकिती या रिसीवर हारा आरी रखी जा सकेगी तथा यदि सनन्देकिती या रिसीवर प्रपील को कारी रखने में प्रसफल रहता है तो प्रक्षिकरण स्वप्नेरणा से या प्रस्थवीं के द्वावेदन पर प्रपीस की खारिज कर सकता है।
- 13. घषिकरण हारा मामले का प्रतिप्रेषण——(1) घषिकरण , जब भी बहु घावस्थक समझे, सक्षम प्राधिकारी के किसी घावेस की घपास्त कर सकता है और मामले को ऐसे निवेशों की ब्यान में रखते हुए जैसे बहु वे, पुतः घनघारण के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है।
- (2) ग्राधिकरण यथि कार्यवाई के किसी श्रनुक्रम पर ग्रावश्यक समझता है तो, ऐसे विक्यों पर जो कह विगिविष्ट करे, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष मांग सकता है।
- (3) जप नियम (2) के मधीन निर्विष्ट किसी ऐसी रिपोर्ट या निष्कृत की मित पक्षकारों की दी आयेगी और इसके पूर्व कि मधिकरण मंतिम मधिकों की मोवणा करें, उन पर पुनः सोचा आयेगा।
- 14. प्रक्षिकरण के समक्ष प्रतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना --- (1) पक्ष कार, प्रविकरण के समक्ष प्रतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौक्षिक हो या वस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे किन्तु निम्नलिखित बनाओं में प्रविकरण ऐसा साक्ष्य या वस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्षियों की परीक्षा करने की प्रनुता वे संकता है, प्रचीत :---
 - (क) वहां सक्षम प्राधिकारी ने, जिसके प्रावेश के विषद्ध ग्रापीक्ष याचिक की गई है, किसी ऐसे साक्य को प्रहल करने से इंकार कर दिया हो तो जो प्रहल किये काना काहिये था, या
 - (च) नहीं धरिरिन्त संक्य प्रस्तुत करने की प्रार्थमा करने क्षांना पंचकार यह सिक्क कर देता है कि सम्यन् तस्परता करते जाने

- पर भी ऐसा साक्य जनकी जानकारी में नहीं था या, सन्यक् तत्परता वरते जाने के पश्चात् भी वह उस समय उसके द्वारा मस्तुत नहीं किया जा सकता था जब वह धारेण पारित किया गया था जिसके विश्व द्वापील की गई है, या
- (ग) जब अधिकरण उसे प्रावेग चौक्ति करने में समर्थ बनाने के सिये, या किसी प्रत्य तारिक्क कारण से, कोई दस्तावेश प्रस्तुत करने या किसी सानी का परीक्षण करने की प्रवेशा करता है, या
- (च) क्ष्य प्रशिक्षरण का यह समाधान हो जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने मामले का विनिक्ष्य प्रपीकाणी को उस विवय पर सक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित प्रवसर प्रवान किये विका किया है ।
- (2) मधिकरण जहां भी मतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुका देता है नहां वह जसे ग्रहण करने के कारणों को नेखनग्र करेगा।
- 15. प्रपील की सुनवाई—प्रपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिये प्रक्षिकरण की बैठक का स्थान खुसा न्यायासय समझा जायना कहां साधारणतः जनता की पहुंच वहां तक हो सकेगी जहां तक कहां जनके लिये सुविधाजनक स्थान है:

परन्तु प्रधिकरण, यदि वह ठीक समझता है तो, प्रपील की सुनवाई के किसी प्रमुक्तम पर यह प्रादेश कर सकता है कि सुध्वारणतया अनता, या कोई व्यक्ति जिलेष, प्रधिकरण द्वारा उपयोग किये जा रहे कक्ष या ध्वक में नहीं पायेगा या बहा नहीं रहेगा या वकेगा।

- 16. धारेश का सुनाया आला--सुनवाई की सनाप्ति पर श्रिक्षरण तुरस्त श्रपना प्रावेश सुना सकेशा या अपने भावेश धारिक्षत रखे जाते हैं तो श्रीक्षरण संतिम धावेश सुनाने के पूर्व किसी भी समय या तो स्थोरणा से या किसी पक्षकार के श्रावेशन पर यह श्रावेश कर सकेशा कि अपीक्ष या श्रावें की पून: सुनवाई की जाये।
- 17. घावेल का पक्षकारों की संसचित किया जाना----प्रधिकरण का प्रत्येक घावेल लिखित में होगा और प्रधिकरण के प्रत्येक अंतिम धावेश की प्रति, जो रिजस्ट्रार द्वारा सत्य प्रतिलिपि के क्य में प्रशालित की गई हो, पक्षकारों की, प्रवासंघव लीध, निःमुल्क वी जायेगी।
- 18. झावेजों पर हस्ताकार ——(1) यदि निनिश्चय पर मिश्वकरण के सभी सदस्य सहमत हीं तो झिशकरण के सभी सदस्यों हारा एक ही झावेज पर हस्ताकार किये जायेंगे।
- (2) जहां राय िश्र हों, वहां विनित्त्वय सिकरण के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया कामेगा ।
- (3) को सबस्य बहुमत के विनिश्चय से सहमत नहीं है वह समह्यक्ति का प्रायेत पृथक दे सकेगा।
- (4) बहुमत का विनिम्बय सिकित कप में विया जायेगा और उस पर सभी सबस्यों द्वारा, जिनमें प्रसह्तत सबस्य की भी हैं, हस्ताकार किये कार्येगे।
- 19. प्रावेशों का प्रकाशन—प्रधिकरण के ऐसे प्रावेश जिल्हें किसी
 प्राधिकृत रिपीर्ट या सभाषार पत्नों में प्रकाशित करने के लिये उपयुक्त
 समझा आसा है, ऐसे प्रकाशन के लिये, ऐसे निवन्धनों और शतों पर जो
 प्रधिकरण प्रधिकियत करें, दिये जा तकीं।
- 20. कतिपय भामभों में घाडेल और निवेश—इन नियमों में किसी । बात के होते हुए भी प्रधिकरण घपने घावेगों की प्रभावी करने के लिये या घपनी घावेशिकाओं का दुवपयोग निवारित करने के लिये या न्याय के उद्देश्यों की सुनिश्चित करने के लिये ऐसे घावेश या निवेख दे सकेगा जिसे वह प्रावश्यक या समीचीन समझे।
- 21. निरसन और स्थान्ति——(1) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसायक (समपद्वत सम्मक्ति प्रपील घधिकरण) नियम, 1977 निरसित किये कार्ते हैं !

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, जपनियम (1) में निर्विष्ठ नियमों में से किसी के उपवश्मों के प्रधीन की गई कोई बात या कार्यवाद समपहत सम्पत्ति प्रपील द्यक्तिरूप (प्रक्रिया) नियम, 1986 के तरस्वानी प्रपालकों के प्रधीन की गई समझी जायेगी।

प्रस्प

(नियम 5 भीर 6 देखिए)

समपहृत सम्पत्ति सपील श्रीक्षकरण, नई विल्ली के संगर्भ धपील का ज्ञापन

(तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसामक (सम्पत्ति सभपहरण) मर्मिनियम, 1976 की बारा 12]

19 का सब्सब्धवसंश्रियद्ववसंश् (अपील स्रधिकरण के कार्यालयद्वारा भरा अपरेगा)्रे

भी/शीमती----- ग्रपीलाची

धनाम

---- प्रत्यर्थी

- (1) सक्रम प्राधिकारी, नई विल्ली/*बम्बई/कलकत्ता/भव्रास/ श्रहमवाबाव
- (2) प्रत्य प्रत्यर्थी, यवि कोई हैं-----
- चहप्राधिकारी जिसके बादेश के 4िष्य : सक्षम प्राधिकारी, धपील की गई है।] नई विल्ली/*व

संसम् प्राधिकारी, नई बिल्ली/*बम्बई/ कलकत्ता/नवास/ग्रहमदाबाद

- 2. आवेल की तारीच
- 3. दादेश की तामील को तारी व
- विनिद्धिक करें कि सुनवाई व्यक्तिगत स्प : से वाष्टित है या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ।
- 5. स्रथीलार्थी का रिकस्ट्रीकृत पता : (जिसके झन्धर्गत फोन नं०, यदिकोई है) जिस पर सभी सूचनार्ये, प्रादेशिकार्ये और संस्थानार्ये तासील की कार्येगी।
- 6. प्रस्पर्यीका पता
- : (1) तक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली/कंबस्बई/ कलकता/मजाः॥/ग्रहमदा-
- : (2) झन्य प्रत्यची, यदि कीई हैं -----
- तस्कर और विवेशी मुद्रा छलसाक्षक (सम्पत्ति : समपहरण) मिलियम, 1976 की वह धारा या घारा की उपचारा जिसके मिलियम प्राधिकारी ने मार्चेश किये हैं और जिसके विश्वद मिल की गई है।
 - s. **बाबाइत प्रमृतीय**
 - (1) क्या पूरा धार त विवादग्रस्त है

- (2) यदि सम्पत्ति की केवल कुछ मर्वे विवादग्रस्त हैं तो उन्हें उपावन्ध में दीजिये।
- मपील के धावार (यदिस्थान पर्याप्त नहीं है तो प्रवस पुष्ठ लगाइये)

(हस्ताक्षर प्रपीकाणीं)

(हस्ताकार प्राधिकृत मतिनिक्रि यविकोई है)

सरवापस

मैं, प्रियोशार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित करता हूं कि कपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम आनकारी और विश्वास के सनुसार सत्य है।

भाष तारीच-----की सरमापित किया।

*जो आरगून होता हो उसको काट दीजिए।

- रिप्पण : 1. सपीस का जापण भार प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिये और उसके साथ उस झावेश की, जिसके विश्व सपीस की गई है, भार प्रतियां होंगी (जिनमें से एक उस झावेश की, जिसके विश्व सपीत की गई है सपीक्षार्थी पर तामील की गई मूल प्रति या उसकी प्रभाणित प्रति होंगी) । सभी संजनक भी भार प्रतियों में होंगे।
 - 2. घपील का क्षापन अंग्रेजी या हिन्दी में लिखा जाना शाहिये और उपमें घपील के भाषार संजिप्त और वि. म शीवों के घषीन दिये जाने शाहिये तथा प्रसमें कोई तके या कियरण नहीं दिये जाने शाहिएं और ऐसे प्राथारों की कमानुसार संक्योंकित किया काना शाहिये ?
 - ग्रम्य भ्यौरों के लिये कृपया समपहत सम्पत्ति ग्रमीश ग्रिविकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986 वेचें ।

[फा॰सं॰ 91/सामान्य/ससग्रम/86] समपद्दत सम्पत्ति ग्रपीश ग्रविकरण के ग्रावेश से, बी॰ अश्रव्दीं, रेजिस्ट्रार

APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY New Delhi, the 14th April, 1986

- S.O. 1547.—In exercise of the powers conferred by subsection (7) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Appellate Tribunal for Forfeited Property hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—
 - (a) "Act" means the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act. 1976 (13 of 1976);

- (b) "appeal" means an appeal filed under sub-section (4) of section 12;
- (c) "appellant" means a person who, being aggrieved by an order made by the competent authority, prefers an appeal to the Tribunal, and includes the authorised representative of the appellant;
- (d) "authorised representative" means-
 - (i) in relation to an appellant,
 - (A) any person being a relative of, or a person who is, or was, regularly employed by the appellant and authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal; or
 - (B) a legal practitioner entitled to practise in any civil court in India, who is authorised in writing by the appellant to attend before the Triburnal: or
 - (C) an accountant, being a member of the Institute of Chartered Accountants of India constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under section 3 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), who is authorised in writing by the appellant to attend before the Tribunal, or
 - (ii) in relation to a competent authority who is a party to any proceedings before the Tribunal:
 - (A) a Law Officer of the Central Government;
 - (B) a Government Pleader or Standing Counsel to the Central Government by whatever name called;
 - (C) any Officer of the Central Government notified in this behalf by the Central Government by notification in the Official Gazette;
 - (D) any legal practitioner or Officer of the Central Government authorised in this behalf by the Central Government or the competent authority:
 - (E) any other legal practitioner or Officer of the Central Government acting on behalf of the person so notified or authorised;
- (e) "Bench" means a Bench of the Tribunal constituted under sub-section (6) or (6A) of section 12;
- (f) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal;
- (g) "competent authority" means a competent authority as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 3;
- (h) "legal representative" means a person who in law represents the estate of a deceased person, and includes any person treated by the Tribunal as representing the deceased person in the proceedings pending before the Tribunal;
- "member" means a member of the Tribunal and includes the Chairman;
- (j) "party" in relation to an appeal, means an appellant, or the respondent and the expression "parties" shall be construed to mean the appellant and the respondent;
- (k) "registrar" means the registrar of the Tribunal and includes such other officer who is authorised by the Chairman to perform the functions of the registrar;
- (1) "section" means a section of the Act;
- (m) "Tribunal" means the Appellate Tribunal for Forfeited Property, constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 12.
- 3. Language of the Tribunal.—(1) The pleadings before the Tribunal may, at the option of the respective parties, be in English or in Hindi.

- (2) All orders and other proceedings of the Tribunal may, at the option of the Tribunal, be in English or in Hindi.
- 4. Headquarters of the Tribunal, etc.—(1) The headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.
- (2) Appeals and petitions may be heard at the headquarters or at the discretion of the Chairman at Bombay, Madras, Calcutta, Ahmedabad, or any other place.
- (3) The office of the Tribunal shall observe such public and other holidays as are observed by the offices of the Central Government.
- 5. Procedure for filing appeals and petitions.—(1) Any person aggrieved by an order of the competent authority made under section 7 or sub-section (1) of section 9 or section 10 of the Act may prefer an appeal to the Tribunal and every memorandum of appeal shall be in the form annexed to these rules.
- (2) A memorandum of appeal shall be in English or in Hindi and shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.
- (3) Every memorandum of appeal or petition shall be in quadruplicate and in the case of a memorandum of appeal it shall be accompanied by four copies of the order appealed against and one of such copies shall be a certified copy of such order, or the order served on the appellant.
- (4) The address given at serial number 5 of the form appended to these rules as referred to in sub-rule (1) shall be called the "registered address" of the appellant and shall until duly changed by an application to the Tribunal be deemed to be the address of the appellant for the purpose of the service of all notices, processes and other communications in the appeal and other connected proceedings till the final determination of the appeal and a period of two years thereafter.
- (5) In every appeal, the competent authority which passed the order appealed against, shall be impleaded as one of the respondents.
- (6) A memorandum of appeal shall be presented by the appellant in person or when there are more appellants than one by any one of them or by his authorised representative to the registrar or such other officer as may be authorised in this behalf by the Chairman or may be sent by registered post addressed to the registrar.

Explanation.—In this sub-rule, the expression "authorised representative" shall include any person in the employment of a legal practitioner or an accountant who is authorised to appear on behalf of the appellant.

- (7) When a memorandum of appeal is sent by registered post, the date of receipt of the said memorandum at the office of the Tribunal shall be the date of filing of the appeal and the registrar shall on every memorandum of appeal, endorse the date on which it is presented or received at the office of the Tribunal and shall sign the endorsement.
- (8) When an appeal is presented after the expiry of forty-five days of the receipt of the order served upon the appellant but not after sixty days, it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Tribunal that he had sufficient cause for not preferring the appeal within forty-five days.
- (9) Every petition presented to the Tribunal including a petition for stay other than petitions of a formal or routine character, shall be accompanied by an affidavit as also copies of such documents as are religid on in support of the petition.
- 6. Procedure for registration of appeals.—(1) Every memorandum of appeal filed within forty-five days of service of the order of the competent authority, being in the form annexed to these rules and otherwise in order, shall be registered in a book kept for the purpose called the Register of Appeals and the registrar shall intimate the appellant or his authorised representative accordingly.

- (2) If a memorandum of appeal filed under sub-rule (1) is defective, but the defects are minor or technical in character, the registrar may register the appeal provisionally and call upon the appellant to remove the defects within such time as may be specified and upon the defects being removed within such specified time, the registration shall cease to be provisional and the appeal shall be deemed to have been regularly registered under sub-rule (1).
- (3) When the memorandum of appeal is presented after the expiry of forty-five days but within a period of sixty days after the date of service of the order of the competent authority, and is otherwise in order, and is accompanied by a petition for condonation of delay, it shall be numbered and registered provisionally subject to the delay being condoned by the Tribunal after notice to the respondent and after hearing the parties, if the Tribunal considers that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time and condones the delay, the registration shall cease to be provisional and the appeal dealt with as though it had been registered under sub-rule (1).
- (4) When the memorandum of appeal is presented after the expiry of forty-five days but within a period of sixty days after the date of service of the order of the competent authority, and is not accompanied by a petition for condonation of delay, the registrar may register the appeal provisionally and call upon the appellant to file a petition for condonation of delay within such time as may be specified and in the event of such a petition being received, it shall be treated as having been received alongwith the memorandum of appeal and the appeal dealt with in the manner prescribed in sub-rule (3).
- (5) When the defects are not removed or a petition for condonation of delay is not filed within the time specified in that behalf, the matter shall be placed before the Tribunal for its orders.
- (6) Where a memorandum of appeal is defective in material particulars, the registrar may specify the defects and return it for being amended and represented after remedying them and when the memorandum of appeal is represented, it shall be dealt with in accordance with these rules.
- (7) When a memorandum of appeal on the face of it appears to have been filed more than sixty days after the date of service of the order of the competent authority on the appellant, the appeal shall not be registered but the appeallant shall be called upon by the registrar to show cause why the appeal should not be dismissed as being out of time.
- 8. Every petition for condonation of delay and every memorandum of appeal filed out of time shall be placed before the Chairman who may direct the petition/appeal to be posted before the Tribunal for its orders.
- 7. Procedure after registration of appeal.—(1) After an appeal is registered, one copy of the memorandum of appeal and annexures thereto shall be served, as soon as possible, on the competent authority either by registered post acknowledgement due, or through a messenger and the narties shall be called upon to file their paper-books within a period of therety days from the date of receipt of the notice or such further time as may be allowed.
- (2) Each party shall file four copies of his paper-book which shall---
 - (i) he legibly typed or otherwise reproduced by mechanical means:
 - (ii) contain all documents upon which a party proposes to rely during the course of hearing;
 - (iii) contain only such documents and material as have been referred to, produced or relied upon before the competent authority;
 - (iv) have pages numbered serially; and
 - (v) contain a full index or table of contents.
- (3) If the nancr-book referred to in sub-rule (2) contains any document in a language other than English or Hindi, a true translation thereof in English or Hindi shall be added.

- (4) The parties shall be informed of the date and place on hearing of the appeal either by registered post acknowledgement due or by notice served on them through messenger:
- Provided that where the parties are present before the Tribunal, it may inform them orally of the date and place of hearing of the appeal.
- (5) Any petition for summoning witnesses or documents filed by a party may be heard, if necessary, after giving notice to the other party.
- (6) Every requisition, direction, letter, authorisation, or written notice to be issued by the Tribunal shall be signed by the registrar and shall be sent by registered post acknowledgement due or through a messenger.
- 8. Joint hearing and disposal of appeals.—The Tribunal may, whenever it considers necessary or expedient to do so, hear one or more appeals together and dispose of them by a common order.
- 9. Grounds which may be taken in appeal.—The appellant shall not, except with the leave of the Tribunal, urge or be heard in support of any ground not set forth in the memorandum of appeal but the Tribunal, in deciding the appeal, shall not be confined to the grounds set forth in the memorandum of appeal or taken with the leave of the Tribunal under this rule:

Provided that the Tribunal shall not rest its decision on any ground other than the grounds set forth in the memorandum of appeal unless the party which may be affected thereby has had a reasonable opportunity of being heard on that ground.

- 10. Adjournment.—The Tribunal may adjourn the hearing of any case to any other date and inform the parties of the next date and place of hearing of the case.
- 11. Dismissal of appeal for appellant's default.—Where on the day fixed for hearing or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the Tribunal may either dismiss the appeal for default or proceed ex-parte:

Provided that where the appeal has been dismissed for default or proceeded with ex-parte and the appellant appears thereafter and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called on for hearing, the Tribunal shall, after giving notice to the respondent, make an order setting aside the dismissal order or the ex-parte proceedings and restoring the appeal to its original number.

- 12. Effect of death, insolvency, etc. on appeal.—(1) An appeal shall not abate by reason only of the death of an appellant or on his adjudication as an isolvent.
- (2) The Tribunal may on an application made in this behalf by the legal representative of the deceased appellant make him a party and proceed with the appeal.
- (3) When no application is made within ninety days of the death of an appellant or within such further time as the Tribunal may allow for bringing his legal representative on record, the appeal shall abate.
- (4) On the insolvency of an appellant, the appeal may be continued by the assignee or the receiver for the benefit of creditors and if the assignee or the receiver fails to continue the appeal, the Tribunal may on its own motion or on the application of the respondent, dismiss the appeal.
- 13. Remand of case by the Tribunal.—(1) The Tribunal may, whenever it considers it necessary, set aside an order of the competent authority and remand the case to the competent authority for fresh determination in the light of such directions as it may give.
- (2) The Tribunal may if it considers necessary at any stage of the proceedings call for a report or finding from the competent authority on such matters as it may specify.
- (3) A copy of any such report or finding referred to under sub-rule (2) shall be furnished to the parties and they shall be heard thereon before the Tribunal pronounces final orders.
- 14. Production of additional evidence before the Tribunal.—(1) The parties to an appeal shall not be entitled to

produce additional evidence, whether oral or documentary, before the Tribunal, but, however, where—

- (a) the competent authority from whose order the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or
- (b) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the order appealed against was passed, or
- (c) the Tribunal requires any document to be produced or any witness tools be examined to enable it to pronounce orders, or for any other substantial cause, or
- (d) the Tribunal is satisfied that the competent authority has decided the case without giving a reasonable opportunity to the appellant to adduce evidence on any point,

it may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.

- (2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by the Tribunal, it shall record the reason for its admission.
- 15. Hearing of appeals.—The places in which the Tribunal sits for the purpose of hearing appeals shall be deemed to be an open court, to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them:

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at any stage of the hearing of an appeal, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Tribunal.

16. Pronouncement of order.—After the hearing is over, the Tribunal may pronounce its orders forthwith, or it may reserve its orders and if the orders are reserve, the Tribunal may at any time before final orders are pronounced either

Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, under which the Compe-

tent Authority passed the order and which is appealed against:

on its own motion or on the application of a party order that the appeal or petition be re-heard.

- 17. Order to be communicated to parties.—Every order of the Tribunal shall be in writing and a copy of every final order of the Tribunal certified as a true copy by the registrar shall be supplied free of cost to the parties as early as possible.
- 18. Signing of orders.—(1) Where the decision of the Tribunal is unanimous, a common order shall be signed by all the members of the Tribunal.
- (2) Where there is a difference of opinion, the decision shall be in accordance with the decision of the majority of the members of the Tribunal.
- (3) A member who does not concur with the decision of the majority may deliver a dissenting order.
- (4) The decision of the majority shall be reduced to writing and signed by all the members including the dissenting member.
- 19. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Tribunal may lay down.
- 20. Orders and directions in certain cases.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the end of justice.
- 21. Repeal and saving.—(1) The Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Rules, 1977, are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of any of the rules referred to in sub-rule (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Amellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1986.

FORM

(See rules 5 and 6)

BEFORE THE APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY, NEW DELHI MEMORANDUM OF APPEAL

[Section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfelture of Property) Act, 1976]

То	F.P.A.No./M.P.No. of 19 be filled up by the office of the Appellate Tribunal	
Shrì/S	IN THE MATTER OF	- APPELLANT.
	Vs.	
b	the Competent Authority, New Delhi*/Bomnay/Calcutta/Madras/Ahmeda-	RESPONDENTS.
	Other respondents, if any	•
1. A	Authority passing the order appealed against.:	Competent Authority, New Delhi*/Bombay/Calcutta/Madras/Ahmedabad.
2. I	Date of the order.	
3. I	Date of service of the order.	
	pecify whether a hearing in person or through an authorised representative s desired.	
	tegistered address of the appellant (including telephone No., if any) for the ervice of all notices, processes and communications:	
6. A	Address of the Respondent.	(i) The Competent Authority, New Delhi*/Bombay/ Calcutta/Madras/Ahmedabad.
		(ii) Other respondents, if any.
7. S	ection or sub-section of the section of the Smugglers & Foreign Exchange	

- 8. Relief claimed:
 - (i) Specify whether the entire order is disputed:
 - (ii) If only certain items of properties are disputed, enumerate them in an
- Ground of appeal (Annex a separate sheet if space is a

9. Ground of appeal (Annex a separate sheet if space is not sufficient):	
	(Signature of Appellant)
VERIFICATION	(Signature of Authorised Representative, if any)
hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge, info Verified to-day theday of	ormation and belief.

Verified to-day the ---Place: _____ Date: -

(Signature of the appellant or his authorised represen-

*Strike out whatever is inapplicable.

- Notes: 1. The memorandum of appeal should be filed in quadruplicate accompanied by four copies of orders appealed against (one of which shall be a certified copy of the order appealed against or the original copy of it served on the appellant). Any enclosure will also be in quadruplicate.
 - 2. The memorandum of appeal should be written in English or in Hindi and should set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal and should be without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
 - 3. It is enough if the memorandum of appeal is signed either by the appellant or the authorised representative. Where it is signed by the authorised representative, it should be accompanied by an authorisation of the appellant in his favour.
 - 4. For further details see the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Procedure) Rules, 1986.

[F.No.91/Genl/ATFP/86] By Order of the Appellate Tribunal for Forfeited Property B. CHAKRAVARTY, Registrar

(व्ययं विभाग)

मई विल्ली, 4 मंत्रैल, 1986

का. बा. 1548:---राष्ट्रपति, संबिधान के ब्रमुक्छेंव 77 के खण्ड (3) के मनसरण में, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथात :--

- 1. (1) इन निथमों का नाम बित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (पहला संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारी सा को प्रवृत्त होंगे। 2. विसीय प्रक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (जिसे इसमें इसके पक्कास उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपभियम (2) में "यात्रा भत्ता" से संबंधित कम सं. 4 की प्रविष्टि के पश्चात् "4क वैज्ञानिकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति या विदेश यात्वा" प्रविष्टि अंतःस्थापित की ज्याएगी।
- 3. उक्त नियमों में नियम 10 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्न-लिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, प्रथातः ---
 - "(७) संसद द्वारा यथा भ्रमुमोदित बजट में उपअधित मिधियों से द्राधिक निकियां विनियोग की प्राथमिक यूनिट **"वैज्ञा**निक की विदेश में प्रतिनियमित या विदेश याता" से या को विनि-योजित या पुनर्विनियोजित नहीं की जाएंगी "।
- ं अक्त नियमों की प्रानुशुंची 5 के उपबंदा में क्रम सं, 26(क) के स्थान पर निम्नलिखित कम सं. रखी जाएगा, प्रथात्:--

(1) (2)	(3)	(4)
"26(क) (1) सभी कार्यालय	पूरी	(1) ऐसी मणीनों के कथ
उपस्क र जिसके घन्त-	गनितयां	करन, भाड़े पर लेने, रख-
र्गेत टाइपराइटर,		रखाव करने, और मरम्मत
बन्तरासंघार उप स्कर,		करने पर होने वाले व्यय

1	2	3	4
	गणक, इलैक्ट्रानिक स्टेग्सिल कटर, दिक्टा- फोन, टेपरिकार्डर, फोटो कापियर, को- पोइंग सशीन, फैंकिंग सभीन, एँड्रोसोप्राफ, संचिकायन और सूची- करण प्रणालियां, ग्रादि		, विक्त मंत्रालय या पूर्ति विभाग द्वारा समय-समय पर इस निभिक्त जारी किए गए साधारण या विशेष धावेश के ध्रधीन रहते हुए उपगठ किए जाएंगे। (2) कार्यालयों के प्रधान भी निम्नलिखित सोमाओं
•	भी है किस्तु किसी भी प्रकार के कम्प्यूटर- सम्मिलित नहीं हैं।		तक इस संबंध में अधिकथित साधारण याती के पालन करने के अधीन रहते हुए इस संबंध में व्यय उपगत कर सकते हैं: भावतीं 500 रुपए भागवतीं 5,000 रुपए
(2) व्यक्तिगत <i>श</i> म्प्यूटर		10,000 स्	मंत्रालय /विभाग को 5 लाख रुपए की अधिकतम घनीय सीमा तक व्यक्तिगत संगणक ऋय करने की शक्ति होगी जिससे अधिक व्यय के लिए इसैक्ट्रानिकी विभाग से

5. उक्त नियमों की धनुसूची 6 में, तरणी के नीचे टिप्पणी में "एक रुपया और पन्नास पैसे" गुरुदो और "500 रुपए" "अंकों और गुरुदों के स्थान पर कमशः "2.50 रुपए" और "10,000 रुपए" अंक और शब्द खें जाएंगे।

श्रावेश लेना साव-यक होगा।"

(12) श्रधिस्वना

टिप्पणी : वित्तीय	शक्तियों का	प्रस्थायोजन	नियम,	1978	प्रधिसूच ना
सं. का	.भा. 2131	ता रीख 2	2 जुलाई,	1978	के ग्राधीन
प्रकाशिर	ाहुए ये औ	र सत्परभात्	उनके 🤚	निम्नलिख	त संशोधन
किए गर	ξ:				

- (1) अधिसूचना सं. का.भा. 1887, तारीख 9-6-1979 (2) सं. का.धा. 2942, ताराख 1-9-1979 (3)सं. का मा. 2611, तारीख 4-10-1980 (4)सं. का.घा. 2164, तारीख 15-8-1981 सं. का.धा. 2304, सारीख 5-9-1981 (5) सं. का.घा. 3073, तारीख 4-9-1982 (6) (7) सं. का.मा. 4171, तारीख 11-12-1982 सं. का.भा. 1314, तारीख 26-2-1983 (s)सं का मा. 2502, तारीख 4-8-1984 (9) सं. का.भा. 22, तारीख 5-1-1985 (10)सं. का.धा. 1958, तारीख 11-5-1985 (11) शुद्धिपत्न
- (13) ,, सं. का.भा. 3974, तारीख 24-8-1985 (14) ,, सं. का.भा. 5641, तारीख 21-12-1985

सं. का.बा. 3082, तारीख 6-7-1985

[सं. एफ. 1(11)-ई-2 (ए) /85] धार.एल. चौधरी, धवर सम्ब

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 4th April, 1986

- S.O. 1548.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (First Amendment) Rules, 1986.
 - (:?) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 8 of the Delegation of Financial Powers Rules 1978 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) after entry at serial No. 4 relating to "Travel Expenses" the entry "4A. Deputation or Travel abroad of Scientists" shall be inserted.
- 3. In rule 10 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(7) Funds shall not be appropriated or re-appropriated from or to the primary unit appropriation "Deputation or Travel abroad of Scientists" over and above the funds provided for ir the budget as approved by Parliament".
- 4. In Schedule V to the said rules, in the Annexure, for Serial No. 26(a), the following Serial No. shall be substituted namely:—

(1)		(2)	(3)		(4) [']
"26(a)	(1)	All office equipments including typewriters, intercom equipments,	Full powers.	(1)	The expendi- ture on the purchase, hire, upkeep of and repairs to such machines shall

(1)	(2)	(3)	(4)
	ca lcula tors,		be incurred
	electronic		subject to
	stencil cutters,		generalor
	dictaphones,		special orders
	tape recor-		issued by the
	ders, ph oto		Ministry of
	copiers,		Finance or
	copying		Department of
	machines,		Supply from
	franking		time to time
	machines.		in this b, half.
	addresso-		(2) Heads of Offices
	graphs,		may also incur
	filling and		expenditure in
	indexing		this regard
	system g s, etc.		subject to the
	c xeluding		observance of
	computers of		general condi-
	a II kinds,		tions laid down
			in this regard
			upto the
			following
			limits;
			Recurring
			Rs. 500
			Non-recurring
			Rs. 5,000
	(ii) Personal	Rs. 10,000/-	Ministry/-

(ii) Personal Rs. 10,600/s computers

Ministry/Department
shall have
power for
purchase of
personal
computers upto
the monetary
ceiling of Rs.
5 lakhs beyond
which cleararee
from Department of
Electronics shall
be necessary".

5. In Schedule VI to the said rules, in the Note below the Table, for the words "rupces one and paice fifty" and the word and figures "Rs. 500", the words and figures "Rs. 2.50" and "Rs. 10,000" shall, respectively, be substituted.

Note: The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 pub. lished vide Notification No. 80, 2131, dated only 72, 1978 have subsequently been amended by:—

(i)	Notification	No. SO. 1887, dated 9-6-1979.
(ii)	,,	No. SO. 2942, dated 1-9-1979.
(iii)	,,	No. SO. 2611, dated 4-10-1986.
(iv)	**	No. SO. 2164, dated 15-8-1981
(v)	• •	No. SO. 2304, dated 5-9-1981.
(vi)	13	No. SO. 3073, dated 4-9-1982.
(vii)	,,	No. So. 4171, da ted 11-12-1982.
(viii)	,,	No. SO. 1314, dated 26-2-1983.
(ix)	"	No. SO. 2502, dated 4-8-1984.
(x)	,,	No. SO. 22, datcd 5-1-1985.

(xi) Corrigendum No. SO. 1958, dated 11-5-1985

(xii) Notification No. SO. 3082, dated 6-7-1985.

(xiii) ,, No. SO. 3974, dated 24-8-1985.

(xiv) ,, No. SO. 5641, dated 21-12-1985.

[No. F. 1(ii)E II (A)/85]

R.L. CHAUDHRY, Under Sccy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1986

का. आ. 1549. चैंक कारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की भारा 53 द्वारा प्रदक्ष सिक्तयों का प्रयोग करत हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतव्हारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध जम्मू एण्ड कश्मार बैंक रितिमिटेड, श्रीनगर पर 6 मार्च, 1986 से 5 जून, 1986 सक भी तीन महीने की अविध के बास्ते, अथवा जब तक इस बैंक को लिए नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष की निय्वित नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो, लागू नहीं हो गे।

[संख्या 15/4/85-बी.ओ.-3(1)]

(Department of Economic Affairs)

(Bunking Division)

New Deihi, the 1st April, 1986

S.O. 1549.—In exercise of the powers, conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of subsection (1) and (2) of section 10-B of the said Act, shall not apply to the Jammu and Kashmir Bank Ltd., Srinagar for a period of 3 months from 6th March, 1986 to 5th June, 1986 or till the appointment of a regular whole-time Chairman for that Bank, whichever is earlier.

[No. 15/4/85-B.O.III(i)]

का. आ. 1550.—बैं ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (9) के उपबन्ध, जहां तक उनका सम्बन्ध अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए बैंक द्वारा चार महीने से अधिक की अविधि के लिए किसी व्यक्ति की नियुवित करने की मनाही से है, अम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर 5 जून, 1986 तक लागू नहीं होंगे।

[संस्था 15/4/85-बी.ओ.-3(2)]

S.O. 1550.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of subsection (9) of Section 10-B of the said Act shall not, to the extent they preclude the bank from appointing a person to carry out the duties of a Chairman beyond a period exceeding four months, apply to the Jammu and Kashmir Bank Ltd., Srinagar, upto the 5th June, 1986.

[No. 15/4/85-B.O.III(ii)]

नई दिल्ली, 17/31 मार्च, 1986

का. जा. 1551.—बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की भिकारिश एर एत्द्रारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध 8 जून, 1987 तक की और अवधि नक युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता पर उस सीमा तक लाग

नहीं होंगे जहां तक कि इनका संबंध मैंसर्स लुज इलैक्ट्रिकल्स प्रा. लि. के शेयरों की इसकी धारिता से है ।

[संख्या 15/23/84-बी.ओ.-3]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 1986

S.O. 1551.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsection (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the United Bank of India, Calcutta for a further period till 8th June, 1987 insofar as they relate to its holding of the shares in the Luz Flectricals Private Ltd.

[No. 15/23/84-BO.III]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

बाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्मी, 19 भ्रप्रैल, 1986

का० ग्रा० 1552.—ितयांत (क्वालिटी नियंक्षण और निरीक्षण) प्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा भैमर्स दिल्ली टेस्ट हाऊस, सोन् इन्डस्ट्रीयल एस्टेट जी० टी० करनाल रोड, विल्ली-110033 इससे संलग्न प्रमुख्यों में विनिर्दिष्ट के प्रमुखार खिज तथा प्रयस्कों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए प्रभिक्षरण के रूप में 5 प्रप्रैल, 1986 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मास्यक्षा देती हैं।

ग्रनस्ची

- फैरोमैंगनीज के धातु मल सहित फैरोमैंगनीज
- 2. निस्त्र बोक्साइड सहित बोक्साइंड
- भैगनीज डायक्साइड
- 4. कायना इंडे
- 5. सिसीमेनाइट
- 6. संकेन्द्रित जिंक सहित कच्चा निक
- परिदग्ध और विस्तरत मैगनेपाइट सहित मैगनेगाइट
- बैराइटिम
- लाल औक्साइड
- 10. पीला गैरिक
- 1.1. से लखंडी
- 12. स्पतीय (फैल्डस्पार)

[फा॰ सं॰ 5/10/83-ईम्राई एण्ड ईपी] एन० एन० हरिष्ठरन, विदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 19th April, 1986

S.O. 1552.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 5th April, 1986 M/s. Delhi Test House, Sohna Industrial Estate, G.T. Karnal Road, Delhi-110033 as an agency for the inspection of Minerals & Ores as specified in schedule annexed hereto prior to export.

SCHEDULE

- 1. Ferromanganese, including ferromanganese slag
- 2. Bauxite, including calcined bauxite

- 3. Manganese Dioxide
- 4. Kyenite
- 5. Sillimanite
- 6. Zinc Ores, including zinc concentrates
- Magnasite, including dead burnt and calcined magnesite
- 8. Barytes
- 9. Red Oxide
- 10. Yellow Ochre
- 11. Steatite
- 12. Feldsper.

[F. No. 5/10/83-FI&EP] N. S. HARIHARAN, Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय नई विल्ली, 2 अप्रैल, 1986

का. आ. 1553.—द' दून स्कूल', देहरादून को अंबिका चीरिटेबल फाऊ डेशन, लंदन द्वारा उपहार प्राप्त होने पर 60 सं. के सिंक्लेयर माइक्रो-कम्प्युटर माइल 2×81 के आयात के लिए 49,500/- रु. का एक सीमाशल्क निकासी परिकट सं. पी/जे/ 3052529/एन/एम एन/96/एच/85/एम एन एस दिनांक 25-9-1985 इसके जारी करने की तारीख से 9 महीने की वैधता की अबधी के लिए दिया गया था । अब स्कूल ने उक्त सीमा-शुल्क निकासी परोपट की अनुभिषि सीमाशुल्क प्रायोजन प्रक्रि जारी करने का इस आभार पर आवेदन किया है कि सीमाश्चक निकासी परिमट की मल प्रकि खो गई है। लाइसे सधारक ने आवश्यक शपथपत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार उदत सीमा शुल्क निकासी परिमद का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है तथा सीमाधास्क निकासी परिमट का बोष 49,500/- ह. है। इष्टिभमत्र में इस बारे में भी घोषणा की गई है कि यदि बाद में उक्त सीमाशुल्क निकासी परिमट सिल जाता है तो इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को लोटा दिया जाएगा । इस दारे में संतष्ट होने पर कि उक्त सीमाशल्क निकामी परिमट की मूल प्रीत खो गई है, अधोहस्ताक्षरी यह आदेश देता है कि आवेदक को सीमाशल्क निकासी परमिट की अनेलिपि सीमाशल्क प्रायो-जर प्रति जारी की जाए । मैं , आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 की उप-धारा 9(घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सीमाश्ल्क निकासी परिमट की मूल सीमाश्ल्क प्रायोजन प्रति को एतद्वारा रच्द करता हूं।

> [फा. सं. 3/14/85-86/एम.एल.एस./3] एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 2nd April, 1986

S.O. 1553.—The Doon School, Dehra Dun, was granted a CCP No. P[1]3052529 N[MN]96]H[85]MLS, dated 25-9-1985 for import of 60 Nos. Sinclair Micro-Computers Model 2×81 being gifted to them by Ambika Charitable Foundation. London, valuing Rs. 49,500 with a validity period of Nine months from the date of issue. Now the School have applied for grant of a Duplicate Copy of the Customs Purposes Copy of aforesaid CCP on the ground that the subject copy of the CCP has been lost. The licensee has furnished necessary Affidavit according to which the aforesaid CCP has not been utilised at all and the balance against the CCP is Rs. 49,500. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said CCP is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. On being satisfied that the original Customs Purposes Copy of the aforesaid CCP has been lost, the undersigned directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the CCP should be issued to the applicant. I also in exercise of the powers conferred

in Sub-Clause (d) of Clause 9 of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the original Customs Purposes Copy of the above CCP.

[F. No. 3|14|85-86|MLS|3]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports For Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक ग्रायात-निर्यात का कार्यालय) महास, 17 फरवरी, 1986

विषय :--सर्वश्री हिनक्षा टैक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, संख्या 14 भर त्यागराय शेंड, टी० नगर, मद्रास-600017 को जारी किये गये रुपये 7,06,063/- के प्रश्निम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187 दिनोक 21-6-35 का रहीकरण।

का॰ 1554 — सर्वेश्री हिनका टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिभिटेड, 14 सर त्यागराय रोड, टी॰ नगर, मद्रास-17 को इपये 7,06,063/- तक पालीस्टर फिलमेंट यार्ने का धायात करने के लिये घ्रांग्रम लाइसेंस संख्या पी/एस/0435187 दिनांक 21-6-85 जारी किया गया था।

लाइसेंसमारी ने उपर्युक्त भूषिम लाइसेंस की मुद्रा विनियम प्रति की धनुलिपि प्रति आरी करने के लिये इसिलिये माबेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल प्रति किसी भी सीमांगुल्क प्राधिकारी या बैंक से पंजीकृत किये विना या तो उपयोग में लाये विना म्रस्थानस्य हो गयी है।

मूल लाइसेंस का पूरा मूल्य रुपये 7,06,063/- के लिये ब्रध मुद्रा विनियम प्रति की प्रनुलिपि प्रति जारी करने के लिये ब्रावेदन किया गया है।

अपने तर्क के समर्थन मं भ्रावेदक ने ग्राप्य कमिश्नर द्वारा साक्ष्यांकित एक शपय-पक्ष दाखिल किया है।

ब्रधोहस्ताक्षरी इत बात से संतुष्ट है कि ग्रिशम लाइतेंस संख्या पी/ एस/0435187/सं/एक्स एक्स/95/ए/85 दिनांक 21-6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण की मूल प्रति बस्पानस्य हो गयी है। भ्रावेदक के भ्रावेदन पर विचार करते हुए, रुपये 7,06,063/- के ग्रिशम लाइसेंस संख्या पी/एल/0435187 विनांक 21-6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण की मूल प्रति एसव्हारा रह किया जाता है।

लाइसेंस का विवरण

(1) लाइसें स संख्या तथा विनोकः पी/एल/0435187/सी/एक्स एक्स/95/

एम/85 विनांक 21-6-85

(2) लाइसेंक्षिय ब्रधिकारी ः संयुक्तमृत्वय नियंत्रक ग्रायात-निर्यात मद्रासः।

(3) माल का विवरणः : पालीस्टर फिलमेंट यार्न

(4) लाइसेंस की प्रवधि : एएम 86 (5) मुद्राक्षेत्र : जी०सी०ए०

(6) जिथ्योग में लाये गये माल का मूल्य : कुछ नहीं।

(7) उपयोग म किये गर्ये माल का मूल्य : रुपये 7,06,063/-

यदि रुपये 7,06,063/- के झिंग्रम लाइमेंन संख्या पो/एल/0435187 दिनांक 21-6-85 की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रित की मूल प्रति का पता लग जाये तो उसकी उपयोग किये बिना इस कार्यालय को भेज देना बाहिये। मुद्रा विनियम नियंद्यणप्रति की ज्ञनुलिपि प्रति संक्या बी/2464765 झलग जारे। किया जाता है।

[भावेश सं० ए डी बी एल भाई सी ! 163 | ए एम • ८ 4 | ए एल ई ओ] कें कें भार कुमार, उप मुख्य नियंत्रक भायात-निर्यात, कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक भायात-निर्यात। (Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
Madras, the 17th February, 1986

Subject:—Order for cancellation of Advance Licence No. P/L/0435187 dated 21-6-85 for Rs. 7,06,063/issued in favour of M/s. Haniffa Textiles Pvt. Ltd., No. 14, Sir Thyagaraya Road, T. Nagar, Madray-600017.

S.O. 1554:—M/s. Hanista Textiles Pvt. Ltd., 14, Sir Thyagaraya Road, T. Nagar, Madras-17 were granted an Advance Licence No. P/L/0435187 dated 21-6-85 for Rs. 7,06,063/- for import of Polyester Filament Yarn.

They have applied for a duplicate copy of Exchange Control copy of the above advance licence stating that the original have been misplaced without having been registered with any Custom authority or Banks and utilised at all. The total amount for which the duplicate Exchange Control copy is required to cover the entire amount of Rs. 7.06.063/-.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit on stamp paper duly attested by Commissioner of Oath.

I am satisfied that the original Exchange Control copy of the Advance Licence No. P/L/0435187 /C/XX/95/M/85 dated 21-6-85 has been misplaced. Having considered the party's request for issue of duplicate Exchange Control copy of the Licence the original Exchange Control copy of licence No. P/L/0435187 dated 21-6-85 for Rs. 7,06,063/- is hereby cancelled.

PARTICULARS OF LICENCE

1. Licence No. & Date P/L/0435187/C/XX/95/M/85 dt. 21-6-85
2. Issuing authority JCCI & E., Madvas.
3. Description of goods Polyester Filament Yarn
4. Period AM. 86

4. Period AM. 80
5. Currency Area G.C.A.
6. Value utilised Nil

7. Value un utilised Rs. 7.06.063/-

The original Exchange Control copy of the Advance Licence No. P/L/0435187 dt. 21-6-85 for Rs. 7,06,063/-, if traced out later, should be surrended to this office unutilised.

Duplicate Exchange Control Copy No. D/2464765 issued separately.

[Order No. Adv. Lic. 163/AM. 84/ALEO] K.K.R. KUMAR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश मंत्रालय

नई **किल्ली, 17/31 मार्च, 1986**

का. आ. 1555.—राजनियक एवं कोंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार इसके धारा, टोक्यो स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री उमेश कुमार को 25-11-85 से कोंसली एजेट का कार्य करने के लिए प्रीपिकृत करती है।

> [टी. 4330/1/85] आर. दयाकर, तम सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS New Delhi, the 17/31st March, 1986

S.O. 1555.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Umesh Kumar, Assistant in the Embassy of India, Tokyo with effect from 25-11-85 to perform the duties of Consular Agent.

[T. 4330/1/85] R. DAYAKAR, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय गई विल्ली, 24 फरवरी, 1986

का. आ. 1556.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेट 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त कविस्तयों का प्रयोग करते हुए लघु उद्योग संगठन (वर्ग 3 और वर्ग 4 प्रव) भर्ती निगम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थाट् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघू उद्योग संगठन वर्ग 3 और वर्ग 4 पव) भती (संशोधन) नियम, 1986 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारी ह को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लघु उद्योग संगठत (वर्ष 3 और अर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960 की अन्स्ची में
 - (1) अधीक्षक के पद के सामने स्तम्क 9 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिकित रक्षा जाएगा, अर्थात्:—

''लागू नहीं होता''।

(2) उच्च श्रोणी लिपिक की पद के सामने स्तंभ 9 में, दिश्यमान प्रविष्टि के स्थान पर दिम्मलिखित रक्षा जीएगा, अर्थात्:— ''लाग् नहीं होता''।

> [सं. ए-12018/1/85-ए(एन जी)] बचन पाल सिंह, उप-निवेधक (प्रशा.)

टिप्पण : --मूल नियम अधिसूचना का. नि. था. 982 तारीख 12-4-60 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तस्पव्चात् का. आ. 2929 तारीख 4-12-61, का. नि. आ. 2144 तारीख 26-2-1963, का. नि. आ. 3656 तारीख 18-11-1966, सा. का. नि. 2476 तारीख 17-9-1974 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Office of the Development Commissioner)
(Small Scale Industries)

New Delhi, the 24th February, 1986

- S.O. 1556.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Schedule to the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960,—
 - (i) against the post of Superintendent in column 9, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—
 "Not applicable".
 - (ii) against the post of Upper Division Clerk in column
 9, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Not applicable".

[No. A-12018|1|85-A(NG)] B, P. SINGH, Dy, Director (Admn.)

NOTE: Principal rules published vide notification S.R.O. 982 dated 12-4-60 subsequently amended vide S.O. 2929 dated 4-12-1961, S.R.O. 2144 dated 26-7-1963, S.R.O. 3656 dated 18-11-1966, G.S.R. 2476 dated 17-9-1974.

(भरकारी उद्यम विभाग)

नई विख्ली, 31 मार्च, 1986

ग्रावेश

का मा 1557.—विकास परिषय (कार्यविधिक) नियम, 1952 के नियम, 2,4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) मिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रवत्त मिनियमें का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्र्युद्धारा तेल और गैस मन्यविण तथा उत्पादन उद्योग के लिए उपकरणों हेतु विकास परिषद् की संरचना में निम्नलिखिन संशोधन करती है:—

कम संख्या~1. विकास परिषद के प्रश्यक्ष "सचिव, भारी उद्योग विभाग" के स्थान पर "सचिव, औद्योगिक विकास विभाग" होंगे।

क्रम संख्या-2. सवस्य का पदनाम "महानिदेशक, तकनीकी विकास महा-निदेशालय" के बजाय "मचिव और महानिदेशक (नकनीकी विकास)" होगा। कम संख्या- 7. सलाहकार (सकनीकी) और पदेन संयुक्त सचिव "भारी उद्योग विभाग" के बजाय "औद्योगिक विकास विभाग" का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे।

बाकी संरचना, विचारार्थ विषय और शर्ते ग्रादि ग्रपरिवर्तित रहेंगी।

[फा.सं. 1(9)-2/84-टी, एस. बस्स्यू.]

एस.सी. ढीगरा, सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त मचिव

(Department of Public Enterprises) New Delhi, the 31st March, 1986

ORDER

S.O. 1557.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 195!) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby amends the composition of the Development Council for Equipment for Oil and Gas Exploration and Production Industry to the following effect:—

- S. No. 1: Chairman of the Development Council shall be "Secretary, Industrial Development" in place of "Secretary, Department of Heavy Industry".
- S. No. 2: The designation of the Member shall be "Secretary and Director General (Technical Development)" instead of "Director General, Directorate General of Technical Development".
- S. No. 7: Adviser (Technical) & Ex-officio Joint Secretary shall be the Member representing the "Department of Industrial Development" instead of "Department of Heavy Industry".

The rest of the composition, terms of reference and term etc., shall remain the same.

[F. No. 1(9)-2|84-TSW] S. C. DHINGRA, Adviser (Technical) & Ex-Officio Joint Secretary

खाश एवं नागरिक पूर्ति मंद्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) भारतीय मानक संस्था नईदिस्ली, 21 मार्च, 1986

कार्रार्थार 1558---.भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) नियम और विनियम 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) और विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारतीय मानक विणिष्टि संख्या S:10908--1984 तरल पेट्रोलियम गैस के लिये रवड़ की नम्य निलकाओं की विणिष्ट 1984-08-31 से निर्धारित की गई है।

[संख्या सीएमडी/13:2]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 21st March, 1986

S.O. 1558:—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and sub-regulations (2) and (3) of Regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Indian Standard Specification number IS: 10908—1984 Specification for flexible rubber tubing for liquefied petroleum gas has been established with effect from 1984-08-31.

का०आ० 1559.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार भारतीय भानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जो मानक चिह्न उनके डिजाइन, शाब्दिक विषयण तथा तत्सबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिये गये है वे निर्धारित कर दिये गये हैं। ये भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और इसके अधीन वन नियमों तथा विनियमों के निमित्त प्रत्येक के आगे दी गई तारीखों से लागू होंगे।

अनुसुची

ऋम सं	मानक चिह्न डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		सोडियम बाइकोमेट, तकनीकी	IS: 249—1979 सोडियम बाइकोमेट तकनीकी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनो- ग्राम जिसमें "ISI" अक्षर होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई निश्चित गैली और परस्पर मंबद्ध अनुपात में बनाया गया, डिजाइन में निर्देशन के अनुसार मोनोग्राम के ऊपर भारतीय मानक संख्या	1985-01-16
2.	Œ	सरसों का तेल	IS : 546—1975 सरसों के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	11	1985-07-11
3.		वोरैक्स, तकनीकी	IS: 1109—-1980 बोरैन्स की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	n	1984-10-16
4.		निर्जर्मक उपकरण (टेबल मॉडल)	IS : 5022—1979 निर्जर्मक उपस्कर (टेबल मॉडल) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्थाका मोनो- ग्राम जिसमें "ISI" अक्षर होते हैं स्तम्भ (2) में विखाई गई निष्चित गैली और परस्पर सम्बद्ध अनुपात में बनाया गया, डिजाइन में निदेशन के अनुसार मोनोग्राम के ऊपर भारतीय मानक संख्या अकित है।	្ខំ1985-03-01
5.		पलंग चौख टे, अस्पताली सामान्य प्रयोजी	lS : 5029—-1979 पलंग चौखटे सामान्य प्रयोजी की विशिष्टि	,,	1985-05-01
6.	15.16897	कृत्निम दांतों के लिए आधारभूत पोलीमर सामग्री	IS: 6887—1973 कृत्रिम दोतों के लिए पोलीमर सामग्री	n	1985-02-01

[सं॰ सीएमडी/13: 9]

S.O. 1559.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design (s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

24 GI/86—3

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the date shown against each :—

SCHEDULE

	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the design of the Standard Mark	Date effect	of
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)	
1.		Sodium bichromate, technical.	IS: 249—1979 Specification for sodium bichromate technical (Third Revision).	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1985-01	-16
2.		Mustard Oil	IS: 546—1975 Specification for mustard oil. (Second Revision).	The monogram of the Indian Stanards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1985-07	-16
3.	رين المنافقة	Borax, technical.	IS: 11091980 Specification for borax (Second Revision).	-do-	1984-10	-16 🛦
4.	St	erilizer, instruments (table model)	IS: 5022—1979 Specification for sterilizer, instruments (table model) (Second Revision)	-do-	1985-03	10-
5.	القا	Bedsteads hospital, general purposes.	IS: 5029—1979 Specification for bedsteads hospital, general purposes.	-do-	1985-05	-01
6.	\(\sum_{15.6887}\)	Denture base polymer	1S: 6887—1973 Specification for denture base polymer.	-do-	1985-02	10-

[No. CMD/13:9]

का. आ. 1560.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपिविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगने की फीस अनुसूची में दिये गये व्यारों के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से लागू होंगी।

<i>*</i>	·····································	नुसूची ———		
क्रम . उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी सं .	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्ष	प्रति इकाई	मुह्र लगाने की फीस	लागू होने की तारीख
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सोडियम बाइकोमेट तकनीकी	IS: 2491979 सोडियम बाइकोमेट तकनीकी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एक टन	 पहली 500 इकाइयों के लिए रु. 10.00 प्रति इकाई, और 	1985-01-16
	· -		 501वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए र. 7.50 प्रति इकाई 	
2. सरसों मः। तेल	IS: 546—1975 सरसों के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक टन	 पहली 1000 इकाइयों के लिए रु. 20.00 प्रति इकाई, 	1985-07-16
			 1001वीं से 2000 तक इकाइयों के लिए र. 10.00 प्रति इकाई, और 2001वीं और इससे अधिक इकाइयों के लिए र. 5.00 प्रति इकाई 	
3. बोरैक्स तकनीकी	IS: 11091980 बोरैक्स की विभिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक टन	য. 20.00	1984-10-16
4. निर्जर्मक उपस्कर (टेबल मॉइल)	IS: 5022—1979 निर्जर्मक उपस्करों (टेबल मॉडल) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक निर्जर्मक	50 पैसे	1985-03-01
5. पलंग चौखट अस्पताली सामान्य प्रयोजी	IS: 5029—-1979 पुलंग चौखट अस्पताली, सामान्य प्रयोजी की विशिष्टि	ग्किसद	 पहली 500 इका इयों के लिए क. 10.00 प्रति इका ई, और 501वीं और उससे अधिक इका इयों के लिए क. 5.00 प्रति इका ई 	1985-05-01
6. कृत्निम वांतों के लिए आधार- भूत पोलीमर सामग्री	IS: 6887—1973 कृत्निम दांतों के लिए आधारभूत पोलीमर सामग्री की विशिष्टि	एक किग्रा.	 पहली 1000 इकाइयों के लिए 50 पैसे प्रति इकाई, और 1001वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए 25 पैसे प्रति इकाई। 	1985-02-01

बी .एन . सिंह, अपर महानिदेशक S.O. 1560:—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution Certifia Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit

cation Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. Product/Class of No. product	No. and Title of Relevant Indian Standard.	Unit	Marking fee per unit	Date of effect
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Sodium bichromate, technical	IS: 249—1979 Specification for sodium bichromate, technical (Third Revision).	One Tonne	 (i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units and (ii) Rs. 7.50 per unit for the 501st unit and above. 	1985-01-16
2. Mustard Oil	IS: 546—1975 Specification for Mustard Oil.(Second Revision).	One Tonne	 (i) Rs. 20.00 per unit for the first 1000 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the next 1001 st to 2000 units and (iii) Rs. 5.00 per unit for the 2001 st unit and above. 	1985-07-16
3. Borax, technical	IS: 1109—1980 Specification for borax (Second Revision).	n One Tonne	Rs. 20.00	1984 - 10-16
4. Sterilizer, instruments (table model.).	IS: 5022—1979 Specification for sterilizer instruments (table model) (Second Revision).	One Sterilizer	50 Paise.	1985-03-01
5. Bedsteads hospital, general purposes.	1S: 5029—1979 Specificatio for bedsteads hospital, general purposes.	n One Piece	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units and(ii) Rs. 5.00 per unit for the 501 st unit and above.	1985-05-01
6. Denture base polymer	1S: 6887—1973 Specification for denture base polymer	n One Kg.	 (i) 50 Paise per unit for the first 1000 units and (ii) 25 paise per unit for the 10001st unit and above. 	st 1985-02-01
			[No. CM B.N. SINGH, Addl. Direc	ID/13 : 10] tor General

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 31st March, 1986

S.O. 1561.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraphs 7 and 9 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Miinstry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2723, dated 8th August, 1984, namely :—

In the said notification, against serial number 23, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri I. B. Pandey, President,

Coal Mines Officers Association of India,

P.O. Singrauli, District Sidhi (Madhya Pradesh)"

[No. 7(3)/80-Adm,I(PF) (Vol. II)] RAMESH KUMAR, Director

ऊर्जामंत्रालय (कोयलाविभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1986

का. अा. 1561. — केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भिवष्य निधि स्कीम, 1948 के पैरा 7 और 9 के साथ ५ ठित, कोयला खान भिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा उक की उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त हावितयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ऊर्ज महालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2723 तारीख 8 अगस्त, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूधना में, ऋम संख्या 23 के सामने विदामान प्रविच्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

''श्री आई. बी. पाण्डेय, अध्यक्ष भारतीय कोयला खान अधिकारी संगम डाकदर सिंगरौली, जिला सिधि (सध्य प्रदेश)

> [सं. 7(3)/80-प्रशा.-1(पी.एफ.) जिल्य 2] रमेश अमार, निदेशक

नई दिल्लों, 11 अप्रैल 1986

फा.आ. 1562 — केल्डांय मारकार ते, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अभिनियम, 1957 (1957 का 20) को धारा 7 की उप-घारा (1) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, बान और कोयला गंद्रालय (कोयला विभाग) की अधिमूनना सं, का आ 194 (अ) तारीख 16 मार्च 1985 द्वारा जिसे भारत के राज्यात, असाधारण, भाग 2, खंब 3, उप-खंब (ii) तारोख 16 मार्च, 1985 में प्रकाणित किया गया था, जस अधिसूचना से उपा**यक अनुसू**चः में विनिर्विष्ट परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों का अर्घन करने के अपने आग्रय का सूधना दो था, और पूर्वीका परिक्षेत्र में भूमि और अधिकारों के अर्जन के प्रति कोई आक्षेप नहीं किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार से परासर्श करने के पश्यात् यह समाधान हो गया है। कि इससे संलग्न अनुसूज में विणित 1701.363

अतः केर्म्बाय मरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (I) हारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि उक्त अनुसूख? में विणित 1701.363 हैक्टर (लगभग) या 4204.35 एकड़ (लगभग) साप की मृमि का अर्जन किया जाना है;

इस अधिसूचना के अधीन आने बाले क्षेत्र के रेखांक सं. मी $\sim 1 \left(\frac{\pi}{8} \right) / III/डोआ<math>7/304 - 1035$ -तारीख 25 अक्तूबर, 1985 का निरोक्षण कलक्टर, बिलासपूर, (मध्य प्रवेश) के कार्यालय में या कोयला निवंतक, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रोट, कलकता के कार्यालय में या वैस्टर्न कोलफोल्ब्र्स लिमिटेड (राजस्व किभाग), कोयला एस्टेट, सिविल, लाइंस, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची कुमशंका-[[[व्लाक कोरबा कोलफील्डस जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

क्रम सं. ग्राम	पटवारं <i>।</i> सकिल सं.	खेवट सं	. तहसील -	जिला	क्षेत्र हैनटरों में	टिप्पणिय <u>ां</u>
	49	3	कटघोरा	मिलासपु र	7.453	
2. इस्बर	49	4	11))	64.372	1)
3. मालगाँव	49	37	11	11	157.148	"
 सिंगतपुर 	49	39	n	7)	126.935	"
5. बेलटिफ री	49	5	μ	II.	194, 391	,,
6. सिरक ी	4 6	30	11	n	375.678	17
7. रेणकी	55	55	,,	n	26.971	,,
8. सुवाभंडा	5 5	38		n	164.040	[n
9. चैनपुर	5 5	40	1)	11	535.526	2 12
10. रतीजा	56	61	n	n	48.844	,,

कुल क्षेत्र

1701.363 हैक्टर (लगभग)

4204.25 एक (लगमग)

दिपका ग्राम में अजिन किए गए प्लाट सं.

627 (भाग), 628 (भाग), 629(भाग), 630 (भाग) , 634 (भाग), 635 से 638, 639 (भाग), 640, 641 (भाग), 642 (भाग), 644 से 652 और 653 (भाग)।

झाबर ग्राम में अजित किए गए प्लाट सं.

3,9-40 (भाग), 41 (भाग), 42, 43, 44/1, (भाग), 44/2, 44/3, 45 से 94, 95 (भाग), 96 (भाग), 97, (भाग), 127 (भाग), 129 (भाग), 130 (भाग), 131 से 135, 136 (भाग), 137 (भाग), 138 से 164, 165 (भाग), 166 भाग 167 (भाग), 168 (भाग), 176 (भाग), 178 (भाग), 179 (भाग), 180 (भाग), 274, (भाग), 275 (भाग) और 281 (भाग)। मालगौव ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं.

1 से 129, 130, (भाग), 131, 132, 133 (भाग), 134 (भाग), 135 (भाग), 137 (भाग), 138 से 160, में 161 (माग), 162, 163 (भाग), 164/1 (भाग), 164/2 (भाग), 204 (भाग), 205 (भाग), 206 (भाग), 207 (भाग), 210 (भाग) 211, (भाग), 212 से 247, 248 (भाग), 249 (भाग), 250 (भाग), 252 (भाग), 253, 254, (भाग), 256 (माग), 257 (भाग), 258 (भाग), 259 (भाग), 266 (माग), 267 (भाग, 268 से 532, 533 (भाग), 534, 535, 536 (भाग), 537 (भाग), 538 (भाग), 544 (भाग), 545 (भाग), 546 (भाग), 547 (भाग) और 559 (भाग)।

क्षिगतपूर ग्राम में अजित किए गए प्लाट सं

1 से 137, 138 (माग), 139 से 211

बेलटिकरी ग्राम में अजित किए गए प्लाट सं.

ा से 323, 324, (भाग), 325 से 334, 335 (भाग), 339 (भाग), 353 (भाग), 356 (भाग), 357 (भाग), 358, 359 (भाग), 360 (भाग), 363 (भाग), 363, 364 (भाग), 365 से 372 (भाग), 373 (भाग), 374, 375 (भाग), 378(भाग), 379 से 405, 406 (भाग), 407 से 485, 486 (भाग), 487 से 523, 524 (भाग), 525 (भाग), 526 (भाग), 527 (भाग), 529 से 531, 532 (भाग), 533 से 559, 560 (भाग), 561 से 567, 568 (भाग), 570 (भाग), 571 (भाग), 615 (भाग), 616 (भाग), 617 से 630, 631 (भाग), 632 (भाग), 633 (भाग), 634 (भाग), 635 (भाग), 642 (भाग) और 676 (भाग)।

सिरकी ग्राम में अर्जित कए गए प्लाट सं.

67 (मार्ग), 69, 70, 71 (मार्ग), 73 (मार्ग), 74 से 78, 79 (मार्ग), 80 से 148, 149 (मार्ग)), 154 (मार्ग), 155 (मार्ग), 156 से 443 (मार्ग)।

रेणकी भाम में अजित किए गए प्लाट सं.

1 (भाग), 2/1 (भाग), 56 (भाग), 56 (भाग), 57 (भाग), 59 (भाग), 60 (भाग), 674 (भाग), 675 (भाग), और 679 (भाग)। मुतार्गक्षी ग्राम में अजित विहर गए प्लाट एं.

ा से 287, 288 (भाग), 289 से 307, 308 (भाग), 309 (भाग), 311 (भाग), 314 (भाग), 315, 316 (भाग), 317 (भाग) 318 से 344, 345 (भाग), 346 (भाग), 348 (भाग), 350 (भाग), 354 (भाग), 355 (भाग), 356 (भाग), 357 (भाग), और 359 (भाग)। भैनपूरग्राम में अजित किए गए प्लाटसं.

1 से 12, 13 (भाग), 14 से 19, 20 (भाग), 21 से 962, 963 (भाग), 964 से 1065

रतीजा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं.

- क......ख रेखा, जिन्दु 'क' से प्रारम्भ होती है और विपक्षा ग्राम में प्लाट मं. 627, 628, 630, 634, 639, 641, 642 से होकर जाती है, फिर झाजर ग्राम में प्लाट सं. 281, 275, 274 में से होकर जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलक्षं है।
- **ब**⊸-ग रेखा, झाबर और बेलटिकरी ग्राम की सम्मिलित स्रीमा के साथ-साथ जातो है और बिन्दु 'ग' पर मिलता है।
- ग----च रेखा आवर प्राप्त में प्लाट सं.्180 , 179, 178, 176, 165, 166, 167, 168, 137, 136, 127, 130, 129, 97, 96, 95, 39-40, 41 से 4√1 से होकर जाती है। और सावर और सिरका ग्राप्तों के सम्मिलित सामा पर बिन्दु 'ध' पर मिश्रता है।
- म--७ रेखा सिरको ग्राम में प्लाट एं. 155, 154, 149, 73, 79, 71, 67 से हींकर जाती है, तब रतीजा ग्राम में प्लाट एं. 564, 566, 567, 568, 570 में से होकर जाती **है और** प्लाट एं. 570 में बिन्दु क पर मिलती है।
- ह——च रेखा रक्षीजा ग्राम में प्लाट सं. 570, 582, 583, 592, 593, 594/1, 433, 611, 616/1, 621, 332, 833 में से होकर जाती है तब चैनपुर,ग्राम में प्लाट सं. 13, 20, 963 से होकर जाती है और फिर रेणकी के प्लाट सं. 57, 1 में से जाती है और प्लाट सं. 1 में बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- प---छ रेखा, रेणकी ग्राम में व्लाट सं. 1,2/1, 5,56,59,60,674,675,679,57 में से हांकर जाती है और चैनपुर, रेणकी और सुवामंडी ग्रामों के क्रिसंगम बिन्धु 'छ' पर मिलती है।
- छ—ज—स रेखा सुवार्षकी प्राप्त में प्लाट सं. 359, 357, 356, 355, 354, 345, 350, 348, 346, 317, 316, 314, 288, 311, 309, 308, में से होकर जातो है, तब सुवार्षकी और वरदी बाजार की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्धु 'स' पर मिलती है ।
- हा—ङा रेखा मालगाँव ग्राम में प्लाट से. 538, 536, 537, 544, 533 545, 546, 547, 558, 267, 266, 259, 258, 257 256, 254, 252, 250, 248, 249, 210, 211, 207, 206, 204, 205, 161, 164/2, 164/1, 163, 137, 133 135, 134, 130 से दोकर जाती है और मालगाँव और ग्राम गाँव ग्रामों की मस्मिलत सीमा पर बिल्हु "ङ" पर मिलता है।
- का--ट रेखा, मालगाँव और आमगाँव की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ट' पर मिन्दनं। है।
- ट—ठ रेखा, बरेली और मालगाँव ग्रामों की सम्मिलित कीमा के साथ-साथ जाती है जो कीग्रला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधि-नियम, 1957 की घारा 9 (1) के अधीन का. का. 306% नारीख 19 अक्टूबर, 1981 द्वारा अधिसूचित कुसमुद्धा-11 ब्लाक की मस्मिलित कीमा भी है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।
- ठ--ब-- रेखा, प्रांग किमातपुर में प्लाट सं. 133 में से हीकर जाता है फिर मिनापुर भीर बेलटिकरा प्रायों की सम्मिलित सीमा के माथ-साथ जातो है जी कीयला ब्रास्क क्षेत्र (अर्जन और बिकास) अधिनियम, 1957 को ब्रास 9 की उनदास (1) के अ्थान का.आ. सं. 3068 तारीख 19 अक्टूबर, 1981 हारा अधिमुजित कुसमुंडा--11 ब्लाक की सम्मिलित सीमा है, और बिस्टु 'ह' पर मिलती है।

ह—क रेखा, प्लाट सं. 557, 558, 559 और प्लाट सं. 560, 571, 570 की पूर्वी सीमा के माय-नाय बेलटिकरी ग्रांम से प्लाट सं. 567 की पूर्वी सीमा के साय-नाथ जासी है और फिर प्लाट सं. 568, 532, 527, 526, 525, 524, 486, 615, 616, 631, 632, 633, 642 634, 635, 676, 406, 378, 373, 375, 356, 357, 353, 359, 360, 364, 362, 339, 324, 335 से होकर आति है और फिर दिपका ग्राम में प्लाट सं. 653, 629, 628, 627 से होकर आरम्भिक बिन्दू की पर मिलती है।

[सं. 43015/28/86—सी ए] समय मिह, अवर सिवन

New Delhi, the 11th April, 1986

S.O.1562:—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal).

No. S.O. 194(E)—dated the 16th March, 1985 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 16th March, 1985, the Central Government gave notice of its intention to acquire land and rights in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas no objection was made to the acquisition of lands and rights in the locality aforesaid;

And whereas, the Central Government after consulting the Government of Madhya Pradesh is satisfied that the land measuring 1701.363 hectares (approximately) or 4204.25 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that the lands measuring 1701.363 hectares (approximately) or 4204.25 acres (approximately) described in the said schedule are hereby acquired.

The plan No. C-1(E)/III/DR/304—1085 dated the 25th October, 1985 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur (Maharashtra).

THE SCHEDULE KUSMUNDA-III BLOCK KORBA COALFIELDS DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH)

ALL RIGHTS

Serial No.	Village				Patwari Circle Number	Khewat No.	Tahsil District	Area in hectares	Remarks
1	2			· 	3	4	5	6	7
1. Di	pka .	-			49	3	Katghora Bilaspur	7.458	Part
2. Jha	-				49	4	Katghora Bilaspur	64.372	Part
3. M a	ilgaon .				49	37	Katghora Bilaspur	157.148	Part
4. Jhi	ngatpur				49	39	Katghora Bilaspur	126.935	Part
5. Bel					49	5	Katghora Bilaspur	194.391	Part
6. Sir	ki				4 <i>€</i>	30	Katghora Bilaspur	375. 6 78	Part
7. Re	nki				55	55	Katghora Bilaspur	26. 9 71	Part
8. Sw	wabhandi				55	38	Katghora Bilaspur	164.040	Part
9. Ch	ainpur .				55	40	Katghora Bilaspur	535.526	Part
10. Ra	tij a .		r		56	61	Katghora Bilaspur	48.844	Part

Total Area :

1701.363 hectares (approximately)

Or

4204.25 acres (approximately)

Plot numbers acquired in village Dipka:

627 (Part), 628 (Part), 629 (Part), 630 (Part), 634 (Part), 635 to 638, 639 (Part), 640, 641 (Part), 642 (Part), 446 to 652 and 653 (Part).

Plot numbers acquired in village Jhabar:

39—40 (Part), 41 (Part), 42, 43, 44/1 (Part), 44/2, 44/3, 45 to 94, 95 (Part), 96 (Part), 97 (Part), 127 (Part), 129 (Part), 130 (Part), 131 to 135, 136 (Part), 137 (Part), 138 to 164, 165 (Part), 166 (Part), 167 (Part), 168 (Part), 176 (Part), 179 (Part), 180 (Part), 274 (Part), 275 (Part) and 281 (Part).

Plot numbers acquired in village Malgaon:

1 to 129, 130, (Part), 131, 132, 133 (Part), 134 (Part), 135 (Part), 137 (Part), 138 to 160, 161 (Part), 162, 163 (Part), 164/1 (Part), 164/2 (Part), 204 (Part), 205 (Part), 206 (Part), 207 (Part), 210 (Part), 211 (Part), 212 to 247, 248 (Part), 249 (Part), 250 (Part), 252 (Part), 253, 254 (Part), 256 (Part), 257 (Part), 258 (Part), 259 (Part), 266 (Part), 267 (Part), 268 to 532, 533 (Part), 534, 535, 536 (Part), 537 (Part), 538 (Part) 544 (Part), 545 (Part), 546, (Part), 547 (Part) and 558 (Part).

Plot numbers acquired in village Jhingatpur:

1 to 137, 138 (Part), 139 to 211.

Plot numbers acquired in village Beltikri:

1 to 323, 324 (Part), 325 to 334, 335 (Part), 339 (Part), 353 (Part), 356 (Part), 357 (Part), 358, 359 (Part), 360 (Part), 362 (Part), 363, 364 (Part), 365 to 372, 373 (Part), 374, 375 (Part), 378 (Part), 379 to 405, 406 (Part), 407 to 485, 486 (Part), 487 to 523, 524 (Part), 525 (Part), 526 (Part), 527 (Part), 528 to 531, 532 (Part), 533 to 559, 560 (Part), 561 to 567, 568 (Part), 570 (Part), 571 (Part), 615 (Part), 617 to 630, 631 (Part), 632 (Part), 633 (Part), 635 (Part), 642 (Part), and 676 (Part).

Plot numbers acquired in village Sirki:

67 (Part), 69, 70, 71 (Part), 73 (Part), 74 to 78, 79 (Part), 80 to 148 (149 (Part), 154 (Part), 155 (Part), 156 to 443.

Plot numbers acquired in village Renki:

1 (Part), 2/1, (Part) 5 (Part), 56 (Part), 57 (Part), 59 (Part), 60 (Part), 674 (Part), 675 (Part) and 679 (Part).

Plot numbers acquired in village Suwabhandi:

1 to 287, 288 (Part), 289 to 307, 308 (Part), 309 (Part), 311 (Part), 314 (Part), 315, 316 (Part), 317 (Part), 318 to 344, 345 (Part), 346 (Part), 348 (Part), 350 (Part), 354 (Part), 355 (Part), 356 (Part), 357 (Part), and 359 (Part).

Plot numbers acquired in village Chainpur:

1 to 12, 13 (Part), 14 to 19, 20 (Part), 21 to 962, 963 (Part), 964 to 1065.

Plot numbers acquired in village Ratija:

433 (Part), 564 (Part), 566 (Part), 567 art), 570 (Part), 582 (Part), 583 (Part), 584 to 591 592 (Part), 593 (Part), 594/1 (Part), 594/2, 611 (Part), 616/1 (Part), 616/2, 617 to 620, 621 (Part) 832 (Part) and 833 (Part).

"Boundary description:

- A-B Line starts from point 'A' and passes through village Dipka in plot numbers 627, 628, 630, 634, 639, 641, 642, then proceeds through village Jhabar in plot numbers 281, 275, 274 and meets at point 'B'.
- B_C Line passes along the common boundary of villages Jhabar and Beltikri and meets at point 'C'.

- C-D Line passes through village Jhabar in plot numbers 180, 179, 178, 176, 165, 166, 167, 168, 137, 136, 127, 130, 129, 97, 96, 95, 39-40, 41 and 44/1 and meets in the common boundary of villages Jhabar and Sirki at point 'D'.
- D—E Line passes through village Sirki in plot numbers 155, 154, 149, 73, 79, 71, 67, then proceeds through village Ratija in plot numbers 564, 566, 567, 568, 570 and meets in plot number 570 at point 'E'.
- E-F Line passes through village Ratija in plot numbers 570, 582, 583, 592, 593, 594/1 433, 611 616/1, 621, 832, 833 then proceeds through village Chainpur in plot numbers 13, 20, 963, then in plot numbers 57, 1 of village Renki and meets in plot number 1 at point 'F'.
- F-G Line passes through village Renki in plot numbers 1, 2/1, 5, 56, 59, 60, 674, 675, 679, 57, and meets in the trijunction point of villages Chainpur, Renki and Suwabhandi at point 'G'.
- G-H-I Line passes through village Suwabhandi in plot numbers 359, 357, 356, 355, 354, 345, 350, 348, 346, 317, 316, 314, 288, 311, 309, 308 then passes along the common boundary of villages Suwabhandi and Bardibazar and meets at point 'I'.
- I—J Line passes through village Malgaon in plot numbers 538, 536, 537, 544, 533, 545, 546, 547, 558, 267, 266, 259, 258, 257, 256, 254, 252, 250, 248, 249, 210, 211, 207, 206, 204, 205, 161, 164/2, 164/1, 163, 137, 133, 135, 134, 130 and meets on the common boundary of villages Malgaon and Amgaon at point 'J'.
- J.-K. Line passes along the common boundary of villages Malgaon and Amgaon and meets at point 'K'.
- K—L Line passes along the common boundary of villages Bareli and Malgaon, which is also the common boundary of Kusmunda-II Block notified under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide notification No. S.O. 3068 dated the 19th October, 1981 and meets at point 'L'.
- L-M-N Line passes through village Jhingatpur in plot number 138, then proceeds along the common boundary of villages Jhingatpur and Beltikri, which is also the common boundary of Kusmunda-II Block notified under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. No. 3068 dated 19-10-1981 and meets at point 'N'.
- N—A Line passes through village Beltikri along the eastern boundary of plot numbers 557, 558, 559 and in plot numbers 560, 571, 570, along the eastern boundary of plot number 567, then in plot numbers 568, 532, 527, 526, 525, 524, 486, 615 616, 631, 632, 633, 642, 634, 635, 676, 406, 378, 373, 375, 356, 357, 353, 359, 360, 364, 362, 339, 324, 335 and then proceeds through village Dipka in plot numbers 563, 629, 628, 627 and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/28/85—CA] SAMAY SINGH, Under Secy.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1988

का आ 1563 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यक्षः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्भाबद्ध अनुसूची में विणित भूमि में उपयोग का अधिकार अभिक करना आवश्यक है।

अतः अव पेट्रोलियम और खनिजं पाइपलाइन (भृष्टि मं उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त शिक्तयों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधिकात करने का अपना आक्षय एतव्द्वारा घोषित किया है। 24 GI/86—4

बयतों कि उक्त भूमि में हितबब्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विद्याने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, असीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फात ।

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाईन प्रोजेक्ट

			चन्	सूपी	
जिला	तहसील	परगना	ग्राम का	गटा	लिया गया रक्षा चन्य विवरण
		•	नाम		
1	2	3	4	5	6 7
इटावा	औरैय्या	औरैग्या	वसंतपुर	158	0 02
				[सं०	O-14016/79/84-जी० पी०]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1563.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Haira-Barcily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.:

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Hajira Bareilly Jugdishpur Plpe Line Project
SCHEDULE

Distt,	Pargana	Tehsil	Village		Area Acquired
1	2	3		5	<u> </u>
Etawah	Auriya	A _u riya	Basantput	158	0-02
			IN), O	14016/	79/84-GPI

का. आ. 1564. —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशप्र तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैग प्राधिकरण लि. द्वारा विधाई जानी नाहिए ।

और यह: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्रपाबद्ध अनुसूची में विणित भूमि में उपयोग का अधिकार शिंवत करना आवश्यक है।

अतः अत पेट्रोलियम और सितज पाइपलाइन (भूभि मं उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) दुवारा पदन्त शिक्तयों को प्रयोग करने हए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधिकार एनवृद्दारा घोषित किया है।

नधारों कि उक्त भिम में हितबद्ध कोई ब्यक्ति उस भिम के नीचे पाइए लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैंस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 स्. पी. को इस अभिस्चना की तारील से ११ दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेण करने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्ट्य यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

भ्रनुपूरक बाद भ्रनुसूची एख०बी०जे० गैस पाइप साइन प्रोजेक्ट

জ ন ঘৰ	सहसीस	परगना	ग्राम	गाटा सं०	श्रेह्मफल	विवरम
1	2	3	4	5	8	7
इटावा	विद्युमा	 विधुना	हरवंश-	392	001	
	•		पुर			
				[सं∘ O-1	4016/394	84-जी०पी०]

S.O. 1564,—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.I. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.:

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Trhsil	Pargana	Villege	Pict N:	Arc: in
1		3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Harbansh- pu ^r	39.	0-01
			[N > O	1.4016/3	94/84-GP]

का. जा. 1565 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रशासी हजीरा-बरेली-जगवीशपूर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय मैंस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी नाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रकोजन की लिए एसद्दुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि भे उपयोग का अधिकार शिजिश करना शावश्यक है।

अतः अव पेट्रोलियम और विनिज्ञ पाइपलाइन (श्रीक में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) दवारा पदन्त शिक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधिक करने का अपना शास्य एत्ह्व्वारा घोषित किया है।

नवर्ते कि उक्त भूमि में हि:बब्ध वर्ने व्यक्ति उस भूपि के नीचे पाइप लाइन बिळाने के लिए अक्षेप सक्षम पाधिकारी, भारतीय गीस प्राधिकरण लि., बी-58/ती, अलीगंज, लक्ष्मळ-226020 यू. पी. को इस अधिमचना की तारीक से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी स्फवाई व्यक्तिपण रूप में हो या किमी विभि व्यवसायी ती भाषांत ।

ग्रनुपूरक वाव ग्रनुसू**च**ि

एक ० की ० जै० मैस पाई प साइन प्रोजें वट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेक्षफल	विवरण
इटावा	विधुना	बिधुना	वहाबुर-	74	025	
			पुर महार			
	·	~	· r_			-A- 1

[सं॰ O-14016/399/84-जी॰ पी॰]

S.O. 1565.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B 58 B, Aliganj Lucknew-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary ase (Schodule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot	Area in
				No.	acc rs
1	3	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Biğhuna	Bahadar pur Saha		0-25

[No. O-14016/399/84-GP]

का. आ. 1566.—यहाः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी नाहिए।

अीर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में विश्वत भूमि में उपयोग का अधिकार अधिकत करना आवश्यक है।

अतः अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार विजात करने का अपना शास्य एत्द्रद्वारा घोषित किया है।

नगतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विछाने के लिए अक्षेप सक्षम ग्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इत अधिसूचना की तारीक से 21 दिन के भीतर कर सकेना।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्देश्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी स्नवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की गाफाँत ।

धनुपूरक बाद धनुसची एच०बी०जे० गैसापाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद तहसील परगना ग्राम	गाटा सं० श्रेतफल विवरण
1 2 3 4	5 6 7
इटावा विवाता विद्युता धरमगद	1180 0 07
9₹	435 0 31

सिं O-14016/1/85-जी०पी०]

S.O. 1566.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.:

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot	Areain
				No.	acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidh una	Bichuna	Dharma-	1180	0-07
			gad pur)	435	0-31

[No. O-14016/1/85-GP]

का. आ. 1567.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पंट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण कि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन की लिए एतद्दुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उण्योग का अधिकार वर्षित करना बावश्यक है।

अतः अव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भृमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अधित करने का अपना आश्रय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बसतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उसे भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछीने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, ल्खनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेंगा।

अौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिध्दिव्दतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह बाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की गार्फत ।

म्रतुपूरक वाद म्रनुसूची एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिघुना र	न खु नों	1575	0	52
				1197	0	02

[सं॰ O-14016/2/85-जी॰ पी॰]

S.O. 1567.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein. therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B. Aliganj Lucknow-226020 U.P.:

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Luckhno	1575	0-52
			-	1197	0-02

ING. O-14016/2/85-GPT

का. आ. 1568 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. दुवारा विछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णिक्ष भूमि में उपयोग का अधिकार अधिकत करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन) [अधिनियम, 1962] का 50) की भारा 3 की उपभारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधिकत करने का अपना आग्नय एतब्द्वारा घोषित किया है।

बचतों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिस्थाना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

प्रतृपुष्क बाद प्रतृपुषी एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

क्षमपद	तहसीस	परग्ना	प्राम	गाटा सं॰	क्षेत्रफल	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
इटाका	विधुना	विज्ञा .	कैयायां	1055	0	22	
	_	• -		1131	0-	02	
				1110	0	04	

 						AT -
1	2	3	4	5	6	. 7
				1159	0	02
				291	0	30
				295	0	14
				1135	0	09
				1127	0	04
				984	0	04
				164	0	05
				276	0	02

[सं O-14016/3/85-जी०पी]

S.O. 1568.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily in Jagdish-pur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 H.B.J. Pipeline Project B-58 B, Aliganj

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	
1	2	3	4	5	6	
Etawah	Bidhuna	Bidh una	Kuithawa	1055	0-22	
				1131	0-02	
				1110	0-04	
				1159	0-02	
				າ91	0-30	
				295	0-1-7	
				1135	0-09	
				1127	0-04	
				984	0~04	
				164	0-05	
				276	0-02	

. [No. O-14016/3/85-GP]

का. आ. 1569.—यतः केन्द्रीय सरकारको यह प्रतीतः होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. वृदारा विछाई जानी चाहिए ।

और यह: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनें को बिछाने के प्रयोजन को लिए एतद पाबद ध अनुसूची में बर्गित भूमि में उपयोग का अधिकार अधिक करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भिम्मि अपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962) का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदस्त शक्तियों को

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अभिजत करने का अपना आक्षय एतव्युवारा घोषित किया है।

वसर्ति कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विष्ठाने के लिए अक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंब, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सक्या ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टरः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगृत रूप से हो या किसी विधि व्यक्तायी की मार्फत ।

श्चनुपूरक बाद धनुसूची एच०बी०जे०गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं ०	क्षेत्रफल		विवरण
1	2	3	4	5	6		7
ष्टावा	विधुना	विद्युना	प्रसै नी	956	0	50	
				[सं∘ (D-14016/	7/85-	जी०पी०]

S.O. 1569.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 MJ.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case Schedule H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Parg ana	Village	Plot No.	Arca in acres
1	2	3	4	5	6
Etawh a	Bidhuna	Bidhuna	Asaincy	956	0~50
		,,	[No.	O-14016	7/85-GP]

का. आ. 1570.—यतः केन्द्रीय सरकार के यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विकाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव्दुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिस करना आवश्यक है।

अतः अव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइट (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उपथारा (1) ध्यारा प्रदस्त शिक्तयों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीट सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार किंता करने का अपना आध्य एउद्देशरा घोषित किया है।

बयती कि उनत भूमि में हितबह्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विछाने के लिए अक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-228020, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीस से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर कादित विनिध्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी स्नवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फात ।

धनुपूरक बाव धनुसूची एक व्वावजेर गैस पाइप लाईम प्रोजेस्ट

				गाटा सं०	अंत्र फल	विवरण
1 2 3		3	4	5	6	7
मदायुं वि	स ौसी	विसोली	साहनपुर	37	0- 1-05	
				128	0-1-0	

S.O. 1570.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H.B.J. Pipeline Project B-58|B, Aligan; Lucknow-226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (School ulc)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

Tahsil	Pargaoa	Village	Plot No.	Arca in acres
2	3	4	5	6
Besouli	Bo souli	Sahanpur	37 128	01-05 01-0
	2	2 3	2 3 4	2 3 4 5 Besouli Besouli Sahanpur 37

का. जा. 1871.—यतः केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीक्ष होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हुआरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपकाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवुपाबद्ध अनुसूची में बणित भूमि में उपयोग का अधिकार अधिकार करना आबश्यक है।

्रतः अब पेद्रोलियम और सनिजं पाइपलाइन (भूमि में जायोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962) का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) ब्वारा प्रदत्त क्षित्रायों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार क्षित्रा करने का अपना आक्षय एतबुब्हारा घोषित किया है।

व्यतं कि उक्त भूमि मों हितबद्ध कोई व्यक्ति उक् भूमि के नीचे पाइप लाइन बिर्छाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारो, भारतीय गैंस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंब, उक्तक-226020 खू. पी. की इस अधिसूचना की तारीक से 21 जिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिध्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी शनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फीत ।

धनुषुरक वाव धनुसूची एकश्वी०जे० गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	त ह सी ल	परगना	प्राम	गाटा सं०	बोक्रफल	जि च रण
1	2	3	4	5	6	1
बदार्यु	विसौमी	सतासी	सि रौरी	108	0-0-10	,
				114	0-18-0	
				393	0-0-10	
				394	0-0-10	

[सं॰ ओ-14016/21@85-र्जःपं०]

S.O. 1571.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Haira-Bareily to Jazdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Ges Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lncknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village		Arca is	n Remarks acres
Badaun	Besouli	Satasi	Ser	uri	108	0-0-10
					114	018-0
					393	0 - 0 - 10
					394	0-0-10
			[No.	0-1	4016/21	9/85GP-]

का आ 1572 : यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि लोकहिन में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरोली जगदीकपूर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वाग विछाई जानी चाहिए;

और यत: , प्रतीत होता है कि एोसी लाइनों के विशान के प्रयोजन के लिए एतद्वापाबव्ध अनुसूची में विणित भूमि में का अधिकार अधिक

अतः अबः पंद्रानियम और क्षिण पाइए-लाइम (भृधि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अभिकार करने का अपना आह्रय एत्इद्वारा घोषित किया है।

बंशतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्तिः उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. वी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 पू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेंगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टाः यह श्री कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी स्ववाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यक्तियों की मार्फत।

चतुप्रक बाद ब्रतुमूर्वा

एवं बी.जे. गैरा पाइप लाईन प्रोजेक्ट

			ग्राम	गाटा सं	अं त्र फल	विवरण
-	2		4	5	6	7
बदायु	विसोली	विसीली		1	2-0-0	

[मं ओ-14016/224/85-ओं पी]

S.O. 1572.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Haira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supple	ementary Case (Schiduk) H.B.J. Gas Pipe Line Project
District Tahsil	Pargana Village Plot Arcain No. acers
1 2	3 4 5 6
Badown Besauly	Besouly Khajuriya 1 2-0-0
	[No. O-14016/224/85-GP]

का. आ. 1573: च्यत; केन्द्रीय सरकार के यह प्रतीत होता है कि लोकोहत में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोल्यिम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

आर यतः, प्रतीत होता है कि एंसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भिम में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उद-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अभिनत करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बरातें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइए लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिस्चना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकीगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिध्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

ग्रन्पूरक वाद श्र**न्**सूची एच.बी.जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

खनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायुं	बिसौली	सेतासी	ग्रगेई	58	0-7-0	
				191	0-0-5	
				306	0-4-0	
				420	0-5-0	
				414	0-0-5	
				412	0- 1 - 0	
				434	0-1-10	
	다. 생활			461	0-5-0	

स अर-1401*6*/228/85**-जा पा**

S.O. 1573.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-scation (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral's Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there n

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lncknow-226020

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

Di strict	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besoaly	Satasi	Agai	58	0-7-0
				191	0-0-5
				306	0-4-0
				470	0-5-0
				414	0-0-5
				412	0-1-0
				435	0-1-10
				461	0-5-04

[No. O-14016/228/85-GP]

का. आ. 1574: -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरली-जगदीशपर तक पेट्रोल्यिम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यत:, प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में विणित उपयोग का अधिकार अर्जित करना मावश्यक है।

अतः अब पेट्रेलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन्) [अधिनियम 1962] (1982 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधित करने का अपना आश्चय एतदहारा घोषित किया है।

दशते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइय लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिध्विष्टतः यह भी कथन करेंगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तियत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

ग्रनुप्रक बाद ग्रनुसूची

एवं वी जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जन पद	 चप्रसी ल	— – परगता	——- ग्राम	गाटा सं.	
	2	3	-	5	6
बवायुं	त्रिप ौली	जि सी ली	गढ़गवि	562	1-0-0

[सं. 14016/229/85-जी. पी.]

S.O. 1574.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Barelly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No:	Areain aores
1	2	3	4	5	6_
Badaun	Bes ruly	Besouly	Gerhganak 562		1-0-0

[No. O-14016/279/85-GP]

का बा. 1575: —यस; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होता है कि लोकहिट में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरोली--जगदीशपुर तक पेट्रोल्यिम के परिकहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदु पाबश्व अनुसूची में वर्षिणत भूमि में उपयोग का अधिकार अधितत करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम् और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते छुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधिकार करने का अपना आह्मय एतदुद्वारा घोषित किया है।

बरातें कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूषि के शीच पाइए लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-

226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर मकींगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिध्दिष्टतः यह भो कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिरत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

श्रनुपूरक बाद ग्रनुमूची एच.बी.जे.गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	. गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
इदायुं बि	बिसौली	इस्ताम नगर	करनपुर	769	0-3-16
				772	0-11-10
				765	0-8-0

[सं. 0 14016/262/85-जी. पी.]

S.O. 1575.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Arcain aores
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besouly	Islam Nagar	Karanpur	769 772 765	0-3-16 0-11-10 0-8-0

का आ. 1576: — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली — जगदीक्ष पुर तक पेट्रोल्यिम के पीरवहन के लिए पाइप-लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यस: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदु पाबद्ध अनुसूची में विधास भूमि में उपयोग का अधिकार अधित करना आवश्यक है। अत: अब पेट्रेलियम और खनिज पाइण्लाइन (भूमि में उपयोग के अभिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों की प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अधिकार अधिकार करने का अपना आराय एतद्वारा घोषित किया है।

इशतें कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति उस भूमि के भीचे पाइए। लाइन बिछाने के लिए आक्षेप स्थाम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकीगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिध्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या क्षुकुनाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विभिन्न व्यवसायी की मार्फतः।

अनुपुरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहर्स(ल	—— - परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
धदा युं	बिसौली	इस्लाम नगर		67	1- 0- 0

[सं. 14016/264/85-जी. पी.]

S.O. 1576.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user thorein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd.; H B.I. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	б
Badaun	Bisouli	Islam Nagar	Dajram- pu ^r	67	1-0-0
			[No. O-14	 1016/264	/85-GPl

का. आ. 1577 : च्यत; कोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरोली—जगदीशपूर सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन भारसीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा बिलाई जानी चाहिए;

और यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के द्रयोजन के लिए एत्दु पाबद्ध अनुस्ची में विष्णत भूमि में उपयोग का अधिकार अधिजत करना आधरयक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संस्कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना शाहाय एतद्द्वारा घोषित किया है।

ब्हातें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की ठारीख से 21 दिन के भीतर कर सकीगा।

और ऐसा आक्षेप करने बाता हर ध्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तियत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फतः।

भन्पूरक बाद प्रनुसुकी

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

अनपद	नहसील	प्रगना	ग्राम	गादा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
वयामु	बिसौली	इस्लाम	मोहसन	303	0-7-15
		नगर —	पुर		

[सं. 14016/269/85-जी. पी.]

S.O. 1577.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd.; H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

'D'atriot	T thail	Pargna	Village	Plot No.	Area in acres	
_1		3	4	5	6	
Bad rin	Bosouli	Islam Nagar	M)hsan	303	0-7-15	

[No.O-14016/269/65-GP]

का. आ. 1578: —यत; केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरोली—अगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिश्रहन के लिए एाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्यारा विछाई जानी चाहिए;

और यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एसचुपाबद्ध अनुसूची में अणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक हो ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (मूमि में उपयोगं के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संस्कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आध्य एतव्ह्वारा घोषित किया है।

इशतें कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन यिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 (यू. पी.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकोगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यक्तायी की मार्फत ।

हाजिरा, बरेली, से जगवीशपुर तक पाइपलाइन प्रोजेक्ट अनुसुखी

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं ,	लिया गया रक्तबा क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
इटावा	औरैग्या	औरैय्या	सीहापुर	121	0-0-1

[सं. O 14017/337/84-जो. पी.]

S.O. 1578.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Barelly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of, user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project, B-58 B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal pdactitioner.

Hajira-Bareilly to Jagdishpur Pipeline Project SCHEDULE

District

1 Eta wa

Pargana Tahsil Village Plot Ny. Area Ny. 2 3 4 5 6 Auriya Auriya Sheehapur 121 0-0-1

[No. Q-14016/337/84-GP]

का. अप. 1579.—यतः किन्द्रीय सरकार को यह प्रतीतः होता है कि लोकहित में यह आव्हयक है कि उत्तर प्रदेश में हजीग-बरोली—जगवीशपूर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपनाइन भारतीय गैंग प्राविकरण निः. द्वारा विछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को किछ।ने का प्रयाजन के लिए एतद्पाबद्ध अन्सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अधिक करना आवश्यक हो ;

अतः अब पेट्रोलियमः और श्विनिजः पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवेशिकां कियों को प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अणिजा करने का अपना आराय एतद्वारा घोषित किया है।

हशतों कि उक्त भूमि मों हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के पाइपनाइन भारतीय गैंग प्रादिकरण ति . द्वारा विछाई भारतीय गैंग प्राधिकरण लि . बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 (यू. पी.) को इस अधिसूचना की तारीस से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर ब्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा. कि क्या वह चाहता है कि उसकी स्न्याई व्यक्तिस्त रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

श्चनुपूरक बाद श्वनुषूची एच.बी.जे. गैस गाइनसाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहमील	परगना	ग्राम	 गाटा सं.	क्षेत्रफन
1	2	3	4	5	6
हरदोई	विलग्राम	कटिया री	गोमिया सीमाला		0-1-07

_[सं. O 14016/365/85-जी. जी.]

S.G. 1579.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 (U.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplicate for Case (Se't dul)

H.B J. Gas Pipe Line Project

Distinct	Tahul	Pargana	Village	Plut N :	Arca in
1	2	3	4	5	6 7
Hardei	Bilgtam	Katiyari	G miya Sisala	399	0-1-07

[No. O-14016/365/85-GP]

का. था. 1580.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह भावस्थक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधि-करण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध श्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रधिकार भ्राजित करना भ्रावश्यक है।

भतः श्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के ग्रिकार का श्रजेंन) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिधिकार श्रिजित करने का श्रपना श्रामय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के तीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए ध्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण ति. थी-58/बी, ग्रालीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस ग्राधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भाक्षेप भरने वाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

प्रतिपुरक वाद प्रनुसुकी

जनपद	सहसील	परगना	भ्राम	गाटा सं ,	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	
ब रेली	ग्राविला	श्रीवला	गुलेली	495	0-2-0	
					16/370/85-3ft	

[सं. O-14016/370/85-जी पी]

S.O. 1580.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object

to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Ga; Pipe Line Project

Dist; ict	Tahsil	Pargana	Village		Area in acre	Romarks
1		3	4	5	6	7
Barricly	Awala	Awala	Gulely	495	0-2-0	
			[N). O-1	1016/37	0/85-GP]

का.आ. 1581 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रवेश में हजीरा बरेली-जगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप-लाइन बिछाने भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध श्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रधिकार ग्राजित करना श्रायम्थक है।

श्रतः ग्रव पेट्रोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के ग्राधिकार का धर्जन) श्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की खारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिकार धर्जित करने का अपना ग्राधिय एतबुद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उस्त भूमि में हिसबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए धाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी की इस प्रधिसुचना की तारीख से 21 दिमों के भीतर कर सकेगा।

ओर ऐसा श्राक्षेप करने नाला हर व्यक्ति विनिधिष्टतः य**ह भी कथन** करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप **से हो** या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

धनुपूरक बाद धनुसूची एच बी०जे० गैस पाइप लाइम श्रोजेक्ट

जनपद	सहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायू	वातागंज	सक्षेम-	सेरहा	312	0-6-0
		पुर	पोडला	18	1-0-0
				168	0-4-13

सिं. O-14018/372/85-की पी]

S.O. 1581.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to

the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot Nv.	Arca in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Daiaganj	Salempur	Serha-	312	0-6-0-
,			Pokhta	18	1-0-0
				168	0-4-13
			[N). O-	14016/37	2/85-GP]

का. श्रा. 1582.—यतः केन्द्रीय भरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह झावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—वरेली—जगवीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. हारा बिछाई जानी भाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाक्क अनुसूची में बॉणत भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है।

ग्रतः भ्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के इंधिकार का भ्रजन) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का भ्रिषकार भ्रजित करने का श्रपना धाशय एतब्द्वारा योष्ट्रित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबंद कोई व्यक्ति उस मूमि के नीजे पाइप लाइन बिछाने के लिए ग्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, ग्रालीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस ग्राधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

धनुपूरक बाद धनुसूची एच०बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेस्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाद्या सं.	क्षेफव ल
1	2	3	4	5	6
बदायू	बिसौ ली	विसौल <u>ी</u>	मौगका		0-2-0

[सं. O-14016/279/85-जी पी]

S.O. 1582.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary Case (Schedule) H.B.J. Gas Pipo Line Project

District	Tahail	Pirgina	Village I	olot No.	Area in acres
1		3	4	5	6
Badaun	Besouli	Besouli	Naugauwa		0-7-0
		.,	[N v. O-14	016/27	/9/85-GPJ

का. श्रा. 1588. —यतः केन्द्रीय भरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह श्रावण्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवह्न के लिए पाइपलाइन भारतीय गैन प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध धनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रधिकार श्रर्जित करना आवश्यक है।

चतः प्रव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (सूमि ने उपयोग के ग्रिधकार का ग्रर्जन) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए ∫केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का ग्रिधकार ग्रर्जिन करने का अपना ग्राणय एतद्वारा घोषिश्व किया है।

समर्ते कि उक्त भूमि में हितसदा कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए धासेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, ग्रालीगंज, लखनऊ—226020 यू.पी. को इस ध्रधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भ्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः भी यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

श्रनुपूरक बाद धनुसूची एच०बी०जे. गैस पाइप लाइन श्रोजेक्ट

 जन ्द	सतहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेफलल	
1	2	3	4	5	6	
ब दायूं	गन्नीर	ग्रमदपुर	कल्हा	749	0-2-10	
				750	0-0-5	
			ľ÷	0 .40	10/150/05-	Δ1

[म. O-14016/453/85-जी पी]

S.O. 1583.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplimentary case (Schedule)

H.BiJ. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gunnour	Asad pu r	Kalha	749 750	0-2-10
			[N : 0	-14016/4:	53/85-GP]

का. श्रा. 1584:—यतः फेल्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह श्रावप्रयक है कि उत्तर प्रदेण में हजीरा—बरेली—जगवीगपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण लि. द्वारा विखाई जाती चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध श्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रक्षिकार श्रजित करना श्रावश्यक है।

भ्रतः श्रव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का भ्रजैन) भ्रिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिधिकार भ्रिति करने का अपना आशय एसवृक्षारा चौषित किया है।

बशर्से कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, ग्रलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस ग्रधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भ्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाधी की मार्फत ।

भ्रनुपूरक बाद श्रनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेन्ट

जनपद	तहसील	परगना	प्राम	गाटा सं.	
1	2	3	4	5	6
बदायू	गुप्तीर	श्रसदपुर		595 329	0-1-0 0-0-10
ALVERT REPORT TO THE PER		TO SERVE STATE			Table A

[स. O-14016/464/85--जी पी]

S.O. 1584.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the trans-

port of Petrolcum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares it intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

	1~11,111	Palgane	AHISTE	Plot No.	Arca in cores
1	_ _	3	4	5	6
	யே- 10 <i>01</i>	Asad- pur	Jaij∉n₁ Nagar	.f 95 329	B. B. B. 0-1-0 0-0-10

[No. O-14016/464/85-GP]

कार्याः 1585:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भ्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध धनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का ध्रधिकार ध्राजित करना ध्रावस्यक है।

धनः श्रव पेट्रोलियम और खनिण पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) श्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) कः धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रधिकार श्रिजन करने का श्रपना ग्राणय एतनुद्वारा घोषित किया है।

बंगतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध फोर्ड व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन जिलाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ बी-58/बी, ग्रलीगंज, लखनऊ-226020 यू॰पी॰ को इस प्रधिभूचना की तारीख से 21 दिन के भीनर कर सकेगा।

और ऐसा ध्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टन: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

धनुपूरक बाद धनुसूची एच०की०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	सहसील	परगना	ग्राम	गाटा मं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
बदायुं	गुन्नीर	गुन्नीर	सहजना	783	0-0-5
-			महिरान	214	0-0-5
				329	0-1-10

सिं० O-14016/485/85-जीपी]

S.O. 1585.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares it intention to acquire the right ofuser therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B. Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana			Area in	Re-
			N	lo.	acres	mark
1	2	3	4	5	6	7
Bad-	Gun-	Gun-	Sah-	783	0-0-5	
aun	noor	noor	jana	214	0-0-5	
			Ahiran	329	0-1-10	

[No. O—14016/485/85—GP]

का०ग्रा० 1586.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भाषस्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-सरेली-जगदीगपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन मारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा निष्ठाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध शन्सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार धार्जित करना भाषण्यक है;

ग्रतः ग्रव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का धर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मन्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर-कार ने उस में उपयोग का मधिकार मर्जित करने का मपना माणय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बागर्ते कि उक्त भूमि में हिनवाब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए धाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण सि॰ बी-58 बी, अल गंज, लखनऊ-226020 यू०पी० की इस अधिस्थना को ताराख से 21 दिन के मीतर कर सकेता ;

और ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः सह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहना है कि उसकी सुन्याई व्यक्तिगत भप से हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

भनुपूरक वाद भनुसूची एच बी औ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटासं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
षवार्यु	गुन्नौर	२ गुन्न ोर	 सुनवर सराय	1176	1-1	6-15
			सराय	 सिं० O :)	4016/487	

S.O. 1586.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the trans port of petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Uttar Fradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Porvided the any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.; Pipeline

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary case (Schedule) H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.		Re- mark
1	2	3	4	5	6	7
Bad- aun	Gun- noor	Gun- noor	Sunver Sariy	1176	1-16-1	5

[No. O--14016/487/85-G.P.]

भा∘आ० 1587.—पतः केरद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह द्यावस्थक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगवीप्रापुर तक पेटोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन गैस भाषिरीटी आफ इंडिया लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध धनुमुक्ती में वर्णित भमि में उपयोग का श्रधिकार अजिस करना धावश्यक है;

धनः ग्रव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रश्तत मिन्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिष्ठिकार ग्रिजित करने का श्रपना श्राशय एतदुद्धारा घोषित किया है;

बगर्ले कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए ग्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी गैम ग्रायोग बढोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की भार्फत।

भनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईपलाईन बिछाने के लिये। राज्य : गुजरात जिला-पंचमहल तालका-हालोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	ग्रारे	सेग्टीयर
1	3	3	4	5
धानसर	169	0	03	0.0
	175	0	30	18
	177	0	4 2	50
	181	0	01	25

1	2	3	4	5
· . बानसर—जारी	180		18	25
-1, 1 1	183	0	16	23
	कोटर	0	16	50
	2 5/ 3/पी	0	08	50
	24	0	0.5	25
	23	0	10	73
	22/2	O	00	60
	21	0	01	10

[सं० O-14016/547/86-जीपी]

S.O. 1587.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to lagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Gas Authority of India;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Alka Puri;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE
Pipeline from Hazira—Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat	District : Panchmahal	Talu	ka:	Halol
Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen `tiare
Dhansar .	. 169	0	03	00
	175	0	30	18
	177	0	42	50
	181	0	01	25
	180	0	18	25
	183	0	16	23
	Kotar	0	16	50
	25/3/p	0	08	50
	24	0	05	25
	23	0	10	73
	22/2	0	00	60
	21	0	01	10

[No. O-14016/547/86-GP]

का०ग्रा० 1588.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह धावण्यक है कि मध्यप्रवेण राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यहः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध धनुसूची में विणित भूमि में उपयोग का शिक्तार श्रजित करना धावश्यक है; श्रतः असं पेट्रोनियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के शिक्षार का श्रजैन शिक्षिनियम , 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदश्म शिक्षिमों का प्रयोग करने हुए केस्ट्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का श्रिष्ठकार श्रजित करने का अपना श्रामय एतदश्वारा घोषित किया है:

बगार्ट्स कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ 45 मुभाषनगर सांवेर रोड, उज्जैन (म॰प्र॰) 456001 को इस भ्रधिमुचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा।

और ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाययी की मार्फन।

एच०बी०जे० गैस पाइप माइन प्रोजेक्ट

 ग्राम~मसूरिया	ताह्मील-भाबुग्रा	जिला-बायुमा	राज्य (मध्यप्रवेश)
	ग्रन्सू	पी	
प्रनु० ऋ०	थसराः	— —— ——. — नं o	उपयोग मधिकार भर्जन का क्षेत्र (क्षैक्टमें में)
1.	144		0.024
2.	151		0.004
3.	145		0.581
4.	137/	1	0.024
5.	136		0.032
6.	135		0.495
7.	146		0.008
8.	148		0.040
9.	150	11	0.024
10.	149	2	0,425
11.	149	/1	0,162
1 2.	140		0.146
1 3-	138	/ 5	0.041
14.	137	/ 2	0.057
15.	158	5	0.237
16.	138	/6	0,008
17.	139	/2	0.018
18-	139	/ 1	0.033
19.	155	/1	0.048
20.	155	i/ 2	0.041
21.	159	9/ 1	0.064
22.	159	9/2	0,121
23.	160)	0,122
_{फु} ल योग			2, 75

[स॰ O-14016/548/86-जीपी]

S.O. 1588.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H.B.J. Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Vill	age: N	/lasu	riya	Te	hsil :	Jhabua	L	Dist.: Jahbua (M.P
					SCH	EDU	E	
Sl. No.		Sur	vey N	ło.	_ —		Are red	
1.	144	<i>,</i>	,					0.024
2.	151							0.004
3.	145							0.581
4.	137/1							0.024
5.	136							0.032
6.	135							0.495
7.	146							0.008
8.	148							0.040
9.	150/1			,	Ċ			0.024
10.	149/2			,				0.425
11.	149/1							0.162
12.								0.146
13.	138/3							0.041
14.	137/2							0.057
15.	158/3							0.237
16.	138/6							0.008
17,	139/2							0.016
18.	139/1		,				,	0.033
19.	155/1							0.048
20.	155/2		,					0.041
21.	159/1		,					0.064
22. 1	159/2							0.121
23.	160				•	-	•	0.122
	Total /	Area						2.753

[No. O-14016/548/86-G.P·]

का॰ पा॰ 1589: — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हिस में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपूर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ द्वारा बिछाई जानी चाहिए:

श्रीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्गाबद धनूसूची में वर्णित भूमि में उपयोगका प्रधिकार भूजित करना धावण्यक है

भ्रतः श्रव पैट्रोलियम श्रीर खानिज पाइप लाइन (भिम में उपयोग के श्रधिकार का श्रर्जन श्रिक्षियम, 1962 (1962 का 50) की घरा उक्ती उपधारा (1) आरा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय द्विसरकार ने उसमें उपयोग का श्रिकार श्रिक्त करने का श्रपनः श्राक्षय एनद्वारा श्रीकृत किया है:

बगर्ते कि उक्त भूमि में हित्बद कोई व्यक्ति, उन्न भूमि के निषे पाइप लाइन बिछाने के लिए शाक्षेप सुक्ष्म श्रीधिकारी, भारकीय ग्रीम प्राधि-करण लि० 45 सुभाजनगर सोबीर रोड़, उज्जीन, (स० प्र०) (456001) को इस अधिसूचना की सारीख से 21 विनों के भीतर कर महेगा; भीर ऐसा अन्तिन करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सूनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एक० बी० जें० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

		प्रनूम् ची	
मन् ०	ऋ० खसरा नं०	उपयोग का क्षेत्र	स्रधिकार ध्रार (हैक्टर्स में
1	2	:	· ——
1.	34		0.24
2.	32		0.40
3.	31/1		0.20
4.	31/2		0.24
5.	39		0,289
6.	41		0.029
7.	42		0.24
8.	43		0.593
9.	4.5		0.02
10.	46		0.008
11.	133		0.33;
1 2.	132		0.016
13.	126		0.032
14.	129		0.380
15.	130/368		0.00
16.	128		0.17
17.	1 2 1/ 2मीसें		0.567
18-	121/2 मीसें		0,041
9.	114 मीसें		1,021
20.	111		0.048
21.	113		0.234
2:2-	106		0.129
23.	107/1		0.010
24.	114मीसें		0.251
25.	115		0,004
26-	108/1		0,186
27.	103		0.008
28-	104		0.631
9.	103		0,014
3 0.	102		0.056
ुल यो	ग		5.504

S.O. 1589.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Gas Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hbj Gas Pipeline Project

Village	: Ghelar Kanla	Tehsil: Jhabua Dist.: Jabua (M	[.P.)
SI. No.	Survey No.	Area to be ac red for R.O.U. Hectures	-
1,	3.1	0.242	
2.	32	0,405	
3.	314	n_ 200	
4.	31/2	0 241	
5,	. 39	0 239	
6.	41	0 025	
7.	42	0.243	
8.	43	0.591	
ŋ,	4.5	0 024	
10.	46	0.008	
11.	133	0.333	
17.	133	0.015	
13.	131	0.032	
14.	129	0.385	
15.	130/468	0.003	
15.	128	Q 170	
17.	121/2 M.	0.567	
18.	121/2 M.	0.041	
19.	114 M.	0.121	
20.	111	0.04%	
21.	£13	9,234	
22.	10.5	0.127	
23.	107/1	0.010	
24.	H‡ M.	0,251	
25.	115	0.001	
26.	107.1	0.136	
27.	14.2	0.003	
28.	104	0 631	
29.	131	0.014	
30.	102	0.056	
		Total Area 5.504	

[No. O-14016/549/86-G.P.]

काश्या • 1590 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतित होता है कि लोक हित में यह भावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली-जग-दीशारूर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राविकरण लि. हारा विछाई जानी चाहिए;

भीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव्याबद श्रनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार भजित करना भागध्यक हैं:

धतः भव, पेट्रोलियम भौर खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के भिन्नितर का शर्जन) भीधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 24 GI/86—6. सरकार में उसमें उपयोग का प्रक्षिकार प्रणित करने का अपना प्राणय एसदद्वारा घोषित किया है:

यशर्त कि उक्त भूमि में हितबढ़ क्रोई व्यक्ति, उस भूमि के मीचे वाइव वाइव किछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधि-करण ति॰, 45 त्यानतार संबिर रोड़, उज्जैन, (म॰ प्र॰ 456001) की इस अधिस्थान की तारीख से 21 दिनों के भीक्तर कर सकेगा।

प्रौर ऐसा पाओप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह बाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

धानुसूची एच, बी० वे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

प्रामः मोद	तहसील: झाब्ग्र	ा जिला: झा ब् धा राज्य	r (मध्य	प्रदेश)	
ন্ৰ্ মৃত %ৰ	ः खास्य त		 योग झो का क्षेत्र	म्रश्चिका १ (हैक्टसं	भर्जन गॅ)
_					
Ι.	76			Ĺ.	22!
2.	77			0	073
3.	H 7			0	. 12
4-	Ð 1			0	. 41
5-	92			0	. 00
6.	94/1			0	.ε4
7-	97			c	.00
8-	98			0	.02
Đ.	99			0	, 05
10.	53			0	. 01
11.	55			0	. 26
1 2.	54/.			1	, 33
1 3.	69/1			0	. 75
14.	2 4			1	. 11
15.	31			0	.03
1 6	43			0	. 36
17-	44			0	. 25
15.	45			0	. 09
19.	33			0	. 32
	-,	फुल योग		6	34
		कुल योग [सं० O-	14016	6	341

S.O. 1590.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) A.4, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H.B.J. Gas Pipeline 45 Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

		HBJ Gas Pipeline	Project
Villag	ge: Mod.	Tehsil: Juabua	Dist.: Jhabua (M.P.)
Sl. No.	Survey No.		Area to be acquired for R.O.U. in Hectares
1.	76	<u> </u>	0.225
2.	7 7		0.072
3.	87		0.128
4.	91		0.418
5.	92		0.005
6.	94/1		0.845
7.	97		0.008
8.	98		0.024
9.	99		0.056
10.	53		0.016
11.	55		0.267
12.	54/1		1.330
13.	69/1		0.756
14.	29/1		1.116
15,	31		0.037
16.	43		0.360
17.	44		0,254
18. 19.	45 38		0.096 0.328
-		Total area	6.341

[No. O-14016/550/86-G.P.]

1591:—यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भावस्थक है कि उत्तर प्रदेश में हुजीरा-बरेली-जगदीशपर '''''' तक पैटोलियम के परिवहन के लिए पाइप लोइन मारतीय गैस प्राधिमारण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए। भीर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने का प्रयोजन

के लिए एतद्पाबक पनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार ग्रजित करना ग्रावश्यक है।

मतः प्रव पेट्रोलियम भीर खनिज पाइप लाइन (भूमि में ६९थोग के भ्रधिकार का भर्जन) भिधिनियम, 1962 (1962 का 50) क़ी धारा 3 की उपन्नारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने यह उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्वारा पोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए बाक्षेप सकम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधि-करण लि॰ बी-58/बी, मलीगंज, लबनऊ- 226 020 यु॰ पी॰ की इस मिक्षिसूचना की तारीख से 21 दिन के मीत्तर कर सकेगा।

भीर ऐसा झाओप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि नया वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत धप से हो या किसी विधि अ्यवसायी की मार्फत।

मनुसूची

	Q H3F0−		·ગગવાશ ુ ર	गस पा	इप लाइन	प्राजक्ट	
<u> </u>	सहसील	परगना	प्राम	गाटा सं द्या	मजित र	ध्या	विवरण
					बी	वि	वि.
1	2	3	4	5		6	7
बर्वाम्	गुसीर	रजपुरा	क्रैल	17			2
		_		16		19	1 2

)	2	3	ন	5		6	7
				15			
				14		16	7
				13		4	9
				12		, 6	16
				11	1	10	11
				9		- 15	18
				10		-	3
				42		ŧ	1
				61	1	17	2
				71			j 4
				73		8	5
				72	1	3	13
				88	_		3
				60		-	18
				53	_	1	11
				56	•	6	10
				59		4	14
				[सं.	O-14016/	551/86 -जी	की]

S.O. 1591.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the such schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by lagal practitioner.

SCHEDULE H.B.J. Gas Plpe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B-B-B
1	2	3	4	5	6
Bad- aun	Gun- naur	Raj- pura	Kail	17	<u> </u>
				16	— 19 12
				15	— — 8
				14	— 16 7
				13	— 49
				12	— 6 16
				11	1 10 11
				9	— 15 18
				10	3
				42	- 1 1
				61	1 17 2

									
1 2 3 4 5	6	1	2	3	4	5		6	
71 73	- 14 8 5					440	0	13	10
$\frac{73}{72}$ $\frac{1}{1}$	3 13					441	0	17	15
88 —	′ 3					442	0	3	0
60 —	18					443	0	1	10
53 — 56 —	l 11 6 10					444	0	2	0
59. —	4 14					445	0	3	5
						453	1	2	0
[No. O-14016/5	551/86G.P.]					446	0	1	5
						452	0	15	5
कां भां 1502 :—यसः केन्द्रीय सरकार व	-					449	0	9	15
होता है कि श्रोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर						450	0	4	5
बरेली-जगदीशपुरतक पैट्रोलियम है लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण ति० द्वारा	•					470	0	0	15
ालए पाइपलाइन सारताय गस आवकरण तिरु द्वारा साहिए ;	विछाई जानी					475	0	3	5
चारहर,				-		473	1	3	10
और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को वि	।छाने का प्रयोजन					484	0	0	15
के लिए एतदुपाबक मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयो	ग का प्रधिकार					483	0	0	10
मजित करना मावस्थक है ;						485	2	6	0
ग्रसः ग्रव पैट्रोलियम और खनिअ पाइपलाइन (sefe ii maka					49 3	0	5	0
के प्रक्रिकार को प्रजैम) ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का						-492	0	9	15
क आक्रमार का अवग) आवागमम, 1962 (1962 का 3 की उपधारा (1) हारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग ।						489	1	18	0
सरकार में उस में उपयोग का ध्रधिकार ग्राजित करने र	•					490	0	1	5
एतदृद्वारा कोषित किया है:	જાા અત્રવા સાક્ષવ					501	0	8	15
एतवृक्षाच नामव सम्मा ह.						343	0	6	0
यंत्रर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्धा कोई व्यक्ति उ	स मुमि के नीचे					338	0	2	5
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भा						339	1	8	0
करण लि॰ बी 58/बी, मलीगंज, लखनऊ 226 020 यु						340	0	6	10
मिम्रियूचना की तारीं वा से 21 दिन के भीतर कर सके	•					341	0	2	5
और ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति वि	नेर्बिष्ताः यह भी					502	0	0	5
कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवा	•			_		344	0	4	5

[सं. O-14016/552/86-जी पी]

एम. एस. श्रीनिवासन, निवेशक (एन जी)

भनुसूची हाजिरा, मरेसी, जगबीमपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

जिला	तह सील	परगना	ग्राम	गाटा सं ख्या	1	वेजपल	
			भी	विस्ता	विस्वान्सी		
1	2	3	4	5		6	
बदौयू	गुभौर	रजपुरा	भकरौली	543	. 0	6	10
				546	0	0	1
				545	0	1	1
				544	0	2	C
				537	0	8	10
				538	0	6	o
				535	1	5	1 1
				534	0	3	10
				533	0	2	15
				532	0	0	10
				417	0	0	5
				435	0	0	1
				436	0	3	5
				520	0	1	15
				438	0	7	5
				438	0	6	15

S.O. 1592.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And, whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58-B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

5 6			SCHEDU « Pipe Ui		Т	
340 06-10						
341 0-2-5	Area in	Plot	Village	Pargana	Tahsil	District
502 0-0-5	B-B-B	No		•		
344 0-4-5	6	<u>-</u> 5	4	3	2	1
[No. O-14016/552/86-G	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4			
M. S. SRINIVASAN, Director (No	0-6-10	543	Bhak-	Raj-	Gun-	3ad-
	0-0-1	54 ō	rauli -	pura	naur	un
	0-1-1	545				
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्नालय	0-2-0	544				
•	0-8-10	537				
नर्ष दिल्ली, 3 अप्रील 1986	0-6-0	538				
,	1~5–15	535				
का. थ्रा. 1593 – यायुर्विज्ञान परिषद्य नियस 1957 के नि	0~3~10	534				
2 के अण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतड्ड	0-2-15	53 3				
, ,	0-0-10	532				
डा० वी. पी∴ चकावर्ती, रजिस्ट्रार, उड़ीसा कांऊसिल व	0-0-5	417				
मैं डिकल रजिस्ट्रेशन, भुवनेश्वर को भारतीय प्रायुविक	0-0-1	435				
The state of the s	0-3-5	436				
परिषद् श्रिधिनियम, 1956 (1956 का 102) की ध	0-1-15	520				
3 को उपधारा (1) के खण्ड य के श्रधीन भारतीय भ	0-7-5	438				
विज्ञान परिषद के एक सबस्य का उड़ीसा पाज्य में चुन	0-6-15	429 440				
	0-13-10 0-17-15	441				
कराने के लिए निर्वाचन ग्रिधिकारी के रूप में नियुवत का	0-3-0	442				
है।	0-1-10	443				
	0-2-0	414				
[सं. वीं. 11013/4/86एम. ई . (पी	0-3-5	445				
भन्द्र भान, ग्रवर सचिव	1-2-0	453				
पम्म मान, अपर सामम	0-1-5	446				
	0155	452				
	0-9-15	449				
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE	01-5	450				
(Department of Health)	0-0-15	470				
NT. TO THE ME HE AND A ME AND A	0-3-5	475				
New Delhi, the 3rd April, 1986	1-3-10	4 76				
S.O. 1593.—In pursuance of clause (d) of rule 2 of	00-15	484				
Medical Council Rules 1957, the Central Government h	0 0-10	463				
by appoints Dr. B. P. Chakravarty, Registrar, Orissa Co	2-6-0	485				
cil of Medical Registration, Bhubaneshwar, as Return	0-5-0	493				
Officer for the conduct of election of a member to	0915	492				
Medical Council of India under clause (c) of sub-sec	1-18-0	489				
(1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1	0-1-5	490				
(102 of 1956) in the State of Orissa,	0 9-15	501				
	0-6-0	343				
[No. V. 11013/4/86-ME	() - 2 - 5	338				
CHANDER BHAN, Under S	1-9-0	339				

सूचना और प्रतारण मंत्रात्रय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1986

आवेण

-मारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस. ओ 3792, दिनोब 2 दिसम्बर. में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्हारा इसके साथ गरी अनुसूची के कालम 2 में दी गई

ऋम संख्या फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	नया वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक षटनाओं की फिल्म है या धाकुमें ट्री फिल्म है।
1 2	3	4	5	6
1. अगेंस्ट दि करेंस्ट	595	फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026	, भारतसरकार	डाकुमेन्द्री फिल्म । सामान्य प्रवर्शन के लिए।
2. महिती चिल्ल संख्या 404	298.70	सूचना सहायक निवेशक (फिल्म) गुजरात सरकार 77 डा॰ ऐनीबसेंट रोड, यर्ली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक गुजरात सरकार सचिवालय, ब्लाक 7, गांधी नगर- 382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । गुज- रात सर्किट में प्रदर्शन के लिए ।
3. भहिती चित्र संख्या 405	265.70	 तदेत्र	तदैव .	 सर्देश
4. देखो समझो मानी	422.00	फिल्म प्रभाग , 24 पैंडर रोड, बम्बई-400026	भारत सरकार	डाकुमेन्द्री फिल्म।सामान्य प्रदर्शन के लिए।
5. ऋाफट् चरक्कु	437	तदैव		तद ंव
6. मंजिल हवे न दूर	349.91	सूचना सहायक, निवेशक फिस्म, गुजरात सरकार, रामनार्ड रिसर्च लेखोरेट्री लि., 77 डा० ऐनीबेसेंट, रोड़, वर्ली, बम्बई-400018	सूचना निवेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक 7, गोधी नगर-382010	डाफुमेंन्ट्री फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
7. गुई्निया वार्म	281.64	धालराम जोगले कर 7/6 शिवाजी नगर, ग्लैक्सी के सामने, वलीं, बम्बई-400018	8	आकुर्भेन्द्री फिल्म । सामान्य प्रवर्शन के लिए ।
8. वार्तासंचिका	360.00	आन्द्र प्रदेश राज्य फिल्स पिकास निगम लि., 11-5-423/1, जफरनाग सकड़ी का पुल हैदराबाद-500004		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । ऑन्ध्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।
 वार्तालरंगिनी संख्या 50 	268.00	रादेव		— - तर्वय—-
10 मां का प्यार	27.75	यूनिसेफ, रविन्त भेनसन, श्री, वच्छा रोड, बम्बई-20		त. अकुमन्द्री" फिल्म । सामान्य 18 प्रवर्गन के लिए ।
11. इ. यू. नो.	27.75	<u>त्वय</u>	—रादैव—	सर्वेष
12. गेरी	435,86	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म) गुजरात सरकार रामनार्ड रिसर्च लेवारेट्री लि., 77 डा० ऐनीर्वेसट रोड, बर्ली, धम्बई-400018	सरकार, सचिवातय, ब्लाक	डाकुभेन्द्री फिल्म । गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।

1 2	3	4	5	6
13 महाराष्ट्र न्यूज मं. 395	299,00	सूचना और जनसम्पर्क, महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, 68, तारादेव रोड़, अम्बर्ध	फिल्म केन्द्र, सम्बद्ध	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
14. पोरट्रैट आफ ए पेन्टर	576.99	देब व्रत राय 189/1, रीजेंट ग्रोष, कलकत्ता 700040	देबबत राय, प्रोडक्शन्स 189/1, रीजेंट, ग्राव, कलकत्ता-700040	"डाकुमेंन्ट्री" फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
15. इन्डियन नेबी टूडे	492.00	फिल्म प्रमाग, भारत सरकार 24 पैंडर रोड	मम्बई-40 0026	सर्वेव
16. महिती चित्र संख्या 406	289.56	सहायक निदेशक सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड, रिसर्च लेकोरेट्री लि. 77, डा० ऐनीबेसेंट रोड, वर्ली बम्बई-400018	निदेशक, सूचना गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक 7 गांधीनगर, 382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्केट में प्रदर्शन के लिए।
17. बिहार समाचार चित्र संख्या 24	265.48	एम झा, फिल्म सम्पादक बिहार सरकार सूचना और जनसम्पर्के विभाग, पटना	निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। बिहार सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
18. बिहार समाचार चित्र संख्या 25	274.02	तदेब	तदेव	—-तवैव
19. वरल हैस्य	94.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026	भारत सरकार,	"बाकुर्नेट्री" फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
20. महिती चित्र संख्या 407	288.70	सहायक निवेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनावं रिसर्च लोबोट्री लि. 77 वा ऐनीबेसेंट रोब, यली, बम्बई-400018	निदेशक, सूचना गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक-7, गोधीनगर-382010	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।
21. गायकवाड	324.00	दिलीप जगवर, एम-7/16, भानूमति, बंगुर नगर, गोरेगांव (पं०) बम्बई-400	090	क्षाकुमेंन्द्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
22. बिहार समावार चित्र संख्या 26	257.56	एम . झा फिल्म सम्पादक, सूचना और अनसम्पर्क विभाग, विद्वार सरकार, पटना	निदेशक, सूचना और जन सम्पर्कविभाग, बिहार सरकार, पटना	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । बिहार सर्कंट में प्रदर्शन के लिए ।
23. विहार समाचार चित्र संबमा	27 293.58	सर्वेथ	तदैव	तदैव
24. सेवामूर्ति रविशंकर महाराज	599.85	सूचना (फिल्म)	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, सजिवालय ब्लाक-7, गांधीनगर-382010	बाकुमेंन्ट्री फिल्म । गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।

1 2	3	4	5	6
25 पिन कोडआन थोर मेल	276.00	के. वैकुण्ठ 12-ए, विनोदबिला, बी. जी. खैर रोड, वर्ली, बम्बई-400018		बाकुमेंन्द्री फिल्म, । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
26. वार्तातरंगिनी संख्या 51	278.04	आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-4231, जफरबाग लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म । आन्द्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्गन के लिए।
27. वार्तात रंगिनी संख्या 52	277.74	तदैव		सदैव
28. सर्प	470.00	सहायक निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, रामनाडं रिसमं लेबोरेट्री लि 77, डा. ऐनी-बेसेंट रोड, वर्सी, बम्बई 400018	्गुजरात संरकार सम्बिबालय 1., ब्लाक-7,	डाकुमेंन्ट्री फिल्म । गुजरात सर्कटमें प्रदर्शन के लिए ।
29. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	472.00	फिल्म प्रमाग, भारत सरका 24, पैंडर रोड, बम्बई-400026	र	बाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
30. वार्तातरंगिनी संख्या 53	286.58	आन्द्र प्रदेश राज्य फिल्म वि 11-5-423/1, जकरकाग, हैदराबाद-500004		समाचार और सामधिक घटनाओं की फिल्म । जान्ध्र प्रवेश सर्वंट में प्रवर्शन के लिए ।
31. बिजी है ण्डस, बेटर होम्स	301.75	पुरुषोत्तम बाओकर, 12, जे० पुरजा साहित्य, सहधास, बान्त्रा (पू.) वम्बई-400051	खादी एंव ग्राम उद्योग आयो ग्रामोदय विलापार्से, वस्वर्ष-400056	ग, डाकुमेंन्द्री फिल्म सामान्य । प्रदर्शन के लिए ।
3 ∴ मिट्टी के फूल	426.72		एल. आर. गीख, 51, हैनेसरोड़, महालक्ष्मी बम्बई-400034	"डाकुमेंन्ट्रो" फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए।
33. पदकार	335.28		·	_ · · · · · ·
34. उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 113	284.38		धीरेन्द्र पांण्डे, ो न्यूजरील निर्माता, सूचना और जनसंपर्क निदेशालय, उ. प्र. सरका लखनऊ	घटनाओं की फिल्म । उत्तर प्रदेश सर्कट
35. उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 114	289.86	तदैव	 सदैव	—तदैव—

[Part II—Sec. 3(ii)]
6
डाकुमेंन्ट्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
डाकुगेन्द्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए ।
आकुर्मेन्द्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
तदैव सदैय

1	-0	ı	١
1	78	ı	J

THE	CAZETTE	OE INITAL	. ADOTT TO	1000 (CITIA ITT) A 30	1000
HE	GAZELLE	OF INDIA	: APKIL 19.	. 1986/CHAITRA 29.	TAMO

1	2	3	4	5	6
36. ¥	कान्तिगुरु दयासन्द	599.95	सहायक निवंशक, गूचना (फिल्म') गुजरात सरकार, रामनाई रिगर्च लेबोरेट्री लि० 77, का० एनीबेसेट रोड लली, धम्बई-400018	निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक-7, गांधी नगर-382010	डाकुर्मेन्द्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
3,7. জ	ीव सार्गी	88.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24 पैंडर रोड़, बम्यई-400026		डाकुगेन्द्री फिल्म । सामान्य प्रदर्शन के लिए।
. 7	ो ऐलिफेंट मोटिफ इन इन्डियन स्कल्पचर्स	458.73	टी एस नरमिहम, मैसर्स कोमल प्रोडक्शन्स, 4/54, फर्स्टमैन रोड़, टाटा-सिल्क-फार्म, बसवानागुड़ी, बंगलीर-560004		डाकुमेंन्ट्री फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
39. ₹	नैदर पपेट्री आफ कर्नाट	क 336.80	— त र्व व —		 तदेव
	दे हाथसला, एण्ड चालुकमान आर्क्टिक्चर आफ कर्नाटक	493.78	तद ैव		—–तदेव—- -—-तदेय—
	हिती चिन्न संख्या 409	268.22	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार रामनाई रिसर्च लेबोरेट्री लि., 77, डा. ऐनी- बेंसट रोड़, वर्ली, वम्बई-400018	निदेशक सूचना गुजरात सरकार सचिवालय, ब्लाक 7, गांधीनगर- 382010	समामार और कशियक घटनाओं की फिल्म (गुज- रात सर्कट में प्रदर्शन के लिए।

[फाइल सं. 315/2/86-एफ (पी)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd April, 1986

ORDER

S.O. 15)4 .- In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Scheduleannexed hereto

in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

SI. No		Length of the film in metres.	Name of the Applicant	Name of the Producer	Brief synopsis whether a scientific film or for edu- cational purpose or a film deals with news & current events or docu- mentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Against the Current	595	Films Division, Govt. of I Bombay-400 026.	ndia, 24-Peddar Road,	'Documentary' General release.
2.	Mahiti Chitra No. 404	298.70	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382010.	'News and Current Events' Release in Gujarat cir- cuit.
3.	Mahiti Chitra No. 405	265.90	do	do	do
4.	Dekho Samjho Mano	442.00	Films Division, Govt. of I Bombay-400 026.	ndia, 24-Peddar Road,	'Documentary' General release.
5.	Craft Charakku	437		do	do
6.	Manzil Have Na Dur	439.91	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Candhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
7.	Guinea Worm	291.64	Shri Bal M. Jogleker, 7/6, Glaxo, Worli, Bombay-40		'De cumentary' Gen ere release.
8.	Varta Sanchika	360.00	Andhra Pradesh State Filition Limited, 11-5-423/1, Elyderabad-500 004.		'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
9.	Varta Tarangini No. 50	268.00		do	do
10.	Maa Ka Pyar	27.45	UNICEF, Ravindra Mansion, D. Vachha Road, Bombay-400 020.	SUKRITI FILMS Kavi Arts, Worli Sea Face Bombay-400 018.	'Documentary' General release.
11.	Do You Know	27.75	— do	do	do
12.	Geri	435.86	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Bleck 7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.

1	2	3	4	5	6
	Maharashtra News No. 395	299.00	Directorate General of Inf Relations, Govt. of Mahar 68-Tardoo Road, Bombay	rashtra Film Centre,	'News and Current Events' Release in Maharashtra circuit.
	Portrait of a Painter.	576.99	Debebrata Roy 189/1, Regent Grove, Calcutta- 700040.	Debabrata Roy Productions, 189/1, Regent Grove, Calcutta-700 040.	'Documentary' General release.
	Indian Navy Today	492.00	Films Division, Govt. of In Bombay-400026.	ndia, 24-Peddar Road,	do
	Mahiti Chitra No. 406.	289.56	Asstt. Director of Information (Films), Govt of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382 010.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.
17.	Bihar Samachar Chitr No. 24	268.48	M. Jha, Film Editor, Govt. of Bihar, Informa- tion & Public Relations Department, Patna-1.	Director of Information & Public Relations Department, Govt. of Bihar, Patna.	'News and Current Events' Release in Bihar circuit.
18.	Bihar Samachar Chitra No. 25	274.02	do	do	do
19.	Rural Health	94.00	Films Division, Govt. of Bombay-400 026.	India, 24-Peddar Road,	'Documentary' General release.
20.	Mahiti Chitra No. 407.	298.70	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77- Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382 010.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.
21.	Dadasaheb Gaikwad	364.00	Shri Dilip Jamdar, M-7/1 Bangur Nagar, Goregaon		'Documentary' General release.
22	Bihar Samachar Chitra N.26	257.56	M. Jha, Film Editor, Information & Public Relations Department, Govt. of Bihar, Patna.	Director of Information & Public Relations, Govt. of Bihar, Patna.	'News and current Events' Release in Bihar circuit.
23.	Vihar Samachar Chitra No. 27	293.58	-do-	-do-	-do-
24.	Sevamurti Ravi Shankar Maharaj	599.85	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block 7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
25	. Pin Code On Your Mail	276.00	K. Vaikunth, 12A, Vinod Worli, Bombay-400018.	Villa, B.G. Kher Road,	'Documentary' General release.

1	2	3	4	5	6
26.	Varta Trangini No. 51	278.04	Andhra Pradesh State Film , Corporation Ltd., 11-5-423 Lakdi-Ka-Pool, Hyderaba	3/1, Zafarbagh,	'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
27.	Varta Tarangini No. 52	277.74	—do		-do-
28.	Sarp	470.00	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382010	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
29.	Rashtriya Natya Vidyalaya	472.00	Films Division, Govt. of I Bombay-400026.	ndia, 24-Peddar Road,	'Documentary' General Release.
30.	Varta Tarangni No. 53	286.58	Andhra Pradesh State Film Corporation Ltd. 11-5-423 Lakdi-ka-pool, Hyderabac	/1, Zafar bagh,	'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
31.	Busy Hands Better Homes	301.75	Pu!shottam Baokai, 12, Zapurza, Sahitaya Sahawas, Bandra (E) Bombay-400051.	Khadi & Village Industries Commission, Gramodya-Vile Parle, Bombay-400056.	'Documentary' General release.
32.	Mitti Ke Phool	426.72	T. Hussain 9, Chinch Pokli Road, Bandra, Bombay-400050	L.R. Shaikh 51, Haines Road, Mahalaxmi, Bombay 400034.	'Documentary' General release.
33.	. Padkar	335.28	Asst. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Labora- tory Ltd. 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
34.	Uttar Pradesh Samachar No. 113	284.38	Dhirendra Pande, C/o C/o. M/s. Bombay Film Laboratory (P) Ltd., Bombay.	Dhirendra Pande Producer Newsreel Directorate of Informa- tion & Public Relations, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.	'News and Current Events' Release in Uttar Pradesh Circuit.
35.	Uttar Pradesh Samachar No. 114	289.86	-do-	-do-	-do-
36	Krantiguru Dayanand	599.95	Asstt. Director of Information (Films) Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-38 20 10.	'Documentary' General release.

Division, Govt. of Incay-400026. Narasimhan, M/s. Ko First Main Road, Tat nanagtidi, Bangalore-	ta-Silk Farm 560004.	'Documentary' General release. 'Documentary' General release.
First Main Road, Tat nanagtidi, Bangalore-	ta-Silk Farm 560004.	release.
do-	3 _	.a.,
	-do-	-do-
-do-	-do-	-do-
. Director of mation (Films) of Gujarat, nord Research ratory Ltd., r. Annie Besant , Worli Bombay-40001	Director of Information, Govt. of Gujarat Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar.	'News and Current Events' Release in Gujarat circuit.
	mation (Films) of Gujarat, ord Research ratory Ltd., r. Annie Besant	mation (Films) Govt. of Gujarat of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, ord Research Gandhinagar. ratory Ltd.,

[File No. 315/2/86-F(P)]

आदेश

का.आ. 1595.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस.ओ. 3762, दिनांक 2 दिसम्बर, 1986 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, अम्बर्ध की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्रारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों की, उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है:—

अनुसूची

कम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लंबाई	आवेदक का नाम	निर्माता का माम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंन्द्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1. न	र्मदे योजना मतें नानी बचत	335.26	सहायक निवेशक सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामनार्ड गोध लेबोरेट्रीज, 77, डा. ऐनी बेसेंट रोड वर्ली, बम्बई-400018	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचि- वालय ब्लाक 7, गांधी नगर-382010	डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात सर्कट में प्रवर्शन के लिए
2. संव	हल्प ं	548.84	असेन्द्र कुमार, मार्फत मधुनायक, बम्बई फिल्म लेबोरेट्री, दादारा, बम्बई 400028	असेन्द्र फुमार 223, कार्लटन होटल, लखनऊ-226001	डाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए

1 2	3	4	5	6
 जागे भविष्य के अधिकारी 	380.20	श्रीनिवास जोशी, लिमाये बंगलों, 40/13, भोंडे कालोनी, इरण्वाह, पुणे-4	, ,	हाकुमेंन्द्री फिल्म सामास्य प्रदर्शन के लिए
4. मध्य प्रदेश समाचार दर्शन-48	262.12	आनन्द हतवल्ने मार्फत निदेशक सूचना और प्रचा भध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	निदेशक, र सूचना और प्रचार . मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म, मध्य प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
5. महिती चित्र संख्या 408	298.70	सहायक निदेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार रामनार्ड शो लेबोरेट्रीज लि. डा. ऐनीबेंसेट रोड़, वर्ली, बम्बई-400018	सरकार सचिवालय, ब्लाक 7	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म गुजरात सर्कट में प्रदर्शन के लिए
6. वृक्ष कल्पव्ध	300.00	निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68, तारदेव बम्बई-400034	रोड़,	डाकुर्मेंद्री फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रवर्ण न के लिए
7. बुक्सफार चिलड्रन	347.47	फिल्म प्रभाग, भारत सरक 24, पैंडर रोड, बम्बई-40		डाकुमेंट्री फिल्म सामान्य प्रवर्शन के लिए
8. सुख साधन	190.00	फिल्म प्रभाग भारत सरका 24, पैडर रोड, बम्बई-40	00026	डाकुर्मेंद्री फिल्म सामान्य प्रवर्शन के लिए
9. इट इज वेरी सिम्पल	77.00	—तथैब— ———————————————————————————————————	—त्यै व —	सथैव—
1 2	3 427.94	4 सहायक निवेशक, सूचना (फिल्म), गुजरात सरकार, रामानार्ड शो लेबोरेट्रीज लि डा. ऐनी बेंसंट रोड़, वर्सी, बम्बई-400018	ब्लाक-7,	6 डाकुमेंट्री फिल्म गुजरात प सर्कट में प्रदर्शन के लिए
11. वार्ता तरंगिनी संख्या 54	264.94	आन्त्र प्रदेश राज्य फिल्म 11-5-423/1, जफरबाग, लकड़ी का पुल हैदराबाद-500004		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म आन्द्र प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
12. वार्ता सरंगिनी संख्या-55	239.02	तथैष		तथैव
13. उत्तर प्रदेश समाचार संख्या—115	281.94	धीरेन्द्र पाण्डे, न्यूजरील फिल्म, निर्माता उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	निदेशक सूचना और जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ	समाचार और सामाकिक घटनाओं की फिल्म उक्तर प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
14. उत्तरप्रदेश समा णा र सं क् या——116	275.85	—तथैव—	तर्य ष	तथैय

1 2	3	4	5	6
15. मध्य प्रदेश समाचार दर्शन 49	255.42	एस.जी.किङ्वा ड्रकर, संयुक्त निवेशक सूचना और प्रचार मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	निदेशक, सूचना और प्रचार, मध्य प्रदेश सरकार भोपाल	समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल्म मध्य प्रदेश सर्कट में प्रदर्शन के लिए
16. कलमकारी	251.16	होमी एस सेठना, 72, अशोका एपार्टमेंन्टस, रूंगताले कार्यालय एल. जगमोहन दार बम्बई-400006		डाक्मेन्ट्री फिल्म सामान्य प्रदर्शन के लिए
17. नारद अनाव	491.34	सहायक निदेशक, सूचना गुजरात सरकार, रामनार्ड शोध लेबोरेट्रीज लि. 77, डा. ऐनी बेंसेट रोड़, व वर्ली, बम्बई-400018	गुजरात सरकार , सचिवालय,	डाकुनेन्द्री फिल्म गुजरात सर्कट में प्रवर्शन के लिए
18. आल रंग भूमि	268.40	सूचना और जनसम्पर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र स 68, तारदेव रोड़, क्षम्बई-४	रकार,	शकुनेन्द्री फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रवर्शन के लिए
16. व्हेयर इज दी हरी	80.00		फिल्म प्रभाग भारत सरव 4—टालस्टाय मार्ग, 0026 नई विल्ली	-
20. टाइम आफ हैप्पीनैस,	75.00	— तयैय —	—सर्वेव—	तथै व
21. राजा राम मोहन राय	556.00		फिल्म प्रभाग, सरकार, 24,पैडर रोड़, जम्बई-26	 तर्देय
22. दी लांग आफ ला	550.00	तयैव	तथ ैव	—तर्यंव
23. पोलीसाची दिवाली	201.00	सूचना और जनसम्पर्क महा महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेंन्टर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-400034	निदेशालय,	डाकुमेन्द्री फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए
26. सिम्बल आफ होप	301.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरका 24, पैंडर रोड, वम्बई-400026	τ	ड ाकुमेंन्ट्री फिल्म सामान्य प्रवर्शन के लिए
25. ईजी वे	86.00	फिल्म प्रभाग 24, पैंडर रोड, बम्बई-400026	फिल्म प्रभाग भारत सपका टालस्टाय मार्ग, बम्बई-400026	र, 4,सर्थव
26. कन्ट्रोलिंग ले परोसी	548.64	श्री दहियाँ भाई भक्त 1/13, गुरु नगर फोर बंगलोज वसैंवा रोड, अंधेरी (प) बम्बई-400058	गांधी मैमेरियल लेपरोसी फाउडेशन डाकखा हिन्दी नगर वर्धा, महाराष्	•
27. ऐनीटास्क, ऐनीटाइम ऐनीव्हेयर	477.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार बम्बई-400026	, 24, पैंडर रोड,	 तथैव

1	2 3	4	5	6
28. बंडर गिफ्ट	146.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार, 24, पैंडर रोड,	फिल्म प्रभाग भारत सरकार 4-टालस्टाय मार्ग,	—तथैय— समाचार और सामयिक
26 महाराष्ट्र न्यूव नं. 366	300.00	बम्बई-26 नई विल्ली सूचना और जनसम्पर्क महानिवेशालय, महाराष्ट्र, सरकार फिल्म सेंटर 68, तारदेव रोड, बम्बई-400034		घटनाओं की फिल्म महाराष्ट्र सर्कट में प्रदर्शन के लिए ।

[फाइल संख्या 315/2/86-एफ (पी)] सुकुमार मण्डल, डैस्क अधिकारी

ORDER

S.O.1595.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in the-Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

SI. No		Length of the film in metres	Name of the Applicant	Name of the Producer	Brief synops whether a scientific film or for educational purpose or a film dealing with news & current event or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Narmade Yojana Mate Nani Bachat	335.26	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories, 77-Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382 010.	Teet metrary Release in Gujarat circuit.
2.	Sankalp	548.84	Asendra Kumar, C/o Sri Madhu Naik, Bombay Film Laboratory, Dadar, Bombay-400028.	Asendra Kumar, 223, Carlton Hotel, Lucknow 226 001.	'Documentary' General releare.
3.	Jago Bhavishya Ke Adhikari	380.20	Shrinivas Joshi, Limaye Colony, Erandwanh-Pune.	Bungalow, 40/13, Bhonde -4 Colony, Pune-4	do
4.	Madhya Pradesh Samachar Darshan-48	262.12	Anand Hatvaine C/o Director Information & Publicity Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal	Govt. of Madhya Pradesl	'News & Current Events' Release in Madhya Pra- n desh circuit.
5.	Mahiti Chitra No. 408	298.70	Assit. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd. Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar.	'News and Current Events Release in Gujara* circuit.

2	3	4	5	6
Vriksha, Kalpavriksha	300.00	Directorate General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardco Road, Bombay-400 034.		'Documentary' Release in Maharashtra circuit.
Books for Children	347.47	Films Division, Govt. of India, 24-Pcddar Read, Bombay-400 026.		'Documentary' General release.
Sukh Sadhan	190.00	—do⊶		do
It is Very Simple	77.00	_do_		do
Adhar	427.94	Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Block-7, Gandhinagar-382 010.	'Documentary' Release in Gujarat circuit.
Varta Tarangini No. 54	264.94			'News and Current Events' Release in Andhra Pradesh circuit.
Varta Tarangini No. 55.	239.02	do		—do
Uttar Pradesh Samachar No. 115	281.94	Dhirendra Pande, Newsreel Film Producer, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.	The Director of Information and Puls Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.	'News and Current Events' Release in Uttar Pradesh circuit.
Uttar Pradesh Samachar No. 116	275.85	do	do	do
Madhya Pradesh Samachar Darshan-49	255.42	Shri S. G. Krishnadhar Jt. Director, Information & Publicity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.	Director of Information & Publcity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.	'News and Current Events' Release in Madhya Pradesh circuit.
Kalamkari	251.16	Homi S. Sethna, 72, Ashoka Apartments, Rungta Lane, Off. L. Jagmohandas Marg, Bombay-400006		'Documentary' General release.
Narad Anarad	491.34		Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachaivalaya, Gandhi- nagar, 382010.	'Documentary' release in Gujarat circuit.
Bal Rang Bhoomi	298.40	Directorate General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68- Tardeo Road, Bombay-400 034.		'Documentary' Release in Maharashtra circuit.
Where is the Hurry?	80.00	Films Division, Govt. of India, 24-Pedder Road, Bombay-400 026.	Films Division Govt. of India 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	'Documentary' General release.
Time of Happiness	75.00	do	do•	do
Raja Rammohan Roy.	559.00	Film Division, Govt. of In Bombay-400 026.	ndia, 24-Peddar Road,	'Documentary' General release.
	550.00	do		do
	Books for Children Sukh Sadhan It is Very Simple Adhar Varta Tarangini No. 54 Varta Tarangini No. 55. Uttar Pradesh Samachar No. 115 Uttar Pradesh Samachar No. 116 Madhya Pradesh Samachar Darshan—49 Kalamkari Narad Anarad Bal Rang Bhoomi Where is the Hurry? Time of Happiness Raja Rammohan	Ralpavriksha Books for Children 347.47 Sukh Sadhan 190.00 It is Very Simple 77.00 Adhar 427.94 Varta Tarangini No. 54 Varta Tarangini No. 55. Uttar Pradesh Samachar No. 115 Uttar Pradesh Samachar No. 116 Madhya Pradesh Samachar Darshan—49 Kalamkari 251.16 Narad Anarad 491.34 Bal Rang Bhoomi 298.40 Where is the 80.00 Raja Rammohan 559.00	Relations, Govt. of Mah 68-Tardeo Road, Bombay Books for Children 347.47 Films Division, Govt. of Bombay-400 026. Sukh Sadhan 190.00 —do— Adhar 427.94 Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay- 400 018. Varta Tarangini No. 54 Varta Tarangini No. 55. Uttar Pradesh Samachar No. 115 Uttar Pradesh Samachar No. 116 Madhya Pradesh Samachar Darshan-49 Kalamkari 251.16 Homi S. Sethna, 72, Ashol Lanc, Off. L. Jagmohanda Narad Anarad 491.34 Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratory Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018. Bal Rang Bhoomi 298.40 Films Division, Govt. of India, 24-Pedder Road, Bombay-400 026. Time of Happiness 75.00 Film Division, Govt. of India, 24-Pedder Road, Bombay-400 026. Time of Happiness Raja Rammohan 559.00 Film Division, Govt. of India, 24-Pedder Road, Bombay-400 026. Film Division, Govt. of India, 24-Pedder Road, Bombay-400 026.	Relations, Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034. Books for Children 347. 47 Films Division, Govt. of India, 24-Pcddar Read, Bombay-400 026. Sukh Sadhan 190.00 —do— Adhar 427.94 Asstt. Director of Information (Films), Govt. of Gujarat, Ramnord Research Laboratories Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018. Varta Tarangin No. 54 — Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1 Zafaragh, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500004. Varta Tarangini No. 55 — Hyderabad-500004. Varta Tarangini No. 55 — Ao— Samachar No. 115 — Arish Samachar No. 116 — Ao— Uttar Pradesh Samachar No. 116 — Ao— Samachar No. 116 — Ao— Varta Tarangini No. 55 — Ao— Samachar No. 116 — Ao— Varta Tarangini No. 55 — Ao— Varta Tarangini No. 56 — Ao— The Director of Information & Publicity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal. Apartments, Rungta Lane, Off. L. Jagmohandas Marg, Bombay-40006 Narad Anarad Anarad Apartary Ltd., 77, Dr. Anni Beseant Road, Worli, Bombay-400 18. Bal Rang Bhoomi Pilms Division, Govt. of Gujarat, Sachiavalaya, Gardhinagar, 382010. Where is the Hurry? Pilms Division, Govt. of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-400 034. Where is the Hurry? Pilms Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, New Delhi. — Ao— Pilms Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, New Delhi. — Ao—

23.	Polisanchi Diwali	201.00	Directorate General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68- Tardeo Road, Bombay-400 034.		'Documentary' Release in Maharashtra circuit.
24.	Symbol Of Hope	301.00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		'Documentary' General release.
25.	Easy Way	86.00	—do—.	Film Division Govt. of India, 4-Tolstoy Marg, New Delhi.	⊸do
26.	Controlling Leprosy	548.64	Dahyabhai Bhakta, 1/13, Guru Nagar, Four Bungalows, Versova Road, Andheri (W) Bombay-400058	Gandhi Memorial Leprosy Foundation P.O. Hindi Nagar, Wardha, Maharashtra.	do
27.	Any Task, Any Time, Any where	477.00	Films Division, Govt. of India, 24 Peddar Road, Bombay-400 026.		—do—
28.	Wonder Gift	146.00	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.	Films Division, Govt. of India, 4-Tolstoy Marg, New Delhi-110 001.	—do⊶
29.	Maharashtra News No. 396	300.00	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68- Tardeo Road, Bombay-400 034.		'News and Current Event' Release in Maharashtra circuit.'

[File No.315/2/86-F(P)]

SUKUMAR MANDAL, Desk Officer

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग) नई दिल्ली, 7 भन्नैल, 1986

का आ . 1596:—स्थायो आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंधार विभाग ने कुगालुर, ठकानई केनपालायम तथा नांवियुर टेल फोन केन्ब्रों, तमिल नाडू, में दिनांक 21-4-1986 से प्रमाणित वर प्रणालो लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-26/86-पो. एच. बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Deptt. of Telecommunications) New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1596.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Department of Telecommunications, hereby spe ifies 21-4-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kugalur, Thuckanaickenpalayam and Nambiyar Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-26/86-PHB]

नई दिल्ली, 8 श्रप्रैल, 1986

का था. 1597 :—स्थायी ब्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने ब्रजागप्पापुरम, कुरूक्ककपट्टी तथा वीरावानल्लूर टेलीफीन केन्द्रीं, निमलनाडू, 24 GI/86—8

में दिनांक 28-4-1986 में प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[सं. 5-25/86-पी. एच. बी.]

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1597.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 28-4-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Azhagappapuram, Kurukkalpatti and Veeravanallur Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-25/86-PHB]

मई विल्ली, 14 अप्रैल, 1986

का. धा. 1598: —स्यायी भादेण संख्या 627, विनोक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू फिए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 454 के खंड III के पैरा (क) के प्रनुसार महानिदेशक, दूर संचार विभाग ने गंगापुर सिटी टेलीफोन केन्द्र, राजस्थान में विनोक 25-4-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-31/86-पी एच बी.]

के पी. शर्मा, सहायक महानिवेशक (पी.एच.बी.) New Delhi, the 14th April, 1986

S.O. 1598.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules. 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 25-4-1986 as the date on which the Measured System will be introduced in Gangapur City Telephone Exchanges, Rajasthan Circle.

[No. 5-31]86-PHB]

K P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नर्धे दिल्ली, 31 मार्च, 1986

का. आ. 1599.—मेंसर्स विजयानगर स्टील निमि-टिड, रिजस्ट के आफिस शकरानासम बिलिड ग-25. एम. जी. रोड, बंगलीर (के. एन./10381) (जिसे इसमें इसके एरबात् उक्त स्थापन कहा गया हैं) ने कर्मचारी भिष्य निश्चि (और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे परचात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 17 की उपधारा 2 क) के अधीन छूट वियो जाने के लिए आवेदन किया हैं।

और कोन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक बिभादाय या प्रीमियम का संदाय किये विना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामु-हिक गीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उन एहे हैं और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हों अनुस्थ हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त कित्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अत्सूची में विनिर्दिष्ट क्षतं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्क्रीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दोती हुं।

अन्सृची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को एसी विवरणियां भेजेग और एसे जेना राजेगा क्या निरक्षिण के निए एसे स्थिपोयों प्रवास करोग जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविद्ध करें।
- 2. निरोजक, एसे निरक्षिण प्रभारों का प्रस्थंक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करोगा जो केन्द्रीय सरकार उपत अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करों।
- 3. सामृहिक भीमा स्कीम के प्रशासन मों, जिसको अन्तर्गत लेखाओं का रहा जाना, विधरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, जिरोक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हो, होने बाले सभी वार्यों का बन्न निर्दोक्षक दुनारा दिया जाएना ।
- 4. नियोजन, कोन्द्रीय सरकार युवारा अनुमादित साम्हिल बीमा स्कीम की नियमों की एक प्रति और जब कभी अनमों संबो-धन किया जाये, तब उसा संबोधन की प्रति तथा कार्यचारियों को बहुसंस्था की भाषा में उस्की म्ह्य कार्तों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई एसा कर्मणारी जो कर्मणारी भविष्य निधि का या उचत अधिनिधम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियंजित किया जाता है तो, नियंजिक सामृहिक बीमा स्कीम के स्वस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत जावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदर्श करेगा।
- 6. यदि उनस स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हो तहे, नियोजक साम्हिक बीमा स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करोगा जिससे कि कर्मचारियों

के लिए साम्हिक बीमा स्कीम के अधीर उपलब्ध फायबं उस फायदों से अधिक अनुकार हो जो उक्त स्कीम के अधीर अगुरुय हों।

- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीभ के अधीन रहिया रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेग होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, निराजक कर्मचारी के जिथिक बारिस/नामिशदौंशिती को प्रतिकार के क्षम में दोनों रक्षमों के असर के बरावर रक्षम का संदाय करिया।
- 8. सामृष्टिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भीवष्य निधि आयुवत, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मशारियों के हिन्त पर प्रतिकृत प्रभाव एक की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भिष्य निधि आयुवत अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का ग्विक्स्यूका अससर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मवारी भारतीय जीवन दीया निगम की उस साम्हिक बीमा क्कींग के. जिसे स्थापन पहले अपना चुका ही अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कारवी किसी रीति से कम हो जाते हों तो, यह रव्य की जा रक्ती है।
- 10. यवि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीव के भीतर जो भारतीय जीवन थीमा नियम नियत कार, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो, खाट रहाद की जा सकती है।
- 11. नियंजक द्वारा प्रीस्थिम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम दियाँ कितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न की गई होती को, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के क्या का उत्तर-वायिस्थ निर्णेजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कोध के अधीन वाने वाने किसी सबस्य की बत्य होने पर उसके हक बार नाम निदेशिक यों/विधिक धारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिध्यत करोगा।

[संख्या एस-35014/139/86-एस. एस.-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st March, 1986

S.O. 1599.—Whereas Messrs Vijayanagar Steel Limited Regd. Office, Shankaranarayana Building, 25, Mahatma Gandhi Road, Bangatore-I (KN/10381) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Bangalore maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses invloved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Covernment and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are cohances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grent of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case wihin one month from the receipt of the claim complete all respects.

[No. S-35014/139/86-SS-II]

का. आ. 1600.—भैंसर्स अरकोट टेक्सटााईल मिल्ज्स ति., पो.बो. नं. 1 कलाकरीची-606202 एस.ए. जिला तमिलनाड्-(टी.एन./6091) (जिसे इसमें इसके परकात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अविषय निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उकत उधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है।

और क्षेट्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समृहिक बीमा स्कीभ के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उम्म फायदों से अधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाह्म उक्त स्कीम कहा गया है) के उधीन उन्हें अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकर, उक्त अधिनियम की भारा 17 की उपभारा (2क) द्वारा प्रवत्त शिवितयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाब अनुसूची में विनिर्देष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधा के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देशी है।

अनुसूची

- उक्त स्थान के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त हिमलनाष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविध्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्थेक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर गिर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रहा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययं का वहन नियोजक द्वारा दिया प्राएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय गरकार द्वारा अनुमोदित साम्हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संबोधन किया आए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंस्था की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनु-बाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापण में नियो-जिल किया जाता है सो, नियोजंक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरना वर्ष करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।

- 6. यदि उदत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायबे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन उन्हों हैं।
- 7. संभूहिक बीगा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यिद किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधील संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोज क कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेशिक्ती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संबोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तिमगनाडू के पूर्व अनुमोदन के दिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुयोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अधरार देगा।
- 9. यदि किसी कारणविश्व स्थापन के कर्मकारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन गहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रब्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर्षा नियोजक उस नियह तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, भीभियम का संदाय करने में अस्फल रहता है और पालिसी की व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय भे किए रए किसी व्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाग निदेशितियों या विभिन्न दारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो, उक्त स्कीम के अन्दर्गत होते । दीमा फायदों के संदाय का उत्तर वायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निवेशितयों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निकास से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मृनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(140)/86-एस एस -2]

S.O. 1600.—Whereas Messrs Arcot Textile Mill Limited, Post Box No. 1, Kalla Kuridhi-606202, South Arcot, Tamil Nadu (TN/6091) (hereinatter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. The employer involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on that Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amesdmest is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund

Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to tapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(140)/86-SS JI]

का. था. 1601. पिसर्स दि मालया को. ओ. मिल्क प्रोड्यूसरज यूनियन लिमिटेड, संगहर पंजाब पां. एन. / 4635) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवच्य निधि और ग़लीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आधेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीरियम का स्वाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीन के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अन्कूल हैं जो कर्मचारी निक्षेत्र सहस्द्र बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाक्ष उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रिय हैं:

अतः कोन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2%) द्वारा इदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए जीर इससे उपावक अनुसूची में विनिर्देष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के इवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिज्य निधि आयुक्त पंताब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रहेगा तथा विरीक्षण की लिए ऐसी सविधाएं प्रवत्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उगधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 3. साम् हिक बीमा स्कीम के प्रधासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिण मों का प्रस्ता किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण अभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्षक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय गरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म- चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद स्थापन के मृचना पट्ट पर प्रविदित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मभारी जो कर्मभारी भविष्य निधि का या उन्ने अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरना दर्ज करेगा और उसकी बाहत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के जिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुबूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अमृजोय हैं।
- 7. सांकृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रक्षम से कम हो जो कर्मचारी को उस दक्षा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीण के अधीन होता तो, नियोज क कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निधेशिक्षी को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संबोधन प्रावेशिक भविष्य निर्मि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमीदन के दिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावना हो, नहीं प्रावेशिक भविष्य निष्धि आयुक्त अपना अनुमीदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युका अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवशः स्थापन के कर्मचारी भारतीन जीवन बीमा दिसम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वालं फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीहा के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में इसफल रहता है और पालिमी को व्यवसात ही जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए एए किसी व्यतिकर की दशा में उन मत स्वस्यों के नाग निदेंशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध को नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होनं पर उसके हाजचार नाम निदंशितयों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दक्षा में भाष्ट्रीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्गिरिचत करेगा।

[संख्या एस-35014(143)/86-एस . एहा . -2]

S.O. 1601.—Whereas Messrs. The Malwa Co-operative Milk Productes Union Limited, Sangtur (Purjab) (PN/4635) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the rujotity of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employeer under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount

payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the promium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of clahn complete in all respects.

[No. S-35014(143)/86-S·II]

का. ा. 1602 — भैंसर्स राजस्थान हाऊ सिंग बोर्ड, भगवार दोस रोड, जरपूर-302005 (थार. जे./1564) (जिसे इसमें इसके परचात्ं उपहा स्थापन कहा गया है) ने कर्मगारी भिषय दिश्व और प्रकीण उपवस्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उकत अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) की अधीन छुट दिए जाने के लिए आपेदन किया हैं;

और क्षेत्रीय सरकार का समाधीन हो गया है कि उक्त स्थापन को कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय था प्रीमियम का स्थाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्हिल बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं। और एक्षे कर्मचारियों के लिथे ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निथाप सहबद्ध बीमा स्कीन, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकर, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त दाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अन्सूची में विनिर्देष्ट कर्तों के अधीन रहते हुए, उका स्थापन को तीन दर्ष की अविधा के लिए उक्त स्कीन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसुची

1. उन्नेत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रदेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विषयणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा गिरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियस का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय गरकार द्वारा अनुमीवित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, सब उस संबोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्वाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उदित अधिनियम के अधीन छूट प्राणः किसी स्थापन की भित्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जिल किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरना दर्ज करेगा और उसकी बाबत आयहयक प्रीक्षियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम को अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे कहाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम की अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचिम रूप से बृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृत हैं।
- 7. सम्मूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यिष किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस दश में स्वेय होती जब वह उकत स्कीय के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेधिती को प्रतिकर के रूप में बोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संबोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोवन के दिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभव पड़ने की संभावना हो, यहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश्च स्थापन के कर्मणारी आरतीय जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना च्या है अधीन गहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रहेद की जा सफती है।
- 10. यदि किसी कारणविष नियोजक उस नियक तारीक के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत धरे, प्रीमियम का संवाय करने में इसफल रहता है और पारिसी को ध्यपमत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।

- 11. नियोजन द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वका में उन मृत सदस्यों के नाम विदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्दर्भत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक ६२ होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदे शितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक बन्ना में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास की भीतर सुनिष्ठित करेगा।

[संख्या एस-35014(125)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1602.—Whereas Messts Rajasthan Housing Board, Bhagwan Das Road, Jaipur 302005 (RJ/1564) (hercinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Secton 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submisson of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(125)/86-SS-III

का. आ. 1803. — मैंसर्स सुनील टेक्सटाइल मिल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, हमीर गढ़ रोड, पो. बाक्स नं. 27, भिल्वाड़ा (आर. जे./3550) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपम्बन्ध अधिनियम, 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दियों जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए दिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अन्कूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाम उक्त स्कीम कहा गया है) की अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकर, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रक्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्वोष्ट शतों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से शुट देती है।

अनुसूची

- 1. उस्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रदेशिक भीकष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदात करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सभय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के संड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत मेराओं का रसा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीस्थिम का संदाय, लेराओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने दाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय रारकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संघोधन किया जाए, तब उस संघोधन की प्रति तथा कर्म- चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्- वाद स्थापन के सचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मणारी जो कर्मचारी भविषय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविषय निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामहिक यीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरुत वर्ष करेगा और उस्त बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृज्जित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उने फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. से भ्रिक्ष बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यिद किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदेशिती को जितकर के रूप में दोनों रक्मों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राष्ट्रस्थान के पूर्व अनुभोदन के बिना रहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभव पड़ने की संभावना हो, तहां प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवृश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मा।रियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रदद की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवृद्ध नियोजक उस नियत तारीस के भींसर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. वियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम विदेशितियों या विश्विक यारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्वीम के अध्यक्ति होते । बीमा कायदों के संदाय का उत्तरदालित्य नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाल किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकादार नाम निदेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन वीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस:-35014(129)/88-एस. एस. -2]

S.O. 1603.—Whereas Messrs. Suncel Textile Mills (Private) Limited, Hamirgarh Road, P. B. No. 27, Bilwara-311001, (RJ|3550), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the henefits admissible under the Employees Deposit Linked Lisuance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provides such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. Shall be borne by the employer.
- 4. The employer shalf display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith, a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in 24 GI/86-9

- his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be Iess than the amount that would be payable had employee been covered under the sald Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to exclain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy 15 allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominec|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(129)|86-SS-IJ]

का. आ. 1604.—मैंसर्स कटेल फिडप्लांट. नदाशाई, भरतप्र (ए यनिट आफ राजस्थान को. ओ. डेरी फेंडरोशन लिमिटोड नजदीक गांधीनगर रोलवे स्टोशन फेंडएर आर. जे/ 2798) (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम. 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीद छाट दियों जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो सया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिवास या प्रीनिस्सम का संवास किए बिना ही. भारतीय जीवन बीमा निस्म की सामृहिक तीमा स्कीस के अभीन जीवन बीमा के रूप में फायते उठा रहे के और एसे कर्मचारियों के लिए से फायते उन फायदों से अधिक अन्-कल हों जो कर्मचारी निक्षेप सहस्वाध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गरा। है) के अधीन उन्हें अनुहोस हैं; अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त शिक्तरों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध अनुसूची में निनिर्दिष्ट शतीं के अधीर रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपहन्धों के प्रवर्तन से छाट देती है।

अनुसूचो

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भोतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त अधिनियम को धारा 17 को उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत खाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक बारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक में मा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारों, जो कर्मचारों भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उस के स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जावन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि उनन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की श्विजाने के व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकुष हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा ।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्यान, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कमचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी करणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, ब मा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाल किसी सदस्य की मृत्यु होते पर उसके हकद्वार नाम निवेशिनियों/विधिक वारिसों को बोमाकृत रक्षम का संदाय स्त्यारता से और प्रत्येक दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित् करेगा।

[संख्या एस-35014(131)/86-एस एस-2]

S.O. 1604.—Whereas Messrs, Cattle Feed Plant, Nabbal, Bharatpur (A Unit of Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited, Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur) (RJ|2798) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Com-

missioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shalf display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be fess than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Gioup Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adorted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shalf be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(131)|86-SS-II]

का. बा. 1605. —राजस्थान को-आपरोटिय डोरो फेडरोशन चिनिमटोड. नंजदीक गांधी नगर रोलवे स्टोशन, अयप्र (आर. अ./2408) (जिसे इसमें इसके परचात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आबेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्तर स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हों और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन्तर स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हों अनुजय हों ;

अतः कंन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबव्ध अन्सूची में निनिद्धिष्ट शतो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायों प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी अ्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियाजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमादित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मनारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिश्त करेगा।
- 5 यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिष्य निधि का या उक्त अधिनयम के अधीन छूट प्राप्त किसो स्थापन की भिवष्य निधि का पहाले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदें बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो तो उक्त स्कीम के अधीन अधीन अमुत्रीय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में िकसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अभीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वका भें संदेय

होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्म-चारी के विधिक वारिस/नाम निवेधिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनु-मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युवित-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो, यह रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणबा नियोजक उस नियत तारीक्ष के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रहुद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दशा में उन मृत सबस्यों के नाम निर्देशितयों या निधिक निर्देशित को जो यदि यह छुटून वी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। नीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आनं वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्निष्यत करेगा।

[संख्या एस-35014/147-86-एस. एस.-2]

S.O. 1605.—Whereas Messis Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited, Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur (RJ|2406) (hercinafter referred to as the said establishment) have applied tor exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shalf display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regionar Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not temain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(147)[86-5S-II]

का. आ. 1606: ---राजस्थान राज्य सहाकार भूमि विकास बैंक लिमिटेड, पो. बा. 55, नेहरू बाजार, उपपुर (आर. जो./931), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि-नियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उकत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छुट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम् हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो कर्मचारी निक्षंप सह बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया हैं) के अधीन उन्हों अनुक्रय हों ;

अत: कोन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिवतायों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्विष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्त्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्देष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करोगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर रिविंड करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययां का बहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुगोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविकत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निष्धि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निष्धि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरला दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को इंदल करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृत हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनक्षय हैं।

- 7. हाम्बिहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन हदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में हदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन प्राविश्वक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्म- बारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संसावना हो, वहां प्राविश्वक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युवितयुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना जुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कर हो जाते हैं तो, यह रददे की जा सकती है!
- 10. यदि किसी कारणविक नियोजक उस नियत तारीस के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यवस्त हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। धीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में दियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितयों/िदिक दारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्वीन-रिचत करेगा।

[संख्या एस-35014/143/86-एस. एस.-2]

S.O. 1606.—Whereas Messrs. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd, P. B. 55, Nehru Bazar, Jaipur, (BJ 931) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transter of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shalf display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the fanguage of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of all establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the engioyees under the said Scheme are enhances, so that the cenefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Schenge of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shalf be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomines legal

heirs of the deceased member entitled for it and in any case with one month from the receipt of claims complete in all respect,

[No. S-35014(145)|86-SS-II]

का. आ. 1607: —मेंसर्स अलवर डेरी प्लांट, (अलवर) राजस्थान को-आपरेटिव डेरी फंडरशन लि. को एक शाला गांधी नगर रोलवे स्टेशन के निकट जयपूर (आर. जं./2722), (जिसे इसमें इसके परचीन उवत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधा और प्रकीण उावन्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उपत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छट विए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मजारी किसी पृथक अधिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फाय्दा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मजारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक जनकूल हैं जो कर्मजारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया हैं) के अधीन उन्हें अनुक्रोय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसृष्टी मे दिनिद्दिष्ट शक्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्त्तन से छूट देती है।

अनुसुची

- उन्ह स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिल्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेन और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सृविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्मिद्द करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करोगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-सगय पर विधिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत हं हाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, गिरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हो, होने बाले सभी व्यया का वहान नियोजक द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें स्को-धन किया जाए, तब उस संघोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का अनुबाद स्थापन के सचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्ता अधिनिगम के अधीन कूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीगा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरना दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को स्दल करेगा ।

- 6. यदि उच्कत स्कीम के अभीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों से अधिक अनुकृत हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- 7. सामूहिके बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, पियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराइर रकम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्राविधिक अविध्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनु- के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म- चारियों के हित पर प्रिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन कर्मचारियों को अपना बृष्टिकोण स्पष्ट करने का यूक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी, कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन वीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रहद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवशः नियोजक उस नियत तारीस के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निरम नियत करे, प्रीमियम का संदान करने में अमफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकतो है।
- 11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी अ्यतिकाम की देशा में उन मूक्त सदस्यों के नाम निदेशिक्षतियों या विधिक दारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्स स्कीम के अन्तर्गत होते। पीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निदेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तन्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्नि-िज्बत करेगा।

[संस्था एस-35014/124/86-एस. एस.-2]

S.O. 1607.—Whereas Messrs. Alwar Dairy Plant Alwar (A Unit of Rai, Co-operative Dairy Federation Ltd., Near Gandhi Nagar, Railway Station, Jaipur) (RJ|2722) (hereinafter) referred to as the said establishment) have applied for exemption ender sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) 'hereafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any

Esparate contribution or payment of premium, in enjoyment

benefits under the Group Insurance Scheme of the Life
surance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than

benefits admissible under the Employees Deposit Linked
assurance Scheme, 1976 (hereinatter referred to as the said
theme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by ab-section (2A) of section 17 of the said Act and subject the conditions specified in the Schedule annexed hereto be Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said sheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall thmit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direction from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of subsection (3A) of Section 17 of the said act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. Shall be borne by the employer.
- 4. The employer shalf display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately entol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately. If the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurence Scheme, if on the death of an employee the amount rayable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal teirlnominee of the employee as compensation.
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insunce Scheme, still be made without the prior approval the Regional Provident Fund Commissioner Raiasthan d where any amendment is likely to effect adversely the Perest of the employees, the Regional Provident Fund ammissioner shall before giving his approval, give a assomable opportunity to the employees to explain their pint of view.
- 9 Where, for any reason, the employees of the said tablishment do not remain covered under the Groun Insunce Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as bready adopted by the said establishment, or the benefits to a semployees under this Scheme are reduced in any manner, be exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where for any reason, the employer fails to now the remium etc. Within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shalf be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomine legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

INo. S-35014(124) 86-SS-II]

का. बा. 1608 : मैंसर्स कैटल फीड प्लांट जांधपूर (राज-स्थान के-आपरेटिव डोरी फैंडरोबन लि. जयपूर की एक बाखा) (आर. जे./3242), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि-नियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की भारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिनाय या प्रीमियन का संदाय किए विचा ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप से फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया हैं) के अधीन उन्हों अनुकेय हों ;

अत: क्षेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भारत है। जिन्हा स्थान करते हुए, अरेर इससे उपावद्ध अन्सूची में किनिक्षिय करते हुए, अरेर इससे उपावद्ध अन्सूची में किनिक्षिय करते हैं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उनते स्कीम के सभी उपावधीं के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अन्सनी

- 1. उक्त स्थाप के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिवष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवर्णियां भेजेंगा आरे ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सृविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय गरकार, सस्य-स्मय पर निरीदेश्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का गत्येक सास की समाप्ति के 15 दिन के जीतर संदाय करेगा जो के जीय सरकार, उक्त अधिनियस की धारा 17 की उर्-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन सगय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. साम्हिक होगा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत हेशाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, विरीक्षण प्रभारों संवाय जादि भी हैं, होने वाले सभी व्यथों का बहुन नियोजक दुवारा दिया जाएगा।
- 4. वियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम्हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो-

- धन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तका कर्चारियों की बहुसंस्था की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविश्वत करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी जो कर्मवारी शिंदण निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिविष्य निधि का पहले ही सदस्त है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियोजक साम्मोइक बीमा स्कीय के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उमकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन वीया निगम को स्वक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अभीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामहिक भीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपवन्ध फायदों उन जयदों से अधिक अनुकृत हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृष है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के वराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्राविश्विक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुवोदन के विचा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म- चारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्राविश्वक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचिरियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन दीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसो को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा ग़ीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवेशितियों या विधिक वारिसों को जो यिव यह छूट न दी गई होती तो, उकत स्त्रीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायनों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीस के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निदेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनि-श्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/130/86-एस. एस.-2]

S.O. 1608.—Whereas Messrs. Cattle Feed Plant, Jodhpur (A Unit of Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., Jaipur) (RJ|3242) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees the the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available under the Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be Jess than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal bein nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regionar Provident Fund Commissioner Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
 - 24 GI/86-10

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of Iudia, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, it any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with one month from the receipt of claims complete in all respect.

[No. S-35014(130)]86-SS-III

का. आ. 1609. — मैसर्स अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ निमिटिड ''दुग्ध भवन'' नियर सरकट हाऊस. अनवर. गाजस्थान (आर. जे./2445) जिसे इसमें हमके पण्चात जनत स्थापन कहा गया है। ते कर्मचारी भिलप्य निधि और पक्षणि उपवन्ध अधिनियम. 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात जनत अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 17 की उपधारा 2 क के अभीन छट दिये जाने के लिए आबंदन किया हैं;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उत्तर स्थापन के कर्मचारी. किसी पथक अभिदाय या प्रीमि≎म का संदाय किये बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निरम की शाम-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे अधिक अन्कृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहब्रह्मध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है) के अधीन उन्हों अनुदेय हैं ;

अतः कोन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाण 17 की उपधारा-(2क) द्वारा अदत्त श्वित्तयों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपावद्ध अन्मूची में विनिद्धिष्ट अतो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अवधि को लिए उक्त स्थापत को समी

अनुस्ची

- 1. उन्त स्थापन के संबंध में नियाजिक प्राविधिक भविष्य निधि आयत्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और एमें लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए एमी मीत्रधायाँ प्रदान करेगा जो कोन्द्रीय मरकार, समय-समय पर निर्देष्ट करें।
- 2. नियोजक, एमें निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनत अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के लंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामितिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्हर्गक लेकाओं का रका जाना, विवरणियों का प्रस्तत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेकाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय

आर्थि भी है, होने वाले सभी व्ययाँ का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

- 4. नियाजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्काम के नियमों की एक प्रति और जन कभी उनमें संका-धन किया जाये, तब उस संकाधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा ।
- 5. यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनयम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता हैं तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीस के सबस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबस आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उस्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृत हो जो उक्त स्कीम के अधीन अन्क्रेस हैं ।
- 7. सामृष्टिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिदाँ शिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के बन्तर के बराबर रकम का संदाय करोग ।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपभन्धों में कोई भी संशोधन प्राविधिक भिवष्य निधि आय्क्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्राविधिक भिवष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस साम्हिक बीमा स्कीम के. जिसे स्थापन पहाले अपना चूका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियाजक उस नियस तारील के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियस करें, प्रीमियम का संदाय करने के असफल रहता है और पोलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रब्द की जा सकती हैं।
- 11. नियांजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायिस्य नियांजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके ह कदार नाम निवेधिक वारियों को बीमाकृत रकम का संबाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन शीमा

निगम से बीमाकृत रकाम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिश्चित करोगा।

[संस्था एस-35014(127)/86-एस. एस.-21

S.O. 1609.—Whereas Messers. Alwar Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Limited, Dugdh Bhawan Near circuit House Alwar-301001 Rajasthan (RJ|2445) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of inspects a charges etc. Shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan

and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(127)|86-SS-II]

का. आ. 1610 : — भीसर्स जयप्र छैरी प्लांट जयप्र ए प्रानिट आफ राजस्थान का. ओ. डेरीफ डेर शेन िलमिटिंड, नियर गांधी नगर रोल बेस्ट शेन जयप्रा (आर. जे. /2952) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 17 की उपधारा (2 क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया हैं।

और कोन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीम्यिम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुकूष हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) व्वारा प्रदस्त किसत्यों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्विष्ट क्षतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हो ।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध के नियोजक प्राविधिक भविष्य निर्मिध आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायं प्रवान कारोगा जो कोन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यंक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय कारगा जो कोन्द्रीय सरकार, उन्क्त अधिनियम की धारा-17 की उपभारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट कारे।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तूत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण. निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा ।
- 5. यदि कोई एसा कर्मबारी जो कर्मबारी भिष्य निधि का या उक्त अधिनयम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, नियाजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हों तो, नियाजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृभित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रय हों।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यवि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिष्टिंशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संज्ञोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमादन के जिना नहीं किया जाएगा और अहां किसी संज्ञोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस साम्हिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्व की जा सकरी है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारी के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने भें असफल रहता है और पोलिसी को व्ययगत हो जाने विया जाता है तो, छुट रब्द की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सवस्यों के नाम निद्निशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उन्तर स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तर- हायिस्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके ह कदार नाम निद्निंदितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से आर प्रस्के दशा में भारतीय जीवन बोमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करगा।

[संख्या एस-35014/128/85-एस. एस.-2]

S.O. 1610.—Whereas Messrs Jaipur Dairy Plant, Jaipur (A Unit of Rajasthan Co-Op. Dairy Fedn. Ltd., near Gandhi Nagar, Railway Station, Jaipur-7) (RJ-2952) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the

- amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(128)86-\$\$-11]

का. आ. 1611. — जोधपूर डोरी प्लांट (ए यूनिट आफ राजस्थान को-आपरोटिव डोरी फॉडरोशन लि., जयपुर) जोधपुर (आर. अ./2672) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिव्यत्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) की भारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

अरि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपक स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के बाद में फायब उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायबे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेत्र सहयद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुद्देय हैं;

अतः कोन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भाग 17 की उपधारा-(2क) व्वारा प्रवस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिधिकट शतों ये अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपकुन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अन्सची

 उसत स्थापन को संबंध में नियोजक प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी संविधायं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, एसं निरीक्षण प्रभारों का प्रस्क मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करणा जा केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क्र) के खंड (क्र) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसका अन्तर्गत लेकाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेकाओं का अन्तरण, निरोक्षण प्रभारों का संवाय शादि भी है, होने बाले सभी अधीं का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोविक सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संबा-धन किया जाये, तब उस संबोधन की प्रति तथा वार्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूख्य बालों का अन्यद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करोगा।
- 5. यदि कोई एसा कर्मधारी जो कर्मधारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्रान्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही स्वस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज कर्गा आर उसकी गावर आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त कर्गा।
- 6. यदि उत्तर स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोंजक सामृहिक बोमा स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बोमा स्क्रीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृत हो जो उत्तर स्क्रीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बास के हाते हुए भी यदि किसी कर्मचारी को मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामीजविधिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के सराबर रकम का संदाय करगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपवन्थों में कोई भी संसोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव एड़ के की संभादना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि जायुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्तियक्त अवसर पंगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीय के, जिसे स्थापन पहुले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदों किसी रीसिसे काम हो जाते हैं तो, यह छाट रच्च की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीए के भीपर को भारतीय जीवन बीमा नियम नियत आरी, प्रीमियम का संदाय करने में अस्फल रहता है और पोलिसी को व्ययनत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रदद की जा सकती है।

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में कियं गयं किसी व्यक्तिक म की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निद्धिशित्तयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तां, उनत स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के सदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक दस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हक दार नाम निविधितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता सं और प्रत्यक दशा में भारतीय जीवन बीसा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक सास के भीवर स्निधित करेगा।

[एस-35014/144/86-एस. एस.-2]

S.O. 1611.—Whereas Messrs. Jodhpur Dairy Plant, (A Unit of Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., Jaipur) Jodhpur (RJ[2672) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellanzous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hercinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 lof the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are

more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee]legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(144)/86-SS-II]

का. शा. 1612.— मैसर्स नवीन इन्डस्ट्रीज, 18-ए करोस चिनमाया सिम्नन अस्पताल रोड, लक्ष्मीपुरम, ऊलसूर, बंग-लौर (के. एन. /8494) (जिसे इसमें इसके परचात उक्ट स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निध्य और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिस इरामो इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया हैं) के उन्हें अनुक्तेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनस्पी

 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विषरणियां भेजेगा और ऐसे

- लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायों प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके जन्तर्गत लेखाओं का रखा माना, विदरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया पाएगा।
- 4. नियोजन, कंन्द्रीय सरकार व्वारा अनुमोदित साम्-हिक बीमा स्त्रीम के नियमों की एकप्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अनुवाद स्थापन के स्थाना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मजारी जो कर्मजारी भविष्य निधि का या जकत अधिनियम के अधीन छूट गाप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बातत आवश्यक ग्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्स करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप से वृद्धि किए ताने की व्यवस्था करेगा जिससे कि वर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्ज्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रक्षम उस रक्षम से कम हैं जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेंशिसी को प्रतिकार के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेषिक भिट्य निधि आयुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म-चारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ाने को संभावना हो, यहां प्रावेशिक भिष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना क्रुष्टिकोण स्पष्ट करने का य्कित-युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणविक स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को पापा होने वाले फायदे किसी रीति सं कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवा नियोजक उस नियस तारी के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रदद की जा सकती है।

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी य्यतिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदे पितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उकत स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकवार नाम निर्देशिक्तयों/विधिक धारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक गास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(132)/86-एस. एस. -27

S.O. 1612.—Whereas Messrs Naveen Industries, 18A Cross, Chinmaya Mission Hospital Road, Lakshmipuram, Ulsoor, Bangalore-8. (KN|8494) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance

- Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karlataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to nave the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomincellegal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(132)/86-SS-II]

का. बा. 1613.—मैसर्स जयप्र गोल्डन ट्रांसपोर्ट कॅरियर (रिजस्टड) काल्प्र कॅरिपिटा, टेलियिफिल्ज केम्प, अहमदाबाद (जि. जे./3775) (जिसे इसमो इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अविनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मकारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मकारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृल हैं जो कर्मकारी निश्चेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके प्रकात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्चेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उन्तत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त कवित्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अन्सूची में विनिदिष्ट शतो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अनुमुची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्योक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा को केन्द्रीय सरकार, उसा अधिनियम की भारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मों, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, लिरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हो, होने वाल सभी व्ययों का वहन नियोजक बुवारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार वृत्तरा अगमोदित साम्रोहक हीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उत्में संबोधन किया जाए, तब उम संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी जो भदिष्य निधि का या उकत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भदिष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उन्तत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उनलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्चित रूप ने विद्य किए जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों जो उन्न स्कीम के अधीन अनुकाय है।
- 7. गाम्हिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीप के अधीन संदेय रक्ता उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दबा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदेशियत को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपजन्भों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अन्-मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव एड़ने की संभावना हो. वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन जीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना कका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मीवारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी गीति से कम हो जाते हैं तो, यह छाट रहद की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवृद्ध नियोजक सम नियत तारी हैं के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यप्तात हो जाने दिया जाता है तो, छूट रखद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियंभ के संवाय में किए एए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक व्यक्तिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो, उन्तर संकीम के अन्दर्गत होते । बीमा फायदों के संवश्य का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निवेशितियों/विधिक दारिमों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्निविचत करेगा।

[संख्या एस-35014/142/86-एस. एस -2]

S.O. 1613.—Whereas Messrs Jaipur Golden Transport Carriers (Regd.) Kalnpur Kerlpitha, Teliya Mills Compound, Ahmedabad (GJ|3775) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Quiarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the class of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurence Scheme, including maintenance of accounts submission o, returns navment of insurence proglam transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Fmolovees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomidees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

INo. S-35014(142)/86-SS-II)

का. आ. 1614. — मैंगर्स प्रीसिणन टेलकम प्रोड कर्ले नं. वी-17, आईं.टी.आईं. एनसिलरी इंडस्ट्रीयल एस्टेट महाद्रविप्री, दंगलौर-48 (के. एन. -6369) जिसे इसमें इसके प्रधात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रधात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए बावेदम किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उत्तर स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीम्यिम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू- हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदों उठा रहें हों और एसे कर्मचारियों के लिए ये फायदों उन फायदों से अधिक अनुकर्ल हों जो कर्मचारी निकोप सह बद्ध बीमा स्कीम. 1976 (जिसे इसमें इसके परचार उक्त स्कोम कहा गया है) के अधीन उन्हों अनुष्ठ हैं ;

अतः कोन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त अक्तियाँ का प्रयोग कर हो हुए और इससे उपावद्भ अनुसूची में विनिर्विष्ट शहां के अधीन रहते हुए, उक्स स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से खूट देती हैं।

अन्संभी

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविधिक स्थापन के एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के सिए एसी सुविधाया प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविधाय करें।
- 2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्थंक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के संड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृता किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, नेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय अपेद भी है, होर वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमंदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोध्या धन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की यहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदेशित करेगा ।
- 5. यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भेविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य हैं, उसके स्थापन में नियंजित किया जाता है तो, नियंजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाल करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों कः उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक नीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक नीमां स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अन्कृत हो जो उक्त स्कीम के अधीन अन्कृथ हों।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी यदि किसी कर्मधारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संबंध रकम उस रकम से कम है जो कर्मधारी को उस बशा में संबंध होती जब बहु उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिदाँशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बरावर रकम का सद्ध करगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपनन्थों से कोई भी संशोधन प्राविशिक्ष भिविष्य निधि आयुक्त, बंगलीर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो. वहां प्राविशिक भिविष्य निधि आयुक्त अपना जन्मोतन दोने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

1 14 --- 11

- 9, यदि किसी कारणवध्य स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चूका है अधीन नहीं रह जात है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायवे किसी राति से कम हो जाते हैं तो, यह रख द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियस सामेक के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियस करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहिसा है और पालिसी को व्यपनत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रद्व की जा सकती है।
- 11. नियाजिक द्वारा प्रीमियम के संदाय में कियं गये किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वोधितियों या विधिक वारिसों को जो शदि यह छूट न दी गई होती तो, उचत स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उच्चर-दायित्व नियाजिक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हक जार नाम निद्विधितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रक्तम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवज बीका निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्निचिवत करोगा।

[संख्या एस-35014(136)/86-एस. एस.-2]

S.O. 1614.—Whereas Messrs Precision Telecom Products, No. B-17, ITI Ancillary Industrial Estate, Mahadevapura, Bangalore-18 (KN 6369) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government

- and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to nave the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellogal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(136)/86-SS-II]

का. आ. 1615. — मैसर्स मैटल स्क्रीप ट्रंड कार पोर्श्यात लि., 225 एफ, ए.जी.सी. बोस रोड, काकता-700020 (इडल्यू. बी./12726) 'जिसे इसमें इसके परचान उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी स्विच्य निष्ठि और प्रकीर्ण उपहरण अधिनिध्य, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पञ्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अखेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या जीपियम का स्वाय किए दिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिन अन्कुल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परकात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्स्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ. 330 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उन्बद्ध अनुसूची में विनिधिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थाणा को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रविशिक विषय निधि आयुक्त, परिचम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निकित करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति को 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रला जाना, विवरणियों का प्रस्तूत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक दुवारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, कोन्द्रीय सरकार वृथारा यथा अनुमंदित साम्-भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अन्याय स्थाएन के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजिल किया जाता है तो, नियोजिक साम्हिक बीमा स्कीम के स्वस्य के रूप में उसका नाम तुरक्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आव्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायदी बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उसते स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फ यदों से अधिक अनुकृत हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञीय हैं।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो निवच्य निधि का या उकत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकत उग रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निव^कितती को प्रतिकार को रूप में बोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- सामृहिक बीमा स्कीम के उपनन्धों में कोई भी संबोधन प्रादिशिक भविष्य निधि आयुक्त, परिचम बंगाल के पूर्व अनु-

- मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमदन दोने से कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर वेगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम क अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रदद की जा सकती है।
- 10.यिव किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीक के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यप्यत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सवस्यों के नाम निद्धांशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों क संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्क्रीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निवाधिक विधिक वारिसों को उस राशि का स्प्याय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिध्चत करेगा।

[संख्या एस-35014/396/82-पी . एफ . -2/एस: . एस . -2]

S.O. 1615.—Whereas Messrs Metal Scrap Trade Corporation Limited, 225-F, AIC, Bose Road, Calcutta-700020 (WB/12526) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 330 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of 7-1-1989.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Art within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thedeof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/396/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1616 - मैंसर्स टैक्लेमिट इन्डिया लिमिटिड, गोपालपूर, बूज रोड, पो.आ. सरकारपूल जिला 24 परगना (वृस्ट बंगाल/1787) (जिसे इसमें इसके परचात उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके परचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के क्यीन छूट दिए जाने के लिए आबसेस किया है।

अप्रैर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृष्टिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके परशात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त कांबितयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ 608 तारीख 11-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबक्ष अनुस्पी मे विनिर्दिष्ट क्षतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्काम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देवी है।

अन्स ची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिष्ठण निधि आयुक्त, पिश्वम अंगाल को ऐसी विवरणियां भजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विकेट करें।
- 2. नियोजक, 'ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की ममारित के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड़ (क) के अधीन समय-समय पर निर्धिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तूत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, हाने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंस्था की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अन्याद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रवर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भिवन्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवन्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्ज करेगा और उसकी दावत आदश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6 यिश्व सामृहिक बीमा स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायब बढ़ाए जाते हैं, तो नियाजक स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि किए जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्क्रीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकर्त हों जो उस्त स्क्रीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्षम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोज क कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदंकिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संघोधन प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त, परिचम बंगाल के पूर्व अनुभोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संघोधन सं कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यहां प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन वेने सं पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवहा स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन वीक्षा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मीचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रह्द की जा सकर्सा है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा जिनम द्वारा नियस तारीख के भीतर प्रीक्षियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यथमत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रहद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दका में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों का विधिक कारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त संक्षीम के अन्दर्गत होते । बीमा फायदों के संचाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी स्टब्स की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हुक दार नाम निवेशिकी/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हुर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/397/82-पी. एफ. -2/एस. एस. -2]

S.O. 1616.—Whereas Messrs Tecalemit India Limited, Gopalpur, Budge Road, P.O. Sarkarpool. District 24 Parganas (WB/7767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 608 dated the 11-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insulance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insutance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured so the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/397/82-PF-JJ(SS II)]

का. आ. 1617. — मैसर्स नेम्को होड्रॉलिक्स लि., उद्यामकार कनप्र रोड, बैलगांब-59008 (के. एन./168) (जिसे इसके इसके पक्कार उक्त स्थापम कहा गया है) के कर्मकारी भविषय निध्य और प्रकीर्ण उपबंध अधिनयम,

1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अभिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अभीन छूट दिए जाने के लिए ाखेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधन हो गया है कि उवत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सदाय किए दिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायबा उठा रहे हैं वे ए'से कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूज हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त आधिनियम की वारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त कवित्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमूचना संख्या का आ . 607 तारीख 11-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्विष्ट कतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को , 22-1-1986 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 21-1-1989 भी समिलिक है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अन्सुची

- 1 जनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविधट करें।
- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति को 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3 क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मों, जिसके अंतर्गत से साओं का रक्षा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीसियम का संवाय, से साओं का अन्तरण, निरोक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक हारा विया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमादित सामूहिक शीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उर्वा संशोधन किया पाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थाएन के सचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यति कोई ऐसा कर्मचारी जो भविषय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक जीया स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्ष वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उप-लब्ध फायते बकाए जाते हैं, तो नियाजिक स्कीम के कर्मचारियों को उपसम्ध फायदों में समृष्यित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करना जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से बिधक अनुकल् हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकाय हैं

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते दुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रखान उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उदस स्कीम के अधीन होता सो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निद्येषिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अनार के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के उपकन्थों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य दिश्वि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव प्रकृते की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन बेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर बेगा।
- 9. यदि किसी कारणवह स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीया निगम की उस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति के कम हो जाते हों तो, यह छूट रद्य की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालियी को व्ययसत हो जाने विया जाता है तो, छूट रहद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सर्वस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यवि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू पर भारतीय जीवन नीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकादार नाम निवेधिकती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर स्निष्टित करेगा।

[संख्या एस-35014/398/82-पी. एफ. -2/एस. एस. -2]

S.O. 1617.—Whereas Messrs Bennco Hydraulics Limited, Udyambag Khanepur Road, Belgaum-590008 (KN/168) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 607 dated the 11-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed bereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

- I. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 1. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirlnominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where, any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grent of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/398/82-PT-II (\$S-II)]

का. का. 1618: — मेसर्स, एस. एण्ड एच. नियर्स ध्यह्नेट लिन्दिटेड, स्टेशन रोड, दिवास, मध्य प्रदेश (एस. पी./2766) (जिसे इसमें इसके प्रधात् उन्हां स्थापन कहा गया है) ने कर्म- नारी भिष्ण निधि भौर प्रकीण उपबन्ध अभिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परकार उदत अविनियम कहा गया है) की भारा 17 की उपभारा (2क) के अभीत छूट दिए जाने के लिए आयेदन किया है;

जौर केंद्रीय सरकार का समाधान हो रथा है कि उक्स स्थापन के कर्मदारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीसियम का संदाय किये दिना ही, भारतीय जीवन योदा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन दीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इस्के परचात् उक्त स्कीम कहा गया हैं) के अधीन अनु-जय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, जक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2क) दूबर, प्रदत्त किनायों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की अधिक्ष बना मंद्रात का आ। 397 तारीख 9-12-1982 के अनुसरण में और इससे उधाव द प्रमुखी में विनिर्वित्व कार्ती के अधीन रहते हुए, जक्त स्थापन को, 15-1-1986 में तीन वर्ष की अधीन रहते हुए, जक्त स्थापन को, 15-1-1986 में तीन वर्ष की अधीन सहते हुए, उक्त स्थापन को सिम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुस्ची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भीवष्य निधि आयुक्त, गुजरात का एंसी विवरणया भेजगा और एंस लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करगा जा कंकीय सरकार, समय-समय पर जिविष्ट कर ।
- 2. नियोजक, ऐसं निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उबत अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मी, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा माना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरोक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुभोदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और एक दानी उनमें संशोधन किया आयं, तद उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाब स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त आधीनयम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियो- जित किया जाता है तो, कियोगक सामृद्धिक जीना स्काम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा और उसकी वावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायबे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उकत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायबों मां समूचित रूप से वृद्धि की वाने की ध्वस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उन्तव्य फायबें का पायबों से अधिक अगुकूव हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अगुक्त हों।

- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी जात के होते हुए भी, यि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कन है जो कर्मचारी की उस दहा में सदेय होती जन वह उका स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेधिती को अधिकर के सन्दर्भ में दोनों रकमों के बराबर रकम का सन्दान करेगा।
- 8. एममूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संघोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मन्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया लाएगा और जहां किसी संघोधन से कर्म एएपियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पद्धने की संभावना हो, यहां प्रादेशिक भविष्य गिधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कमें सारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गृक्ति- यक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवहां स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीति बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमें स्थापन पहुले अपना चका है अधीन नहीं रह पाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रहद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवज्ञ, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निय्यत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रब्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्यारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यक्तिकम की दक्षा में उन मृत सदस्यों के ताम निवेधिकित्यों या विधिक वारिमों को जो यदि यह, छूट न वो गई होती तो उक्त स्क्रीम के अन्तर्गम होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-वारित्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राधि के हं कवार नाम निवे धिति/विधिक गारिसों को उस राधि का संवाय तत्य-रहा से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिधिचत करेगा।

[संख्या एस:-35014/377/86-पी. एक . -2/एस . एस . -2]

S.O. 1618.—Whereas Messrs S. and H. Private Limited, Station Road, Dewas, MP (MP/2766) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 397 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of 14-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts

- and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for crant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt rayment of the sum assured to the agminee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/377/82-PF-H (SS-H)]

का. था. 1619: —मैंसर्स इण्डिया पैकेंजिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 24895 मील, बेलरी रोड डगसीर 24 (के. एन. /3657) जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है (ने कमंचारी भीवष्य निश्चि और प्रकीण उ। बन्ध अधि-नियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम, कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जान के लिए आवंदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीस्थिम का संदाय किए जिसा ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा क्लिंग की माम्हिक बीमा स्कीम के अवीग जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिस अन्कूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षण सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परचाद्द् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभय हैं;

उदाः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, जौर भारत सरकार के श्रम मंत्राचय की अधिसूचना संख्या का. उन. 37 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में जौर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विकित्विष्ट क्षतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से ती। दर्ग की अविधि के रिए जिसमें 31-12-1988 भी सिम्मिनित है, उन्हें स्थीम के सभी उपयन्भों के प्रपर्वन से छाट देती है।

अनुसुची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में तियोजक प्रादेशिक भाँविष्क निवि आगृहः, कर्याटक को ऐसी विष्रियां भेजेगा और ऐसे लेका रखेगा पथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायों प्रवान करेगी जो कीन्द्रीय सरकार, समाप पर निविध्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे गिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीगर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिक्षियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड . (क) के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. तामृहिक वीमा स्कीम के प्रचारन में, जिसके अन्दर्गत के लाओं का रखा जाना, विवरिष्यों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियाम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, जिरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन वियोजक क्षारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एकप्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, वब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मभारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्रवारी जो कर्मचारी शिवच्य निधि का या उक्त किधिनयम की अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भिवच्य विधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में वियो-वित किया जाता है तो, नियोगक सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य को रूप में उसका नाम सूरल वर्ज करेगा और उसकी मानत वाद्यक्त ग़ीरियम भारतीय जीवन बीमा निधम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि साम्हिक बीमा स्कीम के अधीत कर्मचारियों को उपलब्ध फानदे बढ़ाए जाते हैं सो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से विवृध की जाने की वावस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को निया सामित क्या करेगा जिससे कि कर्मचारियों को निया सामित वीमा स्कीम के क्यीन उपसब्ध फायदे उन फायदों से अधिक बब्कूत हों, जो उक्त स्कीम के बधीन अनुक्रेय है।

24 GI/86---12

- 7. सामृोंहक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर चारी की उस दक्षा में संदेय होती जब यह उनत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विशिषक वारिस/नाम निवेधिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन पादित्य भविष्य निधि आगृक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया गएना और वहां किसी संशोधन ते कर्म-चारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभान पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मणियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-यदन अवसर देगा।
- 9. यदि किमी कारणाज्ञ स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन दीमा जिल्हा की उस साम्हिक बीमा स्कीम के, जिसे, स्थापन पहले अपना नका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के कथीन कर्मचारियों को प्राप्त होने थाले फन्यदे किसी रीति से कर्म हो जाते हैं तो, यह छूट रदब की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा निय्त तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यगगण हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक इवारा प्रीमियम के संदाय में फिये गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवेकितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो, उक्ते स्क्रीम के अन्तर्गत होती। बीमा फायवों के संदाय का उत्तर-दायित नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी स्वस्थ की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा दिगम, दीमाकृत राशि के हक-दार नाम निदेगिती-धिधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दक्षा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीवर मृनिश्चित करेगा।

[इंस्था एस-35014/379/82-पी.एफ.-2/एस.एस: -2]

S.O. 1619.—Whereas Messrs India Packaging Products Private Limited, P.B. No. 2480, 5th Mile, Bellary Road. Bangalore-24 (KN/3657) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 37 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Confessioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- ... The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under characters (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount navable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where, any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any teason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the rolley is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employee in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal hairs of the deceased member entitled for it and in an case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/379/82-PT-II (SS-II)]

का. आ. 1620: --गैंगर्स गौस्ट कीन विविध्सम विमिटेड. स्कीय एण्ड फास्टर्स डियिजन, लोन यहादुर शस्त्री मार्ग. भरा-इए, बस्बई-400028 (एम एच./9074) (जिसे इसमें डसके पश्चात् उक्त रथापन अहा गया है) ने कर्मवारी अविषय निर्धि और प्रकीण उपदन्ध अधिनयम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमे इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अवेदर किया है:

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उदा स्थापन के कर्मचारी किसी पृथका अभिवास या शीमियद का मदाप किए दिया ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीय की सामुहिक धीमा स्कीम के अबीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे दहमें इसके एक्जान् उपन स्कीम कहा गा। हों) के अपीय अनुक्रीय हैं;

ात: केन्द्रीय मरकार, उनत अधित्यम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के अम मंत्रावय की अधिस्प्चा में. का अग. 732 शारीख 17-12-1982 के अनुमरण में और इमने उपावह अनुम्बी में निर्दिष्ट सती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 29-1-1986 से तीन वर्ष की अधीन के जिए जिसमें 28-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपस्थान के प्रवर्तन से कृट देती है।

अनसूची ै

- उक्कर स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भीविष्य रिधि आरक्त, महाराष्ट्र को ऐसी दिवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सरिधाएं प्रदार करेता जो केन्द्रीय गरकार, समय-समय पर निर्विद्द करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की गमान्ति के 25 दिन के भीतर गंदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उवत अधिनियम की धारा 17 की उर-धारा (3-क) के रूण्ड (क) के रूधीन सगरा-सगर पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृहिक दीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रहा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, वीमा ग्रीसियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बीसा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें स्वो-धन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी मुख्य कातों का अनवाद स्थापन के सचना पटट पर प्रदिश्वित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी जो कर्मचारी अविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीत छट प्राप्त किसी स्थापन की अबिष्य निष्य किसी स्थापन की अबिष्य निष्य का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो- जिल किया जाता है तो, नियोजक सामितिक बीया स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरल वर्ष करेगा और उसकी बाबत अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निराम को संदर्भ करेगा।
- 6. यदि मामहिक दीमा स्कीम के अधीर कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे दढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के

किए जाने की व्यवस्था करेगा जिनसे कि कर्मचारियों के जिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों जो उबस स्कीम के अबीन कर्जांग हैं।

- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रफम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में सदेय होती जब वह उबत स्कीम के अधीन होता तो, ियोजक कर्मचारी के विश्वक व्यक्तिस्त्रीमः निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों है अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।
- 8. साम्हिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन, प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन के विमा नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन में कर्म-बारियों के हिरा पर प्रीतकत प्रभाव पड़ने की स्थानना हो, बहा
- ाप्त भविषय निर्णि आयुक्त अपना अन्मोदन देने से पूर कर्म आरियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का याविसयुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मश्राणे मारणीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस महीम के अधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने ताले फायदे किसी पीति से कर हो जाते हैं तो, यह छूट रदद की जा सुकती है।
- 10. यदि किसी कारणवधः नियोजक भारतीय जीवन बीमा निषम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफत रहता है और पालिमी को व्यपमत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा श्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवेकितियों या विधिक वारियों को जो जीद यह छूट गदी गई होती सो, उन्हर्स स्क्रीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधी। आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारोतीय जीवन बीमा निगमा, बीमाकृत राधि के हुकाबार नाम नियांशिकी/विधिक वारिसों को उस दावा में हुए प्रकार से पूर्ण दावे की शीकि के एक मास के भीतर सुनिधिक करेगा।

[संख्या एस-35014/307/82-पी. एफ . -2/एस . एस . -2]

S.O. 1620.—Whereas Messrs, Guest Kean Williams Limited, Sciews and Fasteners Division, Lal Bahadur Shastri Marg, Bhandup, Bombay-400078 (MH|9074) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee.' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Fuployees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the

Ministry of Labour, S.O. 732 dated the 17-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-1-1986 upto and inclusive of 28-1-1989.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the United Government may, from time to time direct under chause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance scheme, including maintenance of accounts, subtrission of teturns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Lapployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance between and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Gloup Insurance Scheme appropriately, it the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be Jess than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirinominee of the employee as compensation.
- 5. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where, any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the pagainm etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employee in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased rembers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the

Legal heirs of the deceased entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/307/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1621.—मैंसर्स गाजरा बिवेल गियरस लिमिटेड, इण्डिस्ट्रियल एरिया, ए. बी. रोड, दीक्षास—मध्य प्रदेश (एम. पी./3424), (जिसे इसमें इसके परचार, उक्त स्थापत कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवण्य अभिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके परचार, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदान किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके प्रकात् उवंत स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिक्यम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्त यों का प्रयोग करते हुए, और भारत हरकार के श्रम मंगालय की अधिस्वना संख्या का. आ. 613 तारीख 13-12-1982 के उन्सरण में और इससे उपादद्व अनुसूषी में विनिध्दिट शूपों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अविधा के लिए जिसमें 21-1-1989 भी हिम्मलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुस्ची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रावेशिक भेविष्य निधि आयुक्त, पच्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण कु निए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का अत्येक मान की समाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनका अभिनयम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के कण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. साम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, फिस्के अनार्यत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का स्वाय आदि भी है, होने बाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया आए, जब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रविचित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निश्चिका या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में

उसका नाम शुरन्त वर्ण करेगा और उसकी बाबत कावश्यक प्रीमि-यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा।

- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुक्ल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस रकीम के अधोन सबय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा मा सबैय होती जब वह उदता स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेशिक्षती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के असर के बराबर रकम का सबाय करेगा।
- 8. सामृहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी हंशोधन, प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के विका नहीं किया जाएगा और जहां किसी हशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्भचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन एहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जान ही, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हा जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा साजी है।
- 10. यदि किसी कारणबहा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में अक्षकल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रबुद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दश मों, उन मृह सदस्यों के नाम निवेधिकियों या विधिक व्यार्थों को जो यदि यह छूट र दी गई होती तो उद्या स्कीम के जनार्थत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्य रियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निसम, भीमाकृत राशि के हकदार साम निदेशिक्षति/विधिक वारिसों को उर राशि का स्याय तत्वरण से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक सास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/366/७2-पी. एफ. -2/एस. एस. -2]

S.O. 1621.—Whereas Mesers Gajra Bavel Gears Limited, Area, AB Road, Dewas-MP-455001 (MP/3424) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Missellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Aministry of Labour, 8.O. 613 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transier of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in rayment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased numbers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/366/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1622.— मैंसर्स किरलोसकर व्यम्मिन्स लिमिटेड, कोध्रुड, पूणे-411029 (एम.एच./7063), (जिसे इसमें इसके प्रवात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपदन्त अधिन्यम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रचात उक्त अधिन्यम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधार हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अन्कूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षंप सहबद्ध दीमा स्कीम, 1976 (जिस इसमें इसके प्रकाह उक्त स्कीम कहा गया हैं) के अधीन अनुभय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त किन्द्रयों का प्रयोग करते पुण, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिस्तृतन संख्या का. आ. 612 तारीक 13-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाइद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 21-1-1989 भी समिमलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्त्त से कूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के राष्ट्रस्थ में नियोजक प्रादेशिक भारिष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भोजेन और ऐसे लेखा रखेना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विद्य करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक सास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर गंबांय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उ-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक तीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का स्वाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक हारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा उन्मोदित साम-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अन्याद, स्थापन की सूचना-पत्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त फिसी स्थापन का भविष्य

दिधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक साम्हिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमिन्यम भारतीय जीवन बीमा रिगम को संदत्त करेगा।

- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे दढ़ाए जाते हैं तो, नियोज क उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में िकसी बात की होते छुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्तन उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दश में संदेय होती जह वह उक्त स्कीम के उधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के दराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएना और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य रिधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का गृवितयुक्त अदसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवस्न, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर, नियोजक भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में अस्फल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संबाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की ददा में, उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका स्कीम के अन्तर्गत होते, शीमा फायदों के संबाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम को अधीन आने वाले किसी सदस्य की मूटा होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि की शुक्रदार नाम निवेशिकी/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सर्पन्ता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण बावे की प्राप्टि के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

S.O. 1622.—Whereas Messrs Kirloskar Commins Limited, Kathrud, Poona-411029 (MH/7063) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees that the benefits adm ssible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 612 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall infinediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is fiable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case with n one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/367/82-PF-II (SS-II)]

का आ. 1623. — मैरेस दिशेरगढ़ पावर स्प्लाई कम्मनी निर्मिटेड, 8 वलाइवरो, कलकत्ता-700001 (उटल्यू बी/634 और इटल्यू, बी./637), (जिसे इसमें इसके प्रचात् उदत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निष्धि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके प्रचात् उयत्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए डावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्हें स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीस्थिय का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) क अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्त यों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ. 898 तारीख 18-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुष्णि में विनिर्विष्ट करों के अवीग रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अविव के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंबों के प्रवर्तन से छुट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बद्ध में नियोज क प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त एश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक सास की समाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विद्य करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिस्के अन्तर्गत लेखाओं का रहा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होन वाले सभी व्ययों का बहुव नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, कब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृक्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविश्वित करेगा .
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविषय निश्चिका या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के भविषय निश्चिम किया उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के भविषय निश्चिम किया जाता है तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के स्दस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्भ करेगा और उसकी दादत आवश्यक प्रीप्तिनयम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन क्रमंचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोज के उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समृहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुक्ल हों, जो उनत स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकाम उस रकाम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती पह वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के इराहर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी स्शोधन, जिक मेविष्य निधि आयुक्त, परिजय बंगाल के पूर्व अनुमीदन के बिना नहीं किया जाएगा औं जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संशोधना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निराम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश्, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में अरुफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निवेकितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिक नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निवेशिती/विधिक शारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर स्निश्चित करेगा।

जिंख्या एस-35014/371/82-पी.एफ.-2/गम गक -97

S.O. 1623.—Whereas Messre Dishergarh Power Supply Company Linsted, 8, Clive Row, Calcutta-700001, (Wi4634 & WB/037) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 thereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 898 dated the 18-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

- t. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the sald Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the bentils available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reason-

- able opportunity to the employees to explain their point or view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as atready adopted by the said establishment, or the benefits to employees under the scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is fiable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the 1 egal heirs of the deceased member entitled for it and in any cure within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/371/82-PF-II (SS-II)

का. था. 1624. — भैरर्म स्वील फैब्रीकेटर्स, 33-ए., इण्डिस्ट्रियल एरिया, गोबिन्द पूरा-462023, भोपाल (एम. थी./2055), (जिसे इसमो इसके एक्टाट् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविषय निधि और प्रकीर्ण उपदस्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमो इसके पश्चान् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के सिए आवेदन किया है;

और केन्द्रांग सरकार का संभाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए किना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा मंजीस की सामृहिक बीमा स्कीम के अभीन जीवन बीमा के एन में जी फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनक्षत हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध दीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचार, उक्त स्कीम कहा गया है) को अधीन अन्त्रीय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदस्त किन्द्रियों का प्रयोग करने पूए, और भारत सरकार के धम मंत्रालय की अधिस्करा संख्या का. आ. 34 तारीक 6-12-1982 के उग्सरण में और इससे उपाबद्ध अन्सूषी में विनिर्दिष्ट क्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन ्वर्ष की उवधि के विग् जिसमों 31-12-1982 भी सम्मिनित है, उक्त स्कीम के सभी उपवंधों के प्रवर्तन से छुट दोती है।

अन्सूची

- उसत रथाएन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिव्चय निधि आयांकर मध्य प्रदेश को ऐसी विधरणियां भेजेगा और ऐसे सेसा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विध्य करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रतयेक मास की समाप्ति की 15 दिन के भीदर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविषय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविषय निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बादत आदश्यक ग्रीहिन-यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्चित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम्हिक बीमा स्कीम के अवीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुक्त हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदेशिकी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के दराहर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्राये-शिक भिवष्य निधि श्रायुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मणारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवह, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में अरुफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक हारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दहा में, उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितियों रा विधिक वारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्क्रीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिक नियोजक पर होगा।
- 12. इत स्कीस के अधीन अने वाले किसी सदस्य की मन्द्र होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकन प्र 24 GI 86—13

नाम निर्देशित/विधिक यारिसों को उस रिश का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/375/82-पी. एफ. -2/एस. एस. -2]

S.O. 1624.—Whereas Messrs Sushil Fabricators 33-A, Industrial Area, Govindpur-462023, Bhopal (MP/2055) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) \$

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 34 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount nayable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Machya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is fiable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince or the I egal helrs of the decased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

INo. S-35014/375/82-PF-II (SS-II)]

का. था. 1625. — मैसर्स दावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमि-टेड, 70 नक्ष्मी इन्होरेंस बिल्डिंग सर पी. राम रोड, इम्बई (एम. एच./6797)- (जिसे इसमें इसके पश्चात् उद्ध्त स्थापत कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त अधिनियमं कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उत्तर स्थापन के कर्मधारी किसी पृथंक अधिदाय या प्रीमियम का संवाध किए खिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनक्त हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके एश्चात् उबंत स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त किन्द्रयों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसचना संख्या का. आ. 408 तारीख 10-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद अन-स्ची में विनिध्दिष्ट क्यों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को. 15-1-1986 में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 14-1-1986 भी समिमलित है, उक्त स्कीम के सभी उपदन्धों के प्रवर्त्त से छूट देती है।

अनससी

1. उकत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भीषध्य निधि आयक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे नेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मिक्शएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करे।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक सास की समाफि की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंग्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन सभय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अलागीत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संवाय, सेखाओं का अल्टरण, निरीक्षण जगारों का संवाय आवि भी है, होने वाले सभी न्यूयों का नहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमीदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उत्में संघोधन किया जाए, जब उस संघोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद, सायन के सुषरा-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविषय निश्चिका या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन के भिष्ठिय निधि का गहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में निर्माणित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीकि-यम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मणरियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मणरियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मणरियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अदिक अनुक्ल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अगुझेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात की होते जुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेग रक्तम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दहा में संदेग होती जब नह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेकिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के असर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधना, प्राये-शिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्रा के पूर्व अन्मोदन के निना नहीं किया जाएगा औं जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभाधना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोबन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण सण्ट करने का ग्वित्यक्त अवरार देगा।
- 9. यदि किसी कारणवता, स्थापन के कर्मकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुंचे अपना च्का है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हों जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवह, नियोजक भारतीय जीवा बीहा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने भें अस्फल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवास में किए गए विभी व्यतिकाम की दश मों, उन मृह सबस्यों के नाम रिवेशिक्तियों या विभिन्न वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका

स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अपीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निदंशियति/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/404/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 1625.—Whereas Messrs Daver Engineering Private Limited, 70, Lakshmi Insurance Building, Sir P.M. Road, Bombay (MH [6797) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 408 dated the 10-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 15-1-1986 upto and inclusive of 14-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manuer, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life lasurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/404/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1626.—भैसर्स जनर निटिंग वर्कस प्राईवेट जिन्दिटेड, इन्डस्ट्रियल एरिया, तानसेन रोड, ग्वालियर, मध्य प्रवेद (एम.पी./1800) (जिसे इसमें इसके पश्वात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपभारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए बावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीत की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षत सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिस इस्यो इसके परकार उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुष्टेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिन्यम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस्त शिव्हयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंशालय की अधिम्बना संस्था कां. आ. 20 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में यिनिविध्य स्त्री के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन कों, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सिम्मलित हैं, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अनुस्ची

- 1. उद्धा स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रावेधिक भाषिष्य विधि आयुक्त मध्य प्रवेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाण्ति की 16 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अभिनयम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के रूण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. साम् हिक बीमा स्कीम के प्रकासन में, जिसके अंतर्गत सेसाओं का रक्षा जाना, विवरणियों का प्रस्तुक किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक क्षारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम्हिक भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनसें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबन्द, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मजारी, जो कर्मधारी भविष्य रिशि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोणित किया जाता है तो नियोषक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाअत आवष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सप्यृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उन्ना स्कीम के अधीन अमृज्ञेय हैं।
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी.
 यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संवेय
 रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में स्वेय
 होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी
 के विधिक वारिस/नाम निदेशिश्ली को प्रतिकर के रूप में दोनों
 रक्तमों के अन्तर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेधिक भविषय निधि आगुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के दिना नहीं किया, जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो गहां, प्रावेधिक भिष्णय विधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिस्कृत अवसर देना।

- 9. यहि िह है कारणब्क, स्थापन के कर्मचारी, भारतीम जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीय के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह इट रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किशी कारणवश्च, नियोजक भारतीय जीवन बीका निरम द्वारा वियत तारीख के भीतर प्रीमियम का स्वाय करने में असफले रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जार दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दक्षा में, उन मृत स्दस्यों के नाम निदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उन्ता स्क्रीस की अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक ५ र होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी स्वस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार गाव निदेशिती/विधिक शारिसों को उन राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीवर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/289/82-पी. एफ. -2/एस. ए४: -2]

S.O. 1626.—Whereas Messrs Amar Knitting Works Private Limited, Industrial Area, Tansen Road, Gwalior-MP (MP/1804) (hereinafter referred to as the said establishment (have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2.1) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 20 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Go ermuent may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, subsion of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The cooployer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schene as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the Laguage of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the bentfis available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount apayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employers to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to Japse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of driault, if any made by the employer in payment of premia 1 the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

INO. S-35014/289/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1627. — मैसर्स अम्बर कापोरिशन, तानसेन रोड, गवासिन र-474002 (एम.पी./2261) (जिस इसमें इसके एक्नाह् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निध्न और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन्हें का उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाक्ष उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुझेय हैं;

अतः कंन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ . 4075 हारीख 12-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाध्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट छतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अधिक के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सिम्मलित है, उक्त स्कीम के सभी उपगंधों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अगुसूची

- उक्क स्थापन के संस्वन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेरा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विध्य करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भारा 17 की उप-भारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुह किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, शिरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन दियोजक द्वारा किया आएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, जब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बादुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुसाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविश्वित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उकत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामृहिक बीमा स्क्रीम के नदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी गाइत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अगुजेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अशीन संदेय रक्षम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दक्षा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोध क कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवैधिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्थीभ के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भिवाय निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमादन के दिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मधारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां, प्रावेशिक अदिष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मधारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देना।
- 9. यदि किसी कारणदश, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम की, जिसे स्थापन पहले अपना चूका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह सूट रहुद की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणबन्ध, नियोजक भारतीय जीवन की हिन्म द्वारा नियत तारीस की भीतर प्रीमियन का संदाय करने में असफल रहता है, और पिलसी को ध्यापत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम को संदाय में किए गए किसी क्यितिक्रम की दक्षा में, उन मृत सदस्यों के नाम निवे कितियों या विभिन्न वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्क्ष स्क्रीम की अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी ६ दस्य की मन्त्र होने पर भारतीय जीवन बीमा नियम, बीमाकृत राशि के हुकराए नाम निवेधिती/विभिक वारिसों को उस राशि का संवास

तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण क्षत्रे की प्राप्ति के एक मास के शीतर सुनिधिचत करेगा ।

[संस्था एस-35014/248/82-पी.एफ.-2/एस.एस:.-2]

S.O. 1627.—Whereas Messrs Amber Corporation, Tansen Road, Gwalior-474002 (MP/2261) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hreinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4075 dated the 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of 3-12-1988,

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for Inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments recopy of the rules of the Group Insurance Scheme as up roved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the fanguage of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to ephance the benefits available to the employeer under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/248/82-PF-II (SS-II)]

का. जा. 1628.— पौसर्स एम. जी. ई. एफ. लिमिटिड सेंग्स आफिस बाम्बे दिवसिकनोन हाऊस, ई. मोसिस रोड, महालक्ष्मी बम्बई-400011 (एम. एच./17509) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिवष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी एथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्तीम की सामृहिक बीमा स्तीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकुल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पक्चाम उक्त स्कीम कहा गया है) के अभीन अनजेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिस्थाना संख्या का आ 4068 तारील 12-11-1982 के अनसरण में और इससे उपानद अन्सूची में विनिर्दिष्ट स्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 3-12-1988 भी समिमलित है, उक्त स्कीम के सभी जाडंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसुची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिवष्य निधि बायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरिणया भेजेगा और ऐसे लेखा रक्षेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की हमाप्ति की 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के इण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकासन में जिसके अंतर्गत ने बाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, निमा प्रीमियम का संवाय, लेबाओं का अन्तरण, निरीक्षण भारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का यहन ने योज क द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक रीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें श्वीधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों ही बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भीवष्य निधि हा या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का विष्ट निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित कया जाता है तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के अप में उसका नाम तुष्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत विषयम भारतीय जीवन बीमा निगम को स्वरा
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे दढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से विद्वि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिस्से कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दक्षा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि अध्यक्षत महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सीमिहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो∮यह छूट रदद की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश्, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख को भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफाल रहता है, और पालिसी को व्यवनात हो जाने दिया जाता है सो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दक्षा में, उन मृत स्दस्यों के नाम निदेशितियों या चिविक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती हो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्दे शिली/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक सार के भीतर सनिश्चित करेता।

[संख्या एस-35014/207/82-पी. एफ. -2/एस. एस. -2]

S.O. 1628.—Whereas Messrs NGEF Limited, Sales Office Bombay Tiecicon House, E Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-400011 (MH/17509) (hereinafter referred to as the said establishment(have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Eployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter refered to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hreinafter referred to as the said Scheme);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4068 dated the 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of 3-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or he majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner. the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lanse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of his exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the commee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|297|82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1629 — मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम प्लाट नं. 18, मालवीया नगर, भोपाल-462003 (एम.पी./3583), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्षीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात् उकत प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रिभवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रनुत्रेय हैं;

श्रमः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते द्वुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधिमूचना संख्या का श्रा. 907 तारीख 21-12-1982 के श्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की श्रविध के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिवष्य निधि श्रायुक्त, श्रान्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के ग्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत सेखाओं का रखा जाना, विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय श्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी 24 GI/86—14.

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त करेगा।

- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि धायुक्त, श्रान्ध्र प्रदेश के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि धायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के ग्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसी को उस राशि

का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/361/82-पी०एफ०2/एस एस H]

S.O. 1629.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Bhoomi Vilkas Nigam Plot No. 18. Malviya Nagar, Bhopal-462003 (MP)/3583) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and incontinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 907 dated the 21-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 apto and inclusive of 11-2-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necesary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount

payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/361/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 1630: — मसर्स किनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड डी-1, ब्लाक प्लाट नं. 18/2, चिनाचिबाड, पूणे-411019 (एम. एच /14219), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीणं उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 था 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधःरा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

शेर केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा कि रूप में सामूहिक बीमा स्कीम के ग्राधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन पायदों से श्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध (बीमा स्कीम 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्राधीन उन्हें श्रमुक्तेय हैं;

मतः केन्द्रीय सरहार, उक्त ग्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रधिसूचना संख्या का ग्रा. 737 तारीख 17-12-1982 के ग्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिधिष्ट शतौं के ग्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 29-1-1986 से तीन वर्ष की

प्रविध के लिए जिसमें 28-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भिवष्य निधि श्रायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निर्दक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क्ष) के खंड (क) के ग्रिधीन समय-समय पर निविध्ट करें।
- 3. सामूहिक बेमा स्कोम के प्रणासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निर क्षण प्रभारों संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक बे.मा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्म-चारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का श्रनुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदक्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बेमा स्कोम के प्रश्लोन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कोम के प्रश्लोन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बोमा स्कोम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के श्रधीन अनुजीय हैं।
- 7. सामूब्रिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कमंचारी की मृत्यु पर, इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के स्प में दोनों रकमों के धन्तर के बरावर रकम का संवाय करेगा।

- 8. सामूहिक स्कंम के उपबंधों में कोई भी संणोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रीमुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम की जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम ही जाते हैं, तो यह रह की जा सकता है।
- 10. यदि किसी कारणवया, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तार ख के के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, और पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होतो तो उक्त स्काम के अंतर्गत होते, बीमा फायदीं के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के श्रधीन श्राने वाले किसी सदस्याँ की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हक्षदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित कंरोगा।

[संख्या एस-35014(358)/8297, एफ.-2/एस. एस-2]

S.O. 1630.—Whereas Messis Kinetic Engineering Limited D-1 Block, Plot No. 18/2, Chinchwad, Pune-411019(MH/14219) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and incontinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 737 dated the 17-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of 28-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment small submit such returns to the Regional Provident found Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time affect trader clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be come by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, teatures thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of hims to the Life Insurance Colporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, it the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Mahatashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of able opportunity to the employees to explain their point of deceased members who would have covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]358[82-PF. II(SS II)]

का. आ. 1631: — मैंसर्स श्री बैंकंटेसा पेपर एन्ड बोर्ड (प्राइवेट) लिमिटिड, स्वामीनाथापुरम, महायकुलमपोस्ट, 642113, उदुमुटपट लालुक (टी.एन/11266), (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने वर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रधीम छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचार, किसी पृथक श्रिभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से श्रधिक श्रमुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रमुक्नेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रधिसूचना संख्या का ग्रा. 4134 तारीख 22-11-1982 के प्रनुसरण में और इसमें उपाबद्ध श्रन्सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को, 11-12-1985 से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए जिसमें 10-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के तभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

प्रनुसुची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा को केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के श्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा।

- 5. मदि कोई ऐसा कर्मचारी, को कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक, बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उकत स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से युद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रनुत्तेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, तिभलनाडु के पूर्व भ्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, भपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मधारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमे स्थापन पहले प्रपना चुका है ग्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत सारीख के भीतर, प्रीभियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दशा में उन, मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, श्रीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन शाने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि

के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक देशा मे हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/318/82-पीठ एफ०-2-एस.एस-2]

S.O. 1631.—Whereas Messrs Sri Venkatesa Paper and Boards (Private) Limited, Swaminathapuram, Madathukulam Post 642113, Udumalpet Faluk, (TN|11266) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4134 dated the 22-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 11-12-1985 upto and inclusive of 10-12-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount

payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of dedeceased members who would have been covered under the Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/318/82-PF. II(SS.II)]

का. प्रा. 1632: — मैससं जय हिन्द सायकी लिमिटिड, डी-1 ब्लाकः, फाट नं. 18/1, चिमाचिवाड, पूना-411018 (एम. एच /14766), जिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीणं उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

कार केन्द्रीय संरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वह ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी मिक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्षेय हैं;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधिसूचना संख्या का आ. 4267 तारीख 26-11-1982 के श्रनुसरण में और इससे उपावज भनुसूची में विनिविष्ट शतों के श्रिधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की, 18-12-1985 से तीन वर्ष

की ग्रवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक श्रविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के क्षिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदोध करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन निरोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना पष्ट्र पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य मिधि का या उक्त अधितियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन भीम निगम को संदक्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की ध्यवस्था वारेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृष हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/माम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिता नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की सम्भायना हो बहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्था-पन पहले अपना चुका है ग्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह् की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, निशोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यातकम को दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्वेशितियों या विधिक बारियों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायवों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्रधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा। [सं. एस-35014 (314)/82 पी० एफ० 2-एस. एस-2]
- S.O. 1632.—Whereas Messrs Jay-Hind Sciaky Limited D1 Block, Plot No. 18/1, Chinchwad Pune-411019(MH/14766) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and incontinuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4267 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Com-

- missioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rule of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view
- 9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group, Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the level heirs of deceased numbers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in the case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

नई दिल्ली, 4 अपैल, 1986

का. आ. 1633 — मैंसर्स मोमासून्दाराम मुपर स्पीनिंग मिल्ज मुधानन्दल (पोस्ट-623602) (रुजदीक) मानामद्राई रामानन्द जिला समिलनाडू (टी. एन. /5323), (जिले इसमें इसके पश्चात् उत्तर स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण जाबन्ध अधिनियम, 1952 (1952) का 19) जिले इसमें इसके पश्चात् उत्तत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा िगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मा जायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेण सहबद्ध नीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है ;

अतः केन्द्रीय रुकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपबद्ध अन्भूषी में विकिदिष्ट शती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रदर्शन में छूट देती हैं।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय गरकार, समग-समग पर निर्देश्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक साम की सम्माप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-शारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत सेसाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों मंदाय आदि भी है, होने वालें मभी व्ययह का बहुन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।
- 4. नियोजन, किन्सीय सरकार द्वारा अन्मोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशो-भन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य दातों का अनुवाद स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाना है तो, नियोजक सामहिक बीगा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम त्रला दर्ज करेगा और उसकी साबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।
- विच उपत स्कीम के अधील कर्मचारियों को उपलब्ध कायदें बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से बृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।

- 7. सामृष्टिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती जब बहु उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदें िकती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के रुपसर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृष्टिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य रिधि आयुक्त, तिमलनाडु के पूर्व अनुमोदन के निना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म- भारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवस्र देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगय की उम सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियंत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियंत करें, प्रीमियम का मंदा व करने में असफल रहता है और फिलिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम, की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्क्रीम के अन्तर्गत होते । वीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायिस्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यू होने पर उसके हकवार नाम निवेधितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनि-

[संख्या एस-35014/148/86-एस . एस . -2]

S.O. 1633.—Whereas Messrs, Somasundaram Super Spinning Mills, Muthanendal (Post) 623602, (Near) Manamadural Ramnand Distt., Tamil Nadu (TN|5323) (hereirafter as referred to as the said establishment) have applied to exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on that Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount rayable under this Scheme, be less than the amount that vould be payable had employee been covered under the aid Scheme, the employer shall pay the difference to the egal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insuance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and where any amendment is likely to effect adversely the nerest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonble opportunity to the employees to explain their point of iew.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said stablishment do not remain covered under the Group Insuance Scheme of the Life Insurance Corporation of India s already adopted by the said establishment, or the benefits the employees under this Scheme are reduced in any nanner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 24 GI/86—15.

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of the claim complete in all respects.

[No. S-35014(148)/86-SS-II]

का. आ. 1634. — मैसर्स श्री रानी मिल्ज (प्राइरट) निमिटेड 2/38 चिनामप्लाम कोयम्बटूर (टी. एन.-11102) (जिसे इसमे इसके पर्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू- हिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अन्कल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहब्द बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अन्जय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त शिधितयम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अन्स्ची में विनिर्विष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन दर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के गभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट देती है।

अनसची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिवष्य निवि आयुक्त, तिमलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर रिविंडट करे।
- 2. दियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मार की मामाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समग समय पर निर्विद्य करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम को प्रशासन मों, जिसकी अन्तर्गत लेकाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय: सेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन निरोक्षक द्वारा विया जाएगा।
- 4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें रंगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूख्य वालों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिक्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी जो कर्मधारी भनिष्य निधि का या उरत अधिनियम के अधीन छाट प्राप्त किसी स्थापन में नियोणित किया जाता है तो, नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निराम को संबद्ध करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अमार्थ हैं।
- 7 सामृहिक बीमा स्कीम मो किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू ५२ इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती बाब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निवेधिती को प्रतिकर के रूप मो दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तिमल नाहू के पूर्व अन्मोदन के बिना नहीं किया वाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन गहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम ये जधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रदद की जा सकती है।
- 10. यदि फिसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ज्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदान में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निवेधितियों या विधिक वारिनों को जो यदि यह छाट न दी गई होती हो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के हंदान का उत्तरदायित्य विद्योजक पर होगा।
- 12. उक्त क्यां के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी संदग्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय सल्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनिष्टित करेगा।

[संख्या एस-35014/146/86-एस.एस.-2]

S.O. 1634.—Whereas Messrs, Sri Rani Mills (Private) Limited, 2/38, Chinniampalayam, Combatore-641062 (TN/11102) (hereinafter or referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Govvernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on that Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme, be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date. as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(146) 86-SS. II]

का आ 1635: — मैसर्म देसीन (नई दिल्ली) प्राइवेट लिमिटिड देसीन हाऊस, ग्रेटर कैलाण II, नई दिल्ली- 110048 (डी.एल /3406) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रिधीन छूट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

अंर केन्द्रीय सरकार का सभाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी। किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की श्रधिमूचना संख्या का ग्रा. 3495 तारीख 18-9-1982 के श्रनुसरण में आर इसमे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 2-10-1985 से तीन वर्ष की श्रविधि के लिए जिसमें 1-10-1988 भी मम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में निशोजक प्रादेणिक भविष्य निधि आधुक्तः दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथः निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं ग्रांन करेगा जो केंग्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2 निशोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास ही समाप्ति के 15 दिन के भी⊤र संदाय करेगा जो केन्द्रीय इरकार, उक्त अधिनिथम की धारा 17 की उपधारा (3क) ह खंड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके भंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया भाना, बीमा प्रोमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, नरीक्षण प्रभागों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों ा वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. निशेजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक रीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें रिषोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथ। रिमंचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों रा अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविशित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या अकत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है ती, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आविष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्दल्त करेगा।
- 6. यदि साम्हिक बामा स्काम के अधान कर्मचारियों, को उपलब्ध फायदे बढ़ ये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्काम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्काम के अधीन अनुशेय हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होतो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने ना युक्तियुक्त अधसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिय बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, जो प्रीमियम का संदाय करने में असकल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो. छूट रह की जा सकतो है।
- 11. नियोजक द्वर्रा प्रांमिथम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियां या विधिक वारिसों को जी यदि यह छूट न दी गई होती हो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व निशीजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के श्रधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाक्कत राशि

के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतोय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (192)/82-पी॰ एफ 2/एस. एस.-2]

S.O. 1635.—Whereas Messrs Desain (New Delhi) Private Limited Desain House, Greater Karlash II, New Delhi-110048 (DL/3406) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3495 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of 1-10-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient, features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount

payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the said "Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No. amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of dedeceased members who would have covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/192/82-PF. II(SS,II)]

का था. 1636: — मैसर्स किलोस्कर फिल्टरस प्राइवेट लिमिटिड "प्रतिभा" 758/104, दक्कन जिम्खाना, पुणे-411004, (एम.एच/12280), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए थ्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक वीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और वे ऐसे भर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुकूथ है;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रधिसूचना संख्या का श्रा. 619 तारीख 13-12-1982 के श्रमुसरण में और इससे उपाबड़ श्रमुसूची में विनिर्दिष्ट गतौं के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 22-1-1986 से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से खूट देती है।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 को उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसन उपायद्ध श्रनुसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्त्रीम के सभी उपवंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

ग्रन्स्ची

- 1. उनत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के जिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के श्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतगत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियंजिक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुवाद, स्थापन के सूचना पष्ट पर प्रदेशित करेगा।
- 5. मिंद कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्ठिय निधि का या उक्त ग्राधिनियम के श्रधीन कूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा श्रीर उसकी बाबस ग्रावश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के घ्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक मामूहिक बंगा स्कीम के प्रधीन कर्म- चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुकेष हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी, को उस दशा में संदेय होती जय वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का मंदाय करेगा।
- 8. नामृहिक बंशा स्कीम के उपवंधों में कोई भी संगो-धन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से

कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोधन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्वष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतियं जीवन बीमा निगम की उस आमूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कोम के अधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जी सकतो हैं।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, जो प्रोमियम का संदाय करने में श्राफत रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियाजक द्वारा प्रामिजम के संदाय में किए गए किसो व्यक्तिकम को दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होंने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कृत राशि के हकवार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाधत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा त रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/286/82 पी॰ फ॰ 2-एस.एस-II]

S.O. 1636.—Whereas Messrs Kirloskar, Filters Private Limtled 'Pratibha' 759/104, Deccan Gynkhana, Pune-411004 (MH/12280) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 619 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the satd establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of 21-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life insurance corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and

in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|286|82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 1637: — मैसर्स ब्यैय लैबोटरीज लिमिटिड, एल. बी. शास्त्री मार्ग, घाट कोपर, बम्बई-400086 (एम. एच. 6714). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 315 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट णतौं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसू**च**ी

- 1 उनत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 बिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिशत करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्ठिय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भिष्ठिय निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, उक्त नियोजक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्ष हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम हैं जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिनर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिक।ण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बोमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय व रने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीभियम के संदाय में वि.ए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तंगत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरादायित्व नियोजक पर होगा।
 - 12. इस स्कोम के अधीन अनि वाले किसी सदस्य की मृत्यु

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितो/विधिक वारिसों को उस राशि का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्त के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा

[सं॰ एस-35014/347/82-पी. एफ./एस. एस-2]

S.O. 1637.—Whereas Messrs Wyeth Laboratories Limited, LB Shastri Marg, Ghatkapar, Bombay-4000086(MH|6714) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident' Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter reformed to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 315 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 up to and inclusive of 7-1-1989.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees, Pvroident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to he employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the

amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not reamin covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium, etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/39/82-PF. II(SS. II)]

का.आ.16?8:—मैसर्स फूड स्पैशलिटीज लिमिटिड, एम-5ए, कनाट सर्कस, नई दिहसी-110001 (डी.एल / 4398), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि-,नियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अर्थेटन किया है;

अंदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय मा प्रोमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें उमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुजेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3138 तारीख 17-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में तिर्निदिष्ट णती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-9-1985 में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन् सूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिण्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवर्णाण्यों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी अविध्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाला है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि साम्हिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे वहाये जाते हैं तो, नियोज उसत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उसत स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, निशोजक कर्मचारी के विधित वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रहमों के अन्तर के वराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादिणिक भिविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व आप्रमोदन के विता नहीं िया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त,

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना पृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मधारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मधारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवरा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम डारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यमगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोग इत्या प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्रधीन धाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014196/82-प] .एफ .-2 एस०एस०-2]

S.O. 1638.—Whereas Messes Food Specialities Limited, M-5A, Connaught Circus, New Delhi-110001 (DL|4398) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3138 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-9-1985 up to and inclusive of 3-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendement of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Cornoration of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for nayment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/196/82-PF. II (SS. II)]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

का.आ.1639: — मैसर्स पिनकार्ड इन्डस्ट्रीज, 3453/57, देहली गेट, नई देहली-110006)डी.एल./2654), (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है!

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्राधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से ग्राधिक ग्रानुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्राधीन उन्हें ग्रानुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मित्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ. 2803 तारीख 13-7-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिधिष्ट गतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 31-7-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 30-7-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त देहली को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरंक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदाम करेगा जो केन्द्रेय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भेतर संवाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार, उक्त ग्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के श्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बोमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरोक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने बाले सभी क्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रेय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बोमा स्कोम के नियमों को एक प्रति, और जब कभो उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या को भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त भिधिनयम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके

स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत धावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस देशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के ग्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त देहला के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसा संशोधन से कर्मबारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि ग्राधुक्त, भ्रपना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मबारियों को भ्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवर्ग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भापना चुका है श्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह को जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सवस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायिस्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के घ्रधीन ध्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

प्राप्त के एक भास के भोतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/ 17/82-पोएफ-2/एस. एस-2]

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1639.—Whereas Mesars Picord Industries, 3453|57, Delni Gate, New Delhi-110006 (DL|2654) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2803 dated the 13-7-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 31-7-1985 upto and inclusive of the 30-7-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the acount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delni and where any amendment is likely to allects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Lidia as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|77|82-PF,II(SS-II)]

ना. था. 1640: - मैं स्सं मोड़न फूड इन्डस्ट्रीज (इन्डिया लि.) (जो पहा मोड़न बेकोज (इन्डिया) लि., के नाम) ले गाना जाता था (पुराना एम्बारियान प्रक्रन्ड, ताराताला रोड, कलकता-700088 (डब्ल्यू. बी/15281) (जिले इनमें इनके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिष्य निधि और प्रकर्ण उपबन्ध ग्राधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिले इनमें इनके पश्चात उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) को धारा 17 को उपधारा (2क) के ग्रिधीन कृट दिए जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से भ्रधिक भनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन्त स्कीम कहा गया है) के भ्रधीन उन्हें भनुत्रेय हैं;

्रिश्चेश्वतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिविनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधसूचना संख्या का. आ. 3607 तारीख 27-9-1982 के श्रमु उरण हुँमें और इससे उपावद्ध श्रमुम्चं में विनिर्विष्ट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन का, 16-10-1985 से तीन वर्ष कि श्रविध के लिए जिसमें 15-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभा उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाग्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के ग्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अतिर्गत के आशों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय धादि भी है, होने वाले सभी अपयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मेचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदल्स करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रनुकूल हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन धनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मकारी को उस दशा में भंदेय होती जब यह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मकारी के विधिक वारिस/नाम निर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के करावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया आएगा खीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, धपना

अनुमोदन देने से पूर्व कर्मशारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारीं, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है भ्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फांयये किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्वे-शिनियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीम के मधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्वित करेगा।

[संनमा एस-35014(104)/82~पो.एफ.-2/एस. एस-2]

S.O. 1640.—Whereas Mears Modern Food Industries (India) Limited (Formerly known as Modern Bakaries (India) Limited) Old Exhibition Ground, Taratala Road, Calcutta-700088 (WB)|15281) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Cenral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3607 dated the 27-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 16-10-1985 upto and inclusive of the 15-10-1988.

SCHEDULE

 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time,

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under crause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance or accounts, submission of returns, payment of insurance prema, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prier approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled:
- 10. Where, for any reason, the employer fad, to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the examption is hable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for sayment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ansure prompt payment of the suny assured to the nomines or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|104|82-PF. II (SS. II)]

का. भा. 1641:— मैर सं कैटल पिजप्लाट (ए इिन्ट भाफ राजस्थान को. ओ. डेरी फडरेंशन लिम्टिंड जयपुर) टोबोजी, ग्रजमेर (ग्रार. जे. 2775) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मधारी भविष्य निश्चि और प्रकोणें उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) को धारा 17 को उपधारा (2य) के मधोन खूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रेय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारों किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुजेय हैं;

म्रतः केन्द्रोय सरकार, उक्त मधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इपने उपावस मनुसूची में विनिधिष्ट शर्तों के भधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भविष्ठ के लिए उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि आमुक्त राजस्थान को ऐसो विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरंक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्र'य सरकार समय समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भे तर सन्दाय करेगा जो केन्द्रेय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामूहिक बेमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन की प्रति जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मवारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य जातों का अनुवाद, स्थापन के मुखना पट्ट पर प्रविक्ति करेगा।
- यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी प्रविषय निधि का या उपत मधिनियम के अधीन खूट प्राप्त किसी

स्थापन की भविष्यितिधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सदस करेगा।

- 6. यदि सामूहिक बेमा स्कंभ के अधंन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कंभ के अधंन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि के जाने के व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बेमा स्कंभ के अधंन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कंभ के अधंन अनुक्रोय हैं।
- 7. सामूहिक बंमा स्कोम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कमंचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कमंचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उकत स्काम के अधीन होता तो, नियोजक कमंचार के विधिक वारिस/नाम निर्वेशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बरावर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई मी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसार देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका हैं के अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कोम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम ही जाते हैं, तो यह छूट रह की जा संकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यप-गत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उकत स्कीम के अतर्गत होते, बोमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उमत स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कोम के अर्थ न आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा

्तिगम से बामाकृत एकम आप्त होते के एक मास के भातर निश्चित् करेगा।

[संख्या एस-35014(126)/82-एस एस-2]

S.O. 1641.—Whereas Messrs Cattle Feed Plant (A Unit of Rajasthan Co-op. Diaty Federation Limited Jaipur) Tabiji, Ajmer, (RJ|2775) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of Section 1/ of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Centrar Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in emoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India in the nature of Lite insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heerinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed heleto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance or accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of this majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately error him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding snything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajusthan and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the suid establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to Iapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any rade by the employer in payment of promium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been govered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(126)|86-SS-II]

का. आ1642:—मैंपर्स हिल्टन रबर्स प्राइवेट लिमिटिड, हिन्ट हिल्टन हाऊउ एप-23, ग्रोन पार्क एकाटेन्सन, नई दिल्ली 110016 (डी. एल/3141) (तिले इप्पें इसके पण्यात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपवन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इति इपके पश्चात् उक्त श्रिधितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट थिए जाने के लिए ग्रावेटन किया है;

और केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारें, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमयम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे ही वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुसेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपघारा (2क) द्वारा प्रदत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की अधिमूचना संख्या का. 3401 तारीख 9-9-1682 के अनुसरण में और इससे उपायग्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट मतौं के अधिन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूचः

- 1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक अविषय निधि आयुक्त, देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरिष्ट करे।
- 2. नियोजक ऐसे निर'क्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समािक्ष के 15 दिन के भारत संदाय करेगा जो केन्द्रं य सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 17 के उपधारा (3क्र) के खंड (क) के अध'न समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रभियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी क्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक केन्द्रिय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक कीमा स्काम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की आवा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचार, जो कर्मचार भिष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधिन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्य निधि का पहले हैं सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा सकेम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबल आवश्यक प्रीमियम भारत ये जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने को अध्यक्षों करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभेष हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किस बात के होते हुए भी यदि किस कर्मचार को मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचार को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्काम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचार के विधिक वारिस/नाम निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक वीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक मिविष्य निधि आयुक्त, सेहली के पूर्व अनुभोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसे संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

- 9. यदि किसी कारणवग, स्थापन के कर्मजारो, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना जुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मजारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्व की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवधा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा नियम द्वारा नियत कारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसो को व्यगत हो जाने दिया जाता है तो, खुट रद्व को जा सकता है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकाम के दशा में यह उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक दारिसों को यदि यह छूट न दा गई होता तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बामा फायदों के के संदाय का उस्तरदायिस्य नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक बारिसों को उत राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (157) 82/86-एस. एस. -2]

S.O. 1642.—Whereas Messrs Hilton Rubbers Private Limited, Hilton House, S-23, Green Park Extension, New Delhi-110016 (DL;3741) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Punds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Givernment is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3401 dated the 9-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Givernment may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance prensa, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enror him as a filember of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Grup Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely o affect adversely interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9 Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed b, the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premula the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure promot payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. \$-35014|157|82-PF. II(\$S. II)]

का. आ:—164 उमैससे नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशम लिमिटेड, बन्दना बिल्डिंग, वसवीं मंजिल कमरा नं 11, टाल्सटाय मार्ग, मई दिल्ली-110001 (डी. एल./2980) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमैंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 16) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

जिंधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अबीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन यीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रयीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों की जो उन फायदों से ग्राधक अनुकूत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्राधीन अनुजेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मंख्या का. आ. 2952 तारीख 4-8-1982 के अनुसरण में और इसमे उपायद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 27-8-1985 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 28-6-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्थीम के सभी उपदन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भ्रनम्ची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त देशका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-सगय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियंशिक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतप संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्राधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के ग्राधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अंतर्गत निखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना. बीमा प्रीमियम का संदाय, लखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है होते वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- ा. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बीमा रकीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें मंगोधन किया जाए, तय उस संगोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रीधिनयम के श्रधीत छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत श्राबण्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा।

6. यवि सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उका स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप मे धृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में श्रधिक अनुकृष हो जो उक्त स्कीम के श्रधीन अनुजेय है।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दानों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेणिक भविष्य निधि श्रायुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ते की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मनारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है श्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के श्रवीन कर्मनारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छुट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन वीमा निगम हारा नियन नारीख के भीतर, प्रीभियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है, ऑर पालिसा को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो. छुट रह की जा सकती है।
- 1. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की दणा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूद न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अनर्गत होते. बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम. धीमाकत राणि के हकदार नाम निर्देणिकी/विधिक धारिकी को उस राणि का संशय तत्परता से और पत्थेक दला में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्रास्ति के एक मांस के भीवर सुनिष्यित करेगा।

सङ्ग्रा एम: 35014(195)/82/पूर्-एम, एस.-2

S.O. 1643.—Whereas Messrs National Textiles Corporation Limited Vandana Building, 10th Flaor, Room No. 4, folstoy Marg. New Delhi-110001 (DL/2988), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under

sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2952 dated the 4-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-8-1985 upto and inclusive of the 26-8-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall hay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Groun Insurance Scheme as approved by the Control Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employer, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund or an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall Immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the bonefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Groun Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- * 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India' as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced

- in any manner, the exemption shall be liable to be can colled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the late insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the 19th Institute Corporation of India's all ensure prompt paymen' of the sum assured to the nominee of the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]195[82-PF,II(SS.II)]

का. आ॰ 1644:—मैसर्स इन्डियन अ(क्सीजन लिमिटेड, भाएकर भवन, भिमली रोड, विशाखापटनम-530013 (ए. पी./236) और भैसर्स इन्डियन आक्सीभन लिमि. फतेह मेडन रोड, हैदराबाद (ए. पी. 1951) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उत्तत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य भिधि और प्रकीर्ण पवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चात उत्तत अधिनियम कहा गया है की धारा 12 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उदत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रांसदाय या प्रीतियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सापूहिक बोमा स्कीम के ग्राधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को एए फायदों मे ग्राधिक श्रनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कोम 1976 (जिस इसमें इसके पण्चात उक्क स्कीम कहा गया है) के ग्रावीन अनुजेय हैं।

अतः केन्द्रीय गएकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रक्रम शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमूचना संख्या का. आ. 3538 तारीज 23-9-1982 के अगुसरण में और इससे उपावद्ध अनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 9-10-1985 में तीन वर्ष की अधीय के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है। श्रनसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त, आर्ध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे तेखा रक्षेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केट्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐथे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्थेत मास की सभाष्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय संस्कार, उपत श्राधिनियम की धारा 17 की उपधारा

- (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सम्मूहिक बंस्मा स्काम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत नेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वोमा प्रामियम का गंबाय, नेखाओं का अंतरण, निर्देक्षण प्रभारों का संवाय भ्रादि भी हे, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. ित्योदक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बोमा स्कोम के नियमों की एक प्रति, और एव कभा उनमें संयोक्षित किया आए, तब उन संयोधन की प्रति तथा कर्मह-चारियों की बहुतंख्या की भाषा में उसकी मुख्य दाती का जनवाद, स्थापन के मुचना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 5. सिंद कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचरित भिवस्य निधि ना मा उकत प्रधिनियम के प्रधार छूट प्रस्त किसी स्थापन का भिवस्य निधि का पही हो स्दस्य है, उसके स्थापन में नियोगित किया साता है तो, नियोगक, नामृहिक वामा स्काम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुसन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि स.मृहिक बोमा स्काभ के अधान वर्मचारियां को अपलब्ध फायरे बढ़ाये जाते हैं तो, नियाजक उक्त स्कीम के अधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि का जाने को ब्यवस्था करेगा जिल्ले कि वर्मचारियों के लिए वामृहिक बामा स्काम के अधोन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल ही जो उन्त स्कीम के अधीन अमुजेय है।
- 7. नामूहिक बंभा स्काम में किसा क्षात के हाते हुए भा, यदि किसा कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्काम के क्रधीन संदेश रक्षम उस रक्षम से काम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेश होती जब वह उस्त स्काम के अधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिता की प्रतिकर के रूप में दीनों रक्षमों के अन्तर के द्यावन एकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिया बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त आस्थ्र प्रदेश के पूर्व श्रनुमीदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की सम्मादना हो, वहां प्रावेशिक शिराय निधि भायनत. श्रमना अनुमीदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकाण स्पष्ट कर्रन का युक्तियुक्त श्रवत देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, तथापत के कर्मचारी, भारतीय जीवन वीमा नियम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के, जिते स्थापन पहीं अपना चका है अधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधान कर्मचारियों की आपते होंने बाते फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

- 10 यदि किसी कारणपण, नियंतिक भारतीय जीवन योमा निगम द्वारा निगत तारीख के भीतर, प्राप्तियम का संदाय करने में अतुफल रहता है, और पालिसा को व्यानत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह को जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रांतियम के सदाय में किए गए कियों व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक बादिशों की जो यदि यह छूट न दो गई होता तो उक्त स्टाम के अंतर्गत होते, बामा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीय के अधान आर्न जांग किसी सदस्य की मृत्यु हीने पर भारतीय आवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हिसार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता ने और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मान के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[अब्बा एव-35014(202)/82-एस.एस-2 पी एफ -2]

S.O. 1644.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited, Bhaskar Bhavan, Bhimli Road, Vishakhapatnam-530013 (AP|236) and Messrs Indian Oxygen Limited, Fathemeidan Road, Hyderabad (AP|1951), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3538 dated the 23-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-1985 upto and inclusive of the 8-10-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges c/c. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the

salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Prodesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|202|82-PF.II(SS.II)]

का. आ 1645— मैंसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सटूक्शन लिमिटेड, 1, शैक्सिपियर सरणी, आठवीं मंजिल,
कलकत्ता-700007 (इब्ल्यू. बी. 12619) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1652
(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम
कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीमी 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजोग हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3342 तारीख 27-8-1982 के अनुसरण में और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1888 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रन्सूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी वित्ररणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के श्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय श्रादि भी है, होने वाले सभी क्यायों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा श्रनुमोदित वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का श्रनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनियम के श्रिधीन छूट प्राप्त किसी, स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचा-रियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन ग्रनुकैय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिई शिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व ग्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त ग्रपना ग्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले ग्रपना चुका है, ग्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में ग्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के ब्रधीन ब्राने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकटार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/207/82-पी एफ-2]

S.O. 1645.—Whereas Messrs Hindustan Steel Works Construction Limited, 1, Shakespeare Sarani (8th Floor) Calcutta-700071 (WB|12619), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3342 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

- 1. The employers in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal maintain such accounts and provided such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhances, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insutance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any

case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. \$-35014]207[82-PFJI(\$\$.11)]

का. आ. 1646:— मैसर्स सैंडाबिक एशिया लि. वाम्बे-पूना रोड, पूना-411012 (एम. एच/5949) तथा इसर्का बम्बई, बंगलीर, कलंकत्ता, नई दिल्ली तथा मब्रास स्थित शाखाएं जो इसी कोड नम्बर के अन्तर्गत आती हैं। (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें ग्रनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिव्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 328 तारीख 6-12-1986 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तों के अधीन रहतं हुए, उक्त स्थापन को, 8-1-1986 ने तीन वर्ष की अविधि के लिए जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिष्ठय निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी बिवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करें करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक बारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा रकौम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की

- बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट गर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कमेंचारी जो कर्मचारी भिष्टिय निधि का या उक्त श्रधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्टिय निधि का पहले ही नदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमिथम भारतीय जीवन वीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, मह। राष्ट्र के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मजारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रभना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना वृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तिमुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किमी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहल अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वारो फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, नो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में ग्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्दे-शितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के प्रधीन म्राने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाछन राशि के हकदार नागनिविधिका वर्गरमो को 30 राशि का संदाय नत्परना में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चिन करेगा।

[संख्या एम-35014/251/82-एस . एस-2]

"S.O. 1646.—Whereas Messrs Sandvik Asia Limited. Bombay Poone Road, Poone-411012 including its branches at Bombay, Bangalore, Calcutta, New Delhi and Madros covered under Code No. MH|5949 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2.N) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the soid establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in convement of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Denosit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 328 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of the 7-1-1989.

SCHEDULE.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtta and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premial transfer of accounts, payment of inspection charmes etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof. In the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefit available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be carrelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the resemble for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the letth of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee of the Leval beits of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of child, complete in all respects.

[No. S-35014[251]82-PF.II(SS.II)]

का. आ 1647:—मैसर्स सुकुम कैमिकल्स, प्लाट नं. 10/3, जी. आई. डी. सी. एस्टैंट बरबा, अहमदाबाद (जी. जे/9295) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से श्रधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिस इसमें इसके पण्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रन्क्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4257 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की. 18-12-1985 में तीन वर्ष की अथिय के लिए जिनमें 17-12-1988 भी सम्मितित है, उक्त रकीन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देनी है।

प्रनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिविष्य निधि श्रायुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय सगय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3 क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निदिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले गभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा श्रनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुबाद, स्थापन के सूचना पटट् पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के श्रधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहुँवे ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरत्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- (८. यदि सामूहिक स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से श्रधिक श्रमुक्त हों जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रमकेय हैं।
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दुणा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होतातों, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देणिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अस्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबधो में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि ब्रायुक्त गूजरात के पूर्व ब्रमुमोदन के बीना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संगोधन से कर्षचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि ब्रायुक्त,

श्रपना श्रनुमोत्स देने से पूर्व कर्मनारियों को श्रपना दृष्टिकोण रपष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस गामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी गीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणविश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में श्रमफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत गदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के श्रधीन द्यान वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों की उस राणि का संदाय तत्परता ने और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिण्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(258)/82-पी. एक.-2/एस. एस-2]

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1647.—Whereas Messrs Sukam Chemicals, Plot No. 10[3, GIDC Estate, Vatva, Ahmedabad (GJ[5295) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4257 dated the 26-14-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shalf be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Consoration of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]258[82-PF.II(SS.II)]

का०ग्रा० 1648: मैंसर्स भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापट्नम (ग्रा०प्रा०/3495) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का

19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उनत म्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट दिये जाने के लिये ग्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजोय है;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनयम की धारा 17 की उपधारा 1 (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तिमों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की श्रिधिसूचना संख्या काल्ग्राल 4260 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपावद्ध धनुसूची में विनिर्विष्ट शतों के ग्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन बर्फ़ की ग्रविध के लिये जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

ग्रनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सभय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के भाधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मिवष्य निधि का या उक्त अधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेंगा और उसकी बाबत श्रावस्थक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदस करेगा।

- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के म्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के म्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से मृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के म्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन अनुकूष हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, आध्य प्रदेश के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, भपना प्रनुमोदन देनें से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मभारी, भारतीय भीवन वीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहलें प्रपना चुका है, श्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने, वालें फायदे किसी रीति से कम हो ज.ते हैं, तो यह छूट रब्द की सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में भ्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छुट रह को जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होति तो उक्त स्कीम के श्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदांथित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के मधीन माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन वीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिवेशिती/विधिक वारिसों की उस राणि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक भास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/262/82-पी.एफ-2-एस.एस-2]

S.O. 1648.—Whereas Messrs Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Vishakhapatnam (AP]3495) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4260 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the sai! Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/262/82-PF-II (SS-II)]

का ज्या । 1649 मैंसमं दी तीरू चीरापल्ली जिला को-ओप्रेटिक स्पिनिंग मिल्स लिं०, करूर, जिला तिची (टी० एन/5562) (जिले इसमें इमके प्रश्वात् उक्त स्थापने कहा गया है) ने कर्मवारी निवध्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छ्ट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जोवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जों फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुनेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिष्ठियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिष्ठसूचना संख्या का ब्याब 4261 तारीख 26-11-1982 के श्रनुसरण में और इससे उपाब श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की श्रविध के निये जिसमें 17-12-1988 भी सिम्मिलत हैं, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त नामिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भ्रन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,

- बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय श्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रिधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्त हों,
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब बह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त तामिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त श्रपना श्रानुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतींय, जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययमत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमीयम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा मे, उन मृत सदस्यां के नाम-निवीमातयां या विधिक बारिसां, को जा यदि यह, छूट न दी गई हातो ता उक्त स्काम के अंतगत हात, बोमा फायदां के सदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर हागा।

12. इस स्कोम क भ्रजात भ्राने वाले किसा सदस्य का मृत्यु होने पर भारतीय जोवन बोमा निगम, बोमाकृत राशि क हुकदार नामानवाशती/वाधक बारिसा की उस राशि का सवाय तत्परता स और श्रत्यक वशा में हर अकार से पूर्व वाके का आफ्त के एक माल क भातर सुनिधंवत करेगा।

|संबंधा एस- 35014/263/82-पोएफ-2 एस. एस-2|

S.O. 1049.—Whereas Messrs The Tiruchirappath District Co-operative Spinning Mills Limited, Karur, Trichy District, (1197000) (herematier referred to as the said establishment) nave applied for exemption under sub-section (2A) of section 1/ of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinatter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment or penetus under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more tavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 19/6 (hereinatter reterred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4261 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

- SCHEDULE

 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reason-able opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said esta-blishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/263/82-PF-II (SS-II)]

का०मा० 1650 मैसर्स टी०टी० इनवैस्टमेंटस एण्ड देखर्स प्राइवेट लि॰, बालो बन रोड, सन्जौर-613005 (टी॰ एन०/6839) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भ्रधीन छूट दिये जाने के लिये ध्रावेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक ग्राभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना हुँही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदें उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायवों से प्रधिक प्रनुकुल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के मधीन उन्हें मनुज्ञेय हैं ;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रधिसुचना संख्या कार् आ० 43 तारीख 9-12-1982 के भ्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध • **अनुसूची** में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से सीन वर्ष की ग्रावधि के लिये जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उपत स्कीम के सभी उपगन्धों के प्रधर्तन से छूट देती है।

प्रनुसुची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त त्रामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 को उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद, स्थापन के मुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई एसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या जक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदय के रूप में उसका नाम तुरक्त दर्ज करेगा और उसकी दावन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
 - 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अम्बीन अमुकूष हैं।
- 7ै सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अभीन संदेय रकम उस रकम से अम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में मन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अभीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक्ष वारिस/नामनिदें चित्री की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
 - 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी न संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि म्रायुक्त तामिलनाडु के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो-धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि म्रायुक्त, श्रपना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है, ग्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन खीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में ग्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दणा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के धन्तर्गत होते, बीमा फायबों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्रधीन भाने वाले किसी सदस्य की मृ्स्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावें की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

संख्या एस-35014/283/82-पी.एफ-2 एस.एस-2]

New Delhi, the 7th April, 1986

S.O. 1650.—Whereas Messrs T. T. Investment and Traders Private Limited, Vallaw One Road, Tanjore-613005 (TN| 6839) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Governenment is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exericse of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 43 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submis-

sion of teturns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the sabent features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provisions Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No: S-35014/283/82-PF-II (SS-II)]

का॰ आ॰ 1651: मैंसर्स जूपिटर रेडियो (रिज॰) सी-46, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली (डी॰एल०/3424) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिये जाने के लिये श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगमक्की जीवन बीमा स्कोम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय मरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) ब्रारा दिल्ल गिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रिधसूचना संख्या का॰ श्रा० 4031 तारीख 8-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपायद्ध श्रनुसूची में विनिद्धिट शतों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अविधि के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

ग्रन्सूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिष्य निधि ग्रायुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें,।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के श्रिधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय भादि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी अनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरत्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के स्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म-चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध

फायदे उन फायदों ने प्रश्चिक भ्रमुकूल हों. जो उक्त स्कीम के सधीन भ्रमुजेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारों की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में काई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, दिल्ला के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त श्रपना प्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर वेगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख़ के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में ग्रसफल रहता है, या पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम- निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त रकीम के ग्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिर्वेषिती/विधिक वारिसों की उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/230/82 पी०एफ०-2-एस०एस०-2]

S.O. 1651.—Whereas Messrs Jupiter Radios (Regd.) C-46. Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi-87 (DL/3434) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible

under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 the smaller referred to as the said Scheme?

Now, t erefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4031 dated the 8-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

- 1. The employer in relation to the said establishment thall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India,
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and where any amendment is likely to affect advetsely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to hapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in navment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[230]82-PF-II (SS-II)]

का०ग्रा० 1652.—मैंसर्स श्री वैंकटेसा मिल लि०, उदमलपेट पो०ग्रा०, 642128 उदमलपेट (टी०एन०/51) (जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त श्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रधीन छूट दिये जाने के लिये श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्राभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामुहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन कीमा के स्प में जो फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रधिसूचना संख्या का श्रा 320 तारीख 6-12-1982 के श्रनुसरण में और इससे उपावद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट णतौं के धधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 8-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 7-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपयन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भ्रनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त तीमलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जा केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निधिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक्ष मार की समाध्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के ग्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंत-गंत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, कीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरी-क्षण प्रशारों का संदाय ग्रादि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारायया भ्रनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का श्रनुवाद, स्वापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिविष्य निधि का या उक्त श्रधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते तुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अश्रीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त तिमलताडु के पूर्व ग्रायुक्त के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त, ग्रपना ग्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त ग्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक धीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, ऑरपालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्दे-शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न क्षी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीम के घंधीन घाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकवार नामनिर्देणिती/विधिक वारिसी को उस राणि का

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/490/82-पी. एफ.-2 एस.एस.-2]

S.O. 1652.—Whereas Messrs Shri Venkatesa Mills Limited, Jdumalpet, P.O. 642128 Udumelpet (TN/51) (hereinafter reterred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favor table to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 thereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers onfitted by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the nodification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 320 dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provision of the said Scheme for a further period of three years with effect from 8-1-1986 upto and inclusive of the 7-1-1989.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance-Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 24 GI[86—19]

- shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees—to explain their point of view.
- 9. Where, for any, reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shalf be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium e.c. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/400/82-PF-II (SS-II)]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

का.आ 1653 — मैंसर्स दि महसाता जिला सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटिङ, राजमहल रोड, महसाता (जी.जे./4654), (जिसे इसमें इमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आयेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचार, किसे पृथक ग्रामदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा के स्पर्भ जी प्रामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के स्पर्भ जी फायदा उठा रहे हैं ने ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से प्रधिक ग्रमुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के ग्रमीन उन्हें श्रमुक्केय हैं;

अतः केन्द्रीय भरकार, उका अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या था.आ. 3335 तारीख 27-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबढ़ अनुसूची में विनिर्दिष्ट णतों के अधीन रहते हुए, उका स्थापन को, 10-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी अपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

यनुसूर्चः

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त गुजरान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्शक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-ममय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों, का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रिय सणकार, उक्त अधिनिधम की धारा 17 को उपधाना (3क) के खण्ड (क) के अर्धन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, वेमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय प्रादि भी हैं, होने बाले सभी व्ययों का बहुत स्थितिक द्वारा किया जाएगा।
- ं नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुतंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधिका या उक्त श्रिधिनयम के ग्रधान छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हों, जो उक्त स्कीम के प्रधान प्रमुक्त हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सीचारी की उस दबा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देणिती की प्रतिकर के ख्या में दोनों रक्तों के अंतर के बरावर एकम का सदान करेगा!
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त तमिलनाडू के पूर्व अनुमीदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़न को संशोधन हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, शपना श्रनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन वीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे . स्थापन पहले प्रमना चुका है, श्रद्धीन नहीं रह जाते हैं,

- या इस स्कीम के ग्रधान कर्मचारियों को प्राप्त होने बाते फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकतो है।
- 10. यदि किमी कारणबल, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निराम द्वारा नियन तारंख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में शसफल रहता है, तो पालिसी को स्थमगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रंमियम के संघाय में किए गए किले! क्यतिक्रम की दणा में, उन गृत-सद्रस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारियों की जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्क्रांम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उन्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कॅम के अधान आने वाले किसे सदस्य की मृत्यु होने पर भारत य जावन बामा निगम, बामाइत राशि के हकदार नामनिर्देशित विधिक वारिसों की उस राशि का सदाय तत्परना से और प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भंतरसुनिश्चित करेगा!

[संख्या एस-35014/17/82-पो. एक. -2/एम. एस-2] New Dehi, the 8th April, 1986

S.O. 1653.—Whereas Messrs The Mahasana District Central Co-operative Bank Lunited, Rajmahal Road, Mehs na-1 (GI/4654) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution, or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3335 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissoner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India,
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the account that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is fixely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the I ife Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/17/82-PF.JJ(SS.II]

का. आ. 1654: -मैसर्स हिन्दुस्तान एवरीनाटिक्स लिमिटिड (बंगलीर कस्पर्णक्य) विमानपुरा, बंगलीर-17 (के.एन./24) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उत्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिने इसमें इसके पण्चात् उत्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केर्न्द्रिय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रक्तियाय या प्रोमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा नियम का जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बंमा स्कीम के अर्धन जंबन ब मा के रूप में जो फायदा 3ठा रहे हैं वे ऐस नर्मचारों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारों निक्षेप महबद्ध बंमा स्थाम, 1976 (जिसे इसके परचात् उक्त स्काम कहा गया है) के अर्धन अनुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गांक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ. 4251 तारीख 26-11-1982 के अगुसरण में और इसते उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट गती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमे 17-12-1988 भी सम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रन्यूच:

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियाजक प्रादिशक भानव्य निधि धायुक्त कर्नाटक को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीभण के चिह होसे सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्र'य सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, एसे निरक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास का ममापित के 15 दिन के भारतर संदाय करेगा जो केन्द्राय सरकार, उनत श्रधिनियम को धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- अ. सामृहिक बंमा स्कंम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना जिबरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बंभा प्रभियत का संघाय, लेखाओं का अंतरण, तिर क्षण प्रभारों का संघाय आदि भा है, होंगे वाले सभी ब्ययो का चहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियाजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें राशाबन किया जाए, तत्र उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वालों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रिधिनयम के श्रधीन छूट प्राप्त किसो स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियाजक सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुजित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्म-

चारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हां, जो उन्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी,
 यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के भवीन
 संदेय रक्षम उस रक्षम से कम हे जा कर्मचारी को उस
 बन्ना में संदेय होती है, जब वह उक्त स्कीम के भ्रधीन होता
 तो, नियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती
 को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षम के अंतर के बराबर
 रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिवष्य निधि ग्रायुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का श्रयना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसा कारणवर्ग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है, श्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हा जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकतो है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियाजक भारतीय जीवन भीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने मं असकल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है ता छूट रह को जा सकती है।
- 11. नियांजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह, छूट न दों गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, आमा फायदों के संवाय का उत्तर दायित्व नियाजक पर होंगा।
- 12. इस स्कीन कं प्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हकदार नामनिर्देशितयों विधिक वारिसों की उस राणि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्त के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एत.-35014/29/82-पी.एफ-2 एस. एस.-2]

S.O. 1654.—Whereas Messrs Hindustan Aeronautics Limited, (Bangalore Comptex) P.B. No. 1784, Vimanpura, Bangalore-17 (KN|24) (necemafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hercinafter referred to as the said Azt);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making

any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation India in the name of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the nonfication of the Government of India in the Ministry of Labour 5.O. 4251 dated the 20 11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more tavourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karrataka and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable oportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of detault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim coin plete in all respects.

[No. S-35014]29[82-PF, II (SS. II)]

का.आ. 1655:—मैसर्स मद्राम फोर्जिगंस एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लिपिटिड, (सी.बी.आई) कमेदिरी, कोयम्बट्रर-641104(टी.एन./5499), (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमेचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आयेवन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिला ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा नया है) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उनत अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3551 तारीख 23-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की, 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

धनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निवि भ्रायुक्त, तिमलनाडु को ऐसी विवर्राणयां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भातर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्राधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंत-गैत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत जाना

- बीमा प्रीसियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, ओ कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापत को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सायूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अधिक्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. वदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उस स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, लॉमलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मवारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रतिकृत भविष्य निधि भ्रायुक्त, भ्रपना भनुमोदन देन से पूर्व कर्मवारियों का अपना दृष्टिकाण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले ग्राप्ता चुका है, ग्राधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ग्राधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियस तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम संदाय करने में प्रसक्त रहता है, और पालिसी की ब्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए नए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्दे-श्वितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीम के श्रधीन श्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाइत राजि के इकवार नाम-निर्देशिता/विधिक धारितों का उस राजि का संवाब तत्परता से और प्रत्येक इसा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सब्या एस-3501 4/48/82-पी.एफ- Π एस.एस- Π]

S.O. 1635.—Whereas Messrs Madras Forgins and Allied Industies, Kamoderi, Coimbatore-641104 (TN|5499) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exempton under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinfater referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable o such employees than the beefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3551 dated 23-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-1985 upto and inclusive of the 8-10-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall aubmit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respec of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, it the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is fikely to effects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable Opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heurs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[48]82-PF.II(SS.II)]

का. भा. 1656:— मैसर्स निमेन्ट कार्पोरंशन धाफ इंडिया लिमिटीड 59, नेहरू प्लेग, नई विल्ली-110019 (डी. एल/ 2227) ((जिने इसमें इसके पश्चात् उत्तत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारो अविष्य निधि और प्रवीर्ण उपबाध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिने इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) को धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए धाबेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकुल हैं, जो कर्मचारी निकेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन अनुकुष हैं ;

मतः केन्द्रीय भरकार, उक्त प्रधितियम की धारा 17 की उपवारा (2क) द्वारा प्रदत्त ,णिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत भरकार के श्राप मंत्रालय को ग्रिधिसचना संबंधा का. ग्रा. 3728 त रोख 11-10-1982 के प्रमु-सरण में और इससे उपाबद अनुसूचों में विनिर्दिष्ट णतीं के अभीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 30-10-1985 से तीन वर्ष को श्रविध के लिए, जिसमें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कोम के सभी उपजन्धों के प्रचर्तन में छूट देती है।

धनुसूची

- उन्त स्थापन के संबंध में नियोशक प्रादेशिक शिवस्य निधि श्रायुक्त, जिल्लां, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीजण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीया प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निश्तिण प्रभारों का संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी क्यायों का वहन नियोंजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा श्रनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का श्रनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य शिक्ष का वा उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत ग्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्न करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के ब्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के ब्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के ब्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ब्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रनुक्रेय हैं!
- 7. साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के श्रधीन सन्देय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देह होती, जब बह उक्त स्कीम के श्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देगिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के श्रन्तर के तरावर रक्षम का सन्दाय करेगा।
- सामृहिक बीमा स्कीम के उपबृद्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिष्य निधि श्रांक्त, दिल्ली, के

- पूर्व अनुमोदन के बिता नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि ब्रायुक्त अपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त श्रयसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, जिसे भारतीय जियन बोमा निजम को उस सामूहिक बीमा स्काम के, जिसे स्थापन पहले प्रपता चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या स स्काम के प्रप्रा का कार्या है। का निज्य हो के प्राप्त का कार्या है। पानिस्ता है किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीर्मियम का सन्दाय करने में श्रसफल रहता है, और गालिसी को व्यक्ष्मत हो जाने दिया जाता है, ता छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी क्यतिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के श्रन्तगैत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के श्रधीन श्राने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूणं दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्चित् करेगा।

[संख्या एस-35014/84/82—पी. एफ.-II]

S.O. 1656.—Whereas Messrs Cement Corporation of India Limited, 59, Nebru Place, New Delhi-110019 (DL/2227) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 1% of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisons Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3728 dated the 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of the 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and

provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer small pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the tenefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members, covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heir of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/84/82-PF.II(SS.II)]

का० च 1657 — मैं पुर्स, एस. पी. श्राई. सी. नगर कोंगा, इंश केंदोा-628005 (टो. एन/9540) (वि इसमें इसके पश्चात् उनत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रभितियम, 1952 (1952 का 19) (जिस इसमें इतके पश्चात् उक्त प्रक्षितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रभीन धूट दिए जाने के लिए ग्रावदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स स्थापन के कर्मवारी, किसी पृथक श्रिभदाय या श्रीमिमम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सह-बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रोय अरकार, उक्त अधिनियम को भारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंद्रालय को अधिसूचना संख्या का. आ. 3501, तारोख 18-9-1982 में और इसमे उपाबद्ध अनुसूचा में निर्निद्ध यर्ती के अभीन रहते हुए, उक्त स्थापन की, 2-10-1985 में तीन वर्ष की अवधि के लिए, निर्मां 1-10-1988 भी सम्मिलत है, उक्त स्थाम के समी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट दती है।

ग्रनुसूची

- ग. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक मिवष्य निधि श्रायुक्त- निमलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सनय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्ये ह नास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जा केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की श्रारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के श्रधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंत-गैत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा शिवियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरी-क्षण प्रभारों का संदाय भ्रादि भो है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजन हारा किया जाएगा।
- .4. नियोजक. केन्द्रीय ग्रस्कार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोध धन किया जरए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वार्तों का अनुवाद स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मवारी अविषय निधि का या उत्तत अभिनियम के धधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूक में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और

उसकी बाबत भ्रावण्यक श्रीमियम भारतीय जीवन वीमा निगम को संवक्त करेगा।

- 6. यदि सामूहिक वीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक वीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों मे प्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के ग्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेय होती, जब बह उक्त स्कीम के ग्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9 यदि िसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी ध्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के प्रधीन श्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय नत्परता और प्रत्येक दशा में हर प्रकार मे पूर्ण दाबे की प्रास्थित के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/81/82-फी एस-2 एस. एस.-2] 24 GI|86—20 S.O. 1657.—Whereas Messrs SPIC Nagar Council Tuticorin-628005 (TN/9540) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the sad Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3501 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of the 1-10-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-secion (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insuracne Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Com-

missioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group fusurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[86[82-PF.II(SS.II)]

का. श्रा. 1658.- - मैसर्स इन्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड श्रनुपुरम पी. बी. नं.-30, कोलमलरी-683104-- केरल (के. श्रार/35) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रिधीन छूट दिए जाने के लिए श्रीवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों की उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. श्रा. 907 नारीख 8-2-1982 के श्रनुसरण में और इमसे उपाबद्ध प्रनुसूचों में विनिर्दिष्ट गर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थाधन को, 27-2-1985 से तीन वर्ष की ग्रवधि के लिए जिसमें 26-2-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निश्चि आयुक्त, केरल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्काम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आवि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया आए, जब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी गुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीम स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम जुरन्त दर्ज करेगा और उसके ब्याव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बोमा निगम को संदत्त ंरेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधोन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन वनक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दिशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्राविशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाध पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मधारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अयसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापम के कर्मचारी, भारतीय जीवन क्षीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के

जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकतो है।

- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जासकता है।
- 11. नियोजक क्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ यदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन अने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय नत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/104/81-पी०एस० 2-एस०एस०-2]

S.O. 1658.—Whereas Messrs Indian Aluminium Conspany Limited, Alupuram, P.B. No. 30, Kalamasery-683104 (KR|35) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said A-t);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heerinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 907 dated the 8-2-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 27-2-1985 upto and inclusive of the 26-2-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 Jays from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enror him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of Indu.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the vaid Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and where any amendment is likely to affects adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is limbe to be canceled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of promium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal leirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014]104[81-PF. II(SS. II]

का. था. 1659:—मैंसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. पिन्जोर, भ्रम्बाला (हरियाणा) (पी. एन./34429) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनि मा, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा श्रया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के श्रधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय संस्कार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या द्रीभियम का संदाय किए जिना ही, भारतीय कीवन कामा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1975 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेप हैं;

ग्रतः केन्द्राय सरकार, उक्त ग्रधिनियम को बारा 17 को उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गिनिनयों का प्रयाग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रधिस्चना संख्या का. भा. 2943 तारोख 4-8-1982 के श्रमुसरण में और इससे उपावद्ध श्रमुसूचा में विनिर्दिष्ट गर्तों के ग्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 21-8-1985 से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए जिसमें 20-8-1988 भा सम्मिलित है, उक्त स्थाम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसुची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निश्चि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक हारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, जब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कैमंचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक जीवन बीमा स्कीम के अबीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मभंचारियों के खिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन

उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उनत स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी,
 यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय
 रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दमा में संदेय
 होतो, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक
 कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितो को प्रतिकर के
 रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय
 करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बीमा म्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मवारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीम। निगम बारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती हैं।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए किसी व्यक्तिकम की दणा में, उन मृत-सदस्थों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन अने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाफृत राणि के हुकवार नाम निर्देशितियों/विधिक बारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावें की प्राप्ति के एक भास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/117/82-पी . एफ . 2-एस. एस .-2]

S.O. 1659.—Whereas Messrs Hindustan Machine Tools Limited, Pinjore, Ambala (Haryana) (PN 3429) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 19/6 (hereinafter reserved to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2943 dated the 4-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a turther period of three years with effect from 21-8-1985 upto and inclusive of the 20-8-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident. Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance prensia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident band or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately curol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approvar of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any tenson, the employer fail, to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Instrumed Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, it any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the life insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[117]82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 1660:—मैंसर्स, एलोडाक डिस्ट्रिब्यूटर्स, ईसानपुर प्रहमदाबाद-382443 (जी. जी./10832) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपजन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निकाप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रय हैं;

श्रतः केन्द्रीय रारकार उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रधिसूचना संख्या का. श्रा. 3051 तारीख 17-8-1982 के श्रमुसरण में और इसे उपावद श्रमुस्या में विनिर्दिष्ट शर्ती के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 28-8-1985 के तीन वर्ष की श्रवाध के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्थीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से खूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-सनय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारीका संदाय गादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. मिरोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के निथमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना बृद्धिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंग, स्थायन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वांग नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 1.1. लियोजक द्वारा प्राप्तियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नाम-

मिर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि के हक्षदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राणि का संदाय तत्परता से ऑर प्रत्येक दशा में हुर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सूनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/134/82-पी.एफ. 2-एस.एस-2]

S.O. 1660.—Whereas Messrs Alidac Distributors, Isonpur, Ahmedabad-382443 (GI/10832) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3051 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees

under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Grono Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Whereas, for any reason, the employess of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of india, and the policy is allowed to Japse, the exemption is liable to be cancelled
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt gayment of the suny assured to the nomines or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|134|82-PF, II(SS, U)]

का. ग्रा. 1661:— मैसर्स टिटेनियम इक्यूपमैन्ट एन्ड एनोडे मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बन्दालुर-मद्रास (टी एन/8597) (जिसे इसमें इसके पण्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध प्रधित्तियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पण्चाह उक्त प्रधितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रधीन छूट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रेय हैं;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की अधिसूचना संख्या का. ग्रा. 3400 तारीख 9-9-1982 के भनुसरण में और इतसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के अधीन एहते हुए, उक्त स्थापन की, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपअन्धीं की प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसू ची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रधान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मेचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अमृकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्चेय हैं।
- 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मकारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, क्योजक कर्मकारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती की प्रति-कर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रक्तम कर संवाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में काई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट यह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीलर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि, यह छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकवार नामनिर्देशिती/विधिक वारिमों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस--35014/156/82-- भी . एफ .- 2 एस . एस-2]

S.O. 1661.—Whereas Messrs Thanium Equipment and Anode Manufacturing Company Limited. Vandalur, Madras-45 (TN|8597) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premiurs, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conforred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3400 dated the 9-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1938.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately eurof him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Whereas, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of Lagra, and the policy is allowed to Japse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the croployer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sung assured to the nomines or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

का. आ. 1662: -- मैंसर्स डी सी एम. इंजीनिरंग प्रोडेक्टस, पी. बी.-5, रोपर-140001 (पंजाब) (पी. एन/5959) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा था है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा रकीम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से ग्रधिक श्रनुकूल हैं, जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन श्रनुक्रेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) बारा प्रदक्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4083 तारीख 13-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिधिष्ट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अविध के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सिम्मिलत है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

श्रनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिष्ठिय निधि ध्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उंक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का भ्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय भ्रावि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त श्रधिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन् में 24 GI 86—21

- नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दन्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के ग्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से ग्रधिक ग्रनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन ग्रनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होतातो, नियोजक, कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त पंजाब के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि ग्रायुक्त, ग्रयना ग्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में भसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक बारिसी को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के भ्रन्तर्गत होते, बीमा फायवों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के श्रधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेंगा ।

[संख्या एस-35014/245/82-47.एफ.-2-एस०एस०-2]

S.O. 1662.—Whereas Messrs DCM Engineering Products, P.B. No. 5, Ropar—140001 Punjab (PN|5959), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exexemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4083 dated the '3-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspecion as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately carol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be rayable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirlnomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Puniah and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any male is the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt rayment of the sum assured to the nominee of the Legal being of the deceased member entitled for it and many case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014[245]82-PF.II(SS.II)]

का०ग्रा० 1663:— मैसर्स श्रीराम रेमन्स, श्रीराम नगर कोटा-320004 (ग्रार०जे०/1128) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त ग्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रिधीन छूट दिये जाने के लिये ग्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रिमदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामृहिक बीमा स्कीम के ग्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायवों ने श्रधिक श्रनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन श्रमुक्रंय हैं;

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रधिसूचना संख्या का॰ भ्रा० 4070 तारीख 12-11-1982 के श्रनुसरण में और इससे उपायद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के ग्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की श्रविध के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सिम्मलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, राजस्थान को ऐसीविषरणियां भजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्राय नरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धन्तर्गत दिखाओं का रखा जाना, विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रोमियम का संदाय, जिखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय धादि भी हैं, होने विज सभी व्ययों का वहनं नियोजक द्वारा किया जायेगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रोथ नरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बोमा स्कोम के नियमों को एक प्रति, और गब कभो उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म-चारियों को बहुसंख्या को भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उपत श्रिधिनयम के श्रिधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कोम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत श्रावश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि तामूहिक बोमा स्कीम के प्रधोन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जात हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के प्रधोन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप स बृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये जामूहिक बोमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक प्रमुक्त हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रमुक्तेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भो, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होतो जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियागक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिसी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के भ्रन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. लामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी रांग्रोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी शंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, अपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्त्रष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. विद किसो कारणवश, स्थापन के कर्मचारो, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहने अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले

- फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकतो है।
- 10. यदि किसो कारणवण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सा, छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदार में किये गये किसी व्यविक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के श्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायांत्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राणि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दणा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

संख्या एस-35014/276/82 पी.एफ.-2-एस०एस०-2]

S.O. 1663.—Whereas Messrs Shriram Rayons, Shriram Nagar, Kota-4 (RJ/1128) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4070 dated the 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employed been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/276/82-PF-II (SS-II)]

क.शा. 1664—मैसर्स पांडियान रोडवेज कार्पोरेशन लिमिटेड, मदुराई (टी॰एन॰/6882) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के ग्रिधीन छूट दिये जाने के लिये श्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारों किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदार्श किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारो निक्षेप सहबद्ध र्वःमा स्कोम, 1976 (जिसे इसके पश्चास उक्तस्कोम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ग्रिधसूचना संख्या का॰भा॰ 4064 तारीख 11-11-1982 के भ्रनुसरण में और इससे उपाबद श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की भ्रविध के लिये जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसो विवरणिया भजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरंक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रंथ सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्ति के 15 दिन के मीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, विभा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षक प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुभोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन की प्रति जाए, जब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मवारियों की बहुसंख्या इस भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविशित्त करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक साभूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सन्दर्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुवित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

- 7. सामूहिन वंभा स्कंम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसा कर्मचारों की मृत्यु पर इस स्कंम के अध न सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारों की उस दशा में संदेथ होती जब यह उकत स्कोम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारों के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्सर के बरावर रक्षम का सन्दाय करेगा।
- 8. सामूहिक स्कंम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसे संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृल प्रमाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय किन बोमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की द्वारा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक यारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्वेशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(278)/82-पी. एफ-2-एस एस-2]

S.O. 1664.—Whereas Messrs Pandian Roadways Corporation Limited, Madurai (TN/6882) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4064 dated the 11-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable and employee been covered under the said Scheme; the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insutance Scheme of the Life Insurance Corgoration of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but, for grant of this exemption, shalf be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in

any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/278/82-PF-II (SS-II)]

का ब्या व 1665—मैंसर्स फैसिट एशिया लिमिटेड, पैरुनगुह्डी, मद्रास-600096 (टी ब्एन व / 4805) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्म् वारी भविष्य
निधि और प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है)
की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिये जाने
के लिये प्रावेदन किया है;

और केन्द्रेय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचार, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्णात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुक्रेय हैं;

ब्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्यः का०श्रा० 44 तारीख 9-12-1982 के श्रनुसरण में और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शतीं के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की श्रविध के लिये जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूर्चः

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक मिविष्य निधि आयुक्त तमिल नामु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रधान करेगा जो केन्द्रांय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।
- 2. नियाजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्देश्वर करें।
- 3. साभूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, नियरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरोक्षण प्रभारों का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा अनुभोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन की प्रति अपन कर्म-आरियों की बहुसंख्या को भाषा में उसकी भुद्धय बासों का अनुबाद, स्थापन के सुखना पट्ट पर प्रविश्वत करेगा।

- 5. यिष कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्किय निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।
- 7 सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब बहु उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशिती जो प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय, करेगा।
- 8 सामूहिक बंभा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक अविष्य निधि आयुक्त तमिल नाषु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्भचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने को सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मधारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रिति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जासकती है।
- 10. यदि भिसी कारणवश, नियोजकः भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के माम निर्देणितियों या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होनी तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायवों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा
- 12. इस स्कोम के अबीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हरुदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/282/82-पी. एफ 2-एस.एस-2]

S.O. 1665.—Whereas Messrs Facit Asia Limited, Perungudi, Madras-600096 (TN/4805) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Contral Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or nayment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 44 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer,
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in has establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already a opted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the remium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lanse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in rayment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/282/82-PF-II (SS-II)]

का. आ. 1666—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स मैटिरियल प्रोटैक्शन एजेन्सी, रूम नं. 3, कोयप्पा बिह्डिंग, पो. नलयालम काल कट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगकरते हुए उक्त ग्रिधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (151)/86-एस.एस.-2]

S.O. 1666.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Material Protection Agency. Room No. 3. Koyappa Building, P.O. Nallalam, Calicut have agreed that the Frovisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[Nq. S-35019(151)/86-SS-II]

का. था. 1667. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंसर्स कोन्टोनेन्टल प्राटो एन. सी. लेरी लिमिटिड यूनिट प्राईषर प्रीशीयन मणीन्स प्लाट न. 75 सेक्टर 6, फरीदांबाद 121006, हरियाणा और इसका 16 ब्रासफ पत्नी रोड, नई दिल्ली, 110002 स्थित रिज. कार्यानामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु- गंड्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उकत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

स्रतः केरद्रीत सरकार, उक्त स्रधिनियम की धारा 1 को उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्रिप्तियम के अपबंध अन्त स्थापन को लागू करते? है।

S.O. 1667.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Continental Auto Ancillary Limited. Unit-Eicher Precision Machines, Plot No. 75, Sector 6, Faridabad-121006, Haryana including its Regd. Office at 16 Asaf Ali Road, New Delhi-110002 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(149)/86-SS-II]

का. या. 1668. - --केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीस होता है कि फलोबैल पलाम्बिग एण्ड फिक्कर कम्पनी, ओल्ड नजफगढ़ रोड, गुड़गांव और इसकी जबाहर नगर दिल्ली-110007, स्थित णाखा। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म-चारियों की बहुनंख्या इस बात पर सहमत ही गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को सागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार अक्त अधिनियम की धारा 1 को अपधारा (4) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अक्त अधिनियम के अपबंध अक्त स्थापन को लागू करती है।

S.O. 1668.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s Flowell Plumbing and Fixture Company, Old Najafgarh Road, Gurgaon, including its branch at Jawahar Nagar, Delhi-110007 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(148)/86-SS-II]

का. श्रा. 1669 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लैम्पस एण्ड लाइटिंग लिमिटिंड उपत्सया इंडस्ट्रीयल एरिया, ग्रालवर (राजस्थान) और इसका 1101, नई विल्ली हाऊस 26, बाराखम्बा रोड, नई विल्ली स्थित मुख्य कार्यालय, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु-

मंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध भ्रधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम के धारा 1 को उपधारा (4) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

S.O. 1669.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Langs and Lighting Limited, 3, Matsya Industrial Area, Alwar (Raj.) including its Head Office at 1101, New Delhi House-27, Barakhamba Road, New Delhi, have agreed, that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(147)/86-SS-II]

का. थ्रा. 1670:—केन्द्रोय सरकार को यह प्रतीत होता है के मैसर्स रेशिम ट्रिस्ट होम, हिल पैलेस रोड, चाथारो, तिरूपुनीयुरा-682301, नदमा गांव, कन्यानूर ताल्लुक, धरनकुल्लाम कस्वा केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रोघ मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

S.O. 1670.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Reshmi Tourist Home, Hill Palace Road, Chathari, Tripunithura-682301, Nadama Village, Kanayannur Taluk, Ernakulam Distt. Kerala have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellanecus Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(150)/86-SS-II]
A. K. BHATTARAL Under Secy.

नई चिल्ली, 4 अप्रैल, 1986

का. आ. 1671. — आंद्यींगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 को अनुसरण में, कोन्द्रीय सरकार इलाल हाइड्रो इलींक्ट्रक प्रोजेक्ट के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में दिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के गंचाट को प्रकाशित करती हैं, जो कोन्द्रीय सरकार कर 24 मार्च, 1986 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 42012/57/83-डा-2(बी)]

New Delhi, the 4th April, 1986

S.O. 1671.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Indusgrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Salat Hydro Electric Project and their workmen which was received by the Central Government on the 24th March, 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. J.D. 27 of 1984

PARTIES:

Employers in relation to the management of Salal Hydro Electric Project

AND

Their Workman : Shingara Singh

APPEARANCES:

For the Employers : Shri J. N. Kochhai

For the Workman : Shri R. K. Singh

INDUSTRY: Hydro Electric Project STATE · J & K

AWARD

Dated the 19th of March, 1986

The Central Government, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act per their Order No. L-42012(57) 83-D.II(B), dated the 12th of July, 1984 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

- "Whether the termination of employment of Shri Shingara Singh, Foreman by the Management of Salal Hydro Electric Project with effect from 27-5-83 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"
- 2. The petitioner-workman Shingara Singh joined services at the Respdt, Salal Hydro Project as a Foreman Special on 10-7-1978 and worked there as such till 16-11-1981 when he proceeded on 15 days medical leave. According to the petitioner his illness got prolonged and therefore he sought extension of leave by sending periodical requests to the management but for the reasons better known to them, they did not respond to his correspondence. However, after recovery he reported for duty on 27-5-1983 and produced all the relevant medical certificates regarding his illness as well as subsequent Fitness but they did not re-act favourably and ultimately dispensed with his services under the impunged order dated 29-10-1983 even though the concerned Assit. Engineer had recommended regularisation of his services on condoning the absence in view of their own requirements besides his satisfactory work and conduct. The petitioner thus complained that the management acted illegally in terminating his services without complying with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act 1947 as neither prior notice nor terminal benefits were given to him 24 GI/86-22.

- that otherwise also they had no justification for disengaging him when some of his juniors were still working on the Prosect.
- 3. Contesting the petitioner's story, the management accused him of voluntarily abandining the job without intimating his intentions at any stage. It was averred that even though the petitioner had proceeded on sanctioned leave up to 30-11-1981 yet he never sought any extension and so much so that he did not even apprise them of his whereabouts till one fine morning when after a lapse of almost 1-1/2 year he appeared before them on 31-5-1983 seeking condonation of absence and regularisation of his services on the ground that during the meanwhile he had fallen sick. Elaborating their version the management submitted that on 2-7-1982 a memorandum, calling upon the petitioner to resume duty within 15 days, was sent on his home address under a registered cover but received back undelivered with the endorsement of the postal authorities that he had left his home without leaving behind any trace; thus forced by the circumstances they had no option but to dispense with his services under Model Standing Order No. 6(iii) applicable to the Project for doing away with the services of such employees who abstain themself for more than 10 days witout any prior intimation or permission.
- 4. The controversy between the parties could not be amicably settled despite the intervention of the A.L.C.(C) at the Conciliation stage and hence the reference.
- 5. In support of his case the petitioner examined himself whereas the management produced their Personnal Manager Shri J. N. Kochhar and one Gulshan Chaudhary, Liason Officer of Mls. Som Dutt Builders New Delhi; of course, both the parties filed a number of documents also whose authenticity was not disputed from either side.
- 6. On a careful scrutiny of the entire available data and hearing the parties I am inclined to sustain the Management's view point that the retifioner had voluntarily abandoned the job in search of green pastures. The pertinent point is that on his own showing he did not attend the Project after 15-11-1981 and even though his absence up to 30-11-1981 was on account of sanctioned medical leave yet no further Medical certificate was submitted by him during the period of this absence. Under the weight of oath, in his cross-evanuination, the petitioner admitted that he did not inform his employer about his indhiana address despite his assertion that during this period he was living there: of course he claimed having produced all the medical certificates in a hunch at the time of reporting for duty after recovery from sickness; but by necessary implication he conceded that at no stage of his absence, he had ever submitted any medical certificate to the management on the basis of which they could assum that he was realy down with some or the other disease, or that he was living away from his home where they could contact him.
- 7. Against such back drop their version projected in the evidence of Shri J. N. Kochhar that the registered memo dated 2-7-1982 calling upon the petitioner to resume duty within 15 days was returned by the Postal authorities undelivered from his home address with the remarks that the whereabouts of the addressee were not known gains credibility for the obvious reason.
- 8. The next chain of evidence is available in the denosition of Gulshan Chandharv of Mls Som Dutt Builders who produced the documents Fx. M2 to M7 to show that us a reafter of fact during all this while the netitioner was working abroad under them in Baghdad (Iran). It was in response to the management's query Fx. M2 dated 8-5-1983 that they confirmed the proposition of his having left India on 22-11-1981 for Iran with nassport No. 1-777449 on recruitment as a Machinic Forenan. Lecter Ex. M4¹A dated 3-11-1981 shows that the petitioner was in clandestine correspondence with Ms. Som Dutt Builders for taking up a foreign assignment under them. Similarly from the documents Ex. M4, M5, M6 and M7 there remains no manner of doubt about the retitioner's recruitment by Mls. Sor Dutt Builders and ultimate solourn to Iran. And it eves without saving that et no stace he cared to inform his existing employer i.e. Resedt. Project about his venture.
- 9. On behalf of the petitioner it was argued that the person Shingara Singh sent by Mis. Scm Dutt Builders to Iraq

could be some other worker carrying the same name. But the submission is completely devoid of force because from the documents Ex2 M4/A; Ex. M6 and M7 it is abundantly clear that it was the same very Shingara Singh who is the petitioner in these proceedings before the Tribunal with whom Mls. Som Datt Builders were dealing. It is besides the point that the documents Ex. M2 and M3 have a significance of their own in removing all the element of doubt regarding the identity of the paradoner Shingara Singh as the person who had actually taken the forcing assignment under M/s. Som Dutt Builders and proceeded to Iraq during the relevant period i.e. when the remained absent from the Salal Project.

- 10. I, therefore, find no impropriety in the Management's action in refusing to condone his absence from duty; and then terminating his services under Rule 6/iii) of the Model Standing Orders on the assumption of his having voluntarily abandoned the 10b regardless of their own requirements and his past conduct or credentials.
- 11. However, in so far as the terminal benefits are concerned I think the same should have been paid to the petitioner even though he had abandoned the job on his own notion after 30-11-1981 as meanwhile he had proceeded on the foreign assignment as mentioned hereinbefore. The primary consideration is that by then the petitiener had put in more than 240 days of continuous, service within the preceding 12 calendar months and by the time of passing of the formal orders of disengagement he had returned to India. I, therefore, direct the Management to accord him all the terminal benefits with in the next two menths on the assumption that he had served them from 10-7.78 upto 30-11-81.
- 12. Award returned accordingly.

CHANDIGARH, 19-3-1986

> I, P. VASISHTH, Presiding Officer [No. I-42012]57[83-D,H(B)] HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 म्राप्रैल, 1986

का. ग्रा. 1672:—औद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की घारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्षकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर (यू. पी.) के पंचाट को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्रकाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-3-86 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/6/82-एफ. सी. आई. बी. -IV(0)]

New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1672.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur (U.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Lucknow, and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th March, 1986.

BEFORE SHRI R B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVFRNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

PRESPNTS:

Shri Shakeel representative-for Workman.

Shri R. R. Mansingh representative—for Management.

Industrial Dispute No. 5 of 1983

Reference No: L-42011(6)|82-FCI-DIV(A) dt. 17-9-82, In the matter of dispute

BETWEEN

The President Bhartiya Khadya Mazdoor Sangh, 1 Abdul Aziz Road, Lucknow.

AND

The Senior Regional Manager Food Corporation of India 6/7 Haibibullah Estate, Lucknow.

AWARD

- 1. The Central Government Ministry of Labour, vide its notification no. L-42011(6)|82-FCI-D. IV(A) dt. 17th September, 1982, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;
 - Whether the action of the senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow in nor regularising the services of 54 workmen whose names are mentioned in the annexure, and not bringing them on regular scale of pay is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?
- 2. It is common ground that the 54 workmen mentioned in the reference orders annexure are working at the management the establishment of dal mill is a permanent Mill of vorking since 1976 atleast. According to the claim statement the establishment of dal mill is a permanent Mill of the management and the work of the establishment is also permanent in nature and the workman working without any break in service. All these workers are directly paid their wages by the management and the management has also paid them bonus in the past years. It is further averted that besides the workmen about 203 more workers are working in the said Dal Mill and have been declared regular after completion of 240 days of work w.e.f. 15th June, 1973, that the workmen in question here have all completed 240 days of continuous service in a calender year. That under the FCI Staff rules and regulation 1971 wherein it is laid down that no person will be employed on temporary basis after more than a years service in the corporation, that regularising service of other workmen from 15-6-73 and refusing the 54 workmen the same benefits and pay scales at the son place of work is discriminatory and in the end it is prayed that the workmen be declared regular and be allowed benefits of regular scale of pay and DA etc.
- 3. The management has contested the case of the applicants on the ground that the workmen are all daily rated casual workers and that the nature of the work at Dai Mill is that it is not warranted to be run continuously nor its working renders it possible to make services of its workers permanent and that those casual rated workers can not be equivated with denartmental workers and that the processing plant of Dai Mill cannot be equivated with the depot handling food grains as the function in the later case are regular functions and that the working in Dai Mill does not make these casual workers a permanent workmen having regular status. It is also averted that the work in the Dai Mill is not of a continuous nature and is permanent on several factors. According to the management this Dai Mill workers are functioning within the frame work of factorles Act workers and Dai Mill workers are being paid their legal wages under LP Minimum Wages Act. It is further averted that these 54 workmen are being paid weekly holiday wages, wages for national holiday etc. and not utilised beyond working hours. It is consequently prayed that the claim be dismissed.
- 4. In the rejoinder it is averred on behalf of the workmen that in their identification card management has defined them only as daily rated worker and not as casual labour and that afteer completion of 240 days of work in a calender year they are entitled to get all benefits of regular employees. This being not given to them is discrimination on the part of the management.
- 5. In support of its contention a number of documents have been filed on behalf of the workmen. Annexure I dt. 6-7-84, is letter of the District Manager to the Acett. Manager FSD Talkatora asking him to release payment of lay off to all eligible daily workers as per law who have put in 240 days service or more at the time they were laid off unto maximum of 45 days in a vear counting from the day when the workman were first laid off, Annexure II have record of workman Asharfii Lal showing that in the year 1979 he had not in 261 days of work and was paid for 21 days for lay off making the total 288 and

that he had asked 14 days leave, in year 1980 he had worked for 240 days and was laid off total 283 days and in all he earned 14 days leave ruising the total due to 28 days. Similarly Annexure III is to leave account of Ram Autar II who had put in including the days of laid off 284 days work in 1979 and 289 days work in 80 raising hi, leave to 29 days and that in the year 1981 (March) he had put in 73 days of work. They have further filed wage slip IV A to IV-D of A Shri Asharii Lal, Sudhir Kumar, Santram and Man Bahadur, all of whom worked for full month in July 84 and paid basic pay Ra. 240-25 besides DA EF CPF were given to them and ESI EPF CPF and ESI were deducted from their total emoluments.

- 6. The workmen have further filed photo copies of their identification card annexure SI to SIII showing that Sudbir Kumar and Hanuman are working in Dal Mill Talkatora. It may be mentioned that Ram Autar II and Hanuman are not mentioned in the annexure of the reference order. The photo copy of the agreement annexure 6 between the management and Shri M. Shakeel President of the Worker's Union of Dal Mili whereby the management agreed to give compensation for lay off as well as annual leave with wages w.e.f. 1-1-79 and that lay off to be paid for actually laid off period subject to the maximum of 20 days in calender year. Annexure 8 is the letter dt. 5-7-84 of the Joint Manager addressed District Manager Food Corporation of India, Lucknow, wherein he intimated it has now have been decided to pay to pay laid off compensation to all eligible workers as per law who put in 240 or more in service at the time they were laid off i.e. upto the maximum of 45 days in a year counting from the date when the workmen were first laid off. Annexure 7-A to 7-D is the original wage slip for July 83 of workman Santram, Guru Prasad, Omkar Nath and M. B. Wasi, showing that they all worked for full 31 days and besides basic pay at the rate of Rs. 240 were paid, Annexure IX is the wage slip of Mewalal Sharafatullah, R. K. Dubey for the month of August, 1980. Annexure 10 and 11 are the office order labour Ram Sagar Savita and Hari and none of them were mentioned as workmen in the reference order, out of the workmen Uma Shanker Sudhir Kumar have filed their affidavit that they have worked for more than 240 days were same persons namely Bari Prasad Mohd. Wasi and Ram Sagar have filed their affidavit but their names does not appear in the reference order.
- 7. The management got its written statement amended by adding paragraph 14 A and took the plea that out of 54 workers mentioned in Annexure I it has been contended that S|Shri Raghai Saran (Sl. No. 30), Mohishwar (Sl. No. 33), Rajendra Prasad (Sl. No. 35) Pesh Raj (Sl. No. 37), Menauna (Sl. No. 42), Mohi Lal (Sl. No. 46) and Vinod Kumar (Sl. No. 50) were neither engaged by corporation in any capacity during the relevant period commencing from 76 and that Arun Kumar Singh (1) worked as daily rated worker for one year in 1976. The names of Shri Ram Sajeewan, Sant Ram, Pyare Lal, Vijai Kumar I and Rameshwar have been mentioned twice in the reference order.
- 8. The workman have further filed the pay slips of Kalloo annexure 13 whose name does not appear in the reference order, photo copy of the leave record of Rameshwar II showing that in the year 1979 including lay off he worked for 288 days, and in the year 1980 he worked for 248 days and lastly in 81 he worked for more than 240 days. Annexure 14B is the leave record of Shri R. P. Dwevedi showing that he worked for 285 days in 79, 289 days in 80 and about 240 days in 1981. Annexure 14 C is leave record of Sant Ram showing that in 79 he worked for 269 days in 80, 103 days and about 240 days in 81, Annexure 14D is recorded of one Melu Lal who too worked for more than 240 days in 79, similarly 1980 about 80 days in 81 233 days but his name does not appear in the reference order. Similarly leave record of Moneshwar have been filed who has worked almost in similar way since 1979 but his name does not appear in the reference order, and lastly annexure 14K is leave record of Radhey Shyam whose name also does not appear in the reference order though he worked since 1979. Annexure 16 is settlement for payment of wages with leave. Muneshwar and Radhey Shyam have filed their affidavit testifying that they are working in Dal Mill since 1976, but their names does not appeared in the reference order beside Sant Ram has filed his affidavit that he is working. Dal Mill since 1979 and he had completed

240 days alongwith other workman and that they were all getting only leave bonus D. A. lay off compensation weekly nondays and CFF etc.

- 9. Workman has further filed annexure 18 showing that bonus was paid to the workmen of FCI Talkatora Dall Mill Lucknow. In this letter it was specifically mentioned by the General Manager to the Asstt. Labour Commissioner that he head office had issued instruction for payment of exgratia bonus at the rate of 8.33 per cent to the casual employee of the corporation for the year 1977-78, annexure 19 agreement showing that the management entered into agreement with the president of Dal Mill Workers Union regarding payment of bonus to casual workers and other workers of Dal Mills.
- 10. On the other hand the management have filed elocureent alongwith annexure and also along the the affidavit of Shri D. C. Gupta the District Manager of the management Corporation at Lucknow. He has filed the attendance cum pay sheet of the workers of Dall Mills for the month of July 80 which relates 75 workers, they were paid their wages on daily rate wages for the number of days worked by them, he has further filed the copy of bill regarding payments made to the respective 72 workers for the month end year 1981, showing that besides wages at the daily rate they were also paid DA at the rate of 60.90 per month. He stated in his statement that the functioning of the dall mill depends upon the availability of raw materials and it has it lean parts when most of the casual workers not given any work. He however admits that since 1985 on account of stability of stocks the casual workers are being provided work daily. In cross examination Shri A. C. Gupta District Manager of the management corporation has admitted that all those workman whose photo copies of attendance register he has filed for the month of January 80 working in Dal Mill in 1978 also and that CPF deduction is made from them. He further admits that out of the 54 workmen only some one were distributed lay off compensation, he expressed his ignorance as to whether only leave with wages are given to the workmen or not and further admitted that we are giving weekly holidays to the workmen.
- 11. The workman had summoned some of the documents mentioned in the application from the management which they never produced ultimately Shri M. Shakeer filed his own affidavit testifying that he admitted the signatures of persons mentioned in the affidavit which names and signatures corroborated to the documents of agreement and orders copies of which he had filed.
- 12. On behalf of the workman three witnesses out them several had given their affidavit appeared in witness box one of them is Shri Santram WW-1. He has deposed in cross examination that he and one Badri Prasad worked for operating the machine beside it his work is to spread dal, get it dried and filling in bags and that both of them lifet bags also. He states that in the reference order Moheshwar wrongly written to Moneshwar and who is working in the Dal Mill. and that Rajendra Prasad Trivedi is also working there. If it was a fact and in view of the averments of the management that he never appeared after 1976 the union has filed the photo copy of his leave account annexure 14B which shows that he worked for 285 days in 79, 289 days in 80 and about 240 days in 80 and about 240 days in 1981. He has also stated that Pesh Raj is wrongly written in reference order for Desh Raj. He has however admitted that there is no Munauna or Munna or Vinod Kumar in the Dal Mill. He states that he is working in the Dal Mill since 1977 and that he is paid Rs. 240 as basic plus DA total Rs. 300 for the month. He has denied that his monthly payment is made to him after calculating daily wages. He however admits ihat the pay for the day or absence is deducted.

- 13. The other workman is Ram Sagar who gave affidavit and has been examined but his name does not appear in the reference order, he too deposes that he is working in the Dal Mill since 1977, but is not in the category of loader. He also gets the payment for the days he works besides holidays and Sundays and for sanctioned leave. He further states that Dal Mill is mill which works for the entire year dependent upon the availability of Dal. He denied management's suggestion that the mill is working on seasonal basis depending upon the availability of the Dal.
- 14. Mr. Shakeel was cross examineed. He stated that in his affidavit he has wrongly written A. K. Towari instead of L. K. Tewari who was Dyputy Manager in the management. On the date of cross examination he filed some otiginal documents two of which are identity card of workman Sudhir Kumar and Sant Ram showing that they are daily workers of Dal Mill and their original record regarding leave of Sant Ram, Sudhir Kumar, Radhoy Shyam Muncshwar, Muncshwar as observed earlier is not mentioned in the reference order, though according to Sant Rans and document filed it appears that he is working since 79 and put in relevant years more than 240 days of work. Similarly Radhey Shyam's name is not in the reference order and it. is alleged that his name has wrongly written as Raghai Saran.
- 15. On the point if Dal Mill is seasonal i.e. running only in some part of the year in some particular season and remain closed for the rest of the year, there is no evidence as to during which part of the season or year the mill was operative and for which part of the year it remains closed. It has come in evidence that its operation is dependent upon availability of Dal. Management witness has however, admitted that since 1981, the position has eased. Dal is a commodity which could be made available throughout the year depending on factors of storage, trans-The availability can not be ruled out that portation etc. for some time when the Dall is not available for operation of the mill and it is probably on that account that lay off compensation for 20 days and then for 45 days in a year has been allowed as per documents filed on record, these circumstances it can not be called seasonal,
- 16. Under section 25-A of the LD. Act industrial establish ments which are seasonal in character have been exempted from the application of section 25-C of the act relating to lay off and retrenchment. The very fact that the lay off has been given shows that the Dal Mill is not a seasonal industry but an industry running for the whole year though remaining closed at times for non-availability of working materials for which lay off compensation has been provided by the management.
- 17. Now the question arises if the workman working in the Dal Mill are all casual workmen. Dictionary meaning of word Casual is happening by chance and a casual labour is not labour permanently and regularly engaged by an employer. Casual work for labour would be work which is not a recurring work but has come as a matter of chance or being a periodic work occurring in all year or so. So along Dal Mill runs and labourers required the work of the mill as well as all the labourer is of regular nature, If the work is of regular nature they are entitled to daily wages, weekly rest, medical leave, provident fund and honus etc. If such a workman have put in continuous service for about a year they are entitled to certain rights for instance that if they have completed 240 days of work in a year or come within the definition of continuous service as given in section 25-B (1) of the Industrial Dispute Act they are entitled to retrenchment compensation on termination and acquire a temporary status and can not be called to be merely casual workman. They will be further entitled to termination on the basis of last come first go and reemployment when need arises in view of provision 25 G and 25 H of the I.D. Act. These are the benefits granted to a workman in an industry under industrial dispute act and which they acquired after having worked regularly under some employmen' and acquiring the category of temporary workman as against casual who are engaged for non recurring type of work for a short duration. All these workmen though called casual workmen acquired temporary status as their working was a continuing nature and not occurring by chance. Under item 10 schedule 5 recently added to the I.D. Act to employ workman as badli or casual or

- as temporary for years with the object of depriving them a states of printment workman is an unfair labour practice. In view of the admission of the management witness that all those workmen passing few whose working in the Mill he has disputed watch working in the Dall Mill since 1978. The documents fined and leave account of the some of the workmen show that they are working for more than 240 days in a year. Thus they all acquired temporary status long ago in 1979, 80 or at least in 1981.
- 18. Thus in view of these circumstances that they are working since long and the work is of a continuing type it had been unfair labou, practice on the management not to have made them regular and started giving them regular pay of scale when they are admittedly paying them DA, bonus EPF, Leave lay off etc. action to regular employment. Out of those 54 working mentioned in the annexure of the reference order, the management has admitted that only 49 of them working, that as the five names namely Sant Ram, Pyare Lal, Vijai Kumar, Rameshwar II and Ramesayewan are mentioned twice in the list. Deleting their names there remains 49, workmen. Their names appears at Sf. 22, 34, 36, 45 and 11 and again at serial Nos. 54, 51, 53, 52, and 48 respectively which names are called by the workman as wrongly written in the reference order. They are Desh Raj, Radhey Shyam Muneshwar and Melu Lal have been incorrectly described as Pesh Raj Raghai Saran, Mahishar and Mahi Lal at 21. The union should have got reference order amended suitably, in the absence of the same no relief can be given to those persons Munna or Munauna and Vinod Kumar which admittedly not working in the Dal Mill as admitted by Sant Ram. There is no evidence about Devi Lal and Mohilal though regarding Rajendra Pratap Trivedi the leave card shows that he is working in the Dal Mill and was there in the year 1981. The managements own paper shows that Shri Rajendra Prasad Trivedi was in paper shows that Shir Rajendra Prasad Trived was in service in the year 1980 and received payment. Thus disallowing to any right to Pesh Raj, Raghai Saran, Mohishar Munna, Devi Lal, Mohilal Mahi Lal and Vinood Kumar there remains 41 persons. In annexure to the reference order serial No, 41 is left blank. Thus the number of workmen who can be given relief comes to only 40.
- 19. Consequently I hold that the action of the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow, in not regularising the services of 40 workmen instead of 54 workmen whose names at mentioned in the annexure and not bringing them on regular scale of pay is not justified and their services will be regularised forthwith.
 - I, therefore, give my award accordingly.

15. Shri Sudhir Kumar 16. Shri Nohar

17. Shri Mohan

Let six copies of this award be sent to the Govt, for its publication. Dt. 18-3-86.

> R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer [No. L-42011/6/82-FCI/D-IV(A)|D. II(B)] HARI SINGH, Desk Officer

S1. Name of the workmen No. 1. Shri Arun Kumar Singh Shir Krishna Kumar 3. Shri Surendra Singh 4. Shri Tika Bahadur 5. Shri Raja Ram 6. Shrimati Monoo 7. Shri Guru Prasad 8. Shri Shiv Narain Shri Man Bahadur 10. Shri Sri Ram 11. Shri Ram Autar I 12. Shri Budhoo 13. Shri Ganga Mal 14. Shri Sri Kishan

- Shri Ram Shai
- Shri Rameshwar
- 20. Shri Chotai Lul
- Shri Debi Deen
- 22. Shri Putti Lal
- 23. Shri Ganga Ram.
- 24. Shri Asharfi Lal 25. Shri Rakesh Chand Saxona
- 26. Shri Bansi Lal
- 27. Shri Uma Shanker
- 28. Shri Bharat
- 29. Shri Rajendra Pratap Trivedi
- Shri Bhagoti Prasad
- 31. Shri Vijay Kumar II
- 32. Shri Sunder Lal
- 33. Shri Ram Dulari
- 34. Shri Rameshwar II
- 35. Shri Omkar Nath
- 36. Shri Ram Saiiwan
- 37. Shri Dwarika Prasad
- 38. Shri Pyarelal
- 39. Shri Vijay Kumar I
- 40. Shri Sant Rain

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

का. आ. 1673:---औंद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 ् (1947 का 14) का धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार, भारताय स्टेट बैंक, कानपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोज हों और उसके कर्मकारों के बोच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आंद्रोगिक श्रधिकरण कानपुर के गंचाट को प्रकाशित करतो है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-3-86 को प्राप्त हम्रा था।

New Delhi, the 7th April, 1985

S.O. 1673.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Kanpur and their workment, which was received by the Central Government on the 24th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 246A/1985

Reference No. 1, 12012/248/84-D.II(A) dated 20-5-1985 In the matter of dispute between:

Shri Rajendra Kunm_r C/o Shri N. C. Pande Authorised representative of the workman, C-323, Guruteg Bahadur Nagar, Kareli, Allahabad.

The Regional Manager, Region III, State Bank of India, The Mall. Kanpur.

APPEARANCES:

Shri A. S. Sanena representative—for the Management.

Shri Mangaleydkar representative—for the workman.

AWARD

1. The Central Govt. Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/248/84-D.Π(Λ) dated 20th May. 1985, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

Whether the action of the Management of State Bank of India, in terminating the services of Shri Rajendra Kumar messenger, State Bank of India, Muthigan Branch, Alfahabad with effect from 30-8-82 and not considering lum for futtner employment while engaging fresh hands is justified? If not, to what telief is the workman concerned entitled?

- 2. The case of the applicant is that he was appointed as temporary messenger in the management bank in Moti Lal Nehru Regional Engineering Coilege Branch, Allahabad, on 10-2-81 and worked there rill 31-5-81, when his services were dispensed with. That thereafter he was again apopinted at managements Johnsonganj branch on 30-10-81 and worked till 20-2-32 and last of all he was appointed at Managements Mutnigani brench on 1-6-82 and worked there upto 30-8-82 with a artificial break of one day on 2-8-82, that for all these arointments he was never given any appointment letter nor any termination letter and thus the pro-vision of para 495 and 522 of the Sastri Award were violated. He was further not given any notice or given notice pay at the time of termination of his services. That after his termination several other persons were appointed at the above said branches, their names being Raj Kumar Agrawal, A. K. Mishra at M. I.. Nehru fingineering College Branch Ashok and Manatma Mishra at Johnsonganj branch and Santosh Mishra at Muthiganj Branch. That though there was work but he was never given a chance nor called for work and in this way provisions of section 25F G and rule 77 and 78 of the Central Rules of ID Act were violated. That the appointment of workman for a particular period of number of days was defiberate with a view that the applicant may not take advantage of para 20.7 or 20.8 of the bipartite settlement, and that despite representations by the workman he was always told that as he has completed 89/90 days of service hence he would not be given further chance in view of the circular of the management resorting period of temporary apopintments.
- 3. The management has contested the case on a preliminary point that the reference was invalid as no demand was made. On merit it was contested on the ground that it is admitted that the workman was engaged as temporary messenger by way of tresh appointment at management's Muthiganj, Branch Allahabad, on 1-6-82 and continued to work there upto 30-3-32, when his services were terminated as no longer required and in this way the workman worked for a total period of 89 days. The management admits indirectly that no apopiniment or termination letter was given to the workman as he never demanded the same. It is admitted that the workman was appointed at management's MLN Regional Engineering College branch, but that appointment can not be legally be clubbed together with the appointment at Muthiganj Branch. Similarly it is alleged that the workman was apopinted at Johnsonganj branch and that being fresh appointment has no relevancy with the appoitment at Mothigani branch and can not be clubbed together for purpose of section 25-B of the I.D. Act. The management further admits non employment of the workman on 2-8-82 but it is averred that his services had automatically came to end on cessation of requirement of work and on expiry of the period of appointment known to the workman, The management has further admitted that few workmen were appointed as temporary hands against purely temporary and odnoc requirement prior to the appointment of workman which were not the same on which the workman
- 4. On behalf of the management Shri A. K. Chatterjee has given his offidavit evidence and has reiterated the averments made in the written statement admitting that the workman worked at Muthiganj Branch of the management bank for 89 days. In cross examination he has admited that branch manager is the authority to appoint a sub staff in permanent capacity but appointment had to be done through interview etc. through personnel department. Information of selection of sub staff is made by branch manager who later does it only after informing the regionar manager as it is the Regional Manager who is controlling authority. He however, stated in the end that prior approval has to be taken by the branch manager from the Regional Manager who

was appointed and their services were terminated as and when bank's requirement were over and it has been denied that provision of 25G and H attracted in the instant case or provision of bipartite settlement have been violated

was the controlling authority in case of sub staff, in the end he stated that no attendance register is maintained in the case of temporary sub staff.

- 5. The workman has filed circular per list dt. 8-11-85, all of which have been admitted by witness Shri A. K. Chatterjee. They are in five documents. The first document is circular staff no. 168 dated 9th September, 1976 regarding temporary employees wherein it is aid down that while in the sub staff cadre temporary appointment can not be avoided on some places following guidelines must be observed while resorting such temporary appointments. That such appointment should be made subject to the condition that no such employee should be permitted to for a aggregate period exceeding 90 days in a year.
- of 1978 dt. 30-11-78 which lays down that it is impressed upon the management (branch managers) once again that they should ensure personally that temporary employees are appointed in the prescribed manner only and for maximum period not exceeding 90 days and certificate was to be sent to the personnel department, that no temporary apopintments including casual fabours were made and in case casual employee or temporary employee was permitted to exceed a total of 90 days except with the prior approval of the controlling authority. The witness further admitted in the written statemnet filed before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kanpur in dispute raised by the workman where it was admitted that the workman worked at MLN Engineering College branch for 89 days in the year 1981 and at Muthiganj branch for 89 days in the year 1981 and at Muthiganj branch for 90 days. Another circular staff no. 129 of 83 dated 24-11-83 was also filed wherein it was again emphasised that temporary employees are still being allowed to work in excess of the prescribed limit of 90 days and lastly circular no. 23 of 1985 dated 17-1-1985, has been filed whe cin it was emphasised that temporary appointments are to be resorted strictly in the guideline issued and for maximum period of 90 days with the approval of the controlling authority.
- 7. The workman has filed his affidavit evidence giving details that after his termination Raj Kumar Agrawal, and A. K. Mishra were appointed at MLN Engineering College Branch, Shri Ashok Kumar and Mahatma Mishra were appointed at Jonsonganj branch and lastly Shri Santosh Kumar Chadha was appointed at Muthiganj Branch of the management. In cross examination he has denied the managements suggestion that he was told the period for which he was appointed or he was being employed rather he states that he demanded the letter of appointment which the management never gave him,
- 8. The preliminary objection raised by the management that no demand was made is repelled on the ground that the dispute was raised before the A.L.C. which itself communicated to a demand and if the management wanted to reconcile the matter than and there it has ample opportunity for the same.
- 9. It is admitted case that neither appointment letter nor termination letter was issued to the workman, thus it can not be said that whether his appointment was for a fixed duration and whether temporary or in any other capacity. Even casual workman employed in the banking industry to perform the work of messenger will be deemed to be temporary workman and will be covered by definition of para 20.7 of bipartite settlement or 508 of the Sastri Award. I have just quoted above that the managements' all circular emphasises that in no circumstances a temporary employee should be continued beyond 90 days unless there is prior approval of the controlling authority. It is probably on this account that the workman was allowed to work in the temporary capacity MLN Engineering College Branch for 89 days, Muthigani branch for 89 days and Jonsongani branch for 90 days. In para 493 of the Sastri Award it is laid down that the management should maintained a register of all temporaty employees also showing names of retrenched employees and in view of para 495 of the said award they should be given appointment letter specifying the kind of appointment and other details.

- 10. On the point of principles of last come first go it is laid down in paragraph 507 of the Sastri Award that in decading that who is junior most amongst superflous A and B class bank should take down as unit while C and D class bank should take state. Admittedly State Bank is A class bank and Ml N ingineering College branch of the management as well Muthiganj and Jonsonganj branch of stationed at Alfalabad would be taken as one unit for the purposes of deciding who is the junior most. It is laid down that retrenchment of a superflous workman should be on principles of last come first go.
- 11. Lastly as required under para 522(5) of the Sastri Award no termination letter or appointment letter was given to the workman and under sub-rule (4) of the said para of Sastri Award no notice or notice pay was given to the workman for termination for any of the three temporary spells. Thus in view of the infringment of the mandatory provisions of the Sastri Award and bipartite settlement the termination of the workman would be illegal.
- 12. It is not disputed that temporary hands were appointed/recruitted in these branches after the termination of the workman, this is nothing but violation of the provisions of these rules 77 and /8 of the I.D. rules Central and section 25H of the I.D. Act.
- 13. In view of the discussions made above, I hold that the action of the management of State Bank of India, in terminating the services of Shri Rajendra Kumar, messenger, State Bank of India, Muthiganj Branch, Allahabad w.e.f. 30-82 and not considering him for further employment while engaging iresh hands is not justified, the result is that the workman has to be reinstated in service with full back wages.
 - 14. I, therefore, give my award accordingly,
- 15. Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dated 20-3-1986.

R. R. SRIVASTAVA, Presiding Officer [No. L-12012/248/84-D.II(A)]

का. भ्रा. 1674:—औद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार, भारताय स्टेट बैंक, कानपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उमके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-3-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1674.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government Intereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on 25th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

REFERENCE No. 1.-12012/167/79-D.H(A) dt. 2-7-84, L-12012/52/83-D.H(A) dt. 2-5-84

Industrial Disputs Nos. 57/1984 & 235/1983 In the matter of dispute between:

- Shri Hori Lal & others (ID No. 57/1984) C/o General Secretary U.P. Bank Employees Union (Federation) 26/104 Birhana Road, Kanpur.
- Shri Swarup Narain Pande C/o U.P. Bank Employees' Federation 26|104, Birhana Road, Kanpur.

AND

The Management of State Bank of India, through the Chief Manager, State Bank of India, Mahatma Gandhi Road, Kanpur.

APPEARANCE:

Shri V. N. Sekhari-for the workmen.

Shri A. S. Saxena-for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. 1.-12012/167/79-D.H(A) dated 2-7-84, (ID. No. 57/1984), has referred the following dispute for adjudication to this tribunal:

Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur in terminating the services of S/Shri Hori Lal, Sunder Lal, Hari Shanker and Braham Prakash with effect from 30-3-78, 17-11-78, 16-8-78 and 16-11-78 respectively was justified in view of the provisions of section 25F. G and H of the Industrial Disputes Act, 1947? If not, to what relief each of them is entitled?

2. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/52/83-S.H(A), dt. 2-5-84 in I.D. No. 235/83 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal;

Whether the action of the management of State Bank of India, in relation to their main branch, Kanpur, in terminating the services of Shri Swarup Narain Pande, casual labour with effect from 16-8-78 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?

- 3. The two cases were consolidated vide order in industrial dispute no. 57/84, as common question of law and facts arise in them and Industrial Dispute No. 57/84 was made leading case. The case on behalf of the union in industrial dispute no. 235/83 was that the workman was appointed on 16-3-75, and continued with breaks till 30-12-76, and was again employed on 2-3-77 and worked for 94 days in 1977, and again for 153 days in 78 and his services were discontinued from 16-8-78 without any notice, notice pay or retrenchment compensation. That he was doing work of a regular and permanent nature in the management bank but was designated as casual labour or daily rated employee in order to deprive him the benefits of regular employee. The said termination by the management was illegal and viod abinitio, the management have further infringement the provisions of section 25G and H of the Industrial Dispute Act as junior most man was not retrenched when workman was terminated and further so many new hands were reemployed but no charce was given to the workman He is consequently entitled to reinstatement with full back wages.
- 4. The management has contested the dispute on the ground that Shri Swarup Narain Pande was not a workman within the definition of section 2(s) of the I.D. Act in asmuch as he was engaged on job contact basis on payment of day rate in connection with ad hoc and casual job/work in the Regional Stationery department and for that he was posted there. It is further averred that casual workers has been excluded from the perview of the bipartite settlement vide para 69 of Desal Award, thus no industrial dispute could be raised for said casual workman. The management has however, further taken the plea that no demand was made, hence no valid industrial dispute. The management admits that he worked in management's main branch Kanpur as casual labour in 75, 76 and 77 only for 28 days, 179 days and 5 days respectively and from 77 till 8th June 78 he worked at Kanpur I ocal Head Office and in the end it is confended that the industrial dispute act and its provisions are not attracted as applicant is not a workman. In rejoinder again workman has reiterated that in 75 he worked for 88 days in the main branch and again in 76 in the said main branch for 265 days thereafter in 77 he worked for 79 days at I ocal Head Office and in 78 he worked for 153 days. He has further named new hands who were appointed as temporary after his retirement.
- 5. In support of its centention, the workman filed certain documents and served introgatories on the management which was duly reolled regarding number of working days, the averments for working in the main branch for the same

as mentioned in the written statement. Thereafter parties gave evidence in the leading case.

- 6. As regards I.D. No. 57/84, it may be pointed out that the dispute relates to four persons as mentioned in the reference order that their respective dates of termination given therein and the ground being non compliance of provision section 25F, G and H of the I.D. Act. In this case also on behalf of the workman it is avered that they worked in the banking industry for regular and permanent nature of the job but they were termed casual and temporary and were paid at daily rate which was illegal as they were temporary employees they should have been terminated by notice, notice pay and retrenchment compensation in the absence of the same the retrenchment being illegal they are entitled to be reinstated with full back wages. The management in this case also contested the case on similar grounds raising the disputed that they are not workmen within the definition of the I.D. Act, that they were engaged for adhoc and casual inture of work for which they are paid, that they never completed 240 days of work, the management has however admitted that Hori Laf worked for a few days or a month in 75 again in 77 and in 78 till month July working days were 305. Similarly Sunder Laf worked for December 75 till January 78 and total number of working days were 303. Hari Shanker from April 74 to January 78 worked for 293 days. It is further admitted that Hari Shanker worked for about 10 days in the stationery department in the management bank and Hari Shanker worked for 40 days in the stationery department Kanpur and Shri Brahma Prakash worked for 445 days from March 72 to November, 1976.
- 7. The workmen served introgatories to the management bank, which was replied. In support of their contention the workman filed the number of documents. The management representative Shri Vijoi Man Singh admitted that after the services of the workmen concerned were dispenced with several others for fresh and independent requirement were engaged from time to time, no attendance register is maintained for such appointments and no appointment or termination letter was issued for such casual labours. No register of casual labour showing the seniority is maintained by the mangement during the continuance of the casual workers or cusual workman are also engaged for requirements. further stated we can not say if the workmen who were dispensed with other workmen were engaged during course of engagement continued after workmen's dispensation of work or not.
- 8. On behalf of the management one Shri S. C. Mishra gave his affidavit evidence and was cross examined on behalf of workman Swerup Narain Pande and Hori Lel. Shri Hori Lal gave his affidavit evidence and were cross examined.
- 9. In cross examination he reiterated that no contract for work was seen between the workmen and the management and that they were neither appointed nor terminated but were simply encaged for casual work on daily wages basis and were paid by vouchers. He further admitted that what work was taken from them was not enumerated in any document. He further stated that engagement of sub staff was made from 1972 to 1978 for 90 days and those contracts continued at places upto 1984. He further admitted that no seniority list of temporary or casual staff was maintained in any branch of Kanpur and further the principles of last come first no was not observed in case of termination or discharge of casual temporary workmen. He further admitted that it was during the banking hours that the workmen concerned worked in the bank but he was not able to tell what work was taken from them. He has no knowledge for how many years the payment vouchers are maintained in the bank.
- 10. On behalf of the workman Swarup Narain Pande and Hori Lal gave their affidavit. In cross examination Shrl Swarun Narain Pande has stated that he worked in the bank during the period 16-9-75 to 16-8-78 and used to go to the bank regularly but whenever he was given work he worked there else. He used to come back. He admirs that he was naid at daily rate basis by nitty cash vouchers. He admird that he was a water boy from 20-5-78 to 16-8-78 of seasonal water boy for 89 days on half pay but he used to work for whole day. Workman voluntarily said that he

used to work fulf time work and used to take dak etc., but nothing was given to him in writing to work as peon.

- 11. Horr Lal has also reiterated his stand taken in the claim statement in his affidavit. In cross examination he admitted working in the bank on 11-10-72 as sub staff and he was paid monthly at the rate of daily wages. He admits that he was not required by any order in writing to appear at 10 a.m. and work till 5 p.m. but he has stated that he used to reach at bank at 9.30 a.m. and stay there till 5.30 p.m. He has stated that he was required to lift records and opening and packing boxes. He admitted that provident fund was not deducted but voluntarily stated that some money was deducted which was returned to him. He admitted that he worked in Gwaltoli Swarup Nagar branches, he has denied that he was working there as casual labour.
- 12. In the case of Swarup Narain Pande the management has filed the photo copy of apopintment letter dt. 19-5-78, which is admitted. According to this the workman was appointed as part time seasonal water boy on half salary w.e.f. 20-5-78 for period of 89 days and the apopintment will be deemed to have come to an end after the expiry of the aforestid period unless extended. The management thereafter, gave a certificate to hie workman photo stat copy of which is admited on 30th September, 78 that w.e.f. 20-5-78 to 16-8-78 workman worked as part time temporary seasonable water boy.
- 13. On the other hand workman has filed management's certificate ext. W-5 showing that in 74 from May to October he worked in the bank for 146 days on daily wages. He has filed another certificate of the management photocopy of which is ext. W-6 showing that in the year 1972 to 1977 he worked for 240 days as temporary massenger and four days as temporary Mall. The workman has filed the appointment letter Ext. W-7 and W-8 showing that he was appointed for one day as massenger on 12-10-72 and again on 11-10-72 on two days. This printed form of appointment contained a stipulation and the temporary appointment may be terminated also at the banks discretion subject to 14 days notice in lieu of notice pay without assigning reason but in those two appointment since the appointment was for a day that portion was scored out. Certificate Ext. W-10 shows that Hori Laj also worked as temporary messenger weef, 27-12-77 to 23-3-78 i.e. for 7 days.
- 14. It is argued that these temporary appointments were given for 87 days or 89 days i.e. less than 90 days in response to staff circular no. 168 of 76 which specifically stated that no temporary employees should be permitted to work for a aggregate period exceeding 90 days in a year. This circular is marked as Ext. M-1 on record.
- 15. Sunder Lal gave application Ext. W-3, that during year 1976 he hopes to have complete 240 days as should be given a fresh. Sunder Lal has also filed Ext. W-15 showing that he has worked for 72 days in the management bank from 14th September 77 to 5th January 78. Ext. W-16 shows that the workman Hari Shanker had worked for 398 days as temperary part time water boy on Khapra Mohal branch during the period April 74 to August 74. Ext. W-18 is the termination letter given to Hari Shanker on 28-6-75 showing that the rainy season had started and therefore his services of temporary part time water boy cum massenger will be terminated on 30-6-75.
- 16. Regarding workman Brahma Prakash managements Regional Manager per ext. W-22 written to ALC that workman Brahma Prekash worked for 446 days as temporary massenger on our Mahatma Gandhi Road Branch during the period March 72 to November 76. Ext. W-23 certificate issued by the management filed shows that workman Brahma Prakash had worked for 446 days during the period 72 to 76 as temporary massenger. Management has filed a number of staff circular relating to curbing of temporary employees for working for more than 90 days.
- 17. The main argument of the management is that daily rated workmen similarly casual workmen were not appointed in any regular vacancies but were employed for casual or iob work which does not pertained to regular nature of work in banking industry. They have referred rata 16.9 of the Desai Award which lays down that casual/job work-

- ers have been specifically excluded from the perview of the bank award. That position is not disputed. If the management engages labourers or a workman for a particular job or a casual nature of job not occurring or recurring in the banking industry generally but arising by chance such workers would be out side the perview of the work in the banking industry and for them bipartite settlement, Sastri Award or industrial dispute act would not apply. But the moment it is established that the work was taken from them not for any extraneous job or casual nature not connected with the banking industry but work was taken in connection with the regular course of business in the banking industry such workmen would come within the definition of the temporary employees as given in para 20.7 of the bipartite settlement and as given in para 524 of Sastri Award. The dictionery meaning of word Casual is happening by chance or often occasional or random as opposed to regular. In a banking industry where customers arriving in number and there is need to serve them water which work becomes more important in the summer senson, 'The work of water boy engaged in summer season would be a work in the banking industry. Similarly if the work is taken from him to work as Mali for maintenance for garden of the management bank the engagement will be in the bank and in connection with the banking industry and would not be an extra job to be termed as casual job. In the case of other workmun it is conceded that they worked as casual massenger of and on with breaks and they have worked for a good span of years. No doubt in circumstances they will be allowed to continue beyond 90 days. The work of temporary messenger though on daily wages would be nothing but a man engaged in the banking industry for managerial work and would be a workmen in the industry and would come within the definition of workman as given in the industrial dispute act, as he has worked for hire or reward.
- 18. The management is alive of situation that in case it engages temporary employees for a period 14 days or beyond and wants to terminate their services in between then it shall terminate his services by paying 14 days pay in lieu of notice as contained in the printed form in ext. W-7 and W-8. It is stronge that all those workmen worked for more than 14 days and their engagement could be nothing but as temporary workmen in the banking industry they too should be terminated by 14 days notice as required in para 522(4) of the Sastri Award, none compliance of the same renders their termination illegal.
- 19. Further for the purpose of temporary employment town has to be taken as unit as laid down in para 507 of the Sastri Award. It is not disputed that after tremination of the workman temporary hands were appointed in bank, in the absence of any seniority list they were not given reemploment which should have been done in view of provision of para 507 or section 25H of the LD. Act, None compliance of the same also renders termination illegal
- 20. On the point of 25G of the I.D. Act the management representative Shri Vijai Man Singh stated that no register of casual labours showing their seniority was maintained by the bank and that during the coningance of his casual workers other casual workers were also engaged for casual requirement. Regarding them he stated that he could not say if the workmen who were dispensed with other workmen engaged during the course of employment continued after workman's dispensation of work or not. Hori I al in his affidavit para 6 has stated that when his services were terminated persons junior to him including Chhotev I al and others were allowed to continue and were subsequently made permanent massengers. The management has not controverted this position by fling any decuments. Sworup Norain Pande in his affidavit para 6 has deposed that many junior hands were retained in service whereas he was retrenched and those junior hands were Shri Ram. Kirnal Rajendra Prasad Singh and Rajendra Agrawal who were made regular massenger later on. The management has not controverted that those rersons were not innior to Shri Swarue Narain Pande and were continued even after their termination. Thus in these circumstances on the principles of last come first go they should have been terminated and not the workman and the termination on that count is also illegal in view of infringement of section 250 of the LD. Act and para 507(1) of Sastri Award.

20. In Lab. 1980 IC page 300 Allahabad Mahmood Versus Balwant Singh it was held that if an employer had employed persons for the purpose of trade or business then even though employment be of a casual nature he would still fail with in the category of workman provided other condition stated are satisfied.

- 21. In the instant case Swarup Narain Pande even though employed as part time seasonal water boy on half salary was employed for the purpose of trade or business in the banking industry.
- 22. In Tapan Kumar Versus General Manager Calcutta Telephones 1981 lab IC NOC 68 Calcutta wherein it was held thus if a casual labour is employed in an industry for hire or reward he will be the workman within the meaning of section 2(s), there is nothing in the definition which includes a casual employer on the contrary section 25-C of the I.D. Act gives a sufficient indication that a badli workman or a casual workman is workman when it includes then from the right of compensation thereof.
- 23. Thus in view of the matter Swarup Narain Pande engaged as water boy and other workman namely Hori Lal, Sunder. Hari Shanker and Brahma Prakash worked for sufficient period in the banking industry through not completing 240 days in any span of one year of claim benefit of section 25F yet they were temporary employees and as principles of last come first go was not observed nor were they called for reemployment when other persons were employed renders theirs termination illegal. Further adimtedly on their termination ther were not given 14 days notice nor notice pay in lien thereof, the termination is illegal on that account also as provided by para 522(4) of the Sastri Award.
- 24. In these circumstances and in view of the discussions and law discussed above I hold (in Industrial Dispute No. 57/84) that the action of the management of SBI Kanpur in terminating the services of S/Shri Hori Lal, Sunder Lal, Hari Shanker and Brahma Prakash w.e.f. 30-8-78, 17-11-78, 16-8-78 and 16-11-78 respectively is not instified in view of the provisions of section 25G and H of the Act as well violative of para 522(4) of the Sastri Award. The result is that termination being illegal they are entitled to be reinstated with full back wages.
- 25. Similarly I further hold that termination of Shri Swarup Narain Pande (ID No. 235/83) Casual labour w.e.f. 16-8-78 was illegal and not justified, on account of vication of 25G and H and 522(4) of Sastri Award. The result is that he too is entitled to be reinstated with full back wages.
 - 26, 26. I, therefore, give my award accordingly,
- 27. Let six copies of this award be sent to the Govt, for publication and further ordered that a copy of this award be sent on the record of industrial dispute no. 235/83 Swarup Narain Pande Vs. State Bank of India, Dated: 18-3-86

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer [No. L-12012/167/79.D.II(A)]

का. था. 1675 — श्रीजीमिश विवाद श्रिविष्यम, 1947 (1947 का 14) की श्रीण 17 के श्रमुसरण में, केर्न्न श्री राज्ञाना 17 के श्रमुसरण में, केर्न्न श्री राज्ञान, जारताय महिट और, हैदरावाद के श्रमुंधरीय से सम्बद्ध नियोज्ञानों और अन्ति कार्यश्री के गाँच, जानबंध में निर्दिष्ट ब्रीब्रोगिक जिलाज में आँगोजिक श्रीकरण हैदनायाद के पंचाद को प्रकाशिक करती है, जो केर्न्नय संस्कार की 25-3-86 की प्राप्त हुया था।

S.O. 1675.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal, Industrial Dispute No. 13 of 1982

BETWEEN

The Workmen of State Bank of India Hyderabad (Alur Branch).

AND

The Management of State Bank of India Hyderabad.

APPEARANCES:

Sarvasri D. S. R. Varma and K. Narasimham, Advocates—for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12012[188]81-D.II(A) dated 3rd March, 1982 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of State Bank of India and their Workman to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to its Alur Branch in terminating the services of Sri Shaik Masthan Sab in July, 1980 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 13 of 1982 and notices were issued to the parties.

- 2. In the claims statement the workman stated that he was appointed at Alur Branch of State Bank of India and worked as Watchman/Sweeper-cum-Waterboy/Messenger from 25th October, 1974 to 10th July, 1976 and he worked too 240 days from October, 1974 to September, 1975 and 372 days till July 1980. It is his case that he attended for Zonal Interview in 1975 which was conducted at Kurnool. According to him he was not allowed to work continuously although the vacancy against which he was working were continuous vacancies and the same is unfair labour practice on the part of the Bank, Finally he mentioned that his services were terminated without any notice or wages in lieu of notice which is condition precedent to retrenchment under Section 25th of the LD. Act and therefore termination after 240 days of service it amounted retrenchment under Section 2(00) of the LD. Act and he is entitled for re-employment as retrenched employee under Section 25th of the LD. Act and he is deprived of the LD. Act. According to him he is a victim of unfair labour practive on the part of the Bank as he is deprived of the benefits of the LD. Act. The workman could not sequre any job inspite of his best efforts. Therefore it is prayed that the termination of the services of the workmen is illegal and improper and that he should be reinstated with retrospective effect and back wages, including attendant benefits and pass such other orders.
- 3. The Management on the other hand filed a counter, lt is denied that the Petitioner worked for 240 days from October, 1974 to September, 1975 and 372 days till July 1980. According to the Management he was given work depending upon the availability of work due to leave vacancies. It is the case of the Management that he put in 199 days of service and as such the question of issuing of any notice of wages in lieu of notice as contemplated under Section 25-F of the LD. Act did not arise, It is the case of the Management that he is only a casual employee and non-allotment of work to the netitioner does not amount to retrenchment under Section 2600 of the LD. Act. Therefore it is contended that the reference should be rejected and there is no award in favour of the workmen.
- 4. The workman himself examined as W.W.1 on his behalf and marked Exs. W1 to W3. On behalf of the Management

two witnesses were examined and marked Exs. M1 to M3. Ex. M4 to M50 were marked by consent.

5. W.W1 mentioned that Shaik Mastan Sab who is a concerned workman in the matter. According to him he joined as Sweeper-cum-Wate boy on 25th October, 1974 and worked with gaps all toth July, 1976 on temporary basis and dering that period he worked for 240 days. Ex. W1 is the certificate issued to han by the branch faminger to that effect. The termination order issued to him on 14th July, 1976 showing that he was comminated with effect from 31st March, 1976. It is marked as Ex. W2. It is his case that he was taken back into service in 1979 and worked again till July, 1980 and without any notice whatsoever he was terminated. According to him till July 1980 in all he had put in 385 days. But there were no written orders showing terminating him in July, 1980. He was orally informed that he was removed from service and that juniors to him were continued that he was not given any interview and subsequently there were recruitments for temporary posts and he was not given 14 days notice prior to his termination and therefore prayed for reinstatement. In the cross-examination he mentioned that he continued for 219 days continuously in the first instance and they used to maintain an account of number of days worked and persons like Sweepers and Watchmen and the Bank used to give him debit vouchers for the wages payable to him. He conceded that he was not passing orders whenever he was taken back into service.

6. M.W1 is one G. Mahaboob Branch Manager of State Bank of India who worked at the relevant Branch where W.W1 worked (Molegavall). According to him the record pertaining to service particulars of employees of Molegavali would be in Alur Branch. He admitted that he worked in Molegavali for six months and that during that period Sk. Mastan Sab was working and Ex. M1 is the application, Ex. M2 is forwarding letter. The correction found in Ex. M1 were there from the beginning. According to him Ex. W1 contains that acknowledgement signed by him and he only certified the number of days worked as shown in it. It is the case that the records would be at Alur Branch and he did not certify the e figures by him as correct or not. He mentioned that in his covering letter he reported that there were "three enclosures" to that application and he was also sending his application for consideration. He conceded that he did not mention in the covering letter that he received the statement of particulars also along with the application from W.W1. He denied Ex. W1 is the certificate issued by him. But it is his case that the Regional Office record would show that he forwarded the application of the workmen to the Management. According to him Ex. M3 was sent in reply to a communication received from the Regional Office and that it is not available with them in the records.

7, M.W2 is the P.B.D. Monager (Personnel Banking Division), State Bank of India, Adoni, To worked for some time at Alur Branch of the State Bank of India, According to him he knew the petitioner W.W1 who worked as Messenger he knew the petitioner W.WI who worked as Messenger under him at Alice Branch at the relevant time. He also admitted that Molegavali was only a pay office of Alice Branch. According to him the Petitioner worked as Messenger for 199 days. By seeing Substitute Engagement Register maintained by them at Alice Branch which is marked as Ex. M51, he deposed the same. After seeing Ex. WI he mentioned that the period of the period of the period of the period. it was the acknowledgement by the then Branch Manager of Molegavali G. Mahboob of State Bank of India on the basis of Ex. M2 given by the Petitioner, According to him the said Mahaboob (M.W1) did not verify Exs. W1 and M2 on the basis of Ex. M51 and M52 and certified the number of working days as 240 days, 380 days as shown thereunder. According to him on the basis of Ex. M4 to M50 the Messenger worked for only 190 days and not 240 days as contended by the worker. He came forward to depose that Muhboob (M.W1) simply forwarded Ex. M2 to the Head Office along with Ex. M1 and the said Branch Manager Mahboob never approached to certify Ex. M2 and he was never called to verify the said statement. Finally he admitted that the records Exs. M51 and 52 are in the custody of Alur Branch. Finally he mentioned that the petitioner never worked for 240 days as mentioned by him. He worked only for 199 days and the question of working for 240 days or 372 days conti-nuously did not arise as he worked for 199 days only continuously in a period of 12 months. According to him Ex. M51 which is a substitute engagement and payment register whenever they enter the substitutes they mention in it showing the period and the amounts paid. He conceded that at page 84 hc entered that one Smt. Immam Bee, mother of this workman

wo.ked as Sweeper-cum-Waterboy in Molegavali Sub-Office and the said entries were struck off in red ink, and for the month of June 1975 the wages were paid for the Sweepercom-Waterboy at Molegavali sub-office as seen at page 84 of Ex. M51. He could not deny or confirm the suggestion that W.W1 was paid before 30th June 1975 after seeing Ex. M52. According to him it might have been that Molehave M32. According to him it might have been that Moles havel Sub-office was opened on 11th November, 1974 and he could not say how Ghaik Mastan was removed in June 1975 when he worked as Sweoper-cum-Waterboy in April and May 1975. He conceded that there was an entry at page 84 of Ex. M1 showing that an amount of Rs. 30 was paid in June 1975 when the same was struck off. He denied the transfer that it related the Markon Sec. the suggration that it related to Shaik Mastan Sab, According to him that the date therein was rounded of in green ink and the same is marked as Ex. M51(a) and denied the suggestion that it related only to Shaik Mastan Sab. He asserted that these entries relate to Shaik Immam Bee, the mother of Shaik Mastan Sab. It is suggested to him that Shaik Mastan Sab worked in the month of June 1975 and to get over the Industrial Disputes Act showing that if he worked for 240 days period he would be entitled to certain benefits, his mother Shaik Imam Bee was substituted in his place for the purpose of these entries and Ex. M51 and M51(a) are false cutries. He could not say from Ex. M51 readily who was paid wages for the period of four days as substituted Watchman after seeing page 71 of Ex. M52. As per the statement Ex. M53 during the calendar year 1st November, 1974 to 30th October, 1975 he admitted that W.W1 worked as part time. October, 1975 he admitted that W.WI worked as part time comployee for 190 days, as per Exs. M4 Shaik Mastan Sab worked for two days full time watchman on 11th and 18th November of 1974; and 2nd December, 1974 he was paid Rs. 40.65 as wages and as per Ex. M6 W.WI worked as substitute on 16th and 17th December, 1974 and he was paid wages, and that on 24th December, 1974 Shaik Mastan Substitute of 1974 was a substitute of 1975 was a substitute o was paid a day full wages as per Ex. M7 and that as per Ex. M10 there was indication that he worked as substitute messenger and watchman full time on 9th December, 1974, 27th December, 1974, 2nd January, 1975 and 11th February. 1975 and similarly he admitted that under Ex. M12, M13 and M14 there were days he worked as substitute watchmen. Then a question put to him whether he worked as part time Sweeper-cum-Waterboy in 1/3rd scales for 199 days during the period October 1974 to October 1975 and in addition to that he attended as full time employee for 270 days and payments were made separately, the witness admitted same as correct. Then the witness was suggested that as per the Circular 73/73 27 days should be converted as part time employee in 1/3rd scale as 81 days. Thus he would be treated as completed 280 days, for which the witness denied the same as not tenable.

7. The admitted facts of the case are Shaik Mastan Sab worked as Sweeper-cum-Waterboy from 25th October, 1974 and with gaps he worked till 10th July, 1976, Now Ex. W1 is the particulars of service signed by G. Mahboob who is examined as M.W1 for the Management, M.W1 admitted that he worked at Molegavali Branch for six n onths and during that period Shaik Masten Sab was working. It is his case that Shaik Mestan wanted him to forward his application to the Head Office which is marked as Ex. MI and M2 is the forwarding letters. According to him the corrections in Ex. M2 were there in the beginning and acknowledgement of this Ex. M1 he signed in the copy Ex. W1 he signed it. So it is his case that Ex. W1 is not a certificate given by him for the number of days worked as shown in it but he admitted that he signed as a copy of the acknowledgement while forwarding Exs. M1 and M2. Now Ex. M2 would show that Shaik Mastan put in an application stating that those who worked for 240 days in 12 months period were being given appointment in Madras Circle and that in 1975 from January to September he worked in all for 240 days and further he worked for 145 days beyond September 1975 and thus he put in total period of 385 days upto 30th September, 1980. He further mentioned that copies of the certificates given by the Branch Manager was enclosed for his reference. He also mentioned that his mother Imam Bee was working as part time employee in Nandyal Branch. Therefore he requested in his application to kindly consider his case fovourably and to absorb in a permanent vacancy for which he mentioned that he would be grateful.

Now M.W1 stated that he did not verify the records while forwarding Ex. M2 with its enclosures which is similarly to Ex. W1. It is his case that he acknowledged Ex. W1 as a statement which was furnished by the workmen himself. Now M.W1 is asked to explain what was the third enclosure

which was referred by him in Ex. M1 he mentioned that he could not remember the same. It is suggested to him that the other enclosure was a certificate issued by him concerning these particulars furnished under Ex. W1 which is shown as enclosure and he denied the same. Now Ex. M1 is admittedly having Ex. M2 and the original of Ex. W1 as per the Management. These are only two enclosures and third enclosure is not there. It is suggested that the third enclosure is the certificate issued by the Manager while forwarding the letter Ex. M1 after verifying the statement. M.W2 who the letter Ex. M1 after verifying the statement, M.W2 who worked as B. P. D. Manager at Adoni mentioned that he worked as Branch Manager Alur and Molegavali was the pay offices is under Alur Branch. He marked Ex. M51 as the Substitute Engagement Register. It is his case that the Mastan worked for 199 days and not 240 days on the basis of Exs. M4 to M50, Admittedly it is the Management case that M.W1 did not verify Ex. W1 particulars and Ex. M2 particulars on the basis of Ex, M51 and M52 and certified the number of working days 240 days and 285 days as shown thereunder. Since Ex. M51 and M52 are available it can be retified whether he worked for those number of days as verified whether he worked for those number of days as alleged by him and whether the particulars rurnished under Ex. W1 were really certified or not by the Management. On 27th June, 1975 at page 84 of Ex. M51 it is shown that one Imam Bee worked as Sweeper-cum-Waterboy at Molegavali sub-office and she is the mother of Shaikh Mastan Sab and the said entries were struck off. It is conceded by M.W2 that the Branch Manager is the authority to appoint substitute like Messengers, Waterboy etc. The witness after seeing Ex. M51 at page 84 and also after clarifying Ex. M52 with reference to June 1975 he could not say when the Sweeper-cum-Waterboy at Molegavali sub-office was paid wages. In other words Ex. M52 which is the charges account register did not indicate the payment of wages at Molegavali sub-office corresponding to page 84 of Ex. M51. M.W2 could not deny the suggestion or confirm the suggestion that Shaikh Mastan was paid the wages for June 1975 and even after verifying Ex. M52 at page 82 he was of opinion that Molegavali Sub-Office was opened probably on 11th Novembor, 1974. That is the state of affairs, Now the case of the worker is that he worked as Sweeper-cum-Waterbov in April and May 1975 and finally M.W2 conceded that Shaik Mastan worked as seen from page 84 of Ex. M51 that there is entry showing that an amount of Rs. 30.00 was paid in June, 1975 and the same was struck off. The witness tried to deny that the same related to Imam Bee but not Shaik Mastan. He denied the suggestion that the date there was rounded of in green ink marked as Ex. M51(a) at page 84 rounded or in green ink marked as Ex. Mol(a) at page 84 and that it related only to Shaik Mastan and he tried to say that the entries related to Shaik Imam Bee and if Shaik Mastan worked for the month of June 1975 then the case of the workman that he completed 240 days during 1975 and that his mother's name was written in his place for the purpose of the entries and it is his case that these entries at Ex. M51 at page 84 was subsequently entered to deprive him of his length of service. It is a matter of verification. him of his length of service. It is a matter of verification. At any rate Ex. M51(a) entry is in a different ink and denial of M.W2 that the correction made at page 84 rounding off the date is not correct. He could not say to whom four days wages were paid as substitute watchman after seeing page 71 of Ex. M52. The witness was suggested that there was no record to show that xyz was paid under the relevant vouchers after seeing page 71 of Ex. M52. The witness merely said that it did not relate to Shaik Mastan. On the other hand Ex. W1 would show that he worked but the Management was not able to show to whom the substitute paid wages and when the workmen was clear and certain that he worked for that period and wages were paid to him it goes a long way to show when he is not an author of Ex. M52 and if they are not able to show to whom they paid the wages and when he is not given any dates as appointment and dates of termination is an oral assertain, then his evidence had great weightage when the records are not properly maintained to contradict him. Moreover Ex. W1 shows that he worked for that period and asserted; coupled with his evidence when there is no clinching material in the records maintained by the Management they paid wages to XYZ for that period go to show that what W.WI is true and correct. Now Ex. W3 would show that there is a staff circular issued to regularise part time employees and it is dated 29th March, 1966. It showed that the temporary part time people were being regularised. M:W2 conceded that Ex. W3 applied to those part time temporary staff who that Ex. W3 applied to those part time temporary staff who have completed 240 days continuously in a calender year and not to others. Now as per the statement Ex. M53 during the calender year from 1st November, 1974 to 30th April, 1975 it is the case of the Management that he worked for

199 days. Under Ex. M4 Shaik Mastan worked for two days on full time wages on 11th and 18th November, 19/4 and on 2nd December, 1974 he was paid Rs. 40.65 ps. as wages as Ex. M4 and as per Ex. M6 Shaik Mastan worked as substitute on 16th and 17th October, 1974 and paid wages Rs. 25.90 and that on 24th December, 1974 he worked for one day as full time watchman and paid Rs. 13.53 as per Ex. M7, and that Shaik Mastan was paid an amount of Rs. 101.63ps as substitute Messenger and Watchman full time Rs. 101.63ps as substitute Messenger and Watchman full time for working on 9th December, 1974, 27th January, 1974, 2nd January, 1975 and 11th February, 1975 6th, 7th, 8th and 15th January, 1975 as Messenger as per Ex. M5 the petitioner was paid Rs. 12.37ps for working as substitute Messengers on 11th December, 1974 as per Ex. M8 he was paid Rs. 24.74ps for working as substitute duties for two days on 3rd and 4th February, 1975 at Molegavali as per Ex. M14 Shaik Mastan worked as substitute for six days and 198, 76.08ps as per Ex. M13 Shaik Mastan was paid Rs. 76.08ps as per Ex. M13 Shaik Mastan was paid Rs. 13.88ps on 11th April, 1975 for preforming substitute watchman duties. At page 48 of Ex. M51 an amount of Rs. 38.04 was paid to Shaik Mastan for working on 14th, 17th and 27th April, 1975. Finally it is suggested to M.W2 that Mastan was working as part time Sweeper-cum-waterboy in 1/3 scales for 199 days during the October 1974 to October 1975 and in addition to that he worked as part time duty that he attended as full time employees for 27 days as per Ex. M4 to M13 and payment was paid separately and witness admitted the same to be correct and to the suggestion that 27 days should be converted as part time in 1/3rd scale then 81 days will be added to those 199 days and thus he will be completing 280 days by adding other days also. He denied the suggestion as not correct. He could not explain Ex. MI contains two enclosures which are marked as Ex. M2 and what happened to the third enclosure. Ultimately after cross examination of M.W2 the denial of M.W2 that the record did not show actual period worked except saying paid amounts as vouchers seems to be incorrect. The records were not correctly maintained to show how many days he worked as part time and how many days he worked as Sweeper-cum-Waterboy. These vouchers Exs. M4 to M50 and the substitute engagement register Ex. M51 as well as the charges register Ex. M52 reveal that the number of days Shaik Mastan was engaged during November 1974 to October 1975 would come to more than 240 days continuous service though Ex. W1 is signed as Bank Manager M.W1, they take up the stand it is only acknowledgement and it is not a certificate and the third enclosures is not forthcoming. Ex. M53 was worked out by the Respondent Bank itself on the basis of vouchers Ex. M4 to M50 and the same was filed as statement showing the particulars wages baid to Sri Shaik Mastan temporary messenger/watchmen/ waterboy. In fact the evidence of M.W2 would reveal when the same read with Ex. M53 that during the calendar year 1st November, 1974 to 30th October, 1975 the petitioner worked for part time for 199 days and it is also admitted worked for part time for 199 days and it is also admitted to be correct by M.W2. When a suggestion was put to him. Further Ex. M4 to M13 would show that the employee worked as full time substitute for 27 days and he was naid accordingly arrived at on the basis of vouchers referred to above. The same can be seen at page 48 of Ex, M51 and also the same was conceded by M.W2. So the same would come to 199 days plus 27 days would come to 226 days.

- 8. The workman contention that his services were terminated from July 1975 and not from June 1975 as made to appear in the record Ex. M51 at page 84 as seen from page 84. The salary for June 1975 was intended to be paid on 26th June, 1975 and noted as "Ditto" and the said "Ditto" to Shaik Mastan Sab who was shown above as Sweeper-cum-Waterboy for April and May, 1975 in Itme 1975. Though the word "Ditto" was there that was rounded of and in its place Immam Bee name was written. It was specially marked as Ex. M51(a) if this is added for June 1975 30 days then it would show that he worked for 256 days from November 1974 to October 1975 till and thus the contention is certified by Ex. W1 and Ex. M2 of Ex. M51 correction made therein would also justify the same and M.W2 can not deny the said facts in so many words and though he gave evasive and negative replies to a specific question.
- 9. Thus on a careful consideration of the entire record I am of opinion that Shaik Mastan worked for 240 days continuously in a year as per Section 25(B)(2)(a) of the I.D. Act and his services are terminated admittedly without any notice and notice compensation and thus it is violative

of Section 25F of the I.D. Act there is no doubt that non-compliance of Section 25F of the I.D. Act is held abinitio void by number of decisions.

10. If the contention of the Management is right that Shaik Mastan did not put in 240 days continuous service even then for the purpose of argument, it must be held that his termination without notice of 14 days as required under Sastry Award 522(4) must be held abinitio void. It says that the service of any employee other than the permanent employee or probationer may be terminated after 14 days notice if such an employee leaves service without giving such notice he shall be liable for two weeks pay including of allowances and an order relating to discharge or termination of service should be in writing and a copy of such order shall be applied to the employee concerned. So even that was not done in the instant case. Therefore it must be held that the procedure for termination of employees as contemplated under Sastry Award was not one.

11. Now the Management contended that the petitioner is only a casual worker in the question of giving 14 days notice has no bearing. But the Sastry's Award 522(4) directs that service of any employee other than the permanent employee requires 14 days notice for termination. Therefore Sastry Award applied to the temporary employees as well and Bank is bound to apply para 522(4) of the Sastry Award. Para 522(4) is a mandatory directions and under Section 25F of the I.D. Act there is a stipulation that no workmen employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons and also paying wages in liet of such notice etc. The Sastry Award with reference to Banking Companies as modified by the Bank Award Commission has the force of statute law. Therefore the non-compliance para 522(4) renders the termination in case of Shaik Mastan as void and he is entitled for reinstatement with back wages and all attendant benefits. Moreover the procedure as contemplated under Section 25G of the ID. Act that the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman is not followed. The evidence of Shaik Mastan as W.W1 would show that recruitment was made for temporary post after his termination and he was not called for interview at the time of recruitment. This fact was not denied in the cross-examination of the said witness. At any rate his mother who was said to be preferred as indicated under Ex. M51 at page 84 is preferred to him to avoid continuity of service and the record would show that his Mother Shaik Immam Bee was appointed in his place for subsequent periods and wages were paid to her, from July, 1975, So this is in violation of Section 25G. It is not the case of the Management that Shaik Immam Bee was acting even earlier to him and therefore she was preferred when such a retrenchment was done. So the Managements theory that he is only a casual employee and therefore the non-allotment of work to him did not amount to retrenchment under Section 2(00) of the I.D. Act and that he has no claim for re-employment under Section 25H are all made to cover up the violations under the L.D. Act after taking the place that the retrenchment did not arise when the workman is terminated.

12. As a matter of fact Messengers/Watchmen/Waterboy in the regular posts and so that the employees engaged in such posts are casual employees is contrary to the provisions of Sastry Award and Desai Award. Even under Ex. M53 which is the statement given by the Management in the Bank Shaik Mastan is referred as temporary Messenger/Wathmen/Waterboy. Therefore the Bank cannot deny that Shaik Mastan was a temporary employee as per its own record whether temporary or casual, the records reveal that he worked as part time employee against permanent vacancy and as full time substitute employee against temporary vacancies. Therefore it is needless to contend that he is not a workman within the meaning of Section 2(s) of the I.D. Act. Even Sastry Award and Desai Award treated as temporary employee as workman and covered them and it is in Digwadih Colliery v. Their Workmen (AIR 1966 SC page 75) The Supreme Court held while considering amendment of 1964 with reference to Section 25F that Jaldhar Singh who was a Badli workman being a substitute for permanent employee and he worked for more than 240 days in each calendar year though with interruptions and when a dispute arose the termination of service of Supreme Court held when the Badli workman will be illegal when he has put in service of

240 days in each of the years as there was no work for him. The termination of service of Colliery workman 1961 was held illegal when he had put in service of 240 days in each of the year 1959 and 1960. It is laid down that no uninterrupted service is necessary if the total service is 240 days in a period of 12 calendar months either before the several changes or after this. So even if Badli worker is entitled for the benefit of retrenchment as pointed out therein, even when there was lay off, the Badli workman who fell within the Section 25C were held to be entitled to lay off compensation in Laxmi Mills v. Labour Court [1965(I)LLJ page 92]. P. Joseph v. Management of Gopal Textiles [1975(I)LLJ, page 136 at pages 137 and 138]. Therefore the protection benefit which are available under the I.D. Act, for a tempocary workman who comes within the meaning of Section 2(s) must be protected. Even in Management Willcox Buckwell India Ltd, v. Jagannath (AIR 1974 SC. page 1166), It was held by the Supreme Court that they find no distinction between the case of Badli worker and that of a temporary employee. In that case the management case the ground for termination of services as surplus labour. The Supreme Court pooled out that there is no escape from the conclusion that the concerned workman were retrenched and could not have been done without giving them the benefit provided by the relevant provisions of the Act as the same was not done, the Labour Court was justified in ordering their reinstatement.

13. At any rate it is the contention of the Management that the workman did not complete continuous service of 240 days and as such he is not entitled for any benefits, as pointed out whenever there is clear vacancy and he is working as temporary Sweeper-cum-Waterboy. He is substituted by his mother and as such non-allotment of work to him cannot be argued as no retrenchment. First of all the stipulation of 240 days requirement of continuous service is only in relation to Section 25F of the I.D. Act but it cannot be lagged in to every other sections of I.D. Act. If a workman had 240 days and more in a year under Section 25F he is entitled to notice or pay in lieu of notice and compensation for having put in not less than 240 days in a year still the termination is only retrenchment provided it is done for want of vacancy. In the instant case there is vacancy yet his services are terminated. So it is not a case of want of vacancy which prevented him from completing 240 days of continuous service even taking for granted that under Ex. M51 at page 84 that his mother Shaik Imam Bee substituted him for the months of June and July 1975. It shows that it is only after terminating him which amounts to retrenchment she was appointed in the said vacancy. The principle of last come first go is not followed and it is not a case where there is no vacancy for which the termination or retrenchment arose. Under Section 25G and 25H the employer shall ordinarily refrench the workman who was the last person to be employed in category and under Section 25H where any workmen are refrenched and when the employer proposes to take into employment any person should give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment. So under Section 25G and 25F of the I.D. Act which are independent of Section 25F the stipulation of continuous service of 240 days is not there. These sections 25G and 25H of the I.D. Act, apply to all cases of retrenchment irrespective of 240 days continuous service in a year and the principle of last person in the enviloyment to go and that in case of re-employment the employer should give opportunity to the retrenched workman apply to all such cases of workmen who are terminated or retrenched in the given circumstances.

14. In the instant case the evidence of clearly culled out that Shaik Mastan Sab termination is due to non-allotment of work at the instance of the Management. So to it is say that not retrenchment is nothing but trying to cover up the mistakes of the Management as discussed or as could be seen. All 'retrenchment' is termination of service but all termination of service may not be 'retrenchment' (page 322 of Vol. I. Malhotra edition). In order to be 'retrenchment' the termination of service has to fall within the ambit of the definition of 'retrenchment' in Section 2(00) of the Act. Further more Section 25F prescribed the requirements of notice and compensation as conditions precedent to retrenchment of workman. Section 25F introduces the rule "last come first go" in effecting 'retrenchment' of workmen. A termination of service, without satisfying these statutory requirements will be no 'retrenchment' in the eye of law. Hence non-corapliance of these mandatory provisions will render retrenchment as invalid. The industrial adjudication therefore

has jurisdiction to see whether infact, these preconditions are compiled with or not. So as faid down in Workmen of Subong rea Estate v. Subong rea Estate [1964(1)]. I.j., page 233]. The proposition land down therein are useful for the musicial adjudication. It is laid down firstly that the Management can retrench its employees only for proper reasons which means that it must not be actuated by any motive or victimisation or any unfair labour practice. Secondly it is for the management to decide the strength of its labour force and the number of workers to carry out the efficiently of the work in an industrial undertakings. Thirdly if the number of employee may exceed reasonable and legitimate needs of the undertaking if any workmen becomes surplus its open to the Management to retrench them. Fourthly the workman became surplus on the ground of rationals or on the ground of economy. Fifthly the right of the employer to effect retienchment cannot normally be challenged but when there is a dispute in regard to the validity of any retrenchment it would be necessary for the Tribunal to consider whether the impugned retrenchment was justified for proper reasons and it would not be open to the employer either capriciously or without any reasons at all to say that it proposes to reflect its labour force for no rhyme of reason.

15. Of course the burden in such cases is one the workmen who is retrenened to put forward his claim. The employee who is retrenched must prove that he was retrenched from service without proper reasons and that it is nothing short of unfair labour practice in the instant case. It is not a case of voluntary retirement of the workman or any other ground mentioned in Section 2(00) of the I.D. Act. Moreover Shaikh Mastan Sab termination is not on account of any disciplinary action or due to ill-health or retrenchment of age of superannuation. Sri D. S. R. Varma who argued for the workman clearly proved from the evidence of M.Ws.1 and M.W2 admissions as well as the evidence of W.W1 and the documents filed by him that the Management retrenched the said Sweeper-cum-Waterboy without any reasons and with a motive of victimisation which amounted to unfair labour practice, and that same violated the Sections 25F and 25G and 25H and the said termination is not retrenchment on any count under Section 2(00) of the I.D. Act. As already pointed out the said termina-tion and breaks shown to Shaik Mastan Sab were contrary to the provisions of the LD, Act and also the provisions of Sastry Award para 522(4). Therefore I hold that the action of the Management of State Bank of India in terminating the services of Shaik Mastau Sab in July, 1980 is not justified and he is entitled to all the attendant benefits and back wages.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seaf of the Tribunal, this the 25th day of February, 1986.

Sd/-

Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Workmen: W.W1 Shaik Mastan Sab.

Witnesses Examined for the Management: M.W1 G. Mahaboob M.W2 D. Dada Hayat

Documents marked for the Workmen:

- Ex. W1-True copy of the service particulars of Shaik Mastan Sab.
- Ex. W2—Letter No. F26 dt. 14-7-76 addressed by Branch Manager State Bank of India, Alur Branch to S. Mastan Sab with regard to Temporary appointments, Temporary/Substitute basis.
- Ex. W3—Photostat cory of the staff circular No. 18 dt. 29-3-66 with regard to terms and conditions of service of Temporary and part time employees.

 Documents marked for the Management:
- Ex. M1-Letter F. No. 26/1, dt. 2-1-81 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Molegavalli

to the Regional Manager, State Bank of India, Region 11 Hydreabad with regard to staff subordinates/Menials.

- Ex. M2—Representation of Shaik Mastan Sab dated 29-12-80 forwarded by Branch Manager, State Bank of India, Molagavalli to the Regional Manager, State Bank of India, Hyderabad Region-III.
- Ex. M3—Letter dt. 25-6-1981 addressed by Branch Manager, State Bank of India, Molagavalli to the Regional Manager, State Bank of India Region II, Hyderabad with regard to staff Miscellaneous with regard to appointment of Shaik Mastan Sab as ten-porary Messenger/Watchman.

By consent

Ex. M4--Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Waterboy on 11-11-74, 18-11-74 and 2-12-74 with voucher dt. 10-12-74 for Rs. 40.65.

By consent

14x, M5—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Waterboy on 11-12-74 with voucher dt. 13-12-74 for Rs. 12.37.

By consent

Ex. M6-Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman|Waterboy on 16-12-74 and 17-12-74 with voucher dt. 26-12-74 for Rs. 25.90.

By consent

Ex. M7---Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Witchman/Waterboy on 24-12-74 with youther dt. 28-12-74 for Rs. 13.53.

By consent

Ex. M8—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Waterboy on 3-2-75 and 4-2-75 with voucher dt. 8-2-75 for Rs. 24,74.

By consent

Ex. M9—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Waterboy from 17-11-74 to 28-12-75 with voucher dt. 6-3-75 for Rs. 104.00.

By consent

Ex. M10—Statement showing the particulars of wages paid to Shuik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchnam/Waterboy for 9-12-74, 2-1-75, 27-12-74, 11-2-75, 6-1-75, 7-1-75, 8-1-75 and 15-1-75 with voucher dt. 6-3-75 for Rs. 101.63.

By consent

Ex. M11—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Waterboy for April, 1975 with voucher dt 1-5-75 for Rs. 30/-,

By consent

Ex. M12—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Waterboy for March, 1975 with voucher dt. 9-4-75 for Rs. 30/-.

By consent

Ex. M13—Statement showing the particulars of wages paid to Sunik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Waterboy on 7-3-75 with voucher dt. 11-4-75 for Rs. 13.88.

By consent

I.x. M14— Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Waterboy for 24-2-75, 6-3-75, 25-3-75, 31-3-75, 3-3-75 and 8-4-85 with voucher dt 16-4-75 for Rs. 76.08.

By consent

Ex. M15—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporaty Messenger/Watchman/Waterboy for 14-4-75, 17-4-75 and 22-4-75 with Voucher dt. 9-5-75 for Rs. 38.04.

By consent

Ex. M16.—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporaty Messenger/Watchman/Waterboy for May 1975 with voucher dt. 12-6-75 for Rs. 30.00

By consent

Ex. M17—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 15-10-75 and 21-10-85 with Voucher Jt. 31-10-75 for Rs. 25-45.

By consent

Ex. M18—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 2-12-75, 9-12-75, 16-12-75, 17-12-75, 18-12-75, 23-12-75 and 25-12-75 with voucher dt. 26-12-75 for Rs. 93.10.

By consent

Ex. M19—Statement showing the particulars of wages paid to Shark Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 15-11-75 with Voucher dt. 25/28-11-75 for Rs. 13.70.

By consent

Ex. M20—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 13-11-75 and 14-11-75 with voucher dt. 15/20-11-75 for Rs. 25.10.

By consent

Ex. M21—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Watcr Boy for 6-1-76, 12-1-76, 13-1-76, 20-1-76 and 27-1-76 with voucher dt. 16-2-76 for Rs. 67.75.

By consent

Ex. M22—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 3-2-76, 4-2-76, 10-2-76, and 15-2-76 with voucher dt. 4-3-76 for Rs. 54.20.

By consent

Ex. M23—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 2-3-76 with voucher dt. 13-4-76 for Rs. 25.27.

By consent

Ex. M24—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 9-3-76 to 14-3-76, 16-3-76 to 21-3-76 and 23-3-76 with voucher dt. 7-4-76 for Rs. 171.73.

By consent

Ex. M25—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 64-76, 13-4-76, 20-4-76, 23-4-76 and 27-4-76 with voucher dt. 20-5-76 for Rs. 78.11.

By consent

Ex. M26—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/

Watchnsan/Water Boy for 9-7-76, 4-7-76 and 11-5-76 with Voucher dt. 20-6-78 for Rs. 37.98.

By consent

Ex. M27—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 17-5-76 to 25-5-76 with youcher dt. 8-6-76 for Rs. 100.17.

By consent

Ex. M28—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 5-3-79 with petty cash youther dt. 12-4-1979 for 12.40.

Ev consent

Ex. M29—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mustan Sab, Temporary Messenger/Watchmau/Water Boy for 6-3-79 with petty cash youther dt. 14-4-79 for Rs. 12.40.

By consent

Ex. M30—Statement sholwing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Mossenges/Watchman/Water Boy for 1-5-79 to 50-5-79 with each voucher at. 8-6-79 for Rs. 395.40.

By consent

Ex. M31.—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Roy for 23-7-79 to 27-7-79 with cash voucher dt. 8-8-79 for Rs. 65.90.

By consent

Ex. M32—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 3-9-79 with petty cash youther dt. 4-9-79 for Rs. 12.65.

By consent

Ex. M53—Statement showing the particulars ow wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 5-10-79 with petty cash voucher dt. 17-10-79 for Rs. 13.18.

By consent

Ex. M34—Statementing showing the particulars of wages maid to Sbaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 10-11-79 with petty cash voucher dt. 28-11-79 for Rs. 12.80.

By consent

Ex. M35—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 10-12-79 with cash youther dt. 24-12-79 for Rs. 12.80.

By consent

Ex. M36—Statement showing the particulars of Wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 16-1-80 to 19-1-80 with voucher dt. 25-1-80 for Rs. 59.20.

By consent

Ex. M37—Statement showing the particulars of wages gaid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 8-2-80 with petty cash voucher dt. 29-2-80 for Rs. 14.80.

By consent

Ex. M39—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 9-2-80 and 15-2-80 with voucher dt, 18-2-80 for Rs. 29.08.

By consent

Ex. M39—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 6-3-80 with voucher dt. 8-3-80 for Rs. 13.60.

By consent

Fx. M40—Statement showing the particulars of wages paid to Shark Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 14-3-80 with voucher dt. 21-3-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M41—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenegr/Watchman/Water Boy for 22-2-80 with voucher dt. 31-8-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M42.—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Vatenman/Water Boy for 31-3-80 with voucher dt. 3-4-80 for Rs. 13.60.

By consent

Ex. M43—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Water Boy for 23-4-86 and 24-4-80 with voucher dt. 25-4-80 for Rs. 29.10.

By consent

Fx. M44—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/ Watchman/Water Boy for 2-5-80 and 7-4-80 with voucher dt. 27-5-80 for Rs 28.65.

By consent

Ex. M45—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 5-5-80 to 19-5-80 with voucher di. 22-5-80 for Rs. 218.25.

By consont

Ex. M46—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 7-4-80 with voucher dt. 1-5-80 for Rs. 14.55.

By consent

Ex. M47—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy for 4-7-80, 5-7-80, 8-7-80, 9-7-80 and 7-7-80 with voucher dt. 19-7-80 for Rs. 72.75

By consent

Ex. M48—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Water Boy for 23-7-80 with voucher dt. 28-8-80 for Rs. 14.55.

By consent

Ex. M49—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab, Temporary Messenger Watchman/Water Boy for 2-5-80 with voucher dt. 8-5-80 for Rs. 14.10.

By consent

- Ex. M50—Statement showing the particulars of wages paid to Shaik Mastan Sab. Temporary Messenger! Watchman/Water Boy for 7-6-80 with voucher dt. 18-6-30 for Rs. 14.55.
- Ex. M5!—Substituted engaged and payment register from January 1973 to 12-7-77.
- Ex. M51(a)—Service particulars pertaining to Smt. Imembes in Ex. M51 at page 84.

- Ex. M52—Charges account register from 8-3-74 to 26-4-76.
- Ex. M53—Statement showing the particlars of wages paid to S. Mastan Sab, Temporary Messenger/Watchman/Water Boy.

Dated: 12-3-86.

 VENUGOPALA RAO, Presiding Officer [No. L-12012/188/81-D.II(A)(Pt.)]

नई दिल्ला. 8 अप्रैल. 1986

का. आ. 1676:— ओद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) का घारा 17 के अनुसरण म, केन्द्र य सरकार, भारताय स्टेट बैक, लखनऊ के प्रबंधतित से सम्बद्ध नियोजकां और उनक कर्नदारों के बाच अनुबंध में निविष्ट अद्योगिक विवाद में कन्द्राय सरकार आद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के पंचाट का प्रजाशित करता है, जो केन्द्र य सरकार की 25-3-86 की प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1676.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kangur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th March, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. L-12012/127/84-D.H(A)

Dated 22-11-84

Case No. 216/1984

In the matter of dispute between :

Shri G. C. Srivastava S/o Shambhoo Dayal Srivastava, 415/13-A Gali Jiyafal, Chaputia, Lucknow.

AND

The Chief Manager, State Bank of India, Main Branch Hazaratgani, Lucknow.

APPEARANCE:

Shri Brijendra Kumar-for the workman.

Shri Mahesh Chandra-for management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its notification no. f.-12012/127/84-D.R(A) dt. 22-11-84 has refrered the fellowing dispute for adjudication:

Whether the action of the Management of State Bank of India, Main Branch, Lucknow in terminating the services of Shri G. C. Srivastava, temporary Badli Guard with effect from 9-12-83, and not considering him for reemployment while appointing fresh hands under section 25-H of the L.D. Act is justified? If not, to what relief is the concerned workman is entitled?

2. The case of the applicant is that he was appointed as temporary badli guard w.e.f. 30-5-83 and was continued till 7-12-83 as such by issuing various extension letters are expressed to VII. That the applicant was given extension letters and appointment letter as mentioned in annexure I to VII but the workman was required to work beyond 25-11-83 upto to 7-12-83 and 8-12-83 was his weekly rest day but when he reached the management bank on 9-12-83, for duty he was verbally told that his services were treminated. The

applicant has been paid his salary upto 25-11-83, but despute request ne has not been paid from 26-11-83 to 8-12-83. It is further averted that after terminating the workman management appointed Shri Bhim Chandia, Jeet Marain Pance and Lat Bahadur as temporary badli guard, who were stilf working and Mend. Usuf who was appointed as badli guard on 29-11-83 being junior to the workman was retained in service whereas the workman was terminated. That despite making representation annexure 1 to 10 the workman was not taken on duty. In the end it is prayed that the termination be declared illegal and he be remistated with full back wages.

- 3. It is admitted by the management that the workman worked from 30-5-83 to 1-12-83, and the termination letter was issued by the component authority was personally sought to be served on the workman but he refused to accept the same and refused the bank as the workman failed to tuning on subsequent date either to receive his termination letter or to settle his account, the termination letter was sent to him by post. It is further averred that the management tendered the workman at the time of termination two cheques but the workman refused to accept the same also. The two cheques have since been revalidated and being deposited with the court for payment of the workman. In the end it is averred that badh guard were appointed against leave vacancies casual requirements of the bank and they had no eight to claim community of employment and the workman employment automatically came to an end as soon as specified period or period of work came to an end.
- 4. On behalf of the management one Shri J. P. N. Tripathi an officer of the bank management dealing with the personnel mattees has fired his affidavit evidence. He has reiterated the stand of the written statement. In cross examination he has stated that initially the workman was appointed for two days i.e. for 30th and 31st May, and letter of appointment was given to the workman at the time of joining the duty, and he was allowed to continue till the subsequent extension letter/apopintment letter was given to him on 8th extension letter/apoptation letter was given to him on oth June, 1983. He has stated that only weekly lest is given and not Sundays or holidays. He admits that it is likely the appointment letters are given few days later but it is mentioned that service will stand on a particular date. The last appointment letter photo copy of which was given to the workman bears an endersement of Shri P. R. Pande Clerk concerned that the workman did not receive it. The witness that's that it must have been sent to the workman we present to the workman was states that it must have been sent to the workman by mes-senger. The witness was recalled again to testify and rebut the evidence by the workman after close of the case. He has deposed that no one was appointed in place of the workman and that duty register from 20-12-83 to 4-4-84 was thoroughly searched out but the same is not traceable and it is presumed that it is lost. In cross examination he admitted that no information was given either to the police authorities or higher authorities of the bank about the loss of the duty register in his knowledge. Letter, he stated that higher authorities have been informed but no such letter has been filed. He however, admitted that in the duty register the name of Mohd. Yusuf is shown from 23-11-83 to 19-12-83. He further stated that he does not know if Shri Jeet Narain Bhim Chandra were appointed from 19-12-83 on the duty register is not traceable. He specifically admitted that Mohd. Yusuf was junior to the workman and states that Mohd. Yusuf was in service when services of the con-cerned workman were terminated.
- 5. On the other hand workman gave his affidavit evidence reiterating the stand taken in statement of claim. He admits that he was appointed as badli guard but was not given any appointment letter and that was only at the time of giving him pay that extension letters were issued to him which were filed. Regarding first appointment letter Ext. I, he says that it was given to him on 8-6-83 at the time of payment and the Letter of extension of June was given to him at the time of payment in the month of July, 83. He admits that he never raised any objection for the delayed appointments. He simply made verbal objection to the dealing clerk who told him that it was on that letter that the payment authority was made. He denied that the two cheques filed by the management in this case were ever tendered to him and that he was not paid for the period 26-11-83 to 8-12-83 for which he made representation but did not re-

- ceive any reply. He however, stated that he can accept the two cheques if the tribunal directs him to accept those cheques. In the end he stated that he has come to know that badli guard leet Bahadur and Lal Bahadur were appointed after his termination out of Shri Bhim Singh was appointed in December, 1983, and Jeet Narain and Lal Bahadur were appointed in the month of February, 1984 and he also came to know about other appointment from them obky as they were known to him.
- 6. As the management has taken the plea about subsequent appointments of Bhim Chandra, Jeet Natain and Lal Bahadur on the ground that the register of temporary appointments is not traccable and is presumed lost, I am inclined to believe the testimony of the workman that the three persons were appointed after the termination of the workman. Further the management witness has admitted that one junior badli guard Mohd. Yusuf was working at the time of termination of the workman.
- 7. The only question is to be considered now, as to what is the status of badlı guard even in view of the appointment letters annexore I to VII given though the last letter harnot been given.
- 8. Badli workman and casual workman were considered to be a workman in industry if they were engaged for work connected with the industry, though they were not recognised for purpose of lay off compensation as their name were not borne on mustor roll, however, their status in industry was recognised under Section 25C of the Industrial Dispute Act. Serial No. 10 of the 5th Schedule of the Act where it is laid down that to employ a workman as oadli guard or casual or temporary and to continue them as such for years with the object of depriying them with the privilages and status of permanent workman is an unfair labour practice, Thus the position of such badli workman was casual workman would be nothing but temporary workman as given in para 20-7 of the bipartite settlement and para 508 of the Sastri Award. For termination of such temporary employees there should be a register of temporary employees as given in Sastri Award's para 493 and the principles of 250G of the Act should be observed on the principles of last come first go as given in para 507 of the Sastri Award and a termination for such temporary employees as given in para 522(4) should have been observed. Non compliance of all these renders termination illegal.
- 9. The termination is illegal on account of non compliance of section 25-H of the act and rule 77 of the LD. Central Rules in which it was incumbant on the part of the management to have considered the retrenched workman before employing other temporary employees in the name of badli guards.
- 9. In these circumstances and for the reasons discussed above, I hold that the action of the management of State Bank of India Main Branch, Lucknows in terminating the services of Shri G. C. Srivastava temporary badli guard with effect from 9-12-83, and not considering him for reemployment while appointing fresh hands under section 25-H of the I.D. Act is not justified. The result is that the workhas to be reinstated in service with full back wages.
 - 10. I, therefore, give my award accordingly,

Let six copies of this award be sent to the Government for its publication.

Dated: 17-3-86.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer [No. L-12012/127/84-D.II(A)]

मई विस्ली, 9 अप्रैल, 1986

का. था. 1677:— औद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक श्राफ बड़ौदा, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, श्रनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवाद में केन्द्राय संस्कार औडिशिक अधिकरण चंडानढ़ के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्राय संस्कार की 1-4-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 9th April, 1986

S.O. 1677.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government tercity publishes the award of the Central Government industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st April. 1986.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 13/86

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bank of Baroda.

AND

Their workman-Raj Kumar Mukhi.

INDUSTRY : Banking

STATE: Harvana

AWARD

Dated, the 25th of March, 1986

- 1. The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, as per their Order No. L-12012/138/73-LP-III/D-II. (A) dated the 6th January, 1986 reterred the following dispute to this Tribunal for adjudication:
 - "Whether the action of the management of the Bank of Baroda in terminating the services of Shri Rai Kumar Mukhi, Ex-Temporary Clerk Sonepat Branch of the said Bank with effect from the 13th May. 1973 is justified? If not to what relief is the said workman entitled?"
- 2. According to the claim statement filed by the petitioner workman he was engaged in the clerical cadre on temporary basis by the Respott. Bank at their Sonepat Branch for 15 days' fixed tenure w.e.f. 20-2-1973; that in view of the terms of appointment he was entitled for 7 days notice or equivalent salary in lieu thereof in case of premature termination and 14 days notice or equivalent salary in lieu thereof in case he was allowed to continue on the aforesaid fixed tenure of 15 days, but sought to be disengaged thereafter. The netitioner complained that by the time of his abrupt termination on 13-5-1973 he had completed 83 days service and thus carned a right to 14 days notice or equivalent salary in lieu thereof, but for the reasons better known to them the management did not abide by the agreement and so much so that they even turned a deaf our to his protests. He, therefore raised an issue through his Union. Since it defied any amicable settlement despite the intervention of the ALC. (C) at the Conciliation stage; hence the reference.
- 3. On joining the proceedings before this Tribunal the management raised a preliminary objection questioning the propriety of the Appropriate Government in making the reference because according to them, the same ve dispute between the parties had already been adjudicated upon by my predecessor Tribunal and so much so that even its Award had also been published in the Gazette of India. In short the principle of resjudicata, as envisaged by Section 11 of the C.P.C., was invoked and a photostat copy of the relevant Award in the previous dispute registered at No. 88/1977 was also filed.
- 4. On a careful scrutiny of the entire available data 1 am incline to sustain the management's objection because a mere perusal of photostal copy of the Award dated 13-3-1980 in the previous proceedings between the parties would leave no manner of doubt that the same very dispute had been referred by the Appropriate Government to my leatned predecessor per their Order No. L-12012/38/73/LRJII dated

Sile January 1976, and after having been contested on merus by the parties on an elaborate trial, the issue was returned against the petitioner; in short; his termination was held to be valid. In due course of time the Award was accepted by the Central Government per their Notification u/s 17 of the Industrial Disputes Act 1947 dated 28-2-1980 published in the Gazette of India dated 26-4-1980 at page No. 1221 in par. 14-Sec. 3(ii).

5. It goes without saying that neither in the Claim-statement nor any where in our schedule of reference any such indication is available which could vitiate the previous Award or justify any re-opening of the matter. I. therefore, on following the ratio of the case of L.H. Sugar Factories and Cil Mills Pyt. Ltd. Vs. Labour Court AIR 1961 S.C. 1457 sustain the management's objection against the maintainability of the instant preceeding and returns my Award against the petitioner/workman.

Chandigarh, Dated: 25-3-1986.

> I. P. VASISHTH, Presiding Officer [No. L-12012/138/73-LR. III/D. II (A)] N. K. VERMA, Dosk Officer

नई दिल्ली, 8 ग्राप्रैल, 1986

का. आ. 1678:—-भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारेख 30 सितम्बर, 1976 की ग्रिधिसूचना संख्या का. आ. 3871 द्वारा गठित औद्योगिक श्रिधकरण नई दिल्ली के पोठासीन श्रिधकारी का पद रिक्त हुआ है।

सतः, अत्र औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री जी. एस. कालरा को उक्त औद्योगिक अधिकरण में 6-4-1986 से पीठासीन अधिकार। के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं. एस. 11020/1/82-अ)-I(ए. II])

New Delhi, the 8th April, 1986

S.O. 1678.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal. New Delhi, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3871 dated the 30th September, 1976.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Kalra as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal with effect from 8-4-1986.

[No. S-11020(1)/83-D.I.(A) (ii)]

का. थ्रा. 1679:—-भारत सरकार के श्रम मंद्रालय की तारीका 30 सितम्बर, 1976 की ग्रिधिसूचना संख्या का. थ्रा. 4286 डारा गठित श्रम न्यायालय नई दिल्ली के पीठासीन ग्रिधिकारी का पद रिक्त हुआ है।

भ्रतः श्रव, औद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम 1947 (1947 का 14) की बारा 8 के उपबंधों के श्रनुसरण में, केन्द्रीय संग्कार श्री जी, एस. कालरा को उक्त श्रम न्यायालय में 8-4-1986 से पीठासीन श्रधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[सं. एस-11020/1/83-क्षी.-[(ए) (ji)] ए. की. एस. शर्मा, कैंस्क ध्रिधकारी,

S.O. 1679.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court, New Delhi,

constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4286 dated the 30th September, 1976.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Kalra as Presiding Officer of the said Labour Court with effect from 8-4-1986.

[No. S-11020(1) /83-D.I (A)(i)] A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1986

का. था. 1680:— अधिशिक विवाद प्रक्षिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रमुसरण में, केन्द्रीय सरकार य डी. की. सी. बरमी कीलियरी, डाक बरमी जिला गिरीडिह के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बान अनुबंध में निर्दिष्ट आँधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नं. 2, धनवाद के पंचाट को प्रकाशिन करलों है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-86 को प्राप्त हमा था।

New Delbi, the 9th April, 1986

S.O. 1680.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad.

As shown in the Annoxure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of DVC Bermo Colliery, P.O. Bermo District Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th April, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

PRESENT:

Shri J. N. Singha, Presiding Officer.

Reference No. 144 of 1985

In the matter of Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of DVC Bermo Colliery Dist, Giridih and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shvi R. V. Singh, President, DVC Karamchari Saugh.

STATE: Bihat. INDUSTRY: Coal. Dhanbad, the 31st March, 1986.

AWARD

The Govt, of India, Ministry of Labour in exercise, of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the L.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012 (33) 85-D. IV(B) dated the 16th October, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of DVC Bermo Colliery, P.O. Bermo, Distt. Giridin in denying promotion to Shri R. V. Singh to the post of Special Grade when the Orders have been issued in his favour by the Management is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

In this case both the parties filed their respective W.S. After completion of the document stage two adjournments were granted to the parties. But ultimately on 3-2-86 both the parties appeared before me and filed a memorandum of settlement. I have gone through the terms of settlement which appear to be fair and proper. Accordingly I have accepted the same and pass an Award in terms of the memorandum of settlement which forms part of the Award as Annexure.

Dt. 31-3-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer[No. L-24012]33[86-D. IV (B)]MADAN MOHAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, DHANDAD

Reference No. 144 of 1985 Management of DVC, Bermo Mines.

AND

Their Workman.

The parties above named beg to submit that the above case has been settled between the parties on the following terms:—

That it has been decided that the promotion of the concerned workman namely Shri R. V. Singh will be considered alongwith other cases by the management that in view of the above it has been decided that the workman or his representative does not want to proceed further with the above reference.

That the above terms have finally decided the dispute between the parties and no further adjudication is required.

It is therefore submitted that an award be passed in the terms mentioned above and the reference may be disposed, off accordingly.

For Employer, 111/- Illegible

For Workman.
R. V. SINGH, President
D.V.C. K. S. Bermo Mines
I. N. SINHA, Presiding Officer